Wednesday, June 22, 1977
Asadha 1, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Series)

Vol. II

Second Session, 1977/1899 (Saka)

(Vol. II contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 10, Wednesday, June 22, 1977/Asadha 1, 1899 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions:	
*Starred Questions Nos. 142, 144, 146 and 150 to 153	1—31
Short Notice Question No. 3	31—37
Written Answers to Questions:	
Starred Questions Nos. 143, 145, 147 to 149, 154 to 163	37—48
Unstarred Questions Nos. 1293 to 1309, 1312 to 1324, 1326 to 1364. 1366 to 1435, 1437 to 1475 and 1477 to 1484	48—192
Papers Laid on the Table	192—204, 347
Petition *Re.* release of Political Prisoners—	
Shri Dinen Bhattacharyya	204
Elections to Committees—	
(i) National Shipping Board	204-205
(ii) Committee on official languages	205-206
(iii) Coir Board	206
Business Advisory Committee—	
Second Report	206-207
Bills introduced—	
Cardamom (Amendment) Bill	207
Yoga Undertakings (Taking over of Management) Bill	207-208
Statement *Re.* Yoga Undertakings (Taking over of Management) Ordinance—	
Shri Raj Narain	208
Re. Calling Attention	208-209

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

General Budget, 1977-78—General Discussion . . 209—49, 268—346

Shri M. Satyanarayan Rao . . . . . 209—19

Shri M. N. Govindan Nair . . . . . 221—27

Shri Vijay Kumar Malhotra . . . . . 227—37

Shri Venugopal Gounder . . . . . 237—40

Shri U. S. Patil . . . . . 240—48

Shri Laxman Rao Mankar . . . . 248-49, 268—74

Shri Manohar Lal . . . . . 274—82

Shri B. C. Kamble . . . . . 282—87

Shri R. Venkataraman . . . . . 287—95

Shri Om Prakash Tyagi . . . . . 295—303

Shri Nawab Singh Chauhan . . . . . 304—11

Shri P. S. Ramalingam . . . . . 311—15

Shri O. V. Alagesan . . . . . 315—23

Shri Ramji Lal Suman . . . . . 325—29

Shrimati Chandravati . . . . . 329—38

Shri Manoranjan Bhakta . . . . . 338—43

Shri Sheo Narain . . . . . 343—46

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Pre-Election Political situation in Jammu and Kashmir and reported postponement of the Assembly election . . 250—68

Shri Chitta Basu 250, 252-53

Shri Shanti Bhushan . . . . . 250—52, 253—57, 262—68

Shri Vasant Sathe . . . . . 257—61

Statement *Re.* Power Shadding in Delhi and closure of Unit No. 1 in Badarpur Thermal Power Station . . . . . 347—50

Shri P. Ramachandran 347-48

LOK SABHA

Wednesday, June 22, 1977/Asadha 1, 1899 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मीसा और डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्य

*142. **श्री बन्ना सिंह गुलशन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान मीसा और डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्यों की संख्या क्या है; और

(ख) इन्हें किन-किन जेलों में नजरबन्द किया गया और इन्हें कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार दो महिला संसद् सदस्य मीसा के अधीन और एक भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द की गई थीं ।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आपातस्थिति के दौरान नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में सूचना

1. **श्रीमती विजयाराजे सिंधिया** : उन्हें बेसन लाज कम्पलैक्स पंचमदी, होशंगाबाद जिले में 9-7-75 से 2-9-75 तक नजरबन्द रखा गया । उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई :—

(क) अपना रसोइया, बिस्तर, कपड़े, लांड्री इत्यादि

(ख) अपने खर्चे पर समाचार पत्र और पत्रिकाएं

(ग) एक महिला वार्डन

(घ) चिकित्सा सुविधा

(ङ) अपने खर्चे पर एक परिचारिका रखने की अनुमति दी गई ।

2-9-75 को उन्हें केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया, जहां उन्हें 3-9-75 को दाखिल किया गया । उन्हें श्रेणी 'क' सुविधाएं प्रदान की गई । उन्हें 22-11-75 से 30-11-75 तक और पुनः 23-1-76 की पैरोल पर छोड़ा गया था । उनकी पैरोल की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी और उनकी नजरबन्दी का आदेश 12-2-77 को समाप्त किया गया ।

2. **श्रीमती शकुन्तला नय्यार** : उन्हें 9-10-75 को जिला जेल लखनऊ में नजरबन्द किया गया था । उनके साथ उत्कृष्ट श्रेणी के कैदी जैसा बरताव किया गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश सुरक्षा

बन्दी नियम, 1972 के अधीन दी जाने वाली सभी सुविधाएं दी गई थीं। उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। उन्हें एक पृथक रसोईघर की अनुमति दी गई थी। उनका खाना बनाने के लिए एक महिला कैदी उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रयोजन के लिए उन्हें बरतन भी दिये गये थे। उन्हें एक पृथक गुसलखाने की सुविधा दी गई थी जिसमें एक दरवाजा था।

श्रीमती नय्यर को अपना बिस्तर प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी और जब भी आवश्यक हुआ उन्हें कपड़े दिये गये। उन्हें कमरे से बाहर सोने की अनुमति दी गई। इस शिकायत पर कि मानसिक रूप से असंतुलित महिला कैदी रात्रि में उनको परेशान करती है, ऐसे कैदियों को जेल से हटाने की तुरन्त कार्यवाही की गई। जेल के वरिष्ठ अधिकारी सुविधाओं के बारे में उनसे सम्पर्क रखते थे और उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।

17-10-75 को महिला चिकित्सालय लखनऊ की सीनियर मैडिकल सुपरिंटेंडेंट ने श्रीमती नय्यर की परीक्षा की। डाक्टरी सलाह पर उन्हें 1-11-75 को पैरोल पर छोड़ दिया गया। पैरोल की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। नजरबन्दी का आदेश 21-1-77 को रद्द कर दिया गया।

3. **कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल** : उन्हें भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया और 15-8-76 की शाम को अहमदाबाद केन्द्रीय जेल में दाखिल किया गया। उन्हें 16-8-76 को छोड़ दिया गया। उन्हें जेल में एक चारपाई तथा कालीन प्रदान की गई थी।

श्री अन्ना सिंह गुलशन : क्या यह सच है कि भूतपूर्व संसद सदस्या महारानी गायत्री देवी को जयपुर जेल में पागल औरतों के साथ रखा गया और उनके साथ निन्दनीय ढंग से व्यवहार किया गया, रात को उन्हें सोने नहीं दिया गया, सोने के लिये चारपाई नहीं दी गई ?

श्री चरण सिंह : महारानी गायत्री देवी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में महिला वार्ड में रखा गया था। महिला वार्ड वहां पर सी-क्लास कैदियों के लिये है, इस लिये उन को तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन उन के लिये भोजन हम अपने बैरक में बनवा कर भेजते थे।

श्री अन्ना सिंह गुलशन : क्या वह सच है कि उन को पागल औरतों के साथ रखा गया था ?

श्री चरण सिंह : उन को पूरा पागल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर वहां पागल औरतें होतीं तो उन को लूनैटिक एसाइलम में भेजा जाता, इस लिये पूरी पागल औरतें उन के साथ नहीं थीं।

श्री शिव नारायण : जेल में केवल महारानी गायत्री देवी के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि दूसरी महारानियों भी थीं, श्री जार्ज फरनान्डीज़ के भाई के साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी आप कोई स्टैप लेने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : जेल में एमर्जेंसी के ज़माने में जो ज्यादतियां हुई हैं—शाह कमीशन के सामने वे सब बातें आयेंगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी भी उस समय दिल्ली जेल में हमारे साथ थे। क्या यह बात सही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में केवल एक ही महिला वार्ड है और उस में ही आधी पागल औरतों को, प्रीसेज़ को या जेबकतरी औरतों को रखा गया, जिस समय महारानी गायत्री देवी और महारानी सिंधिया

वहां मौजूद थीं? क्या यह सही है कि उन के पास अपना खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और आप के वार्ड से उन के लिये खाना बना कर भेजा जाता था ? अगर यह सब ठीक है तो क्या भविष्य में सुधार करने के लिये पोलिटीकल महिला कैदियों के लिये अलग से व्यवस्था की जायगी, हालांकि जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि पोलिटीकल महिला कैदी उनके कार्यकाल में नहीं होंगी, लेकिन यदि ऐसा हो भी तो उसके सुधार के लिये आप क्या करेंगे ?

श्री चरण सिंह : महारानी गायत्री देवी को तो 'कोफेपोसा' के तहत गिरफ्तार किया गया था। 'महारानी' सिंधिया भी वहां कुछ समय के लिये रही थीं यह ठीक है कि महिला वार्ड में हर प्रकार की महिलायें कैद थीं। लेकिन जहां तक पागल महिला का सम्बन्ध है, पागल को वहां नहीं रखा जा सकता था। अर्ध-पागल, विक्षिप्त वहां हो सकती है। लेकिन पूरी पागल कोई महिला उन के साथ नहीं थी।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह प्रश्न पूछा था चूंकि वहां एक ही महिला वार्ड है, इस लिये आइन्दा महिला पोलिटीकल कैदियों के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे है?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ है और होम मिनिस्ट्री में सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर जेलों में सुधारों को बाबत विचार हो रहा है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : वर्तमान संसद सदस्यों के अलावा क्या देश को विभिन्न जेलों में कुछ ऐसी भी दूसरी महिलाएं रही हैं जो कि भूतपूर्व संसद सदस्य हैं ? क्या इसकी जानकारी आप को है कि उन की संख्या कितनी है और कहां कहां वे रही हैं ?

श्री चरण सिंह : भूतपूर्व संसद सदस्याओं के विषय में यह प्रश्न नहीं है। उस के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मंत्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि हम भी तिहाड़ जेल में रहे हैं। वहां एक वार्ड में जो पागल औरतें रखी जाती हैं उनको शोक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसी एक ही जेल है जिस में पागल औरतों को रखते हैं, यह मंत्री महोदय को मालूम है ?

श्री चरण सिंह : यह तो नहीं मालूम है लेकिन मैं आप के तजुर्बे से इंकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपातकाल के समय में काफी महिलाओं को डी०आई० आर० के अन्दर लिया गया था और डी० आई० आर० में उन के खिलाफ़ मुकदमे चलाए गये थे। ऐसे केसेज अभी चल रहे हैं ? क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि डी० आई० आर० में जो ऐसे केसेज बनाए गये हैं, उन को पूर्णतया समाप्त किया जाएगा और वापस लिया जाएगा ?

श्री चरण सिंह : मैं इसके बारे में क्या कहूं। घोषणा तो पहले ही हो चुकी है और अब कोई केस डी० आई० आर० में नहीं है। कोई महिला इस वक्त डी० आई० आर० के अन्तर्गत डिटेंशन में नहीं है। यह एम०पीज० के मुताल्लिक सवाल था जो इस सदन की मेम्बर रही हों या राज्य सभा की मेम्बर रही हों। केवल तीन महिलाएं ही ऐसी थी एक थीं ग्वालियर की महारानी, दूसरी उत्तर प्रदेश की शकुन्तला जी और तीसरी कुमा

मणिबेन पटेल, सरदार पटेल की सुपुत्री । वे केवल एक दिन ही जेल में रहीं । बाकी दो के बारे में मैं ने बता ही दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपातकाल के समय काफी महिलाओं को डी०आई०आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उन पर आज भी केसेज चल रहे है । आप कहते हैं कि सब को छोड़ दिया गया है लेकिन मेरा कहना यह है कि सब के केसेज को वापस नहीं लिया गया है और उन पर केस चल रहे हैं । इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप फिर घोषणा कीजिए और उन के केसेज को वापस लीजिए ।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतने बल के साथ माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं उन से कहूंगा कि वे मेहरबानी कर के मुझे नाम बता दें और आज ही आर्डर जारी हो जाएगा ।

SHRI K. LAKKAPPA: I would like to know whether there are certain former rulers who were hoarding money, jewels and lots of black money.

MR. SPEAKER: That does not arise out of this.

SHRI K. LAKKAPPA: I want to know whether the present Government is not taking action against them for such things.

MR. SPEAKER: It is not proper. Do not provoke others. You can put a separate question about their hidden wealth etc.

SHRI K. LAKKAPPA: There are certain cases against Maharani Gayatri Devi under COFEPOSA for hoarding money, blackmarketing, keeping a huge amount of wealth etc. I want to know whether they are proceeding against them or not.

MR. SPEAKER: You should not provoke other people. Whether Shrimati Gayatri Devi has done something wrong or not, we are not discussing that now. It does not arise out of the question at all.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Only relevant supplementaries can be put. Should an opportunity be taken to defame people?

श्री अनन्त दवे : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जेलों में महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट सरकार के पास है ? यदि है तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेना चाहती है ?

श्री चरण सिंह : अत्याचारों का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । मैं अर्ज कर चुका हूं कि यदि अत्याचार हुए हैं तो वे शाह कमीशन के पास जाएंगे ।

प्रधान मंत्री सहायता कोष

*144. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रधान मंत्री के सहायता कोष में कुल कितना धन है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उक्त कोष में कितना धन था तथा इस कोष का मुख्य स्रोत क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस कोष के लिए धन दिया तथा उन्होंने कितना-कितना धन दिया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से कितना धन खर्च किया गया तथा इसको किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 31 मई, 1977 तक 11,89,63,994·83 रु० शेष था ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक लेखा वर्ष (जुलाई से जून तक) के अन्त में उक्त कोष में शेष इस प्रकार था :—

1973–74	87,51,977.57 रु०
1974–75	89,87,145.00 रु०
1975–76	10,77,59,940·99 रु०

इस कोष के मुख्य स्रोत लोगों द्वारा समय समय पर दिये गये अंशदान तथा बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल अंशदान इस प्रकार है :—

1973–74	22,19,153.82 रु०
1974–75	32,12,853.72 रु०
1975–76	11,61,01,768.55 रु०

सदन की मेज पर उन अंशदाताओं के नाम तथा उनके अंशदान के विवरण रख दिए गए है जिन्होंने बड़ी मात्रा में अंशदान दिये हैं [**विवरण ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** L.T. 472 77]

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से इस प्रकार धन खर्च किये गये :—

1973–74	20,95,243.44 रु०
1974–75	36,06,207.84 रु०
1975–76	2,00,12,810.00 रु०

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, खान दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से यह धन बांटा गया । सहायता कार्य में लगे कुछ संगठनों को अनुदान दिये गये। ऐसे कुछ व्यक्तियों को भी अनुदान दिये गये जिनके सामने वित्तीय संकट था, जिसका मुख्य संबंध उनकी शिक्षा तथा चिकित्सा की समस्याओं से था, जिससे कि वे अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को पार करने में समर्थ हो सकें । एक दो परोपकारी कोषों में भी अनुदान दिये गए ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री जी की जानकारी में यह है कि 1975–76 में श्री आर एच को जो हैड हैं आर० ए० डब्ल्यू० के उनके परामर्श से उन्हीं के परिवार के लोगों को बड़ी धनराशि दी गई ? क्या इस की केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस पर केन्द्रीय सरकार कोई आयोग या इसी सदन और राज्य सभा के पांच पांच या सात सात सदस्यों की कोई जांच कमेटी बिठा कर इस की जांच कराएंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी जांच बिठाने की जरूरत नहीं है । मैं जांच कर लूंगा ।

श्री बलवीर सिंह : जांच करने के बाद अगर यह पाया गया कि यह धनराशि ठीक ढंग से खर्च नहीं की गई, गलत ढंग से की गई है तो कोई एकशन भी आप उनके खिलाफ लेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : जो जरूरी काम होगा वह करेंगे ?

Shortage of Houses for Scheduled Castes in Delhi

*146. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government or any of its agencies have made a survey of

shortage of houses for Scheduled Caste families in Delhi;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) how many dwelling units have been constructed for Scheduled Caste families in Delhi in the last three years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). While no special survey as such has been conducted, the following two schemes have been in operation during the last three years:

(i) *Grant of financial assistance by the Delhi Administration.*—3492 Scheduled Caste families have been given financial assistance.

(ii) *Allotment of flats by way of reservation by the Delhi Development Authority.*—3165 flats have been allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes families.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि दिल्ली में करीब दो लाख डवैलिंग यूनिट्स की जरूरत है और उन में से अधिकांश शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिन के पास मकान नहीं है। पहली सरकार ने जो पैसा दिया वह बहुत कम था और नाममात्र को ही दिया था। क्या मंत्री महोदय दुबारा सर्वे कराएंगे कि दिल्ली में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कितने मकानों की जरूरत है ? सर्वे करा करके आगे इस साल या अगले साल उनको ज्यादा मकान मिलें क्या इस प्रकार की कोई योजना आप बनाएंगे ?

श्री चरण सिंह : सवाल तो आसानी से हो गया लेकिन जवाब मुश्किल है। आपने यह जो कहा कि दो लाख मकानों की जरूरत है यह मैं नहीं मानता हूं। इसका कारण यह है कि 1971 में 40 लाख 65 हजार 700 जनसंख्या थी। उस में से शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या थी 6 लाख 35 हजार 700। पांच आदमियों के पीछे एक डवैलिंग यूनिट चाहिए। इस तरह से एक लाख 26 हजार चाहियें। अब आबादी बढ़ गई है। डेढ़ लाख हो गई होगी। डेढ़ लाख में से एक लाख तो निकल गए। वे आज आखिर सड़कों पर तो नहीं रह रहे हैं। पचास हजार की आवश्यकता है। अब क्या स्कीम बनेगी वह इसके ऊपर निर्भर करता है कि माननीय सदन कितना रुपया हमें देगा। गुप्त जी इसमें मदद करेंगे ऐसा मैं मानता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय बताएंगे कि 3492 परिवारों को जो रुपया दिया है उनको कुल कितना दिया है और बजट में आपने इस चीज के लिए कितना रुपया इस साल मांगा है ताकि हम उतना दे सकें ?

श्री चरण सिंह : आपने तीन साल का सवाल किया है, 1974-75, 1975-76 और 1976-77 का। तो 1974-75 में 12 लाख रु०, 1975-76 में 18 लाख रु० और 1976-77 में 10 लाख और अब मौजूदा साल चल रहा है इस में इस के लिए रखा गया है 24 लाख 50 हजार रु०। तो इस प्रकार 64 लाख 50 हजार रु० बैठता है।

SHRI P. K. KODIYAN: May I know from the hon. Minister, whether apart from giving houses to the Scheduled Caste people in Delhi, there is any proposal to provide them developed land so that with the money received from Government out of the grant they can construct their own houses?

SHRI CHARAN SINGH: I would say that there are two kinds of schemes: under one scheme—provided the man concerned can produce Rs. 500 of his own—the Development Authority will provide Rs. 1500 in three instalments and there is another condition attached to it and that is the plot should be of 60 sq. yards. Then alone this sum of Rs. 1500 will be given to him.

श्री समर गुह : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है बल्कि और भी बड़े बड़े शहरों की है जहां लाखों की तादाद में आदमी मकान-हीन हैं जो बेचारे रास्ते में रहते हैं और रात भी रास्ते में बिताते हैं। यह लोग अधिकतर शैड्यूल्ड कास्ट के हैं। तो क्या आप सोचेंगे कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि में जहां होमलैस लोग हैं उनको रीहेबिलिटेट करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

MR. SPEAKER: The question will be wide. You may answer it. But the other questions will suffer. If you raise questions about Bombay and Calcutta, the other Members will raise questions about Hyderabad and Bangalore.

SHRI SAMAR GUHA: I have used the word etc.

MR. SPEAKER: Members stand to suffer. The other questions will go unanswered. If you ask questions about Bombay, Calcutta, Allahabad and Lucknow, somebody may ask questions about Gwalior. You will lose the time of the question hour.

New Projects for Power Generation

*150. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any new projects for power generation have been installed in various parts of the country; and

(b) if so, places where they have been located?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). Yes, Sir. Many new projects have already been commissioned in various parts of the country during the first 3 years of the Fifth Five Year Plan. The total Hydro and Thermal capacity installed in 1974-75, 1975-76 and 1976-77 is 5236.4 MW. The units have been installed in various parts of the country *viz.* Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Orissa, West Bengal, Assam, Bihar, Tripura, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Punjab, Haryana, Delhi, Damodar Valley Corporation area and Madhya Pradesh.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the hon. Minister has stated in his reply certain new projects which have already been commissioned in various parts of the country. I would like to know whether he has taken note of the Fifth Plan outplay which is about Rs. 7000 crore which is meant for generation of hydro and thermal capacity for these projects? But before that, there is a point regarding stagnation of industrial growth in the country. They are not only lagging beyond these needs for industrialisation but there are other facilities which are required on which the growth of various States including Maharashtra, West Bengal—except Kerala—and Karnataka depends. The power shortage is very acute. It is mainly because of lack of understanding and coordination between the national policy evolved and the functioning of the various State Electricity Boards. May I know whether the Minister has taken note of the need to have certain national involvement, to adopt a national policy, by creating new projects in various parts of our country. During the tenure of his office in the last two months....

MR. SPEAKER: Ask your question.

SHRI K. LAKKAPPA: My question is this. What is the national involvement of the present Government in this?

SHRI P. RAMACHANDRAN: The hon. Member is referring to industries as well as power. I do not know whether I can answer on behalf of the Minister of industries. But as far as power is concerned, this Government will try to coordinate the requirements of the various States with regard to power deficit. In fact, we are trying to identify the various schemes in various States and are trying to take necessary steps for implementing the projects as and when they are brought before the Central Government. This responsibility is mostly of the State Electricity Boards. Whenever they evolve a scheme and present it before the Central Government, the whole scheme is scrutinised and wherever sanction is necessary, that is accorded. There is no question of non-coordination between the State Governments and the national Power Ministry. There is perfect understanding between the national Power Ministry and the State Electricity Boards, and nothing is required in this matter. Nothing is lacking on the part of the Central Government in implementing the schemes.

SHRI K. LAKKAPPA: He has not answered my question at all. My question was this. What is the national involvement of the present Government regarding power generation in the country and its distribution throughout the country?

SHRI P. RAMACHANDRAN: The national involvement is that some of the super thermal power stations are being considered, and when they are considered and implemented, the power will be put into the national grid. I do not know what the hon. Member wants to know from me; I do not know what he means by 'national involvement'; I am not able to understand his question.

SHRI K. LAKKAPPA: That is because there is no national involvement of your Government.

MR. SPEAKER: This is Question Hour. When the Demands come, policies will be discussed. In the question Hour I do not think that a Minister like Mr. Ramachandran can answer questions on policies. When the Demands come, the Members can certainly raise questions on policies and Government will come prepared to answer those questions.

Now, Mr. Lakkappa may put his second question.

SHRI K. LAKKAPPA: Taking into account the concern of the Ministry regarding the acute power shortage in various parts of southern India, may I know whether, as a short-term measure, Government is thinking of taking up the Karnataka Thermal Project which is under consideration, and by what point of time they will be able to meet the acute power shortage in the country and make this country an industrialised country?

SHRI P. RAMACHANDRAN: The hon. Member was asking about Karnataka Thermal Power Station. I do not know whether he is referring to the Mangalore Thermal Power Station.

As far as this is concerned, it has not yet come up. Techno-economically it has not been approved by the CEA as we are not yet sure what the load demand will be.

With regard to Karnataka, particularly after the completion of the Kakinadi project and also the super-thermal station that might come up in the southern region, we might be able to fill up the gap or the deficiency that has arisen. That is why it is pending techno-economic approval of the CEA.

With regard to the deficit he has referred to, all steps are being taken by the Department to fill up the gap that is likely to arise in the southern region. We have a number of projects on hand and they will be completed by the end of the Fifth Five Year Plan.

श्री ईश्वर चौधरी : बिजली की कमी के कारण हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे काम पीछे पड़ गए हैं। बिजली उत्पन्न करने के लिए बहुत सी परियोजनायें काफी लम्बे समय से चल रहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कितने समय में बिजली के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

SHRI P. RAMACHANDRAN: As for self-sufficiency in power, we hope to achieve it by the end of the Sixth Five Year Plan when all the projects that are on hand and also those in progress are commissioned.

SHRIMATI V. JEYALAKSHMI: May I know from the hon. Minister of Energy the total capacity of the Tuticorin plant and when that plant will be finalised?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Two units of the Tuticorin thermal plant are to come up next year, i.e. in 1978-79. By the end of 1978-79 the two units are expected to be on stream. The third unit is under consideration.

The total capacity of the plant is 400 MW

SHRI BASHIR AHMAD: Will the Hon. Minister state whether the electric and thermal installations will be made by the Central Government or whether they will be entrusted to the State Governments?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Some of the projects will be commissioned by the State Governments and some will be in the Central sector.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You are aware that due to shortage of power, West Bengal industrial are suffering and industrial production is going down. I would therefore like to know from the Hon. Minister whether the Government has any proposal to instal a super-thermal power station at Raniganj. What are the concrete proposals of the Government for saving West Bengal from the power crisis?

SHRI P. RAMACHANDRAN: There is no proposal for a super-thermal station at Raniganj at present, but all steps are being taken to fill up the gap that has arisen for want of power in West Bengal.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : खेती के लिए बिजली की कमी है और उस के अभाव में खेती मारी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि खेती के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है, उस को पूरा करने में कितना समय लगेगा और उस के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Enough energy will be made available to the agriculture sector and we are working in that direction.

SHRI K. A. RAJAN: As all of us find, there is a power crisis all over India. Kerala is a place, where there is high potential of hydro-electric power. I would like to know, whether the Minister would give preference to the hydro-electric power for easing the situation and sanction more schemes that have already been proposed?

SHRI P. RAMACHANDRAN: All the schemes that have come to the Central Government for scrutiny are being scrutinised and as and when the final report is available, these schemes are being sanctioned.

श्री चन्दन सिंह : सभापति महोदय, कृषि के लिए कृषकों को जो बिजली मिलती है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्या रेवेन्यू कम करने की कृपा की जाएगी ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Whether the rates are to be reduced or not is the concern of the State Governments. They have to take any step that is required for the reduction of the agricultural rates.

MR. SPEAKER: A large number of Members want to put supplementaries on this question. I know, it is an important question and I have no objection if we spend the rest of the question hour on this question, but I think, at the time of Demands, we can discuss this. During the question hour, we cannot spend so much time on one question. What will happen to the other questions? Please do not misunderstand me; permit me to go to the next question. A number of members from Andhra Pradesh want to put questions on this.

SHRI P. RAMACHANDRAN: Their demands will also be considered.

Broadcasts and Telecasts by Political Parties for Assembly Elections

*151. DR. BIJOY MONDAL:

SHRI DHARM VIR VASISHT:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) in view of the experience gained through equal number of broadcasts and telecasts for equal time by all the recognised political parties during the recent poll for a number of Legislative Assemblies of States, whether Government propose to make these features regular for all elections in future; and

(b) the difficulties and drawbacks, if any, experienced during the broadcasts and telecasts, and efforts made to overcome them?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Akashvani

The difficulties experienced by the concerned stations of Akashvani were: (i) delays in getting names of spokesmen of political parties in time; (ii) spokesmen nominated by the State Units being different from those nominated by the Central Offices of the same parties; (iii) substitution of the spokesmen for one reason or another; and (iv) delays in scripts and recordings. The difficulties were sorted out by the stations of Akashvani by contacting the State Units and/or the Central Offices of the concerned political parties.

Doordarshan

By and large no difficulties were experienced by the concerned Doodarshan Kendras. As regards drawbacks, if any, it is felt that a solo performance by a single speaker for fifteen minutes does not make a good telecast and cannot always sustain the viewers' interest. It is tentatively felt that the duration of such a solo telecast should not be more than ten minutes. Alternatively, the format that can be tried is the interview format, in which a political party telecaster is interviewed by an interviewer of his or his party's choice. All these things will be considered after a proper assessment of the party telecasts has been made.

DR. BIJOY MONDAL: During broadcasts and telecasts, political parties other than the ruling one occasionally make vague and wild allegations against the ruling party and in some cases in a distorted way. I would like to know, whether the ruling

party either in the Centre or in the States shall be allowed time to answer such allegations and give adequate and proper explanation each time?

SHRI L. K. ADVANI: I am very happy that this time the experience has shown that all the political parties have cooperated fully in ensuring that this media is used in a proper manner. In certain cases where it was pointed out to the person concerned that this goes against the code of conduct agreed among the parties, it was immediately altered. Therefore, the question does not arise.

DR. BIJOY MONDAL: Has the Government made any evaluation of the impact on the rural and backward areas? If so, with what results?

SHRI L. K. ADVANI: At the moment, a comprehensive survey is going on, but the preliminary survey that has been made shows that this new experiment that we have launched has been very well received particularly in the rural areas. So far as the urban areas are concerned and the press is concerned, it has been very widely acclaimed and appreciated.

श्री धर्म वीर वशिष्ठ : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समान अवसर दिया गया लेकिन समान समय देने में क्या सरकार यह भी विचार करेगी कि जो बड़ी पार्टीज हैं जो अधिक सीटें लेकर आई हैं उन को कुछ ज्यादा समय दिया जाय और जो कम या कोई सीट लेकर नहीं आई उन को कम अवसर दिया जाये ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और जब सब पार्टियों के प्रतिनिधि मिले थे तब हम ने यह निर्णय किया कि एलेक्शन कमीशन जिन-जिन दलों को मान्यता देता है उन मान्यता-प्राप्त दलों को समान अवसर दिया जाय।

PROF. P. G. MAVALANKAR: While congratulating the Minister and the Government for taking this initiative of starting Party political broadcasts at election time for the first time in our country during the last 30 years, may I ask him whether he and the various political parties have taken into account the experience already gained in this regard by a number of democratic countries, particularly, Great Britain and the United States and in view of that, should we not consider the question of giving proportionately more time to larger parties and lesser time to smaller parties so that the whole purpose of projecting the various points of view of the parties is achieved? I would also like to know whether these broadcasts, particularly discussions and interviews are extempore or the radio and television authorities want the parties to submit the scripts of their talks in advance.

SHRI L. K. ADVANI: The experience of all countries is always relevant. But I would say that the experience of our own country is far more relevant and, therefore, if there is to be a second look at this, it will have to be in the light of the experience that we have now gained.

I might mention that so far as the scripts are concerned, they were never pre-edited or pre-censored or subject to anything except that they should conform to the guidelines that we have accepted for ourselves and wherever it was pointed out to the member concerned that this goes against the guidelines, it was voluntarily altered.

Secondly, I would also like to point out that there have been certain suggestions made by the Doordarshan Department itself that a 15-minute telecast does not make for a good telecast and that maximum period should be 10 minutes. Therefore, all these suggestions for the revision of the whole scheme or even adopting the format of interviews rather than a

straight talk, are to be considered again in consultation with all political parties.

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आचार-संहिता जैसी चीज बनाने के बारे में विचार कर रही है ताकि राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार के पिछले आरोप न लगा सकें ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : जो व्यापक प्रश्न है, उस के साथ इस का सम्बन्ध नहीं है। जहां तक रेडियो, टैलीविजन, पर ब्राडकास्ट करने की बात है, उसके लिए कुछ गाइड-लाइन्ज स्वीकार कर ली गई थीं और उन्हीं के अनुरूप सारे भाषण हुए।

Discontentment among the Employees of M/s Alcock Ashdown & Company, Bombay

*152. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is great discontent among the employees of M|s Alcock Ashdown & Company, Bombay due to highhandedness of the Personnel Officer;

(b) whether several employees' employment letters providing them permanent employment have been withdrawn; and

(c) whether the Mazagaon Dock Authorities have decided to employ fresh workers instead of those rendered surplus in the M/s Alcock Ashdown?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) No, Sir. Industrial relations in the Bombay unit of M/s Alcock Ashdown & Company are at present quite normal.

(b) No, Sir.

(c) It is the policy of Mazagon Dock Limited to give preference in the matter of employment to the ex-employees of Alcock Ashdown & Company Bombay, subject to their suitability and availability of vacancies. No decision has been taken by the Shipyard to employ fresh workers, ignoring the claims of ex-employees of M/s Alcock Ashdown.

डा० बापू कालदते : 1970 में इस कम्पनी में लाक आउट हुआ था, 1971 में इस को एक्वायर किया गया। 1971 से आज तक इस पुरानी कम्पनी में जितने कर्मचारी थे, उन में से कितनों को मझगांव डाक में एब्जार्ब किया गया ?

SHRI RAVINDRA VARMA: At the time of acquisition of this company, the Mazagon Dock had given an assurance to the Government of Maharashtra that they would endeavour to reemploy as many ex-employees of M/s Alcock Ashdown as possible keeping in view the availability of vacancies and their fitness for the jobs. The hon. Member asked me to state how many of them have been absorbed in the Mazagon Docks. The present position in this ragard is that out of 932 ex-employees, 760 responded for employment by Mazagon Docks by completing the pro-forma prescribed by the company. Out of this 760, 522 have already been employed in the Mazagon Docks.

This is the position as on 31-5-77. As I stated earlier, Mazagon Dock will make every effort to absorb them. The position is that out of the rest 67 did not report for test or interview. 87 refused to accept employment in the Mazagon Docks. 2 were rejected on medical grounds. 38 were disqualified for absorption due to superannuation and 44 are being processed for possible absoption.

It can thus be seen that every effort is being made to re-employ them according to the assurance given by the Mazagaon Dock.

डा० बापू कालदते : यह बात सही है कि अबजोर्ब करने की कोशिश की जाती है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, एक स्टोर सुपरवाइजर जब उन के पास नौकरी के लिए गए, तो उन्होंने उस को पोर्टर की नौकरी देने का वायदा किया। इस ढंग से अगर अबजोर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो हो सकता है कि लोग उन के पास नौकरी के लिए न जाएं। क्या ऐसे कुछ कैसेज आप के नोटिस में आए हैं ?

SHRI RAVINDRA VERMA: There have been no such cases brought to our notice. But if the hon. member brings such cases to our notice they will be considered because the effort of the Mazagaon Dock is to match suitability with job specifications.

श्रीमती मृणाल गोरे : जब 1971 में इस कम्पनी को एक्वायर किया गया था उस वक्त के मंत्री महोदय, श्री टी०ए० पाई साहब ने इस सदन में ही कहा था कि मजदूरों के जो ड्यूज हैं, वे उन को मिल जायेंगे लेकिन अभी तक वे ड्यूज उनको नहीं मिले हैं ?

SHRI RAVINDRA VERMA: I am surprised to hear the statement of the hon. member. I have not checked up the verbatim report of the debates or the statements made at that time but as far as records show, the Government made it amply clear at the time of acquisition that they were not taking over responsibility for the dues of the employees of M/s. Alcock Ashdown & Company. Liabilities were not taken over. Only the assets were taken over.

It was made absolutely clear that the Government was not responsible for the payment of the prior dues for which the Company was responsible.

श्रीमती मृणाल गोरे : कम्पनी के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जा रही है। जब इस कम्पनी को लिया गया था तो यह कहा गया था कि मजगांव डाक्स जिम्मेदार नहीं रहेगा और सरकार ने यह जिम्मेदारी ली थी कि ड्यूज देंगे ?

SHRI RAVINDRA VERMA: At the time of taking over it was made clear that the Government will not be responsible for the payment of dues. Since the hon. member is keen to know the position, I may mention that Turner Moris has gone to the Supreme Court against the High Court's decision on the question of assets claiming that the compensation that was set for them was illusory and that was perhaps the reason why they were not able to make payments. As the hon. Member perhaps knows the Alcock Ashdown Acquisition Act was included, in the omnibus Ninth Schedule by the then Government.

That too is a matter which is under dispute in the Supreme Court.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The hon. Minister is aware of the Bombay City as I am. He must know that M/s. Alcock Ashdown & Company is physically next to Mazagaon Docks. I would like to know from him whether he has received representation from the unions there for the take over and absorption of this Company by the Mazagaon Docks and whether he would take suitable action on the principal events that have been placed before the Government by the unions?

SHRI RAVINDRA VERMA: No representations have been received of the kind that the hon. member referred to. Representations have been received regarding the payment of dues, a reference to which has been made by Shrimati Gore.

On the other question that has been raised by the hon. member regarding the Union's raising certain questions in the normal manner, and their being

discussed by the Management with the two labour unions of the employees in the Dockyard there is no information with us to suspect that the grievances are not being looked into.

पुलिस हिरासत में बन्दियों की मृत्यु के बारे में जांच के लिए आयोग

*153. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत तीन वर्षों में पुलिस की हिरासत में अथवा जेल में बन्दियों की मृत्यु की जांच करने के लिए सरकार का विचार पृथक्-पृथक आयोग अथवा एक आयोग नियुक्त करने का है जिससे यह निश्चित किया जा सके कि क्या उन सभी व्यक्तियों की रोग से प्राकृतिक मृत्यु हुई अथवा कुछ बन्दियों की हत्या कर दी गई और क्या केवल भागने वाले कैदी ही सुरक्षा गार्डों की गोलियों से मारे गए ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां कहीं बन्दियों की मृत्यु के बारे में किसी बुरे इरादे का संदेह किया जाता है वहां जांच बैठाने का काम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। न्यायमूर्ति जे०सी० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आपात स्थिति के दौरान और उसके तुरन्त पहले की अवधि में हुई बन्दियों की मृत्यु के मामले आते हैं और जिन लोगों को शिकायत है वे इस बारे में आयोग को अभ्यावेदन दे सकते हैं ।

श्री मृत्युन्जय प्रसाद वर्मा : प्रश्न के उत्तर में जैसा कहा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का विवरण देने वाले तो अब रहे नहीं, वे तो मर गये है । जो बचे भी हैं उनके पास सबूत नहीं हैं । जो लोग जेलों में मर जाते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि वे बीमारी से मर गये थे या भागते हुए मारे गये जब कि उनको बैठे बिठाये मार दिया जाता है । इस प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों के गवाह मौजूद हैं और इस सदन में भी मौजूद हैं । वे जानते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार की हालत में मरे हैं, बीमारी से मरे हैं या मार दिये गये हैं । पहले किसी को भी पता नहीं था कि केरल में राजन की हत्या कर दी गयी है, दिल्ली में सुन्दर डाकू की हत्याकर दी गयी है । हम तो यह जानते थे कि सुन्दर डाकू डूब गया था । लेकिन अब सन्देह होता है कि वह मार दिया गया । इसी तरह के बहुत से मामले सरकार के सामने आयेंगे अगर आपकी ओर से कोई जांच करायी जाये और साथही साथ इस प्रकार के मामलों की जांच कराने के लिए प्रदेश सरकारों को आदेश दिये जाएं या सुझाव दिये जाएं । क्या सरकार ऐसी जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सुझाव भेजने की कोई जरूरत नहीं है । अगर उनके यहां अन्याय हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है कि वे इस सम्बन्ध में जांच कराये या जो ठीक समझें कदम उठाये । वहां पर भी जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं . उन्हीं से चुनी हुई सरकार है । अगर इस प्रकार के कोई मामले हैं तो वहां उठाये जा सकते हैं और वहीं उठाये जाने चाहिएं ।

दूसरी बात मैं अर्ज कर चुका हूं कि एमर्जेंसी के दौरान जो अन्याय हुए हैं उन्हें शाह कमीशन के पास भेजा जा सकता है । अगर किसी मामले में कोई शिकायत मौजूद नहीं है तो कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, न यह गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और न वह गवर्नमेंट कुछ कर सकती है । अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो कमीशन के पास भेज दीजिए । अगर किसी मामले में

शहादत मौजूद नहीं है तो केसिज भेजे जा सकते हैं। हमने योग्य से योग्य पुलिस अधिकारियों को इस काम के लिए मुकर्रर किया है। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो शाह आयोग को उपलब्ध न हो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार की शिकायतों की जांच शाह आयोग करे या गवर्नमेंट की अन्य कोई ऐजेंसी करे।

श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा : इसी प्रकार बीमारी के नाम पर बहुत से आदमी मर गये हैं लेकिन उनके बारे में शंकाएं होती हैं कि वे मरे नहीं बल्कि मारे गये हैं। जय प्रकाश जी भी बीमार है। उनके बारे में भी कहा गया था कि उनके गुर्दे खराब हो गये हैं लेकिन खराब नहीं हुए बल्कि खराब किए गए अब ऐसी शंका होने लगी है। अतः मैं चाहता हूं कि जिन कैदियों को जेलों में खाने-पीने और रहन-सहन की ठीक सुविधाएं नहीं दी गयीं और वे इस कारण से बीमार होकर मर गये, उनके बारे में सरकार को जांच करानी चाहिए। क्या सरकार इस बारे में जांच कराना चाहती है ? ताकि आगे सुधार हो सके और इस तरह के वाकयात कम से कम हों।

MR. SPEAKER: It is more a request and not a question.

श्री लक्ष्मण राव मानकर : महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डा० गोवडे जो नागपुर मेडिकल कालेज में मर गये थे उनके सम्बन्ध में जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया है। नागपुर में जो लोग इस कमिशन के सामने एवीडेंस देने के लिए गए उनको ठीक से एवीडेंस देने नहीं दिया गया। उनको इसका मौका नहीं दिया गया। इस बारे में जो एवीडेंस देने वाले लोग थे उन्होंने उस कमिशन का बहिष्कार किया। क्या यह बात सत्य है। अगर सत्य है और ऐसी बात होती हो तो इसके बारे में आप क्या करेंगे ? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वह इन चीजों को छिपाना चाहेगी। इसलिये जनता सरकार क्या करने वाली है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री चरण सिंह : महाराष्ट्र में अगर कांग्रेसी सरकार है और अगर वह कमिशन नहीं बिठाएगी तो शाह कमिशन के सामने मामलों को रखा जा सकता है।

श्री लक्ष्मण राव मानकर : वहां कमिशन नियुक्त हुआ है। वहां लोगों को उसके सामने ठीक से एवीडेंस देने का मौका नहीं दिया गया है। इसके बारे में आप क्या करेंगे ?

MR. SPEAKER: After all, the Minister has already answered that it will go before the Commission. Please sit down. I have called Shri Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : एमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई हैं उन की इनक्वायरी के लिए आपने कमिशन बिठाया है। जब से आपने कमिशन बिठाया है तब से विभिन्न राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट आफिसर्स ने उन रिकार्डज को खत्म करना शुरू कर दिया है जिसके आधार पर उन ज्यादतियों को साबित किया जा सकता है। इसको रोकथाम के लिये आपने क्या उपाय किया है ?

श्री चरण सिंह : इसके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। जिन अधिकारियों के पास रिकार्ड है उनका फर्ज है कि वे उसको सुरक्षित रखें। अगर कहीं इसको डेसट्राय किया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है, कत्ल वगैरह कभी नहीं छिपता। अगर ऐसा कोई मामला हुआ है और पुलिस उसमें तहकीकात करेगी तो यह सच्चाई सामने आ जाएगी बावजूद इसके कि रिकार्ड नष्ट किये गये हैं। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। अखबारों में खबर निकल

चुकी है। चार एफ० आई० आर० यहां दिल्ली में दर्ज हो चुकी हैं। कम से कम एक केस का तो मुझे मालूम है कि रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी पुलिस ने मालूम कर लिया। दूसरा एक और केस है। उसमें भी कुछ अफसरों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। मुमकिन है कुछ और केसिस में रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई हो लेकिन सच्चाई सी० बी० आई० के इन्वेस्टीगेटर ने फिर भी मालूम कर ली। अब गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके कि अफसरों से उम्मीद की जाये कि वे सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें, रिकार्डज को सुरक्षित रखें मेरी समझ में नहीं आता हमारे पास और उपाय क्या बाकी रह जाता है सिवाय इसके कि एक और आदेश इसके बारे में निकालें। लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। उनका आलरेडी फर्ज है रिकार्ड सुरक्षित रखने का।

श्री लक्ष्मण राव मानकर : डा० गोबडे की मृत्यु हुई नागपुर मैडीकल कालेज में। उनको हार्ट अटैक हुआ था। उनको वहां सर्जिकल वार्ड में रखा गया पुलिस के आर्डर से जब कि उनको इंटैंसिव केअर यूनिट में रखना चाहिए था। जो लोग एवीडेंस देने के लिए गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन के सामने उनको देने नहीं दिया गया और उन्होंने कमीशन का बहिष्कार किया ? इस तरह की जो चीजें हैं इस सम्बन्ध में आप क्या करने वाले हैं ?

MR. SPEAKER: The hon. Member may please sit down. He has already answered.

SHORT NOTICE QUESTION

Film "KISSA KURSI KA"

3. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the film "Kissa Kursi Ka" was stolen from Government office;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon; and

(c) whether the film was burnt?

'THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). The film "Kissa Kursi Ka" was forfeited to the Central Government by an order issued under rule 51(1) of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 on 14-7-1975. Negatives and prints of this film were taken into custody and kept with the Films Division of the Ministry of I&B. Recently on request from the Film producer for the return of the prints, a preliminary enquiry was made in the Ministry of Information and Broadcasting which disclosed that the prints as well as the negatives were not traceable and foul play was suspected in their disappearance. On the request of the Ministry, the CBI registered a case on 13-4-77 under sections 120-B r/w 380 IPC and took up investigation. In the course of their investigation, empty cans along with labels indicating storage of rolls of this film in the cans were recovered following a search of the premises of Maruti factory at Gurgaon on 25-5-77. The available evidence points to the film having been destroyed by being burnt. Investigation is in the final stage.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही महत्व का है और यह सम्बन्ध रखता है जो पावर हन्गरी और करप्ट पोलीटीशियन्स हैं जो जनता को दबा कर और किसी तरह भी कुर्सी पर बैठना चाहते थे, उस के बारे में यह फिल्म थी और यह पहली फिल्म है जो डी० आई० आर० में बन्द कर दी गई, लेकिन उस के बाद भी कुर्सी बची नहीं। तो मैं मंत्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो फिल्म बन्द की स्क्रीनिंग के लिए वह मेरी सूचना के अनुसार मंत्री महोदय ने मिनिस्ट्री में बन्द की । तो क्या ग्रौबजेक्शन लगाये गये थे इस फिल्म के खिलाफ जिसकी वजह से उसकी स्क्रीनिंग बन्द की ?

दूसरी बात यह कि क्या यह सही है कि प्रोड्यूसर महाराज सुप्रीम कोर्ट में गये थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया सरकार को कि यह दो बार फिल्म दिखाई जाय ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सके कि यह फिल्म ठीक है कि नहीं ? तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आया ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डी० आई० आर० में बन्द नहीं की गई। यह सिनेमाटोग्राफिक एक्ट जो है उसके तहत इस पिक्चर को बन्द किया गया। इसका फारफीचर किया गया डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत ।

जहां तक दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, यह बात सही है कि जब इसके प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट में गये तो उन्होंने जो अनेक याचिकायें वहां पर प्रस्तुत की उनमें से एक यह भी थी कि यह कोर्ट ही स्वयं इस फिल्म को देखे और फिर निर्णय करे । और इस सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन्हें यह फिल्म दिखाये और उसकी तारीख भी तय हुई कि 17 नवम्बर, 1975 को फिल्म दिखाई जाएगी । सरकार ने स्वीकार भी किया । लेकिन एक सप्ताह पूर्व 11 नवम्बर को कोर्ट को सूचना दी गई सरकार की ओर से कि उस फिल्म को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हो रही है । फिर उसके बाद एक, दो मौके और दिये सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म को ढूंढने के । लेकिन सरकार ने कोर्ट को सूचना दी कि इंटरनेशनल फिल्म फैस्टीवल हुआ था उसमें बहुत सारी फिल्स आई थीं और यह फिल्म उनके साथ मिल गई है इसलिए प्राप्त नहीं हो रही है । सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया सरकार को कि जो उसका निगेटिव है उसके आधार पर एक नई फिल्म तैयार करके आप हमको दिखायें । थोड़े दिनों बाद उस पर भी सूचना सरकार की ओर से भेजी गई कि निगेटिव भी नहीं मिल रहा है, वह भी गायब है और इसलिये दिखाने में असमर्थ हैं । तो यह स्थिति रही जहां तक कोर्ट का सवाल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : गवर्नमेंट ने क्या आबजेक्शन किया ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सिनेमाटोग्राफिक एक्ट के अन्तर्गत अगर कोई फिल्म जिसके बारे में सरकार का यह मत है कि....

"It is not fit for public exhibition because it is against the interest of the security of the State, friendly relations with foreign States and public order and is likely to incite the commission of various offences."

तो यह जो धारा है सब-सेक्शन 1 आफ 5-बी आफ सिनेमाटोग्राफिक एक्ट आफ 1952, इस धारा के अधीन उन्होंने इस फिल्म को बंद कर दिया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सिक्योरिटी आफ स्टेट तो इस फिल्म में नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी आफ सर्टेन पर्सन और सर्टेन चेयर था । मैंने तो पूछा था, मेरे ख्याल में इससे भी एतराज किया था कि गांधी टोपी पहने दिखाई थी । अब सी० बी० आई इस पर इन्क्वायरी कर रही है । मेरी इन्फार्मेशन है कि इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के कुछ अफसरों से भी पूछताछ की गई है शुक्ला साहब और मारूति के भी कुछ अफसरों से सी० बी० आई० ने इन्क्वायरी की है । मारुति के अफ-

सरों ने यह मान लिया है कि शुक्ला साहब ने आदेश दिया था कि यह फिल्म दे दी जाये और उन्होंने यह भी मान लिया है कि यह मारुति की प्रैमिसेज में जलाई गई । यह चीज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में मान भी ली हैं । मि० गांधी उस समय मौजूद थे । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री अमृत नाहटा का कोई पत्र आया है ? यदि आया है तो उसके कंटेंट्स क्या हैं और क्या जवाब दिया ?

जिस तरह से इस पार्टी ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पार्टीजन एटीट्यूड लिया और पोलिटिकल कंमीडरेशन की वजह से आंधी पिक्चर को खत्म किया, किशोर कुमार के गाने खत्म कर दिये, तो यह सरकार अब इस तरह नहीं करेगी, तो आप की सरकार की पोलिटिकल पिक्चर के बारे में सेंसर की क्या नीति है और पोलिटिकल इश्यू पर लोगों को एजूकेट करने के बारे में क्या पालिसी है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मैं पहले कह चुका हूं कि जितनी जांच अब तक हुई है, उससे ऐसा लगता है कि फिल्म को जला-कर खत्म कर दिया गया है । सी० बी० आई० अपनी इवेस्टीगेशन थोरो कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है । कोई अधिकारी कहीं का भी हो, चाहे मारुति का कर्मचारी हो, सबसे पूरी जांच की जा रही है और इस समय जांच अपने अंतिम चरण पर है । मैं इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपकी पालिसी क्या है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : जहां तक नीति का सवाल है, नीति पर चर्चा करने का और भी अवसर आयेगा । मैं इतना कह सकता हूं कि अब तक राजनीतिक कारणों से जिनको कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो आगे राजनीतिक कारणों से कोई दिक्कत नहीं होगी । सेंसरशिप की ओवर-आल पालिसी पर रिव्यू किया जा रहा है और ओवरआल गाइड लाइन्स पर रिव्यू किया जा रहा है ।

श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री नाहटा ने जो पत्र दिया, उसका क्या हुआ ?

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, this is a very serious matter. The public are terribly disturbed about this offence and I want the hon. Minister to give some information to the House from which the public could be assured that the investigation is proceeding along the right line and it will be honestly and vigorously pursued.

MR. SPEAKER: He has already given the answer. He has said that they are doing it very satisfactorily (*Interruptions*).

SHRI RAM JETHMALANI: I am only looking for some evidence of what he is saying.

SHRI L. K. ADVANI: So far as the evidence is concerned, this is at the final stage.... (*Interruptions*). I can submit for his information that the tins containing with film were found in a pond 15 kilometres away from the place. From this you can see how thorough the CBI investigation is going on and how well they are doing it.

डा० बलदेव प्रकाश : मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने जवाब दिया कि जो नेगेटिव्ज और प्रिंट्स सरकार की कस्टडी में थे, वे भी गायब हो गये हैं । क्या उसके बारे में कोई केस दर्ज किया गया है, क्या इस सम्बन्ध में इनवेस्टीगेशन हो रहा है और क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी मिली है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मैंने जो जवाब दिया है, वह नेगेटिव्ज और प्रिंट्स दोनों पर एप्लाई करता है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of a Commercial Broadcasting Station at Cochin

*143. SHRI V. M. SUDHEERAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the number of commercial broadcasting centres in Kerala State; and

(b) if so, whether Government have a proposal to set up a commercial broadcasting station at Cochin?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Lease of Land at Budge Budge to M/s S. K. Oil & Co. by Port Trust, Calcutta

*145. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Calcutta Port Trust Authority leased out a land at Budge Budge to M/s. S. K. Oil and Co. on lesser rate of rent than the scheduled rate resulting in a loss of Rs. 1 lakh per annum; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Calcutta Port Trust have reported that the land in question was leased at a concessional rate admissible under the Schedule.

(b) Does not arise.

जापानी कम्पनियों के सहयोग से पावर टिलर का निर्माण

*147. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मित्सविशी ट्रैक्टर और टिलर्ज लिमिटेड, बंगलोर एक जापानी कम्पनी के सहयोग से पावर टिलर का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं और कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पावर टिलरों के मूल्य में कमी लाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :

(क) जी, हां । मे० वी०एस०टी० टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बंगलौर, टोकियो जापान के मे० मित्सुविशी हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, के सहयोग से शक्तिचालित हलों का निर्माण कर रही है ।

(ख) दोनों फर्मों के बीच सहयोग निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया था :—

1. रायल्टी : 3% शक्तिचालित हलों और फालतू पुर्जों पर।

2. तकनीकी जानकारी की फीस : 2,08,550 रुपये

3. जापानी कम्पनी द्वारा 15 लाख रुपये तक का निवेश आंशिक रूप से संयंत्र और मशीनों का संभरण करके और आंशिक रूप से जानकारी की फीस निवेश करके ।

शक्ति चालित हलों की पर्याप्त मांग को ध्यान में रखते हुए 6-4-1966 को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) जी. हां ।

Appointment of Commissions under Commission of Enquiry Act

*148. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many Commissions under the Commission of Enquiry Act have been appointed since the Janata Party has come into power at the Centre;

(b) the name or names of the Commissions; and

(c) the terms of reference of the various Commissions appointed and the period within which the Commissions are expected to report?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Six Commissions have been appointed at the Centre since the Janata Party has come into power.

(b) and (c). The relevant Notifications appointing the Commissions are laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT. 473/77].

Plans for Backward Districts

*149. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the present position of implementation of recommendation of Estimates Committee in paras 2.109-2.110 of their 69th Report (5th Lok Sabha) regarding formulation of district plans for each backward district;

(b) the number of districts which have been covered, particularly in Tamil Nadu;

(c) the stages of implementation of such plans; and

(d) whether Government propose to make a review of such plans with a view to making them realistic and amenable to orderly fulfilment?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Following the recommendations of the Estimates Committee, the Planning Commission had impressed upon the State Governments the need for taking steps for the formulation of district plans.

(b) The position in March, 1976 was reported to the House in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred Question 1272 answered on 24th March, 1976. Tamil Nadu had even then prepared district perspective plans for 23 development districts through 13 district planning cells and techno-economic feasibility studies had been completed for more industrially backward districts, viz. Ramanathapuram, Dharmapuri, Thanjavur and South Arcot Report on the present position of the plans has been called for from the State and will be laid on the Table of the House.

(c) The implementation of the plans will depend on the resources that can be earmarked for the various parts of the plan from the State Plan resources. As regards present position information has been called for and will be laid on the Table of the House when received.

(d) The main parameter for a district plan is that it must be realistic and be capable of performance within a reasonable time frame. With the present thrust on integrated rural development and employment, the district plans will be reviewed and the work will be taken up as preparatory to the Sixth Plan Programme.

Conversion of Trainees to Apprentice in Eastern Coalfields Limited

*154. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the trainees in Eastern Coalfields Ltd. recruited in 1974 were

converted to apprentice under apprenticeship scheme, 1961 forcibly during emergency affecting adversely their service condition as trainees; and

(b) whether the Ministry propose to reconvert them as trainee and give them all facilities as trainees?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) The trainees recruited in 1974 by Eastern Coalfields Ltd. were brought under the Apprentices Act, 1961 between September 1974 and October 1975. This did not in any way adversely affect their service conditions as trainees.

(b) It is not proposed to re-convert them into trainees as no additional benefits would accrue to them by doing so.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

*155. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्राप्त योजनाएं अभी विचाराधीन हैं और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 31-5-1977 की स्थिति के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० के पास राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 34 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 52 स्कीमें विचाराधीन थीं। इन में से, प्रारम्भिक संवीक्षा तथा या क्षेत्र मूल्यांकन करने के बाद निगम ने राजस्थान की 13 स्कीमें और मध्य प्रदेश की 27 स्कीमें संबंधित बोर्डों को संशोधन के लिए वापिस भेज दी हैं। शेष स्कीमें निगम के पास विचाराधीन हैं।

(ख) निगम के पास विचाराधीन राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की 21 शेष स्कीमों में से 20 स्कीमें पिछले पांच महीने के दौरान प्राप्त हुई हैं। एक स्कीम 5 महीनों से ज्यादा अवधि से विचाराधीन है। 1976-77 के दौरान इस स्कीम पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य को आवंटित की गई धनराशि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर अन्य स्कीमों की स्वीकृति के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जा चुकी थी।

निगम के पास विचाराधीन मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की शेष 25 स्कीमों में से 22 स्कीमें पिछले 5 महीनों के दौरान प्राप्त हुई हैं। 3 स्कीमें 5 महीनों से ज्यादा समय से विचाराधीन हैं। इन में से एक विशेष पारेषण स्कीम है और इस पर विचार करके इसके द्वारा पोषित बैक-अप क्षेत्रों की स्कीमों के प्राप्त होने पर किया जाएगा। इन स्कीमों की बोर्ड से प्रतीक्षा की जा रही है। एक स्कीम बोर्ड द्वारा सूचित प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तीसरी स्कीम 1976-77 के दौरान इस कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी कि राज्य के पास न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धन उपलब्ध नहीं था। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृति दिए जाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।

Research and Analysis Wing

*156. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) to what extent the Research and Analysis Wing was used within the country against Congress-opposed political parties and their leaders and even against Congressmen by Smt. Indira Gandhi, her son and Government;

(b) how much Government money has been spent for the said purpose;

(c) under what head of the budget this organisation has been drawing money for running these operations; and

(d) whether the Government propose to publish a White Paper on the activities of this organisation giving details as far as possible?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Research and Analysis Wing has not been given any authority to operate within the country except where this is necessary in relation to their assigned task of collecting external intelligence. There is no proof to suggest that the Research and Analysis Wing has transgressed its jurisdiction.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No, Sir.

Manufacture of Computers by Multinational Companies

*157. SHRI M. KALYANASUNDARAM:

SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether some multinational companies having their branches in India have sought the permission of Government to start manufacturing computers; and

(b) if so, the particulars thereof and reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The only multinational computer company which currently has a branch in India is IBM. However, International Computers Ltd., (ICL) of UK have two subsidiary companies here; ICL (India), which is 100 per cent owned by ICL (UK), and International Computers Indian Manufacture (ICIM) which is 60 per cent owned by ICL (UK). IBM has not proposed starting any computer system manufacturing programme here. ICL have agreed, in response to the requirements of Foreign Exchange Regulation Act, to wind up the operations of ICL (India) and to dilute the foreign equity in ICIM Ltd., to 40 per cent. They have proposed manufacture of the new range of ICL 2903/2904 computers in their current 2900 series and a certain range of computer peripheral units by ICIM Ltd., with a foreign equity of 40 per cent. This proposal of ICL is under the consideration of Government.

People's Committees

*158. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether Government have accepted Shri Jayaprakash Narayan's view that people's committees should be formed through which the people can express their needs and articulate their views;

(b) if so, whether the blueprint is ready for these people's committees; and

(c) how far Government will cooperate with these committees?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Government's attention has been drawn to the suggestions made by Shri Jayaprakash Narayan in his interview broadcast on 25th March, 1977, regarding formation of 'people's committees'. Government fully recognise the need for close vigilance on the part of the people at various levels of the administration and would like to seek their fullest cooperation and participation in different spheres of administration. How best this objective can be achieved would require fuller and more detailed examination.

Tours performed by Shri Rajiv Gandhi

*159. SHRI R. D. GATTANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) for how many days Shri Rajiv Gandhi, son of the former Prime Minister and his father-in-law, mother-in-law travelled in India during December last year and January this Year;

(b) whether these persons were accorded V.I.P. treatment at State expenses and if so, in what States;

(c) what was the total amount of expenditure incurred from public exchequer for arrangements connected with their visit; and

(d) what action Government propose to take against the persons responsible for misusing Government resources and public money?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Complaints against Research and Analysis Wing

160. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of some news and articles appeared in the press in the last two months regarding the functioning of Research and Analysis Wing (RAW) in India:

(b) details of complaints and representations received by Government against RAW during the last two months;

(c) the results of inquiry into the complaints and the articles appeared in the press; and

(d) what steps Government propose to take to make changes in its functioning.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (d). Government are aware of the press reports that have recently appeared in regard to the Research and Analysis Wing. The main allegation against the Organisation is that it was used for political purposes within the country. There is however, no proof to establish that Research and Analysis Wing transgressed their given authority to collect external intelligence.

Measures have been initiated to review and reorganise the working of this organisation.

Expansion of Thermal Power Station Unit at Gangakhed, Maharashtra

*161. SHRIMATI MRINAL GORE:

SHRI R. K. MHALGI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government have asked for expansion of the Thermal Power Station unit at Gangakhed (District Parbhani);

(b) if so, whether Government had undertaken any survey;

(c) whether the survey report has cited Gangakhed site as the best to install Thermal Power Station; and

(d) whether Government have taken final decision in this regard?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) to (d). No such proposal has been received in the Central Electricity Authority.

Contract to Maruti Ltd. for making Bomb Items

*162. SHRI G. M. BANATWALLA:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government of India granted a contract to Maruti Ltd. for

making bomb items at the intervention of former Defence Minister,

(b) if so, whether the Defence Ministry did not agree to grant such a licence to private firms; and

(c) if so, whether Government propose to hold an inquiry into this matter?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No, Sir. However, an order was placed on Maruti and on two other private firms for a small component of a grenade on 15-10-75, i.e., before the previous Defence Minister had assumed Office.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

ज्वायंट साइफर ब्यूरो और भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतन मानों में अन्तर के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

*163. **श्री मही लाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग ने ज्वायंट साइफर ब्यूरो की पठन शाखा (रीडिंग ब्रांच) और भारत सरकार मुद्रणालय की पठन शाखा (रीडिंग ब्रांच) में काम करने वालों के लिए समान वेतन मान निर्धारित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उक्त दोनों विभागों की पठनशाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर के क्या कारण हैं : और

(ग) क्या ज्वायंट साइफर ब्यूरो की पठन शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार मुद्रणालय में काम करने वाले अपने समकक्ष सहयोगियों की तुलना में कम वेतनमान दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रीडर ग्रेड–II के वेतनमान में तो कोई असमानता नहीं है, परन्तु रीडर ग्रेड–I और कापी होल्डर के मामले में असमानता है । 1968 में भारत सरकार मुद्रणालय में विभिन्न पदों का वर्गीकरण करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर मुद्रणालय के रीडर ग्रेड–I और कापी होल्डर के वेतन-मानों में बढ़ोतरी की गई थी । ज्वायंट साइफर ब्यूरो की पठन शाखा के मामले में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था । इसके कारण भारत सरकार मुद्रणालय और ज्वायंट साइफर ब्यूरो के रीडर ग्रेड–I तथा कापी होल्डर के संशोधन-पूर्व वेतनमानों में असमानता आ गई और चूंकि ज्वायंट साइफर ब्यूरो की पठन-शाखा के रीडर ग्रेड–I और कापी होल्डर के संशोधन-पूर्व वेतनमान कम थ, इसलिए वेतन आयोग ने इन पदों के लिए निम्न वेतनमानों की सिफारिश की ।

पंच वर्षीय योजनायें

1293. **श्री उपसेन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक पंचवर्षीय योजनाओं से शहरों की समृद्धि हुई है और गांव सर्वथा उपेक्षित और अछूते रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पंचवर्षीय योजना श्रंखला को समाप्त कर उसके स्वरूप और क्रिया में परिवर्तन कर इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवीन माध्यम पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) योजना आयोग को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है; वह नई सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निवेश प्रोजनाओं की समीक्षा कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार पर अधिक बल दिया गया है । सरकार के उद्देश्य और प्राथमिकताएं छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में और अधिक पूर्ण रूप से प्रकट होंगी ।

Reinstatement of Government Servants whose services were terminated under MISA and D.I.R.

1294. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Government servants whose services were terminated under MISA and DIR during emergency State-wise and category-wise; and

(b) the number of persons reinstated as on 31st May, 1977

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) The Maintenance of Internal Security Act and the Defence of India Rules do not provide for the termination of services of any Government servant.

(b) Does not arise.

कोटा (राजस्थान) स्थित तापीय विद्युत (थरमल पावर स्टेशन संयंत्र

1295. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा (राजस्थान) में नये तापीय विद्युत् सन्यन्त्र के पूरा हो जाने पर कितनी बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : कोटा ताप विद्युत् केन्द्र के पूरा हो जाने पर इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 220 मेंगावाट बिजली की होगी ।

Memorandum Submitted by all Jammu and Kashmir Low-Paid Employees Federation

1296. SHRI R. P. DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the All Jammu and Kashmir Low-paid Employees Federation submitted a Memorandum on Monday the 2nd May, 1977 demanding reinstatement of all suspended employees and release of MISA detenus;

(b) if so, the action taken to release MISA detenus of the Federation; and

(c) whether the General Secretary of the Federation has been released from MISA detention?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by the Government of Jammu & Kashmir all members of the Federation detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971, in the State have been released.

(c) Yes, Sir.

Fare-Chart in Mini Buses

1297. SHRI KARPOORI THAKUR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether mini buses in Delhi do not carry any fare chart duly exhibited in the buses;

(b) whether the conductors of different mini buses on the same route charge different rates for the same distance;

(c) whether Government are aware that trouble is often created with the passengers who are forced to pay different rates for the same destination on different mini buses;

(d) if so, what steps are being taken to save the passengers from this harassment; and

(e) whether there is any proposal to instruct the mini bus owners to compulsorily exhibit fare-rates for all stages at some prominent place in the mini buses?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (e). The Mini Bus Owners operating their buses under D.T.C. control have instructions to display fare-table in the buses. No complaints have been received regarding non-compliance with such instructions by these operators.

(b) to (d). The conductors of mini buses are not allowed to charge different fares for the same distance on the same route. However, complaints in this regard are being received occasionally. Whenever any such complaint is received, action is taken against the bus owner, under the terms of the agreement, by way of imposition of penalty or even termination of the contract.

राजस्थान में झालावाड़ जिले के लिए विकास योजना

1298. **श्री चतुर्भुज :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झालावाड़ जिले के लिए विशेष विकास योजना सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ऐसा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने झालावाड़ सहित राज्य के चार जिलों के लिए मार्गदर्शी आधार पर 10-वर्षीय (1979–80 से 1988–89 तक) एकीकृत व्यापक जिला योजनाएं तैयार करने का निर्णय किया है।

इस कार्यक्रम में जिले की संसाधन सम्पन्नता और उस क्षेत्र के लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष विकास योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है। उक्त योजना तैयार करने में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

Loss of Revenue by Calcutta Port Trust Authorities

1299. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Calcutta Port Trust Authorities had to incur a loss of revenue for Rs. 20 lakhs for delayed revision of rent schedule on Port Estate;

(b) whether the Public Accounts Committee in its 175th Report suggested for an enquiry to fix up the responsibility and punish the officer responsible for the same; and

(c) if so, the action taken so far?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c). The Public Accounts Committee in its report had suggested in para 1.76 that delay in the revision of the schedule of rents is a serious matter and calls for fixation of responsibility for suitable action against the officers responsible for the loss of revenue to the Calcutta Port Trust.

In this connection, C.P.T. have reported that the Rent Schedule of the Port Trust is revised regularly and since 1955, there have been four such revisions. The revision of the Rent Schedule was deferred only once from April, 1972 to April, 1973. The pro-

posal for revision of rent charges which was formulated in 1972 had to be examined in detail after obtaining particulars from other ports and this necessarily, entailed some delay in finalising the matter.

It may be mentioned that the original proposal envisaged on additional income from rent to the tune of Rs. 12 lakhs per annum. The revised proposal which was adopted after detailed scrutiny yielded an additional income of Rs. 21 lakhs per annum.

Thus the revised proposals evolved after a delay have actually resulted in larger yield from rent and overall there has been no loss on account of late revision of the rent.

Calcutta Port Trust have, however, been asked to ensure that delays do not occur in future and that well before the expiry of the currency of the rent schedule, revised proposals are formulated and examined in depth so that the new rates come into force when the old schedule expires.

A note explaining the above position has been furnished to the Public Accounts Committee.

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण

1300. **श्री कल्याण जैन** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विपुल प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की कोई योजना है; और

(ख) मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों को निकालने तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बनाई जाने वाली योजना की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में विद्युत की आवश्यकता

1301. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद:** क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने मैगावाट बिजली की आवश्यकता है और कितनी बिजली दी जा रही है; और

(ख) विशेष रूप से नालन्दा जिले की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता क्या है और वहां कितनी बिजली दी जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) दामोदर घाटी निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्रों समेत बिहार की कुल व्यस्ततम मांग लगभग 900 मैगावाट है तथा इस व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए वास्तविक उपलब्धता लगभग 800 मैगावाट है ।

(ख) नालन्दा जिले की व्यस्ततम काल की आवश्यकता लगभग 45 मैगावाट है जबकि व्यस्ततम काल के दौरान उपलब्धता 35 मैगावाट के लगभग है ।

Fire in Studios of Doordarshan, Delhi

1302. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there was a mysterious fire in the studios of Doordarshan, Delhi immediately on declaration of the emergency;

(b) if so, whether an enquiry has been conducted into the causes of such a fire and findings thereof, if any;

(c) whether the persons responsible have been punished; and

(d) the extent of loss due to the fire in rupees?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The case was investigated by the Crime Branch of Delhi Police. They reported that despite the best efforts no clue to work out the case could be found and they treated the case as untraced.

(c) Does not arise.

(d) Approx. Rs. 19,62,620.

Demands of Employees of Vikram Sarabhai Space Centre

1303. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) whether the employees of the Vikram Sarabhai Space Centre at Thumba have submitted any demands to the management for the redressal of their grievances; and

(b) if so, the main features thereof and the action taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes Sir.

(b) The demands, which have been received very recently, relate mainly to service matters, career opportunities, staff welfare and other facilities. They are under examination.

Loss Suffered by H.E.C.

1304. SHRI SHEO SAMPAT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total amount of loss suffered by the Heavy Engineering Corporation, Ranchi since its inception; and

(b) the steps Government propose to take to improve the situation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) The cumulative loss suffered by the Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, since its inception till 31st March, 1976 was Rs. 115.29 crores. The accounts for the year 1976-77 are under compilation.

(b) The slow build up of production was one of the main factors responsible for HEC incurring losses till 1974-75. With the introduction of a number of measures including: systematic production planning and control, preventive maintenance of equipmet and installation of balancing equipment, the production of the company has improved. In 1975-76 the company for the first time registered a profit of Rs. 2.14 crores. This trend is likely to be maintained in 1976-77. To further improve the performance of HEC Government is taking steps to reorganise and strengthen the managerial structure of HEC.

Development of a New Port at Pipavav

1305. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Engineers India Limited has prepared a report about the possibility of development of a new port with modern facilities at Pipavav on Sauashtra Coast;

(b) whether Port Pipavav has been found to be an ideal on-shore base for off-shore exploration; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken for the development of port Pipavav for off-shore exploration and for establishing salt based industries?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir. The Report was submitted to the Government of Gujarat.

(b) It is understood that the scope of the Report did not include investigations on the suitability or otherwise of the Port as an ideal on-shore base for off-shore exploration, as this was not part of their terms of reference.

(c) The executive responsibility for the development of ports other than Major Ports vests in the State Government. Government of India has no proposal at present for the development of this Port.

Privileges Enjoyed by Shri Jayaprakash Narayan

1306. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the wide spread criticism that the extraordinary privileges enjoyed by Shri Jayaprakash Narayan is gradually making him an extra-constitutional centre of power;

(b) whether Shri Narayan has been allowed frequently to broadcast his messages through All India Radio and Television;

(c) whether Shri Narayan had been provided with an IAF aircraft for going to Bombay while he fell ill; and

(d) how Government propose to explain this strange and extra-constitutional privileges allowed to be enjoyed by an ordinary citizen?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (d). No extraordinary privileges were extended to Shri Jayaprakash Narayan nor is Government aware of any widespread criticism in this regard. However, certain facilities and courtesies have been extended to him in consideration of his health and his standing as a national figure. The rest of the question does not arise.

(b) nothing more has been done in this matter than would be normally the case in respect of a person of his eminence, standing in public life and the wide support that his views command in the country.

(c) Yes, Sir. Airlift was provided to Shri Jayaprakash Narayan from Patna to Bombay on the 25th March, 1977 in an IAF aircraft, as he was critically ill and there was no alternative but to rush him to his hospital in Bombay.

Meeting of Vice-President Acting as President of India with Chief Justice of India regarding Dissolution of State Assemblies

1307. SHRI U. S. PATIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Vice-President acting as President of India Shri Jatti had discussion with the Hon'ble the Chief Justice of India in connection with the dissolution of Assemblies in nine States when the matter was pending before them; and

(b) if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). Government's attention has been drawn to the observations of Justice Goswami in his judgment dated 6th May, 1977 in State of Rajasthan etc. *versus* Union of India and connected writ petitions as well as the press statement made by the Chief Justice of India, which appeared on 7th May, 1977 in all leading newspapers. In view of the relevant provisions of the Constitution and practices and conventions of the House, it would not be appropriate for Government to say anything on the subject.

Passing Information to a Foreign Country

1308. SHRI P. K. DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a Senior Intelligence Officer of R.A.W. was passing informa-

tion to foreign countries and has been detected;

(b) whether he along with his family members has flown to Canada and has settled down there; and

(c) if so, with whose connivance it was possible and what steps Government are taking against those officials involved in this unhappy episode?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Renaming of Prime Minister Sectt.

1309. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether he has rehauled and renamed the Prime Minister's Secretariat;

(b) if so, broad details thereof;

(c) the reasons for effecting such changes;

(d) whether the various "Intelligance Services" have been transferred to respective Ministries and whether some of the services have been closed down; and

(e) if so, broad details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes Sir.

(b) and (c). The Prime Minister's Sectt. has been renamed as Prime Minister's Office. The number of senior officers has been reduced. The system of Ministry-wise distribution of work at the level of senior officers has been done away with. The reasons for effecting this change is that the functions of this Office should be confined to rendering secretarial assistance to the Prime Minister.

(d) and (e). Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Enforcement have been transferred back from the Cabinet Secretariat to the Ministry of Finance.

Excess Production by Multinational Corporations

1312. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether some of the foreign multinational corporations operating in India have produced goods in excess of their licensed capacity in the past three years and have made huge profits from such excess production;

(b) if so, the names of the multinational corporations which had resorted to excess production and the profits made by each one of them from such production; and

(c) what measures Government propose to take to prevent these corporations from violating Government controls and regulations?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) to (c). Multinational companies operate in India through their branches and/or their Indian subsidiaries, i.e. Indian companies in which the foreign companies hold more than 50 per cent of the paid-up equity capital. As on 31-3-1977 there were 482 branches of multinational companies operating in India. The number of subsidiaries of multinational companies operating in the country as on 31-3-1976—the latest date for which such information is available—was 171. A comprehensive list of such subsidiaries/branches of foreign companies resorting to excess production and making profits from such excess production is not available.

Government's policy towards foreign companies in industrial ventures has been to bring them under the industrial licensing discipline even in areas where exemptions are available to other categories of undertakings.

Instructions have been issued to the administrative Ministries that cases of excess production may be brought up before the Licensing Committee for a decision on a case by case basis. In cases where it is established that the capacity installed by the party was more than the licensed capacity and this resulted in production of articles in excess of the licensed capacity, suitable action will be taken as permissible under the law.

Multinational Corporations

1313. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the branches of the Multinational Corporations operating in India as on 31st March, 1977;

(b) the nature of their operations;

(c) whether Government have so far made any study about their operations; and

(d) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) There were 482 branches of Multinational Corporations operating in India as on 31st March, 1977.

(b) These branches were engaged in the following operations:—

Nature of activity	Number of branches
1. Agriculture and allied activities	12
2. Mining and quarrying	8
3. Processing and manufacture	78
4. Construction and utilities	30
5. Commerce (Trade and Finance)	120
6. Transport, communication and storage	39
7. Community and business services	82
8. Personal and other services	13
TOTAL	482

(c) and (d). No study about the operations of Multi-national Corporations in India has been made by Government so far.

टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य

1314. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साइकिलों, मोटरों, स्कूटरों, ट्रकों तथा ट्रैक्टरों के टायरों और ट्यूबों की अलग-अलग कीमतें क्या हैं और यहां से निर्यात करने पर विदेशों में उनकी कीमत भारतीय मुद्रा में कितनी है; और

(ख) देश में विभिन्न साइकिल-निर्माता कम्पनियों द्वारा बनाई गई साइकिलों का विक्रयमूल्य क्या है और विदेशों में इनका विक्रयमूल्य भारतीय मुद्रा में क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) देश में मोटर गाड़ियों साइकिलों के टायरों और ट्यूबों की कीमत उनके आकार और सम्बन्धित टायरों में लगी सामग्री की मात्रा, धागा, प्लाई रेटिंग उसकी डिजाइन आदि के अनुसार अलग-अलग कम्पनियों में अलग-अलग होती है । इसी प्रकार उनके निर्यात मूल्य भी एक देश से दूसरे देश और एक निर्माता से दूसरे निर्माता के मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं । फिर भी मोटर गाड़ियों साइकिलों के टायरों और ट्यूबों के प्रत्येक प्रकार के प्रमुख आकार का औसत मूल्य और पत्तन तक निःशुल्क औसत निर्यात मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1)

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या LT-474/77]

काका कालेलकर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन

1315. **श्री रूपनाथ सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काका कालेलकर आयोग 1955 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए 1 अप्रैल, 1977 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्ञापन को सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) क्या पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु नौकरी में आरक्षण के बारे में आदेश जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा आदेश कब तक जारी हो जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ): सरकार को यह ज्ञापन प्राप्त हुआ है और वह उसमें की गई मांगों पर विचार कर रही है । अभी तक इसे सदन के सभा-पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है ।

Setting up of a T.V. Station at Agra

1310. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration for setting up of a Television Station at Agra which is one of the foremost educational, cultural and tourist centres in the country;

(b) whether the absence of it has proved a great drawback in providing recreational facilities to the tourists; and

(c) if so, the time by which such station is likely to be erected?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Not to the knowledge of the Government. The question of provision of TV facilities in Agra will be examined keeping in view the need of providing such facilities in the country as a whole as well as the financial resources available for this purpose.

पंजाब में श्री संजय गांधी के दौरे

1317. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संजय गांधी के पंजाब के प्रत्येक दौरे पर गत दो वर्षों के दौरान पंजाब सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) क्या श्री संजय गांधी को उनके पंजाब के दौरों के समय पूर्ण राजकीय सम्मान दिया गया था और उन्हें विशेष सरकारी अतिथि माना गया था और यदि हां, तो यह राजकीय सम्मान उन्हें किस हैसियत से दिया गया था;

(ग) क्या भूतपूर्व मंत्रियों या उच्च अधिकारियों के विरुद्ध इस बारे में कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) मांगी सम्बन्धित सूचना पंजाब सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

"Jhupri" dwellers at Andaman and Nicobar Islands

1318. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to remove unauthorised "jhupri" dwellers at Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, total number of 'jhupri' dwellers poor families to be affected?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) The Government have no immediate plan to remove unauthorised "Jhupris" in Andaman and Nicobar Islands. However, the 'Jhupris" being illegal encroachments on Government land are liable to be removed any time under the provisions of the Andaman and Nicobar Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966. Despite legal provision in deserving cases, when unauthorised occupants are removed, an endeavour would be made to allot to them housesites subject to availability of land.

(b) The Andaman and Nicobar Administration have not maintained any statistical record about the number of such 'jhupris'.

Missing of D.T.C. bus from Shahdara Depot

1319. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a DTC bus was found missing from Shahdara Depot, Delhi in the first week of April, 1977;

(b) if so, whether the bus has been traced out; and

(c) whether any arrest has been made in this connection?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Researches at Nuclear Power Research Station at Kalpakkam

1320. SHRI A. BALA PAJANOR: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the precise scope of the researches carried out at the nuclear power research station at Kalpakkam;

(b) whether similar researches are carried out at other parts of India;

(c) if so, steps taken to ensure against overlapping and duplication of efforts; and

(d) the achievements made so far by the research station?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Reactor Research Centre incorporating the Fast Breeder Test Reactor and associated research facilities under construction at Kalpakkam, Tamil Nadu is planned for research and development of technology for the establishment of fast breeder reactor nuclear power stations.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

(d) The Fast Breeder Test Reactor is under construction.

Monthly Income of D.T.C.

1321. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the monthly income of D.T.C. each month during 1974-75, 1975-76 and 1976-77;

(b) the average number of buses on roads in Delhi during each of the months during the above period;

(c) the average number of buses plying on inter-State routes each month during the above period and average earnings from each bus; and

(d) the loans/grants given by Government to the D.T.C. during each of the above three years?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-475/77].

(d) No grant was given during the three years. Details of loans sanctioned are as under: —

	1974-75	1975-76	1976-77
	(Rs. in lakhs)		
(i) Loans for Capital expenditure.	792	130	180
(ii) Loans for Ways and Means support.	685	590	50

'हिन्दुस्तान समाचार' का 'समाचार' में विलय हो जाने के बाद कर्मचारियों और संवाददाताओं की सेवाओं का समाप्त किया जाना

1322. **श्री राघव जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान 'हिन्दुस्तान समाचार' का 'समाचार' में विलय किए जाने के उपरान्त कितने कर्मचारियों और सम्वाददाताओं (वैतनिक और अवैतनिक) की सेवा समाप्त कर दी गई थी;

(ख) उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है, उन्हें नौकरी पर पुनः रखने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग). 'हिन्दुस्तान समाचार' के किसी भी स्थायी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई थीं । तथापि, जिनकी 385 अंशकालिक अवैतनिक सम्वाददाताओं की सेवाएं "समाचार" द्वारा समाप्त की गई थीं । सरकार ने "समाचार" को सलाह दी है कि वह इन मामलों का पुनरीक्षण करे ।

Expansion of Bata and other Shoe Manufacturing Companies

1323. SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that big shoe manufacturing units are displacing lakhs of shoe makers;

(b) whether Government are thinking of preventing further expansion of Batas and other big shoe manufacturers; and

(c) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) to (c). Under the existing policy of Government, the Leather Footwear industry is reserved for development in the small sector only. Applications for expansion of existing units as well as for setting up of new units in the organised sector are considered exclusively for export development. Earlier, an export obligation of 75 per cent was being stipulated in respect of expansion as well as new units in the organised sector. Presently, however, approvals are accorded only on the basis of a 100 per cent export obligation (subject to rejections, not exceeding 5 per cent being sold domestically).

Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute

1324. SHRI K. MALLANNA:
SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Kannada Sahitya Parishad has urged the Centre to implement the Mahajan Commission award to settle the Karnataka-Maharashtra boundary dispute once for all;

(b) whether Central Government are aware that the statement of Railway Minister that a uniform formula would be evolved to resolve all border disputes, had made Kannadigas restless; and

(c) if so, the reaction of Central Government in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c) The whole matter regarding boundary disputes between States has still to be reviewed by this Government.

Commission to enquire into the affairs of Maruti Ltd.

1326. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the progress made in regard to the work of the Commission of Enquiry constituted to inquire into the affairs of Maruti Ltd.;

(b) the terms of reference thereof; and

(c) whether the hearings will be public?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) The Office of the Commission is being set up. Some skeleton staff have joined and are taking up the necessary preliminary formalities.

(b) A copy of the notification containing the terms of reference of the Commission is being laid on the Table of the House.[*Placed in Library. See* No. LT-476/77.]

(c) In accordance with section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Commission shall regulate its own procedure, including deciding whether to sit in public or in private.

Naxalites arrested during Congress Regime

1327. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Naxalites who were arrested during the Congress regime, State-wise; and

(b) the number of them released so far?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Closure of Mysore Tools Ltd., Bangalore

1328. SHRI DINEN BHATTACHARYA:
SHRI MUKUNDA MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Mysore Tools Ltd., Bangalore has been closed for nearly one year; and

(b) if so, the loss of foreign exchange and steps taken by Government to re-open the factory?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) While the demand for Micrometers, the item of manufacture of M/s. Mysore Tools Limited is partly met from imports, it is not possible to indicate the increase in outgo in foreign exchange, if any, on the import of micrometers consequent on the closure of this company as there are other indigenous manufacturers for this item.

Government has not been approached either by the State Government, management or the employees of the company seeking its assistance in the matter of reopening of the factory. The question of Government taking any steps to have the factory reopened therefore, does not arise.

Target of Installed Power-Generation Capacity

1329. SHRI D D. DESAI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there has been a shortfall in the target of installed power generation capacity in the Fifth Plan;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) steps, if any, being taken to make up the shortfall?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). In 1976, the Fifth Plan was finalised and a capacity of around 12,500 MW was envisaged for being installed. Till 1976-77 a total of 5232 MW has already been installed and it is expected that after completion of on-going schemes in the last two years of the Fifth Plan, a shortfall of around 900 MW may occur.

(c) Close monitoring of the construction of projects is being undertaken through monitoring agencies in the States as well as in the Central Electricity Authority. This will assist in better performance in achieving targets for commissioning of new capacity.

Reviving of Press Council

1330. SHRI S. C. MURUGAIYAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have decided to revive the Press Council; and

(b) if so, whether there will be any change in the composition and functioning of the Council?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Details are being worked out

Creation of a Ministry for Consumer Goods and Light Industry

1331. SHRI VASANT SATHE: Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to create a Ministry for consumer goods and light industry to ensure meeting peoples demand for these articles; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Expenditure Incurred on Research in Atomic Energy during 1976-77

1332. SHRI P. RAJGOPAL NAIDU: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether research is being done in atomic energy; and

(b) if so, the total expenditure incurred on it during 1976-77?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes Sir.

(b) The expenditure incurred on the various research programmes (including supporting services) of the Department during 1976-77 is around 60.48 crores.

Supply of Cement to Kerala

1333. SHRI SKARIAH THOMAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state·

(a) whether there is acute shortage of cement in the State of Kerala;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the quarterly quota of cement allocated to Kerala State and actual supply of the same at present; and

(d) whether Government propose to increase the quota of cement for that State?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). Reports of non-availability of cement have been received from different parts of the country including Kerala State due to inadequate production as a result of power cuts and a sudden spurt in demand also. To distribute the shortfall equitably a cut had also to be made in the States' quota.

(c) and (d). The quarterly allocation of cement to the Kerala State and the actual despatches during 1976 and first quarter of 1977 are as under:—

(In lakh tonnes]

Quarter	Allocation	Dispatches
Qr. I/76	1.50	1.78
Qr. II/76	1.50	2.13
Qr III/76	2.25	1.52
Qr. IV/76	2.00	1.90
Qr. I/77	1.75	1.82

The State Government has been persuaded to give more power to the cement factories in the State of Tamil Nadu on the condition that 70 per cent of the extra production of cement from such factories would be allocated to Kerala State. This will result in an additional allocation of 2 lakh tonnes to Kerala State.

Memorandum from Mysore Tools Employees' Association Bangalore

1334. SHRI MUKUNDA MONDAL:

SHRI R. P. DAS:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the Mysore Tools Employees' Association Bangalore;

(b) whether the management of Mysore Tools Ltd. Bangalore has not paid wages to workers and staff for nearly 11 months; and

(c) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir.

(b) Government have no information.

(c) Does not arise.

Radical change in the Planning Process

1335. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government propose to make radical changes in the planning process; if so, the facts thereof;

(b) whether Shri Subramaniam Swamy, M.P. has submitted any formulations to him in this connection and, if so, the main features thereof; and

(c) how they differ materially from the existing policy?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Planning Commission have been requested to formulate the approach and strategy of the Sixth Five Year Plan and look into changes necessary in the planning process.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Price of Printing Paper

1336. SHRI DINESH CHANDRA JOARDER:

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is a demand from the paper industry for a 30 per cent rise in the price of white printing paper;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government are aware that this rise in price will adversely affect the student community?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) to (c). Yes, there has been demand from Paper manufacturers Association for upward revision of selling price of white printing paper but the Govt. has not agreed to it. The paper industry has been supplying white printing paper at the special rate of Rs. 2750 per tonne to meet the requirements of the educational sector and Government departments. The industry had asked for upward revision of the price on the ground that cost of inputs had risen, and that market condition for other types of paper were depressed.

Ambassadors, Governors and Vice-Chancellors belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1337. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the total number of Ambassadors, Governors and Vice-Chancellors who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Among the Indian Ambassadors, two belong to Scheduled Castes and two to Scheduled Tribes. None of the Governors is from the Scheduled Caste or Scheduled Tribe communities. Information regarding the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Vice-Chancellors is being collected.

Survey of villages for setting up Rural Industries

1338. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any survey of the villages has been conducted with the objective to secure a breakthrough in setting up village industries with small investment and help Government frame appropriate policies to encourage and foster growth of rural industries; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). While survey of village industries of the scope indicated in part (a) of the Question has not been undertaken; feasibility surveys and industrial potential studies of village industries in different areas are conducted by the Khadi and Village Industries Commission directly and through State Khadi and Village Industries Boards and its various agencies from time to time wherever and whenever the need arises. The following studies have been undertaken recently:—

1. Industrial potential survey of Himachal Pradesh;

2. Industrial potential survey of North Eastern States;

3. Industrial Potential Survey of Goa;

4. Rapid Surveys of individual artisans in Villages; and

5. Khadi & V.I. Activities in Hill and Border Areas.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों का चयन

1339. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कितने उम्मीदवार बैठे और परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उन परीक्षाओं में बैठने वाले 97.3 प्रतिशत उम्मीदवार अनुत्तीर्ण होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उम्मीदवार के श्रम और धन की बरबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस बारे में नई नीति निर्धारित करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) वर्ष 1973–74, 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठे, थे और उन उम्मीदवारों की संख्या जिनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी, नीचे दी जाती है :—

वर्ष	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	नियुक्ति के लिए सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की संख्या
1973–74	42,887	2,631
1974–75	47,965	2,851
1975–76	57,290	2,850

वर्ष 1976–77 में ली गई परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं ।

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले 97.3 प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं । मोटो-तौर पर परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक 100 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है । उन उम्मीदवारों में से, जिनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जाती, काफी प्रतिशतता ऐसे उम्मीदवारों की होती है जो वास्तव में परीक्षाओं में काफी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, किन्तु पर्याप्त संख्या में रिक्तियां न होने के कारण उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जाती ।

(ग) सरकार, उस समस्या से अवगत है जो उम्मीदवारों की काफी बड़ी संख्या होने और उनके लिए नौकरियों की संख्या अपर्याप्त होने से उत्पन्न होती है, जिन पर उनमें से केवल बहुत ही उत्तम उम्मीदवारों की सिफारिश की जा सकती है । इस मामले पर प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में भर्ती नीति तथा चयन पद्धति सम्बन्धी समिति द्वारा सामान्य रूप से विचार किया गया था । इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Rural Electrification in the country

1340. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the total number of schemes sanctioned by R.E.C. uptil now for rural electrification in the country;

(b) number of villages covered and benefited by these schemes;

(c) total amount spent so far for rural electrification in the country; and

(d) how many small-scale industrial units have come up in rural areas under the above schemes?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) The Rural Electrification Corporation has sanctioned so far 1567 schemes for rural electrification in the country.

(b) The schemes envisage extension of electricity to 1,00,298 new villages and more intensive electrification of 21,495 already electrified villages.

(c) The Rural Electrification Corporation upto 15th June 1977 disbursed loans amounting to Rs. 404.28 crores for rural electrification in the country.

(d) 20,699 small industrial units have been provided with electricity upto 31-12-1976, under the schemes sanctioned by the Rural Electrification Corporation Ltd.

निजी सचिवों वैयक्तिक सहायकों आशुलिपिकों की नियुक्तियां

1341. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :** गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरी में निजी सचिवों, वैयक्तिक सहायकों वरिष्ट आशुलिपिकों और कनिष्ठ आशुलिपिकों के रूप में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के बीच कोई अनुपात निश्चित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Alokudyog Cement Factory

1342. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned a huge amount of money for Alokudyog cement factory which was running at a loss; and

(b) if so, the reasons and amount thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VARMA): (a) and (b). No, Sir. The Central Government has merely agreed to M/s. Jaipur Udyog Ltd. clearing the cement produced by it during the first year of its operation after the date of restart of production without payment of excise duty. The amount of duty so deferred is repayable in five equal instalments together with interest thereon.

.. Working of D.E.S.U.

1343. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the D.E.S.U. authorities could not foresee the break down of generating plants at Badarpur in Delhi and shortage of supplies from Bhakra Dam which resulted in shedding of power supplies and prohibiting the use of airconditioners and coolers etc. when the temperature had gone very high;

(b) whether alternate or stand-by arrangements are not made by the D.E.S.U. to meet such contingency;

(c) steps to reform the working of D.E.S.U.; and

(d) action being taken against the defaulting authorities?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir. It was not possible for Delhi Electric Supply Undertaking to foresee the break-down of generating units in Badarpur and shortage of supplies from Bhakra system.

(b) No, Sir. It is not practicable to have independent standby arrangements of that magnitude.

(c) The Central Government had appointed a Committee in June, 1976 to advise on the steps to be taken to improve the functioning and management of Delhi Electric Supply Undertaking. The Committee have submitted the report and most of the recommendations have been accepted by the Government.

(d) Does not arise.

Revision of Rules for recruitment in Doordashan and Films Division

1344. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to revise the rules regarding the recruitment to the Doordarshan and Films Division to give preference in employment to the talent passing out of the Film and Television Institute of India; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b). In so far as Doordarshan is concerned, provision already exists for giving preference to candidates holding a diploma in the field relevant to a Doordarshan post from the Film and Television Institute of India, Pune. A new staffing pattern for television is under consideration of Government and when the recruitment rules are framed, the claims of diploma holders from the Film and Television Institute of India, Pune and similar other institutions will be kept in mind.

The recruitment Rules in respect of regular civil posts in the Films Division already provide for a degree or diploma in the relevant field from a recognised University/institution, as either an essential or a desirable qualification. The possibility of amending these rules to provide for giving preference to the diploma holders of the Film and Television Institute of India, Pune and other similar institutions is being examined.

बिहार में नक्सलवादी तथा राजनैतिक बन्दी

*1345. **डा० रामजी सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय नक्सलवादी तथा सभी श्रेणियों के राजनैतिक बन्दियों की संख्या कितनी है ;

(ख) पटना साइन्स कालेज के श्री बी० एन० शर्मा तथा श्री प्रसन्न कुमार नामक दो छात्रों के विरुद्ध जो अभी तक जेल में हैं, क्या आरोप हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन छात्रों को शीघ्र ही रिहा करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Gauhati Station of A.I.R.

1346. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Gauhati Station of the All India Radio is the main

centre of AIR catering to the needs of the North-Eastern region; and

(b) if so, whether Government propose to increase the transmitting power of the Gauhati Station for the interest and benefit of the North-Eastern Region?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Gauhati Station of All India Radio is one of the main broadcasting stations catering to the needs of the North-Eastern region. This region comprises seven States/ Union Territories, viz. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura. All India Radio has broadcasting stations operating in each of these States/ Union Territories at the centres indicated below:

Assam: Gauhati, Dibrugarh, Silchar.
Meghalaya: Shillong.
Arunachal Pradesh: Tezu, Passighat, Tawang.
Manipur: Imphal.
Nagaland: Kohima.
Mizoram: Aizwal.
Tripura: Agartala.

(b) There are no immediate proposals for upgrading the power of the transmitters at Gauhati.

गुजरात को सीमेंट आवंटन

*1347. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जून की तिमाही में गुजरात राज्य को कितना (टनों में) सीमेंट आवंटित किया गया ;

(ख) इसमें से गुजरात को 31 मई, 1977 तक वास्तविक रूप में कितना सीमेंट प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या गुजरात में सीमेंट की कमी है और यदि है, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या चालू तिमाही में गुजरात को तीन लाख मीटरी टन का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : (क) 3,07,500 मीटरी टन ।

(ख) राज्य को सम्बन्धित फैक्टरियों द्वारा 31-5-1977 तक लगभग 1,46,807 मी टन सीमेंट भेजी गई थी ।

(ग) गुजरात राज्य से सीमेंट उपलब्ध न होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई है । सीमेंट की कमी का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा बिजली में की गई कटौती के कारण सीमेंट का अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना तथा सीमेंट की मांग का एकदम बढ़ जाना है ।

(घ) जी, नहीं । लेकिन राज्य को 30-6-1977 तक आवंटित मात्रा में सीमेंट की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

पाठा खेड़ा में आपातकाल के दौरान कोयले का उत्पादन

*1348. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान 'पाठा खेड़ा' कोयला खान (जि० बेतूर) में कोयले के अधिक उत्पादन का उल्लेख किया गया जिसके परिणामस्वरूप जमीन के स्टाक में हजारों टन की कमी आयी ;

(ख) क्या यह कार्यवाही उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए की गई ;

(ग) क्या जैसे ही लोक सभा चुनाव परिणाम घोषित हुये खान के अधिकारियों ने घोषणा की कि कोयले का उत्पादन हजारों टन घट गया है ;

(घ) क्या खान से निकाले गये कोयले की मात्रा सूचित की गई मात्रा के अनुरूप नहीं है तथा श्रमिकों की संख्या और उनको भुगतान की गई राशि लेखा प्रस्तावों में दिखाई गई राशि से नहीं मिलती है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध शिकायतें

1349. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के तिवारी मंत्रिमंडल के विरुद्ध विरोधी दलों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन में मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन मंत्रियों और मुख्य-मंत्री के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): उत्तर प्रदेश के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित राष्ट्रपति को सम्बोधित दिनांक 15 अप्रैल, 1977 का एक ज्ञापन, जिस पर राज्य के 19 विधायकों ने हस्ताक्षर किये थे, तथ्यों का पता लगाये जाने के लिए सामान्य कार्यविधि के अनुसार राज्यपाल को भेज दिया गया है । उक्त ज्ञापन में लगाये गए आरोपों का स्वरूप अथवा उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, इस स्टेज पर प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास [illegible] धनराशि का अपव्यय

1350. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अपने मूल उद्देश्य की उपेक्षा की और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं तथा युवा कांग्रेस नेता श्री संजय गांधी की स्वार्थसिद्धि में धनराशि का अपव्यय किया ;

(ख) क्या सरकार ने निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) जी, नहीं । माननीय सदस्य का संकेत सम्भवत: दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर है ।

(ख) प्राप्त हुई कुछ शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sub-leasing of land by D.S.I.D.C.

1351. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a proposal has been sent to the Central Government to allow the Delhi State Industrial Development Corporation (DSIDC) to sub-lease the land utilised for construction of the sheds;

(b) if so, outlines of the proposal; and

(c) reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) Proposal seeks such modification of the condition of allotment of land to DSIDC by Govt. of India as would make the allottee a Sub-leasee.

(c) Matter is under consideration of the Ministry of Works and Housing.

Bugging of Telephones and opening of Mail of Political Leaders

1352. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the present Government are aware that extensive bugging of telephones and opening of mail of Indian political leaders, in political interest of Smt. Indira Gandhi and her Government and party was done;

(b) if so, the facts thereof: and

(c) if so, whether the practice has been discontinued?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). There are no records to disclose that any bugging of telephones and opening of mail of political leaders was done. However, the Government are issuing detailed instructions to all concerned to ensure that bugging of telephones and censoring of mail is not resorted to for political purposes in future.

Representation from a producer of a film in Kannada dealing with the 1942 Quit India Movement

1353. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether in April 1977 the Government have received a representation from a producer of a film in Kannada, based on Shri Basavaraj Kattimani's novel of dealing with the 1942 Quit India Movement; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The proprietor of the film has been asked to send one 35 mm print of the feature film "MADI MADIDAVARU" to ascertain its suitability for field publicity.

L.T.C. concession to Government Employees

1354. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to grant concession to Central Government employees in regard to payment of L.T.C. in full without deducting fare for initial distance of 400 kms?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): No, Sir.

Revamping of D.A.V.P.

1355. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to revamp DAVP;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken/proposed in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the revamping proposals are:—

(i) To lay down an advertisement policy, which does not

admit of any discrimination on political grounds.

(ii) To evolve scientific rate structure for advertisements in consultation with representative bodies of newspapers and advertising agencies.

(iii) To institutionalise procedures and practices for awarding contracts and jobs.

(iv) To set up departmental committees in different spheres of D.A.V.P.'s working to eliminate subjective decisions.

(v) To lay down clear guidelines for the functioning of these committees.

(c) The proposals are still under consideration.

Involvement of technocrats as Administrative functionaries

1356. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to reduce the present number of Secretaries, Additional and Joint Secretaries of Central Ministries on rationalised basis;

(b) if so, the details of the proposal under consideration; and

(c) what is the policy of the Government to increasingly involve technocrats as administrative functionaries at the key levels?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). The approach of the Government is to keep the number of posts at these levels to the minimum required. A review of the requirements at the levels of Secretary/Special Secretary and Additional Secretary is under way.

(c) Senior posts under Government are filled on the basis of selection on merit from various sources keeping in view the requirements of each job and the qualification and experience of persons within the field of choice.

दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा

1357. **श्री कृष्ण कुमार गोयल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) दिल्ली को राज्य का दर्जा देने और अथवा विधान सभा की मांग के अभ्यावेदन सरकार को लोगों से प्राप्त हुए हैं । जनता पार्टी की दिल्ली राज्य शाखा ने हाल के लोक सभा के आम चुनावों के समय जारी किये गये अपने पूरक चुनाव घोषणापत्र में दिल्ली के लिए एक विधान सभा का वचन भी शामिल किया था ।

(ख) वर्तमान सरकार ने अभी तक इस मामले पर विचार नहीं किया है ।

Cancellation of D.T.C. bus routes from Railway Station to various residential colonies in Delhi

1358. SHRI KARPOORI THAKUR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a large number of DTC bus routes from various residential colonies to Delhi Main Railway Station and New Delhi Railway Station were cancelled during the period of Emergency;

(b) if so, whether it has caused untold suffering to the commuters; and

(c) if so, what steps are being taken to link up these two railway stations by bus to the far-off colonies of Delhi?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Frequency of D.T.C. buses on route Nos. 720 and 854

1359. SHRI KARPOORI THAKUR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) percentage of frequency maintained by DTC. Delhi on bus route Nos. 720 and 854 during the month of April 1977;

(b) total number of average daily trips as shown in the time table and total number of average daily trips actually performed by buses on the above routes; and

(c) steps being taken to stick to the time table on these two routes?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The percentage of the trips operated to the number of scheduled trips on route Nos. 720 and 854 was 78.26 and 92.06 respectively during April, 1977.

(b) Against an average daily schedule of 79 trips on route No. 720, 62 were operated, and against a daily average schedule of 83 trips on route No. 854, 77 were operated, during April, 1977.

(c) While there is some irregular operation of the services on route No. 720, the position on route No. 854 is satisfactory. Main reasons for missing of trips on route No. 720 have been the mechanical failure of buses, hold up of buses in the workshop for major repairs, and delays at the Nangal Rai Railway Crossing. Every effort is being made by the Corporation to improve maintenance of buses and speed up the repairs of buses off the road for major repairs.

राजस्थान में सीमेंट कारखानों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1360. **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नये सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ;

(ख) आवेदनकर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इन पर कब तक निर्णय किया जाएगा ; और

(घ) किन-किन स्थानों पर नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) एक नया कारखाना जिसके लिए सरकार द्वारा पहले ही आशयपत्र मंजूर किया जा चुका है । राजस्थान के कोटा जिले में मोरक में स्थापित किये जाने की सम्भावना है ।

सेना में राजस्थान से लोगों की भर्ती

1361. **श्री चतुर्भुज** :

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने लोग सेना में भर्ती किये गये हैं; और

(ख) सशस्त्र सेनाओं में राजस्थान से अन्य राज्यों से की गई भर्ती की तुलना में कितने लोग भर्ती किये गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान से सेना में भर्ती किये गये सिपाहियों की संख्या इस प्रकार है :—

1974	.	4107
1975	.	3053
1976	. .	4453

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, सशस्त्र सेनाओं में सिपाहियों और इनके समकक्ष की भर्ती के बारे में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति निम्नांकित है :—

1974	पांचवां स्थान
1975	छठा स्थान
1976	पांचवां स्थान

Representations from C.I.V. Union, Ahmednagar

1362. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have received two representations dated 30th March 1977 and 12th April 1977 from C.I.V. Union, Ahmednagar (Maharashtra);

(b) if so, whether Government have taken any action or propose to take action in regard thereto; and

(c) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). 139 posts in various grades have been reduced in the Controllerate of Inspection Vehicles, Ahmednagar, as a result of on-the-spot study by the Establishment Study Team. The C.I.V. Civilian Employees Union have represented against this reduction. The following steps have been taken to avoid hardship to the staff: Of the 139 persons affected, 76 are being adjusted against existing vacancies in the Establishment. Of the remaining 63, orders for transfer of 26 individuals to Establishments at other Stations of their choice have already been issued. Efforts are being made to adjust the remaining staff in other Units/Stations.

Filling up Posts in Haldia Complex, Calcutta

1363. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Calcutta Port Trust Authority had invited applications for filling up the post of Deputy Manager (Personnel & Industrial Relations) in the pay scale of Rs. 1400—1700 in Haldia Complex, from candidates having the Bachelor's Degree of a recognised University;

(b) whether applications for filling up the post of Assistant Manager (Personnel and Industrial Relations) in the pay scale of Rs. 1200—1500 was invited from persons having Bachelor's Degree as well as the D.S.W. diploma; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The qualification prescribed for the two posts differed and applications were invited in accordance with these qualifications.

Termination of Services of Nineteen Dock Clerical Staff

1364. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the services of nineteen Dock clerical staff were termi-

nated by their employers M/s. Khemca & Co. and Gladstone Lyall & Co.;

(b) whether their names were not registered in the 'A' or 'B' register under the Calcutta Dock Labour Board as done in the past in accordance with the provision of the Calcutta Dock Clerical Supervisory Staff (Regulation of Employment), Scheme, 1970; and

(c) if so, action taken by the Ministry in the matter?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Consequent on transfer of a shipping line from the agency of M s. Gladstone Lyall & Co., 16 'C' register workers of the Company were absorbed by M s. Sarat Chatterjee & Co. and M/s. E. C. Bose & Co. in Register 'C' itself upon appointment as stevedores of this line. M/s. Khemka & Co. terminated the services of three employees as the firm which took over their business refused to take over the employees in 'C' register.

(b) It is not possible for Calcutta Dock Labour Board to take over these employees in the Register 'A' or 'B' as the existing number of dock clerical and supervisory workers under the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 is already surplus to requirements.

(c) The matter has to be settled directly between the employees concerned and their former employers.

Development of Ancillary and Small Scale Industries

1366. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the present position of development of ancillary and small scale industries by existing and new public sector undertakings;

(b) the findings of the inter-departmental team representing Development Commissioner (SSI), Bureau of Public Enterprises and administrative Ministry stated to have been constituted for boosting promotion of ancillary units; and

(c) the action taken on the findings?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) According to the information available in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, the present position is that 2266 ancillary units are functioning for the existing public sector undertakings in different parts of the country.

Regarding the new public sector undertakings expansion projects, the Bureau of Public Enterprises has already issued guidelines to ensure that the scope of ancillarisation in various projects is clearly spelt out at the draft project report stage itself and suitable action is initiated at proper stage to select entrepreneurs/units to meet the ancillary requirements. The Development Commissioner, Small Scale Industries, has also advised the various State Governments to initiate necessary follow-up action in the matter.

(b) The inter-departmental teams comprising of the representatives from the Bureau of Public Enterprises, the administrative ministries of the Government of India and the Development Commissioner, Small Scale Industries, were not fact finding teams, but were set-up to visit the undertakings and hold discussions with them to evolve a methodology for promotion of small scale ancillaries and to impress upon them the imperative need for constant attention towards ancillarisation.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Study of Institutions working in Gujarat and Maharashtra for Development of Industries

1367. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have made a study of the institutions working in Gujarat and Maharashtra for development of industries in backward areas;

(b) if so, the results of the study; and

(c) the extent to which the beneficial features have been commended for adoption in other States?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) The Ministry of Industry have not made any study of the institutions working in Gujarat and Maharashtra for development of industries in backward areas.

(b) and (c). Do not arise.

Probe into working of Transport Units of Doordarshan

1368. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether three officials of the Delhi Doordarshan had been under suspension for their malpractices in the Transport Section of the Unit;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted into the working of the entire transport unit of the Doordarshan; and

(c) the findings of such an enquiry?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir. Three officials of the Transport Unit of Delhi Doordarshan had been under suspension between the period 24-1-76 to 16-5-77. However, suspension of two out of these three officials has since been revoked w.e.f. 16-5-77.

(b) and (c). A preliminary enquiry was conducted into the functioning of the Transport Unit which was followed by a detailed enquiry. Since these enquiries revealed *prima facie* malpractices, a regular departmental enquiry against the delinquent officials is in progress.

उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी

1369. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को सीमेंट का मिलना कठिन हो रहा है; और.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) . बिजली में कटौतियों तथा एकाएक मांग बढ़ जाने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त उत्पादन होने के बारे में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से सीमेंट के न मिलने की रिपोर्ट मिली हैं। उत्पादन में हुई कमी को बराबरी से बांटने हेतु राज्यों के कोटे में भी कटौती करनी पड़ी थी । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीमेंट उद्योग को अधिक बिजली देने के लिए उन्हें समझा बुझाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठायें हैं । सरकारी विभागों से

भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी इस तिमाही की मांग अगली तिमाही के लिए स्थगित कर दें ताकि आम जनता को अधिक सीमेंट मिल सके । राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे सीमेंट की जमाखोरी को रोकने के लिए उपर्युक्त उपाय करें । इस तिमाही में (अप्रैल से जून) सीमेंट का निर्यात भी कम से कम कर दिया गया है ताकि देश में इस्तेमाल के लिए अधिकतम परिमाण में सीमेंट मिल सके ।

Aid to harassed Daughters-in-Law

1370. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation from Nari Raksha Samiti demanding free legal remedy against mothers-in-law;

(b) whether Government have any plans to give aid to harassed daughters-in-law; and

(c) if so, main features thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is no such plan at present.

Escape of undertrials from Judicial Lock-up in Tis Hazari, Delhi

1371. DR. BAPU KALDATE:

SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a large number of undertrials escaped from judicial lock-up of Tis Hazari, Delhi on the 28th May, 1977;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps being taken for the safe custody of undertrials in judicial lock-up?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). 5 undertrail prisoners had escaped from the judicial lock-up at Tis Hazari, Delhi on the 28th May, 1977. The facts, as reported by the Delhi Administration/Delhi Police, are as follows:—

On 28th May, 1977, 9 undertrail prisoners were brought from the Tihar Jail and lodged in a special cell of the Judicial Lock-up at Tis Hazari, 3 of these undertrials were taken out of the cell for being produced before the concerned Courts. At 1.20 P.M., when these 3 undertrials were brought back and the door of the cell was opened, it was found that 5 out of the remaining 6 undertrials were missing. Those found missing were S/Shri Nasir Ali, Ravinder, Davinder, Nasar Ahmed and Sita Ram. 3 of them were associates of late Sunder dacoit.

As soon as it was noticed that 5 undertrial prisoners had escaped from the judicial lock-up, search parties were sent to Inter State Bus Terminus, Beriwala Bagh, where one of them resided, and Tis Hazari Courts premises. A case u/s 224 IPC was also registered. Instructions were given to the border check posts and Railway police to be on the look-out for these prisoners. Crash wireless messages were also sent to police authorities of some neighbouring districts of U.P. and Haryana. A look-out message with description of the escapees was also flashed to all District Supdts. of Police in India. A special cell was also set up to take all possible steps for re-apprehension of the escapees.

Two of the escapees, *viz.*, Nazir Ali and Ravinder, are reported to have been killed in an encounter with the

police on the Delhi-Lucknow National Highway on June 10/11, 1977. Another escapee, Davinder, has been re-arrested by the Delhi Police on 19th June, 1977.

(c) An enquiry into the escape of the undertrial prisoners mentioned above has been ordered by the Lt. Governor, Delhi. The circumstances leading to the escape of the undertrials and security arrangements, including construction of judicial lock-up cells to preclude the possibility of such incidents happening in future, will be looked into during the said enquiry. The changes in the Jail Manual regarding production of prisoners undertrials in Courts, handing them over to the police, guards etc. will also be recommended, if considered necessary.

Expansion in Vikram Sarabhai Space Centre during 1977-78

1372. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) a brief outline of the expansion programmes proposed to be taken up at the Vikram Sarabhai Space Centre at Thumba during the year 1977-78; and

(b) the total amount to be spent for this purpose during this period?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The major expansion programmes proposed to be taken up during 1977-78 at the Vikram Sarabhai Space Centre are in the area of development of launch vehicles and their related sub-systems, augmentation of existing facilities and application of technology developed at the Centre.

(b) Rs. 152.00 lakhs.

Reducing Expenditure on Security measures for Prime Minister

1373. SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether security and other measures taken in the conduct of Prime Minister's public meetings cost huge sums to the public exchequer; and

(b) if so, the concrete measures initiated to reduce such expenses consistent with the security of the high office?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). The main expenditure incurred on providing security and other measures in the conduct of Prime Minister's public meetings is on essential law and order arrangements for public safety and convenience. The expenditure on protective arrangements for the Prime Minister on such occasions is substantially less. The arrangements have, however been reviewed recently and substantial reduction has been made in the development of men and construction of fixtures at such meetings.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की भारतीय भाषायें यूनिट का विलय

1374. **श्री नवाब सिंह चौहान:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की भारतीय भाषायें यूनिट का अंग्रेजी प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय के साथ विलय किया जा रहा है ;

(ख) क्या इसका परिणाम यह होगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय पर भारतीय भाषा के संबंध में कोई कार्य नहीं रहेगा; और

(ग) क्या आपातकाल के दौरान इस यूनिट के अधिकारियों द्वारा की गई

अनियमितताओं को दबाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग). भारतीय भाषा यूनिट का प्रशासनिक नियंत्रण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के मुख्यालय से इसके प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय में स्थानान्तरण का प्रश्न सुविधा और मितव्ययता के कारणों से अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Memorandum from a Deputation of Sindhi Community

1375. SHRI R. K. NHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(b) whether a deputation of Sindhi community has called on the Prime Minister at Bombay in the first or second week of May 1977;

(b) whether the said deputation has submitted to him a memorandum stating certain problems of Sindhi community which persist for a long time;

(c) if so, what were the demands and requests in the memorandum;

(d) what action has Government taken or propose to take and when; and

(e) whether there are any difficulties to accept the demands or requests made in the said memorandum; if so, what are they?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Some of the main demands relate to reservation of seats in Lok Sabha and State Assemblies/Councils, declaration of Sindhis as a minority community and schemes for rehabilitation of displaced persons.

(d) and (e). The demands made in the memorandum are under examination in consultation with concerned Ministries Departments.

Equipments Fitted in Erstwhile Prime Minister's Secretariat and Establishments

1376. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) details of different equipments including computers and other electronic gadgets fitted in the erstwhile Prime Minister's Secretariat and establishments during 1971—77;

(b) cost of the same and purpose for which they were used;

(c) whether there was a Joint Intelligence Committee under the Prime Minister's Secretariat; and

(d) if so, who was heading it and what was the cost of maintaining the same?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The following equipments had been provided in South Block and in Parliament House for the erstwhile Prime Minister's Secretariat for the last about three years:

(i) Letargard — Two

(ii) Portable X-ray equipment. — Two

(iii) Polaroid copying attachment for the X-ray equipment. —Two

(b) The approximate cost of each of the above items is as follows:—

(i) Rs. 5,040-00

(ii) Rs. 14,481-00

(iii) Rs. 279-00

Items (i) and (ii) are meant for detection of explosive materials concealed in letters and parcels addressed to the Prime Minister and item (iii) is an additional attachment meant for taking photographs of contents of suspected covers.

(c) and (d). No, Sir. However, there is a Joint Intelligence Committee functioning in the Cabinet Secretariat. It is headed by an officer of the rank of Additional Secretary and the expenditure incurred during 1976-77 was Rs. 3,26,000-00.

Equipments fitted at Residence of Erstwhile Prime Minister

1377. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details and cost of equipments and gadgets fitted and kept at No. 1, Safdarjung Road, the residence of the erstwhile Prime Minister Shrimati Indira Gandhi?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): The Hon'ble Member is presumably referring to special equipments and gadgets and not normal equipment supplied in Govt. bungalows. In this case the details and cost of such equipments according to information available with Govt. are as follows:—

1. Two door-frame metal detectors. — Rs. 56,000
2. One hand-held metal detector. — Rs. 875
3. One electric-alarm bell system. — Rs. 33,158

Former Prime Minister's Secretariat

1378. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of personnel in the erstwhile Prime Minister Shrimati Indira Gandhi's Secretariat and cost of maintaining the same between 1st April 1971 to 25th March 1977 (figures to be shown year-wise)?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): The requisite information is as follows:—

Year	No. of personnel (As on 31st March each year)	Expenditure (in lakhs of rupees)
1970-71	211	20·49
1971-72	225	21·30
1972-73	227	21·80
1973-74	232	23·
1974-75	228	27·5
1975-76	227	30 ·5
1976-77	219 (as on 1-3-77)	30.

Export Venture in Manufacture of Computers

1379. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal for a jointly owned 100 per cent export venture in the manufacture of computers; and

(b) if so, the outlines thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a). No Sir.

(b) Does not arise.

बुलन्दशहर जिले के रबूपुरा कस्बे के व्यापारियों को बन्दी बनाया जाना

*1380. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1976 को बुलन्दशहर जिले के रबूपुरा कस्बे के कुछ व्यापारियों को युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं

की इस रिपोर्ट के आधार पर बन्दी बनाया गया था कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो बन्दी बनाये गए व्यापारियों के नाम क्या हैं तथा जिन्होंने रिपोर्ट की थी, उनके नाम क्या है; और

(ग) सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो इस प्रकार झूठी रिपोर्ट लिखा कर आम आदमी को परेशान करते हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Facilities to Christian Community in Kerala

1381. SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI SKARIAH THOMAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether backward classes of Christian community in Kerala State have not been given facilities at par with Hindu backward classes in that State;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether Central Government propose to remove this partiality in that State and if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Information received from the State Government shows that the Backward Classes of Christian community in Kerala are treated at par with the Hindu backward classes in the matter of educational concessions and reservations of appointments in public service.

Address by Director General of UNESCO at Indian Institute of Mass Communication

1382. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Mr. Amadou Mahtar M. Bow, Director General of UNESCO addressed the Indian Institute of Mass Communication during his recent visit to India; and

(b) if so, what are the salient points of his address?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement of the salient points of Mr. Amadou Mahtar M'Bow, Director General of UNESCO's address is attached.

Statement

Salient points of Mr. M' Bow's address

The salient points of Mr. Amadou Mahtar M' Bow, Director General of UNESCO's address at the Indian Institute of Mass Communication are:—

1. Content and flow of information are central to present-day problems in development, education and culture. With the support of the Unesco General Conference in Nairobi in October-November 1976, therefore, Unesco has latterly given to communication, science and technology, the same high priority as was given in Unesco's earlier years to programmes in the fields of education and culture.

2. Education cannot spread without a wide use of mass media. But, generally speaking, educators and communicators have been working in isolation. Nor have communication media been used adequately for the spread of the scientific spirit and knowledge or for preservation of cultures on which the progress of a people depends.

3. Unesco is grateful to India not only for the steps to develop mass media but to place the facilities it commands for the training of information personnel from other countries

4. An important segment of this training relates to science communication. Unesco and India will this year observe the twentyfifth anniversary of the Kalinga Foundation which encourages science communication.

5. Unesco is wedded to freedom of information and free flow of information. For these freedoms to prevail those who purvey information have to function with responsibility. Secondary, those who-receive information have to be able to participate in the process of communication. To the extent responsible communication needs to be protected. Unesco would like to see media personnel relieved of financial and political pressures, whether from official or private quarters.

6. Thanks to imbalances in technological progress, there are hindrances to a free and balanced flow of information between developed and developing countries. Unesco seeks to remove this hindrance. Developing countries should have access to the use of international communication networks.

7. A news agency enjoying Government support does not necessarily lose objectivity or need become a propaganda channel. Governing authorities of news agencies should consist of people who do not succumb to political or financial pressures which can be exercised by Government.

8. Unesco would encourage emergence in developing countries of news agencies which are autonomous, objective and a means for freer flow of information.

9. What is negative or remiss in India's development effort is easily known abroad, but not the achivements and successes.

10. For all the advances made by the press in India, it shares some weaknesses of the press in other developing countries. It puts out news stories about other developing countries, sent by the major international news agencies, without checking the facts. These international agencies provide information which occasionally minimises or undermines the developmental efforts of developing countries. Information media should shed their prejudice about the achievements of peoples in developing countries.

आपात स्थिति लागू किए जाने के विरुद्ध आन्दोलन

1383. **श्री धन्ना सिंह गुलशन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति लागू किये जाने के विरुद्ध किन-किन राज्यों में आन्दोलन चलाये गए थे; और

(ख) आपात स्थिति लागू किए जाने के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में अपील करने वाले कितने व्यक्तियों को कितनी कितनी सजायें दी गई तथा उन पर कितना कितना जुर्माना किया गया और उनमें से कितने लोग बरी किए गए ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में उत्पादन

1384. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में गत तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय उक्त कारखाने में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक कर्मचारी के पास पर्याप्त काम है; और

(घ) बेकार बठे रहने वाले कर्मचारियों (अन्डर एम्पलायड) की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में गत तीन वर्षों के उत्पादन के मूल्य निम्नलिखित हैं :—

1974–75	478.49 लाख रुपए
1975–76	513.27 लाख रुपए
1976–77	476.87 लाख रुपए

(ख) 3,388

(ग) जी नहीं !

(घ) कानपुर प्रभाग के कर्मचारियों की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उक्त प्रभाग को एक उपयुक्त निर्माण-परियोजना सिपुर्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

डा० राम मनोहर लोहिया और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच

1385. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कथित हत्याओं के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये दो पृथक् जाच आयोग नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन आयोगों के निर्देश पद क्या होंगे; और

(ग) उन को कितनी अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा और इटावा में ग्रामीण विद्युतीकरण

1486. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश की डाक् समस्या से अत्यधिक प्रभावित आगरा और इटावा जिले के विकास खण्डों में विकास खण्डवार पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई;

(ख) उक्त जिलों में विकास खण्डवार कितने गांवों का विद्युत करण किया जाना अभी भी शेष है;

(ग) उक्त जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है; और

(घ) क्या उक्त जिलों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ओर से इन जिलों के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये विशेष सहायता उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामों का विद्युतीकरण

1387. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, जिलावार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है और कितने ग्रामों का विद्युतीकरण अभी किया जाना शेष है;

(ख) उत्तर प्रदेश में, जिलावार पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने गांवों को बिजली पहुंचाई गई तथा कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जिलावार, कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने और कितने पम्प सेटों को बिजली देने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Issue of Public Notices by the Calcutta Port Authorities

1388. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether public notices were issued by the Calcutta Port Authorities for leasing out the lands by the Calcutta side on Strand Road; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) During last 3-4 years there was no suitable land available in the Calcutta side of Strand Road for the purpose of leasing out.

Supply of Cement to Maruti

1389. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) total quantity of cement supplied to Maruti Ltd., Haryana todate since inception;

(b) the way in which this quantity was utilised by the company;

(c) whether any allegations of irregularity and misuse of cement have been brought to the notice of Government; and

(d) if so, the facts thereof and action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) 12,930.80 metric tonnes.

(b) to (d). The Government has already appointed a Commission which will, *inter-alia*, inquire into all facts and circumstances relating to allotment of controlled commodities and materials like cement to M/s. Maruti Pvt. Ltd. and its utilisation or disposal other.

Lathi Charge in Jails during Emergency

1390. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names and the places where lathi charge was made in jails during emergency;

(b) the reasons of lathi charge in each case and the number of persons wounded or killed;

(c) whether Government propose to make an inquiry whether the lathi charge was justifiable or not; and

(d) whether Government propose to take action against the officers who ordered for the lathi charge?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) (a) and (b). The following States/Union Territories have reported that no lathi charge was made in their jails during Emergency:—

(1) Assam. (2) Haryana. (3) Kerala. (4) Meghalaya. (5) Nagaland. (6) Rajasthan. (7) Sikkim. (8) Tripura. (9) Andaman and Nicobar Islands. (10) Arunachal Pradesh. (11) Chandigarh. (12) Darda and Nagar Haveli. (13) Delhi. (14) Lakshadweep. (15) Pondicherry. (16) Andhra Pradesh.

Replies from the following States and Union Territories are awaited:—

(1) Bihar. (2) Gujarat. (3) Himachal Pradesh. (4) Jammu and Kashmir. (5) Karnataka. (6) Madhya Pradesh. (7) Maharashtra. (8) Manipur. (9) Orissa. (10) Punjab. (11) Tamil Nadu. (12) Uttar Pradesh. (13) West Bengal. (14) Goa, Daman and Diu. (15) Mizoram.

(c) and (d). The Shah Commission has been appointed by the Government of India to inquire into excesses, malpractices and misdeeds during the Emergency, and the terms of reference cover these points fully. The Government will take action in the light of the Shah Commission's report.

Complaints against Shri Sanjay Gandhi, Maruti Ltd., Maruti Technicals and Maruti Heavy Vehicles

1391. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of complaints received by the Government against Shri Sanjay Gandhi, Maruti Ltd., Maruti Technicals and Maruti Heavy Vehicles in the last 6 months;

(b) whether all these complaints have been referred to CBI or I.B. for making inquiry; and

(c) if so, the result of the inquiry on each complaint?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). A number of complaints have been received against Shri Sanjay Gandhi and the companies with which he is associated. These are being examined with a view to ascertain whether there is any infringement of law which would warrant action on the part of the Government. These complaints will also mostly fall within the purview of the Commissions of Inquiry headed by Justice J. C. Shah and Justice D. S. Mathur appointed by the Government recently, where they will be fully inquired into. It may not be in public interest to disclose further information at this stage.

Arrest of University Teachers and other Social Workers in Delhi

1392. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether many university teachers and other leading social workers were arrested under Goonda Act i.e. under Section 110-G in Delhi during emergency:

(b) if so, their numbers; and

(c) the action Government propose to take against those officers who ordered them to be arrested under Goonda Act?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). According to information received from the Delhi Administration/Delhi Police, only two University teachers were arrested under Section 110(g) Cr. P .C. during the emergency on account of their activities.

Decentralisation of Economic and Political Power

1393. SHRI F. H. MOHSIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Janata Party had pledged to ensure decentralisation of economic and political power; and

(b) the concrete steps taken or proposed to be taken to achieve these objectives?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The abandonment of the personality cult, the restoration of the freedom of the press, the upholding of judicial independence and re-establishment of the Rule of Law are some of the important steps taken to prevent concentration of power. Decentralisation is a continuing process and Government will continue to take steps towards it in various spheres of activity.

Charges against Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh

1394. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any letters have been addressed to the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh to have their comments on the charges made against them and other Ministers of their Cabinets;

(b) if so, what are the charges against them;

(c) whether any replies have been received from them;

(d) whether these charges were looked into by the previous Government and they were found baseless;

(e) what were the special circumstances under which re-examination is sought to be made; and

(f) whether Government would go into the allegations made against Shri Veerendra Patil, the former Chief Minister of Mysore and other Ministers of his Cabinet?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (c). Yes, Sir.

(b) Copies of the notifications by which the two Commissions of Inquiry, headed by Shri A. N. Grover and Shri J. R. Vimadalal, have been set up to inquire, respectively, into the allegations against the Chief Minister and other Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh, have been placed in the Library of Parliament. The matters which have been referred for inquiry have been indicated in the terms of reference of these two Commissions, as given in the aforesaid notifications.

(d) and (e). Government is not aware that any of the matters raised in the Memorandum of allegations dated 6-4-1977 against the Chief Minister and other Ministers of Andhra Pradesh was looked into earlier by the previous Government and found to be baseless. As regards the 36 allegations contained in the memorandum dated 11-4-1977 against the Chief Minister and other Ministers of Karnataka, only 7 allegations are such as were received earlier also; and of these 7, final view appears to have been taken by the previous Government in respect of only one and not the other six.

(f) Does not arise. The present Government has not received any allegations against Shri Veerendra Patil, the former Chief Minister of Mysore and other Ministers of his Cabinet.

Punjab-Haryana Boundary Dispute

1395. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any change in the decision already taken by the pre-

vious Government regarding the border dispute between Punjab and Haryana States, specially in regard to Chandigarh city being included in Punjab and Fazilka and Abhor to be transferred to Haryana:

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when the decision is going to be implemented?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Government have yet to take a view in the matter after consultation with the new Governments in the States concerned.

Central Agency to keep watch over Industrial Projects

1396. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Central agency to keep watch over the processing of proposals for industrial projects in backward areas as recommended in para 2.55 of the 69th Report of the Estimates Committee (Fifth Lok Sabha) and reiterated in para 6 of Chapter 1 of the 95th Report of that Committee;

(b) if so, the composition and functions of the agency; and

(c) if not, the reasons for non-implementation and the alternative method for processing proposals?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) to (c). The Planning Commission are examining the recommendation of the Estimates Committee in para 2.55 of their 69th Report and reiterated in para 6 of Chapter I of their 95th Report in consultation with the various authorities.

Sending of Satellite in Space

1397. DR. BIJOY K. MONDAL: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) the progress made in the direction of completing another satellite for being rocketed into the space for probe or other purposes;

(b) in the light of the experience gained and data collected from the first satellite, what precisely shall be the purpose or objective of the device; and

(c) by what time our satellites will be able to televise Indian programmes for the benefit of the country-man and what areas are proposed to be covered in the beginning?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Work on the second Satellite which will conduct earth observation experiments is progressing according to schedule. The Engineering model has been completed and work on the prototype and the flight models is under way.

(b) While Aryabhata established the basis capability in Satellite technology and provided our scientists & engineers with experience in th design, fabrication and testing of space-worthy structures, the main purpose of the Satellite for Earth Observations is photography and remote sensing of gross features of the Indian land mass, monitoring of meteorological data and generally to collect information related to water resources, forestry, regional geology, hydrology, snow cover, large scale vegetation mapping, etc.

(c) The question of establishing a multi-purpose operational space system providing tele-communications, meteorology and television services from a common satellite in geo-stationery orbit is under examination. At this stage it is premature and not possible to indicate the time frame for introduction of satellite TV services or the areas which would be covered by them.

Restoring of Accreditation of Correspondents during Emergency

1398. DR. BAPU KAIDATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have restored accreditation of correspondents who were denied during the Emergency;

(b) if so, the names of those whose accreditation has been restored;

(c) whether only selected correspondents have been provided temporary accreditation; and

(d) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (d). During the Emergency Government had discontinued the accreditation of 43 correspondents. Requests have been received for fresh accreditation for 26 correspondents out of these. Fresh accreditation in 25 cases have already been granted and one case is under consideration. The names of correspondents to whom fresh accreditation has been granted is given in the Statement attached.

Statement

(A) Correspondent:

S. No.	Name	Organisation
1.	Shri R. Ramanujam	Newsweek, New York
2.	Shri S. P. Sinha	Der Spiegel (Hamburg)
3.	Shri Prakash Mirchandani	B. B. C. London
4.	Shri B. P. Agarwal	Yugwarta Feature Service
5.	Shri N. B. Lele	Tarun Bharat, Poona
6.	Shri O. P. Pandit	Samachar
7.	Shri R. S. Agnihotri	Samachar
8.	Shri D. V. Gandhi	Sakshi, New Delhi.
9.	Shri Inder Jit	India News & Feature Alliance
10.	Shri G. G. Mirchandani	Hindustan Sindhi Daily, Bombay
11.	Shri M. R. Virmani	Enterprise News & Features
12.	Shri Krishan Kumar	Vikrant News Service
13.	Shri R. C. Pandit	Aaj, Varanasi
14.	Shri Chandrakant F. Shah	Gujarat Samachar, Ahmedabad
15.	Shri R. C. Pradhan	Janata Weekly, Bombay
16.	Shri G. S. Bhargava	Ceylon Daily Mirror, Colombo
17.	Shri Pran Sabharwal	Baltimore Sun, USA
18.	Shri P. K. Khanna	K. B. C. News, New York
19.	Shri C. K. Arora	Samachar
20.	Shri T. V. Satyanarayanan	Samachar
21.	Shri C. Raghavan	Long and Distinguished Service
22.	Shri N. K. Trikha	Nav Bharat Times
23.	Shri K. N. Malik	Times of India
24.	Shri V. P. Ramachandran	Samachar
25.	Shri Eric Da Costa	Long & Distinguished Service

शाह आयोग के सचिव का पद

1399. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मई, 1977 के 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में शाह जांच आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने आपात स्थिति का समर्थन किया था (शाह प्रोब की आफिसल बाज फार एमरजेंसी) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या श्री एन० एम० सक्सेना को शाह आयोग के सचिव के पद से हटा दिया जायेगा;

(ख) क्या श्री सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तिका 'केआस, डिस्कार्ड एण्ड अनार्की वर्सेस डिसीप्लीन, आर्डर एण्ड स्टेबिलिटी" को कुछ प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी; और

(ग) क्या श्री सक्सेना ने जिस तरह सरकार का बचाव किया, उच्च न्यायालय के निर्णय का और तोड़ा तथा वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर टीका टिप्पणी की, उसे देखते हुए उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि हां, तो कब तक तथा किस रूप में ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान 21 मई, 1977 के दि इण्डियन एक्सप्रेस में 'शाह जांच आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने आपात स्थिति का समर्थन किया था' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है हालांकि श्री एन० एम० सक्सेना द्वारा लिखित 'केआस, एण्ड डिस्कार्ड एण्ड अनार्की वर्सेस डिसिप्लिन, आर्डर एण्ड स्टेबिलिटी" पुस्तिका केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों में परिचालन के लिए थी, फिर भी इसकी एक प्रति इस बात को ध्यान में रख कर सदन के पटल पर रखी जा रही है [संथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 477/77] कि इसने जनता में जागृति पैदा की है। श्री सक्सेना को शाह आयोग के सचिव के पद पर कभी नियुक्त नहीं किया गया। अब वे सेवा निवृत्त हो गये हैं और सरकार के विचार से उनके विरुद्ध किसी विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों और पायलटों का उपयोग

1400. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अपनी चुनाव सभाओं में भारतीय वायु सेना के विमानों और पायलटों का उपयोग करती थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने तथा उनकी पार्टी ने विमान के किराये का भुगतान किया था तथा भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के निजी उड़ानों के लिए जो भाड़ा दिया गया, उसका हिसाब लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री तथा उनकी पार्टी पर कई राशियां भी भी बकाया हैं तथा किन-किन उड़ानों का कितना भाड़ा बकाया पड़ा है;

(घ) क्या वर्तमान प्रधान मन्त्री ने भी कभी निजी चुनाव यात्राओं में वायु सेना के विमानों का प्रयोग किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इन विमानों का उपयोग किन तिथियों को किया गया था तथा उनका कुल भाड़ा कितना हुआ तथा कितना चुकाया गया तथा कितना अभी भी बाकी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की गैर-सरकारी उड़ानों का किराया प्रधान मन्त्री के कार्यालय के माध्यम से वसूल किया जा रहा है, जो इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सहित सम्बन्धित पक्षों को अलग से बिल भेजते हैं। किराए का हिसाब लगाने का तरीका समय-समय पर यथा संशोधित, 17-8-1968 के सरकारी आदेश में निर्धारित किया गया है और उस आदेश के सम्बन्धित अंश एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के गैर-सरकारी दौरे के सम्बन्ध में 13,76,762.38 रुपए की बाकी राशि का एक बिल प्रधान मन्त्री के कार्यालय को भेजा गया था। प्रधान मन्त्री के कार्यालय में उसकी छानबीन करने पर यह पता चला कि इस राशि में से 11,48,749.08 रुपए की वसूली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से की जानी है और प्रधान मन्त्री के कार्यालय द्वारा इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके बाद बची शेष राशि की वसूली किन स्रोतों से करनी है, 13,76,762 38 रु० की बकाया राशि में सम्बन्धित उड़ानों के तारीखवार ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गैर सरकारी उड़ानों के लिए किराए का हिसाब लगाने में अपनाई गई प्रक्रिया।

गैर सरकारी उड़ानों के प्रभार में निम्न-लिखित सम्मिलित हैं :—

(1) **भाड़ा** :—यदि गन्तव्य स्थान तक नियमित वाणिज्यिक विमान सेवा उपलब्ध है, तो इण्डियन एयर लाइन्स की दर पर हरेक यात्री के लिए भाड़े का हिसाब लगाया जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो नीचे दी गई दरों के अनुसार भाड़ा लिया जाता है:—

दर	प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री	
विमान प्रति मानक मील	0.61 रुपए	0.61 रुपए
हेलीकोप्टर प्रति किलोमीटर	0.38 रुपए	3.60 रुपए

प्रधान मंत्री के जिन निजी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मिलता है, उनके लिए किराया का हिसाब नहीं लगाया जाता है।

(2) **विमान को रोक कर रखने का प्रतीक्षा प्रभार** :—यदि किसी आउट स्टेशन पर लगातार 48 घंटे के बाद विमान को रोक कर रखा जाये, तो उसके लिए प्रतीक्षा-प्रभार लगाया जाता है, लेकिन यह प्रभार पहले 48 घंटे के बाद के हर 24 घंटे के लिए अधिक से अधिक 6 घंटे के लिए लगाया जाता है।

(3) **विशिष्ट व्यक्ति हवाई कर्मीदल (पायलट आदि) के भोजन एंव आवास का प्रभार** :—विशिष्ट व्यक्तियों के हवाई कर्मीदल को यदि किसी आउटस्टेशन पर 3 घंटे से अधिक समय के लिए रोका जाये तो उनके भोजन एवं आवास के लिए निर्धारित दर पर प्रभार लगाया जाता है।

(4) **अन्य खर्च** :—जैसे उचित स्थल पर विमान खड़ा करने, परीक्षण

के लिए विमान उतारने, बेस पर वापस आने, विमान को स्टैंड बाई रखने और ईंधन भरने के लिए की गयी उड़ानों के मामले में उपर्युक्त (1) में बताए गए तरीके से एक यात्री के लिए प्रभार लगाया जाता है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की जिन गैर सरकारी यात्राओं के लिए बकाया बिलों को प्रधान मंत्री कार्यालय को वसूली के लिए भेजा है उनके ब्यौरे ।

क्र. सं.	उड़ान की तारीख	रकम रुपए
1.	17-2-77	9,364.44
2.	18-2-77 से 25-2-77	2,69,204.80
3.	26-2-77 से 28-2-77	1,17,495.20
4.	2-3-77 से 8-3-77	2,79,300.78
5.	9-3-77	26,886.48
6.	10-3-77	20,237.28
7.	11-3-77 से 18-3-77	6,54,273.40
	जोड़	13,76,762.38

Eastern Coalfields Limited

1401. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether rampant corruption is prevailing in cases of filling up vacancies and recruitment in Eastern Coalfields Limited;

(b) if so, whether the Ministry will institute an inquiry to establish the fact; and

(c) whether Government will formulate policy in respect of recruitment in E.C.L.?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A procedure has already been laid down for recruitment in the Public Sector Undertakings, which is applicable to Eastern Coalfields Limited as well.

गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता

1402. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री धर्मवीर वशिष्ट :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1970-71, 1975-76 और 1976-77 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की, राज्यवार प्रतिशतता कितनी थी और अब कितनी है ; और

(ख) उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रहन-सहन के न्यूनतम स्तर के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति व्यय के सम्बन्ध में कुछ धारणाएं बनाने के बाद, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा दिए गए घरेलू उपभोग-व्यय से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पहले अनुमान किया गया था । इन धारणाओं में भिन्नता है और परिणामस्वरूप कोई निश्चित और विश्वसनीय आंकड़े नहीं दिए जा सकते ।

(ख) योजना आयोग से छठी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में गरीबी से सम्बन्धित पहलुओं को पूरी तरह से ध्यान में रखने के लिये अनुरोध किया गया हैं । आयोग गरीबी को दूर करने के लिए नीति और इससे सम्बन्धित योजनाओं तथा कार्यक्रमों की ओर ध्यान देगा । इसी बीच आर्थिक विकास के के माध्यम से वर्तमान योजनाओं से जनसंख्या के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की अपेक्षा है । कृषि और सम्बद्ध विषयों के लिए धनराशि का 30 प्रतिशत आवंटित करने और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में 25 लाख रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से 1977–78 की वार्षिक योजना को नया रूप दिया गया है ।

आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को बहाली

1403. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपात स्थिति के दौरान राजनीति की भावना से आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार और सेवा से निकाले गये व्यक्तियों को बहाल कर दिया गया है जबकि इसी प्रकार भारत रक्षा नियम के अंतर्गत गिरफ्तार किये गय व्यक्तियों को बहाल नहीं किया गया हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम (मीसा) के अधीन जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बन्दी बना दिया गया था और जिन्हें अब मुक्त कर दिया गया है, उन्हें सेवा में बहाल कर दिया जाना चाहिए। फिर भी, भारत रक्षा नियम के अधीन गिरफ्तार किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में संबंधित प्राधिकारियों को प्रत्येक ऐसे मामले की गुणावगुण के आधार पर जांच करनी होगी कि क्या संबंधित कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए अपराध के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सेवा में बहाल किया जाये। जिन कर्मचारियों को डी० आई० एस० आई० आर० के अधीन दोष सिद्ध पाया गया है उनके मामले में भी प्राधिकारी, कर्मचारी के मामले की पुनरीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति को सेवा में बहाल करने के लिए सक्षम हैं ।

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी

1404. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनेक भागों से यह समाचार आ रहे हैं कि बिजली की कमी के कारण औद्योगिक संस्थानों में उत्पादन कम हो रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कितने कारखानों ने कर्मचारियों की छंटनी की है ।

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली की कमी के प्रभाव को कम करने की दिशा में निम्नलिखित उपाय शुरु किए गए हैं :—

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों को अपनाये जाने के लिए भेज दिए गए हैं ।

(ii) विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए अनेक औद्योगिक एककों में डीजल जनरेटिंग सटों का उपयोग किया जा रहा है।

(iii) गैस टर्बाइन सेटों के माध्यम से बिजली पैदा करने की सिफारिश की गई है।

(iv) फालतू बिजली वाले राज्यों से यथा संभव निकटवर्ती कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के लिए व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जनवरी, 1977 के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा सकलित की गई सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि उद्योग के निर्माणकारी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में 10 एककों में, उत्तर प्रदेश में 1 एकक में, महाराष्ट्र में 22 एककों में और तमिलनाडु में किसी भी एकक में छटनी नहीं करनी पड़ी है। फिर भी इस निष्कर्ष पर पहुचना कठिन है कि छटनी केवल बिजली की कमी के कारण की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात की पुष्टी की है कि बिजली की कमी के कारण की गई छटनी सम्बन्धी कोई भी रिपोर्ट उसे अभी तक नहीं मिली है।

कर्मचारियों की बहाली

1405. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री हरि विष्णु कामथ :

श्री के० ए० राजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सब सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में निदेश जारी किये हैं जिन्हें सेवा से निलम्बित किया गया था अथवा जबरदस्ती निकाला गया था ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बिना कारण सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को बहाल नहीं किया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास निलम्बित किए गए अथवा हटाए गए सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। चूंकि किसी सरकारी कर्मचारी का निलबित किया जाना तथा उसे सेवा से हटाया जाना उस पर लागू अनुशासनिक नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है और चूंकि इन नियमों में सेवा से निलम्बित हटाए जाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षा के लिए प्रावधान हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इस सम्बन्ध में इस विभाग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) चूंकि संविधान की 7 वी अनुसूची की सूची II की प्रविष्ट 41 द्वारा राज्य की सरकारी सेवाएं पूर्णतः राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

Implementation of Shillong Agreement

1406. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a Nagaland delegation recently called on the Home Minister to discuss the progress of implementation of Shillong Agreement; and

(b) if so, the outcome of the meeting and the follow up action taken or proposed to be taken to normalise the position?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Their only suggestion was that a meeting should be arranged between the Prime Minister and Mr. Phizo. The Prime Minister agreed to meet Phizo during his visit to London but made it clear that Mr. Phizo must accept that Nagaland is part of India and the Nagas are citizens of India. When Mr. Phizo met the Prime Minister, he did not accept this condition. Consequently no further progress could be made.

Naxalite Prisoners

1407. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of political prisoners lodged in various jails in each State, characterised as Naxalites, who were convicted, detained under MISA or as undertrials;

(b) the number of warrants pending; and

(c) whether Government propose to grant a general amnesty and release all of them?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) A statement is attached.

(b) Information is being collected.

(c) Except for 57 detenus in West Bengal and 5 in Tamil Nadu whom the State Governments do not consider fit for release at this stage, there are no other naxalites in detention at present. In regard to convicts and undertrials, State Governments have been advised to consider sympathetically the cases of those Naxalites who agree to abjure violence and affirm their faith in the democratic process according to the lead given by some of their leaders.

Statement

Naxalites in Prison as on 31-5-1977

Sl. No.	State	Total No. Still in Custody	Number under detention	Number convicted	Number undertrials	Number pending investigation
1	Assam	18	..	3	15	..
2	Tripura	1	..	..	1	..
3	Tamil Nadu	33	5	20	3	5
4	Bihar	250	..	22	158	70
5	Punjab	7	..	7	..	..
6	Delhi	..	..	..	..	..
7	Andhra Pradesh	Information is being collected				
8	Kerala	Do.				
9	Orissa	Do.				
10	Madhya Pradesh	Do.				
11	West Bengal		57	Do		

Setting up of Tannery in Gujarat

1408. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is immediate need of setting up a big tannery in Gujarat;

(b) whether at present, the tanners in Gujarat have to send skin and hide collection to Madras for tanning and export purposes; and

(c) the date by which the tannery is likely to be set up?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Adequate tanning capacity is available in the country for processing of raw hides and skins. A number of tanning units are operating in the small scale sector in the State of Gujarat. Government have also granted a Letter of Intent dated 22nd April, 1976 to the Gujarat Agro-Industries Corporation (which has since been transferred to the Gujarat Industrial Investment Corporation Limited, Ahmedabad), for establishment of a new undertaking in the State of Gujarat for the manufacture of finished leather from hides and skins for an annual capacity of 4.8 lakh numbers.

(b) The tanning industry in the country is at present concentrated mostly in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra and Punjab. Surplus hides and skins from other States generally move into these areas for tanning/finishing.

(c) The Letter of Intent granted to the Gujarat Industrial Investment Corporation Limited, Ahmedabad is valid upto 21st October, 1977. According to the Corporation the project is likely to be implemented in another year.

New Schemes under R.E.C.

1409. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether an additional sum of Rs. 12.37 crores has been sanctioned by the Rural Electrification Corporation for 32 new schemes covering 1,737 villages in 14 States;

(b) if so, the States where electrification is being done under these schemes; and

(c) how much will be spent on electrification of villages in Gujarat under these schemes?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) The Board of Directors of the Rural Electrification Corporation in its meeting held on 30th April, 1977 sanctioned 32 new rural electrification schemes involving a loan assistance of Rs. 10.91 crores envisaging extension of electricity to 1737 villages in 14 States. In the same meeting the Board also approved additional loans amounting to Rs. 1.74 crores for on-going rural electrification projects and Rs. 0.06 crores for extension of electricity to Harijan Bastis. The total loan amount sanctioned by the Board in the meeting amounted to Rs. 12.71 crores.

(b) 32 schemes sanctioned by the Corporation were for rural electrification in the following 14 States:—

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Gujarat
4. Haryana
5. Himachal Pradesh
6. Jammu & Kashmir
7. Karnataka
8. Kerala
9. Madhya Pradesh
10. Maharashtra
11. Orissa
12. Punjab

13. Tamil Nadu

14. West Bengal.

(c) These 32 schemes include two schemes of Gujarat involving a loan assistance of Rs. 25.55 lakhs.

Service conditions of Government Employees

1410. SHRI PRASAENNBHAI MEHTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided that Government employees will have a say in service conditions;

(b) if so, whether the Government are considering to reorganise the present system and adopt a new system by which Government employees' grievances and service conditions can be changed and looked into only in consultation with them; and

(c) if so, main features of this new proposal?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) In October, 1966, Government introduced a Scheme for Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration for Central Government Employees, with the object of promoting harmonious relations and of securing the greatest measure of Cooperation between Government and the general body of its employees. The Scheme provides for Joint Councils at three tiers; a National Council at the national level covering generally all employees of Central Government; Departmental Councils at the level of the Ministries/Departments including the employees of their Attached and Subordinate offices; and Office/Regional Councils for individual offices, for discussions and consultations with the representatives of the staff on matters of common concern coming within the purview of the Scheme. The scope of the Joint Councils includes all matters relating to conditions of work and service, welfare of employees, improvement of efficiency and standards of work, provided, however, that (i) in regard to recruitment, promotion and discipline, consultation will be limited to matters of general principles, and (ii) individual cases will not be covered. This Scheme continues to be operative.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Implementation of Recommendation of a Committee headed by Shri A. K. Chanda

1411. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a committee headed by Shri A. K. Chanda was appointed in 1966 to study the working of the various media units of the Ministry;

(b) if so, whether the present Government propose to implement its recommendations fully; and

(c) how many of its recommendations were accepted by the earlier Government and the steps being taken by the present Government to implement its recommendations immediately?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir. The Committee was set up in 1964.

(b) and (c). The position in respect of recommendations as have not been implemented is being reviewed and the information will be laid on the table of the House.

Coal India Limited

1412. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Coal India Limited is facing financial crisis; and

(b) if so, steps taken to meet the situation?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No., Sir.

(b) Does not arise.

Seizure of Ammunition from the Ashram at Mantalai in J & K

1413. SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received reports that ammunition was seized from the Ashram of Swami Dhirendra Brahmchari at Mantalai in Jammu & Kashmir;

(b) if so. the quantity of ammunition seized;

(c) whether any licence for keeping such ammunition was obtained by Swami Dhirendra Brahmchari; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes. Sir.

(b) It has been reported that the following arms and ammunition were recovered:

FIREARMS

(1) One single Barrel Breach loading .12 Bore Shot Gun, made in Japan (K.F.C. "Spin") No. 12—70, P-206781 Pine and 3 component parts.

(2) One .32 revolver.

(3) One .22 rifle.

AMMUNITION

(1) 18 Cartridges for .12 bore shot gun.

(2) 117 Cartridge for .32 Revolver.

(c) Swami Dhirendra Brahmachari was issued Licence No. 17/JAN/Kotla Mubarakpur/Delhi for the possession of four weapons including:

(1) One .12 bore Shot Gun.

(2) One .32 revolver.

(3) One .22 bore rifle.

The .12 shot gun was imported and after clearance by Customs was sought to be endorsed on the arms licence. This was found to be a semi-automatic weapon and the request for its possession against the arms licence was turned down by the Delhi Administration. In the case of the revolver, for which 117 cartridges appear to have been recovered, the licence authorizes him to keep a maximum quantity of 25 cartridges at any one time. The licence was not renewed in time and application for renewal was received after expiry date of the licence. The matter is being further looked into.

(d) Action under the Arms Act will be taken in the light of further scrutiny of facts and as warranted by the law.

Bad Liquor Deaths in Bombay

1414 SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI SKARIAH THOMAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a number of persons were killed by drinking bad liquor in Bombay during the 1st week, of May, 1977;

(b) if so, the number of persons killed as result thereof; and

(c) whether any preventive measures have been taken by Government and if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have intimated that 49 persons have died as a result.

(c) The State Government is taking action to organise raids against bootlegging activities and have issued instructions to local officers to check godowns to detect unauthorised sale and storage of methyl alcohol and other substances used for the manufacture of poisonous brew.

Loss incurred by DSIDC

1415. SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI OM PRAKASH TYAGI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Delhi State Industrial Development Corporation has suffered a loss of Rs 25 lakhs in trying out certain 20 point economic programme during emergency; and

(b) if so, whether Government propose to hold an inquiry into the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व नौ राज्यों में किए गए निर्णय

1416. **श्री जो० एस० तोहरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उन नौ राज्यों के, जहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के कुछ सप्ताह पूर्व वहां के मुख्य मंत्रियों ने अत्यंत शीघ्रता से जो फैसले किये थे, राज्यपाल को कोई सिफारिश की है या करने का विचार है कि वे उन में जितने फैसले मंसूख कर सकें, कर दें विशेषकर जो फैसले वित्तीय और प्रशासनिक औचित्य की घोर उपेक्षा करके दिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा के तुरन्त बाद संबंधित राज्यपालों को सलाह दी गई थी कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर पुनर्विचार किया जाय ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि वे फैसले वित्तीय तथा प्रशासनिक औचित्य की उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप थे और जहां भी सुविधापूर्वक सम्भव हो वहां उपचारी कार्यवाही की जाय। उन्हें यह सलाह भी दी गई थी कि वे उन अधिकारियों के स्थानानांतरण पर पुनर्विचार करें जिनका संबंध विशेष रूप से जिला प्रशासन, विधि तथा व्यवस्था और चुनावों के साथ था ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्थानांतरण सामान्य लोकहित के विचार से उचित थे।

'किस्सा कुर्सी का' फिल्म के प्रिंट के गायब होने के बारे में जांच

1417. **श्री जो० एस० तोहरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किस्सा कुर्सी का' फिल्म के प्रिन्ट के गायब होने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13-4-77 को भारतीय दण्ड संहिता के खंड 120 बी, आर डब्ल्यू 380 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। यह बताया गया है कि जांच के दौरान 25-5-77 को गुड़गांव स्थित मारुति फैक्टरी के अहाते की तलाशी के बाद खाली डिब्बे, उन डिब्बों में इस फिल्म के रोल रखे जाने का संकेत करने वाले लेबलों सहित, बरामद किए गए। उपलब्ध साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि फिल्म को जलाकर नष्ट कर दिया गया है ; जांच अंतिम चरण में है।

Chhoti Sadri Gold Scandal Case

1418. SHRI MUKHTIAR SINGH MALLIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to re-open the Chhoti Sadri Gold Scandal case?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): The matter relating to the Chhoti Sadri Gold case, amongst others, is referred to in a memorandum, received recently, containing allegations against the former Chief Ministers of Rajasthan which are being processed in accordance with the usual procedure.

Tractor Factory, Pratapgarh

1419. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the progress made in setting up tractor factory in Pratapgarh District, U.P.;

(b) the estimated cost of the tractor and number of tractors to be produced annually; and

(c) the funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) As reported by M/S. Auto Tractors Ltd., which is a Govt. of U.P. enterprise, the land has been acquired, fencing work partically completed, field hostel construction in progress and nucleus design/process engineering/materials management staff in position.

(b) As estimated by the firm, the ex-factory selling price of the tractor would be Rs. 37,000/-. They plan to produce 500, 1500, 2500, 4000 and 6000 tractors during first five years of commencement of production.

(c) The State Government have allocated Rs. 50 lakhs, so far.

Loss on D.T.C. Buses

1420. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether DTC is incurring a huge loss on the buses it owns; and

(b) if so, the number of buses owned by DTC and the loss per month on each bus?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) DTC is incurring losses.

(b) During the year 1976-77, the DTC, on an average had a fleet of 2247 and incurred an estimated loss of Rs. 4,116 per bus per month.

Flat Fare System introduced by D.T.C.

1421. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the flat fare system introduced by D.T.C. has failed to pull the DTC out of red; and

(b) if so the reasons thereof and the remedial measures proposed to be taken in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The flat fare system has not yielded the expected results.

(b) The increase in revenue on account of introduction of two-stage fare system has not been adequate to make up the financial loss. Remedial measures to reduce the losses, so as to make the Organisation financially viable, are now under consideration of the DTC management.

Vacant Top Posts in D.T.C.

1422. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether some of the top posts in DTC are lying vacant for a long time; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir. The post of Additional General Manager has been vacant since 1.9.76 and that of General Manager since 11.2.77.

(b) Shri Abdul Bari, Additional General Manager, was appointed as General Manager of DTC on a temporary basis for six months from 1.9.76. Action for filling up the post of Additional General Manager was deferred until 28.2.77 because Shri Bari could have been reverted to his substantive post anytime thereafter. The question whether the post of Additional General Manager may be filled up or kept vacant, as a measure of economy, is now under DTC's consideration.

The post of General Manager, which fell vacant on 11.2.77, following Shri Bari's proceeding on leave and later reverting to his present organisation, has also not been filled up because it has been decided to combine the posts of Chairman and General Manager. This combined post is expected to be filled soon.

Shri B. B. Mahajan, Joint Secretary in the Ministry of Shipping and Transport has been holding additional charge of the post of Chairman, DTC, since 2.4.77 on which date the incumbent of the post proceeded on leave, before reverting to his cadre post.

Atrocities on Harijans by Landlords

1423. SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

SHRI S. G. MURUGAIYAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the recent atrocities perpetrated on Harijans, agricultural workers, backward classes and weaker section by landlords in Bihar and Andhra;

(b) whether such Harijan repression took place in other States during March-April this year, if so, the particulars thereof;

(c) the steps taken against those who are responsible for these; and

(d) the steps taken to prevent the recurrence of these in future?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Government have seen newspaper reports in this regard. Information whether any such incidents have occurred is being collected from all State Governments.

(d) It has been impresed upon State Governments that all cases involving any form of violence against harijans should be investigated promptly and efficiently and that persons suspected

to have committed any such offence should be brought to book according to law. It has also been impressed upon the State Governments that when such incidents come to their notice effective and adequate measures should be taken to instill a sense of security amongst the affected persons and strengthen preventive arrangements.

Pension to Participants of Moplah Rebellion

1424. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision regarding the grant of pension to the freedom fighters who took part in the famous Moplah rebellion in Kerala;

(b) if not, whether an early decision will be taken; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). The matter is still under consideration.

Passenger Steamer for Konkan Coastal Traffic

1425. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether purchase of one more passenger steamer for Konkan coastal traffic is under the active consideration of Government;

(b) whether Maharashtra and Goa Governments are pressing for this additional passenger steamer; and

(c) whether Government have taken any decision on the report of Saggi Committee on Coastal traffic on the Western Coast of India

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). No, Sir.

(c) Presumably, the reference is to a Committee appointed by the Govt. of Maharashtra under the chairmanship of Shri J. G. Saggi, Managing Director, Mogul Line Limited to go into the question of acquiring additional two small low draughted vessels for operation on the Konkan coast. The Committee submitted its report to the Government of Maharashtra on 18th March, 1975. No communication has been received from the Government of Maharashtra in respect of this report. The questioin of the Government of India taking a decision on the report therefore does not arise.

Nhava Sheva harbour project in Bombay

1426. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether NHAVA SHEVA Harbour Project in Bombay is making slow progress due to lack of finance from the Centre;

(b) when the project will be completed and what provision have been made for each stage; and

(c) how much finance will be provided by the public finance Corporations?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No investment decision has been taken so far on the matter.

(b) and (c). Do not arise.

Compulsory Research Cess on Industry

1427. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the then Minister of Planning announced in the Fifth Lok

Sabha on 26th March, 1976 that a Bill for Compulsory Research Cess on industry will be introduced; and

(b) if so, the steps taken in this direction?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) While answering a Starred Question in the Lok Sabha on the 24th March, 1976 the then Minister of Planning had stated that Government intended to levy a Cess on Industries under the provisions of Industries, (Development and Regulation) Act, 1951, with a view to raise funds for research and development.

(b) The details of the scheme, as worked out, are under the consideration of Government.

Private Sector to be Encouraged

1428. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news report appearing in the Statesman, Delhi edition on April 2, 1977, entitled "Private Sector to be encouraged"; and

(b) if so, the reaction of Government in regard to "discreet objectives regarding nationalisation" and individualised and bureaucratic monopolies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Yes Sir.

(b) The statement referred to in the news report appearing in Delhi edition of "The Statesman" dated April 2, 1977 was withdrawn subsequently. The policy of the Government on the subject will be announced in due course when it is finalised.

Insov Auto Ltd.

1429. SHRI CHITTA BASU:

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the state of affairs of Insov Auto Ltd., a Soviet collaboration project in India; and

(b) if so, the steps taken by Government to remedy the situation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) On orders of the Government, an inspection under Section 209 A of the Companies Act, 1956 was carried out into the affairs of M/S. Insov Auto Limited. Inspection Report brought out several instances of malpractices and irregularities committed by the management of the company. Subsequently by order dated 24.1.1977, the Company Law Board has appointed an advocate of Calcutta as Inspector to investigate into the affairs of the company under section 237 (b) of the Companies Act, 1956 with directions to submit the report on or before 31st December, 1977. Further action will be considered on receipt of Investigation Report.

Mathew Commission report

1430. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government have since received the report of Mathew Commission on L. N. Mishra's murder; and

(b) if so, the follow-up action taken thereon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The report is under examination.

Equity participation to the Coal India Limited

1431. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under consideration to invite public deposits or equity participation to the State-owned Coal India Limited; and

(b) if so, facts and reasons therefor?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Collaboration agreements with Multinational Corporations

1432. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have allowed any Indian companies to have collaboration agreements with multi-national corporations in the last two years;

(b) if so, the number of such collaboration agreements;

(c) the names of the Indian and foreign multi-national corporations involved in these agreements; and

(d) the main features of the agreements?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) to (d). The number of collaboration agreements allowed during 1975 and 1976 with foreign companies is given below:—

1975	:	271
1976	:	277

Detailed quarterly lists of those approved collaborations are available in the Parliamentary Library. These lists *interalia* indicate the name of the Indian company, the name of the foreign collaborator and the item of manufacture. Out of 271 cases approved during 1975 and 277 cases approved during 1976, foreign equity participation was allowed in 40 and 39 cases respectively. In the remaining cases only technical collaboration was approved.

Arms supply to Pakistan

1433. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it has been discuosed recently that there exists a secret U.S.-Pak understanding by which the former has assured massive arms supply to Pakistan; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Government do not have authentic information about any such secret understanding between the USA and Pakistan.

(b) Does not arise.

Complaints regarding pollution

1434. SHRI P. K. KODIYAN: Will the MINISTER OF ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to complaints regarding pollution caused by the Indraprastha and Rajghat Power Units;

(b) if so, facts thereof; and

(c) action taken to put an end to this menace?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) Pollution from Indraprastha Power Station is caused primarily due to poor performance of the dust collecting equipments provided in the plant. Pollution from Rajghat Power Station is negligible.

(c) A number of steps have been taken to improve the performance of the existing equipment. These include improvements in the ash evacuation system, rapping mechanism of the Precipitators, cyclones of the mechanical dust collectors. Linking-coal with reduced ash content to the power station is also being pursued. An expert Group was also set up to recommend measures to reduce pollution. The Group has, in its report recommended:—

(a) provision of a new electrostatic precipitator in place of the mechanical dust collector for Unit I;

(b) replacement of the existing electrostatic precipitators in other units by new precipitators of suitable design;

(c) regulatory orders to provide for local of 20—25 per cent ash content being supplied to Indraprastha Power Station;

(d) Research and Development measures to be initiated to collect data on the behaviour of a full-scale precipitator with low sulphur Indian coals, to study the effect of gas conditioning on the performance of precipitators and to study the optimum settings of precipitator control equipment and improved operating procedures for the same.

The recommendations of the Expert Group are under implementation by Delhi Electric Suplpy Undertaking.

बेरोजगारी समाप्त करने के लिए योजनायें

1435. **श्री कर्पूरी ठाकुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी घोषणा के अनुसार अगले दस वर्षों में देश से बेरोजगारी समाप्त कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या योजनाएं बना रही है ; और

(ग) इन योजनाओं को कब से क्रियान्वित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या अवधि रखी गई है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) । (क) से (ग) योजना आयोग से यह कहा गया है कि वह रोजगार को बहुत अधिक प्रधानता देते हुए छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करे। आयोग इस संबंध में ठोस नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तावित करेगा।

Capacity in Ordnance and Arms Factories

1437. SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is any surplus capacity in Ordnance and Arms factories;

(b) if so, whether Government propose to consider entering international market for small arms; and

(c) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No, Sir. The capacities of Ordnance Factories producing Arms and Ammunition are at present fully booked in meeting the requirements of the three Services and para-military forces.

(b) and (c). The question of exporting small arms to friendly countries is considered on merit as and when we have surplus capacity. It would not be in the public interest to give details thereof?

Expenditure incurred for entertainment of Journalists

1438. SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the total amount of money sanctioned and spent for entertainment by the Minister in 1975-76 and 1976-77; and

(b) whether there is a provision for providing duty free liquor in this entertainment; and

(c) the amount of money spent for entertainment of journalists?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI):

		Money sanctioned	Money spent
		Rs.	Rs.
(a)	1975-76	3,65,800·00	1,61,917·40
	1976-77	3,59,700·00	2,13,131·15
(b)	No; Sir.		
(c)	1975-76		41,234·20
	1976-77		1,06,445·16

Reduction of Secretaries in Government

1439. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been any reduction in the number of Secretaries to the Government of India recently; and

(b) if so, to what extent?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The number of Secretaries/ Special Secretaries to the Government of India stands reduced by six.

Allocation for Tribal Sub-Plan

1440. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Central Government have earmarked some money under the Tribal sub-plan to be spent on various development works in the backward areas in the country during the current year; and

(b) if so, the projects on which this money is going to be spent for development purposes, State-wise?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). The Central Government has earmarked a sum of Rs. 55 crores as Special Central Assistance during the current financial year for States and Union Territories having Tribal-Sub-Plans.

The amount is to be used for tribal development programmes under the Agriculture & allied sectors, Cooperation, Industry & Minerals, Transport and Communication, Social & Community Services and Welfare of Primitive Tribes.

A statement showing the allocation of the Central assistance State-wise is annexed.

Statement

Allocation Rs. 55 crores to various States during 1977-78

S.No.	State/U.T	Amount allocated
1	Andhra Pradesh	2·08
2	Assam	2·57
3	Bihar	7·70
4	Gujarat	4·63
5	Himachal Pradesh	0·90
6	Kerala	0·14
7	Karnataka	0·19
8	Madhya Pradesh	14·41
9	Maharashtra	3·28
10	Manipur	1·24
11	Orissa	7·58
12	Rajasthan	2·59
13	Tamil Nadu	0·28
14	Tripura	0·83
15	West Bengal	2·05
16	Uttar Pradesh	0·14
17	Andaman & Nicobar Islands	0·17
18	Goa, Daman & Diu	0·11
		50·89
	Programmes for Primitive Tribes	3·00
	Unallocated reserve for unforeseen programme	1·11
	Grand Total	55·00 (Crores)

Crisis in Small Units run by Technician Entrepreneurs

1441. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a large number of small scale industrial units run by technician entrepreneurs are facing collapse for want of financial and other support;

(b) whether any memorandum in this regard has been submitted to Government;

(c) whether the Indian engineers who had abandoned lucrative assignments abroad and started various units in India, are planning to abandon their ventures and return to countries of their choice; and

(d) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No Sir.

(b) Technician Association of Gujarat has submitted a memorandum on their various problems.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

Construction of factory by Rare Earths Limited

1442. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the investment, employment possibilities and schedule of construction of the factory built by the Rare Earths Ltd., Chattarpur, District Ganjam, Orissa; and

(b) whether the schedule of construction has been revised a number of times and if so, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The cost of the project originally estimated at Rs. 32.30 crores is now estimated at Rs. 85.67 crores according to the Project report prepared by the Indian Consultants. The escalation is attributable mainly to increased provision for items included in the earlier estimate and provision for fresh items,

escalation in cost of equipment and civil works which occurred in the wake of the oil crisis of 1973 and additional provision on account of sales tax, customs duty, cost of transport, etc. The manpower requirement for the project is estimated at 1170. There is also indirect employment potential in view of the likely development of Gopalpur Port and other activities such as fishing and marine based industries which are likely to receive a fillip from the development of the Port. The construction of the project could be completed within 3-4 years from the start of work. In view of the high capital requirements of the project and the resource constraints, the project is now being reviewed in consultation with the Planning Commission.

Allocation of Funds under Minimum Needs Programme

1443. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) total amount allocated under minimum needs programme and out of which the amount allotted to different States during the financial years of 1975-76, 1976-77 and 1977-78; and

(b) total amount spent under the various heads during the aforesaid period?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). A set of statements indicating the Fifth Plan provisions, approved outlays and expenditure for the year 1975-76, and 1976-77 as reported by respective States and the approved outlays for 1977-78 under different constituent programmes of the National Programme of Minimum Needs is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-478/77.]

Shah and Reddi Commissions of Inquiry

1444. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what progress has been made in regard to the work of the two Commissions of Inquiry headed by Shri J. C. Shah, former Chief Justice of India and by Shri Jagmohan Reddi, former Judge of the Supreme Court, respectively; and

(b) whether the hearings will be public?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Some skeleton staff are already in position in the office of the Shah Commission and the preliminary notification inviting statements relevant to the inquiry from all interested persons has already been published.

The notifications regarding the appointment and terms of reference of the two Commissions of Inquiry headed by Shri Jagmohan Reddi have issued. Action is being taken to set up the offices of these Commissions.

(b) In accordance with section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Commission shall regulate its own procedure, including a decision on whether it should sit in public or in private.

Purchase of Boeing 737 for I.A.F.

1445. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATACHARYYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are going to review the buying up of two Boeing 737 for the VIP squadron of the Indian Air Force; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). The former Government's decision to purchase two Boeing 737 aircraft for the VIP squadron has been reviewed and it has been decided not to purchase these aircraft.

Technology of Integrated Councils

1446. SHRI D.D. DESAI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether Government have made any progress in adopting the latest technology of integrated circuits; and

(b) if so, the main features thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Bharat Electronics Ltd. (BEL), Bangalore is in the process of undertaking production in depth of digital and linear Small Scale Integrated (SSI) circuits. Their digital product line covers a variety of TTL type SSI Circuits, (some of which are based on know-how developed indigenously by the Tata Institute of Fundamental Research) while their linear line includes voltage regulators, operational amplifiers and SSI Circuits for TV receivers. Several of their integrated circuits have been type approved for Defence use. BEL is also developing integrated circuits for communication systems. The company is likely to take up, in addition, C-MOS type SSI circuits shortly. M/s Continental Device India Ltd., M/s Semi-conductors Ltd., and M/s Hindustan Conductors are also engaged in assembly of SSI circuits from imported semiconductor 'chips'. Recently, a new company M/s Solid State Electronics Ltd., promoted in the joint sector in collaboration with the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation, has been approved for the manufacture of Schottky Barirer type SSI circuits, including high frequency, high power devices, based on Bi-Polar technology.

As for the advanced area of Large Scale Integrated (LSI) Circuits, Government approval has been given for the setting up of a Semiconductor Complex under the Department of Electronics to produce these highly sophisticated devices based on MOS technology. Proposals for technology supply from a number of companies in the USA and Europe are currently being evaluated, so as to select the most optimal contemporary technology product mix for the Complex.

Apart from these programmes for the domestic market, 100 per cent export-oriented programmes involving Large Scale Integrated Circuits based on C-MOS technology have been started in the Santa Cruz Electronic Export Processing Zone and are in early stages of implementation.

Concurrent with the launchin of these industrial programmes, the Department of Electronics has also been undertaking a number of promotional activities for facilitating the absorption and application of contemporary integrated circuit technology. These activities have ranged from: the structuring and financing by the Department of programmes for the training of high level manpower specialising in the development and use of integrated circuit technology at the IITs of Delhi and Kanpur, to the organisation of Workshops on Microprocesors (which currently constitute the most revolutionary area in digital LSI technology).

Setting up of Atomic Power Plant in Andhra Pradesh

1447. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether a survey has been made to set up an Atomic Power Plant in Andhra Pradesh;

(b) if so, the place selected; and

(c) the time by which it is proposed to be set up?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Committee appointed by Government for the selection of suitable sites for the setting up of nuclear power stations has examined a number of sites in the Southern Electricity Region of which Andhra Pradesh forms a part. The Committee's report is under consideration of Government.

Facilities to conduct Research in Space Science

1448. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to improve the facilities in Sriharikota to conduct research in Space Science; and

(b) if so, the main features thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Sriharikota is a rocket test and sateilite launching range. No research in Space Science is conducted at the range; only technical and logistic support is provided to Space Scientists who may have experimental payloads on the vehicles launched from Sriharikota.

(b) Does not arise.

Industrial Complex at Renigunta

1449. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to start industrial complex at Renigunta in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the date?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) There is already an industrial complex at Renigunta.

(b) 1975-76.

Introduction of district planning

1450. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce district planning; and

(b) if so, the main features thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The Government has been emphasising from time to time the importance of introducing planning at district level. It will encourage State Governments to set up an appropriate machinery for planning at the district level.

Building of war ships

1451. SHRI SKARIAJI THOMAS: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government of India have formulated any scheme to build indigenously designed war ships in the country;

(b) if so, whether the site for the project has since been selected by Government; and

(c) the funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). Indigenously designed smaller warships like Seaward Defence Boats and Landing Craft are already being manufactured in the country. It is now proposed to build indigenously designed Frigates also in continuation of the existing programme of construction of six Leander Class Frigates at Mazagaon Dock Ltd., Bombay. Allocation of funds for indigenous construction of warships for the Navy is decided from time to time, keeping in view the resources available for the Defence needs and the relative priorities of the various requirements of the three Defence Services. It will not be in the public interest to give any further details in this regard?

राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास

1452. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री चतुर्भुज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में झालावाड़ सहित राजस्थान के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों को स्थापना में तेजी लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : झालावाड़ सहित राजस्थान के पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण कराया गया ; सम्भावित उद्योगों का पता लगाया गया ; अवस्थापना सुविधाओं का विकास ; आर० एफ० सी० द्वारा रियायती दर पर वित्त प्रदान करना ; ग्रामीण उद्योग परियोजना वाले जिलों के लिए कम ब्याज की दर लगाना ; और संसाधनों पर आधारित उद्योगों की विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तथा निवेशपूर्व टिप्पण तैयार करना ।

इन उपायों के फलस्वरूप 1976-77 की अवधि में 1539 एकक स्थापित किए गए तथा 8564 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ।

Performance of Public Sector Industries in Ministry of Industry

1453. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the performance both by value and volume of turnover of public sector industries falling under his Ministry during 1976-77 and how it compares with the previous year;

(b) the capacity utilization in each unit; and

(c) whether there are production losses if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) Public Sector Undertakings and Government managed companies under the Department of Heavy Industry have achieved a total production of Rs. 828.78 crores for the year 1976-77, showing an increase of 10 per cent over the production of Rs. 751 crores in 1975-76 and 46 per cent higher than the production of Rs. 568 crores in 1974-75. This increase in production was largely through improved utilization of existing capacity and at more or less constant prices. The products manufactured by these Undertakings are tailor made, varying from year to year in

unit size, complexity and in the work content. Hence turnover in terms of volume is not applicable.

(b) In view of what is stated under (a) above i.e. variation in unit size complexity and work content of the products of the Public Sector Undertakings it is extremely difficult to indicate capacity utilisation in absolute terms. However, the performance of the Units in relation to the targets fixed for the year which take into account their constraints and order book position is indicated in the statement (Annexure I), laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-479/77].

(c) During the year 1976-77, the production was Rs. 828.78 crores as against the target of Rs. 852.01 crores, leaving a shortfall of Rs. 23.23 crores. The main reasons which contributed to the shortfall in production were power cut, non-availability, in time, of imported and indigenous components, paucity of funds and inadequate demand.

2. A statement (Annexure II) containing figures of production for 1975-76 and 1976-77 in respect of the Public Sector Undertakings under the Deptt. of Industrial Development is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-479/77]. It will appear from this Annexure that quantum of production achieved during the year was of the value of Rs. 122.80 crores as compared to Rs. 98.45 crores achieved during the year 1975-76. Though, by and large, production in general has been higher compared to last year, in a few cases, turnover was slightly lower. This is due to certain unavoidable circumstances, like power cut, lack of orders, etc.

Orders for Bharat Heavy Electricals Ltd.

1454. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the order book position of Bharat Heavy Electricals Ltd. as on 1st April, 1977;

(b) the value of the orders on hand and the approximate time in which they will be completed; and

(c) the steps taken to secure more orders in order to keep this undertaking busy at the present capacity utilisation after completion of the above orders

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) and (b). The total value of orders with BHEL, as a whole as on 1-4-1977 was worth Rs. 1178 crores. At the current rate of production, it would take little over two years to complete most of the orders but even at present there is paucity of orders for some of the products such as 110 & 120 MW Thermal Generating Sets.

(c) To overcome this situation all out efforts are being made to secure more orders for BHEL. As a result thereof, orders for 2820 MW for thermal sets were placed on BHEL in 1976-77. Allocation of more resources for power generation schemes are being pressed for so that the country does not suffer from power shortages and BHEL may get fresh orders. Simultaneously BHEL have also undertaken product rationalization of diversification programme. For instance the BHEL, Ramachandrapuram plant where 110 MW Sets are being produced has now taken up the manufacture of industrial turbines and compressors and certain items of oil drilling rigs. Moreover, Government are extending all assistance to BHEL in its aggressive export drive to secure orders from other countries. BHEL have succeeded in securing, recently, major export orders from New Zealand (ten hydrogenerators), Malaysia (three boilers), Libya (complete power plant comprising of 2X120 thermal turbo sets) and Saudi Arabia (five alternators along with transformers, switchgears etc.)

Orders for H. E. C.

1455. SHRI S. R. DAMANI:
SHRI SHEO SAMPAT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the order book position of Heavy Engineering Corporation as on 1st April, 1977;

(b) the value of the orders on hand and the approximate completion time of the orders; and

(c) the steps taken to secure more orders to keep the unit going after fulfilment of the above orders?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) and (b). As on 1st April 1977 HEC had firm orders of the value of approximately Rs. 210 crores. To fully utilise the manufacturing capacity developed the orders in hand should be a minimum of Rs. 300 crores. The completion schedule for the orders in hand is as follows:

1977-78 Rs. 89.49 crores

1978-79 Rs. 68.05 crores

1979-80 Rs. 36.00 crores

1980-81 Rs. 16.00 crores

(c) In order to procure more orders HEC is diversifying its manufacturing profile to include heavy mining equipment, cement plant equipment and bulk material handling equipment. Concerted efforts are being made to secure export orders. These efforts have borne fruit and recently HEC secured orders of the value of Rs. 30 crores for supply of equipment to third countries through USSR. Steps are also being taken to develop indigenous manufacture of equipment which hitherto has been imported.

Pay Scales of Supervisors of Director General Inspection (Defence Ministry)

1456. SHRI DINESH JOARDER: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether pay scales of Supervisors of Director General Inspection (Defence Ministry) have not been revised in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission so far;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) what steps the Defence Ministry is taking to revise the pay scales of this category?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) There are two grades of Supervisors in the Organisation of Director General of Inspection, viz., Supervisor Grade III (Technical) and Supervisor Grade II (Technical). While the pay scale for the former as recommended by the Third Pay Commission has already been notified, the same for Supervisor Grade II has not yet been revised.

(b) The Third Pay Commission had recommended the merger of both the grades of Supervisors mentioned in (a) above but since this was not accepted by the Supervisors Association, the question of revision of pay scales of Supervisor Grade II (Technical) was heldover.

(c) Government have recently announced revised pay scale for the category known as Supervisor Grade (A) (Technical) in the Ordnance Factories which is equivalent to Supervisor Grade II (Technical) of Director General of Inspection Organisation. The question of extending this pay scale to the latter is under consideration.

Selection of Chulas by Coal India Limited

1457. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Coal India Ltd. has selected to bring in the market certain designs of chulas suited to the pocket of various consumers—rural, semi-urban and the sophisticated; and

(b) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). Yes, Sir. Coal India Limited conducted a national competition for developing the design of domestic chulas with the specific objective to burn lower grade coal and soft coke efficiently and without smoke. Four designs were selected and the prototype of those designs are being developed.

Construction of Super Thermal Power Station

1458. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether the National Thermal Power Corporation is likely to undertake construction of the country's first Super Thermal Power Station this year;

(b) whether the Corporation plans to set up Super Thermal Power projects in different regions also;

(c) if so, total cost involved, and

(d) the States in which these are to be set up?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir. The National Thermal Power Corporation has already started work on the first super thermal power station being set up at Singrauli.

(b) The National Thermal Power Corporation was set up with a view to execute and manage thermal power stations to be set up in the Central Sector including super thermal power stations as and when decided by the Central Government.

(c) and (d). Since the programme for undertaking future super thermal stations has not yet been finalised, it is not possible to definitely indicate the details of location and costs of the future super thermal stations at this stage.

Carbon Project in Tamil Nadu

1459. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Rs. 5.6 crore carbon special project is likely to be set up in Tamil Nadu;

(b) if so, whether this is claimed to be one of the first kind of its projects that will be set up in the country;

(c) if so, the facts thereof; and

(d) date by which it is likely to be set up?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) to (c). A foreign collaboration proposal for manufacture of cathode blocks, electrographitised carbon, telephone carbon and special electrotechnic carbon in a backward district of Tamil Nadu State was approved by Government on the 31st December, 1974. The project envisaged an investment of Rs. 193 lakhs at the time when foreign collaboration was approved, though the project cost may go up by the time it is commissioned. Except telephone carbon and special electrotechnic carbon, all other items are being manufactured in the country.

(d) According to the present indicated progress, the scheme is likely to be implemented during the Sixth Plan period (1980-81).

Administration in Nine States

1460. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether since imposition of the President's rule in the nine States the administration is paralysed and no

work is being done in the offices and the law and order situation has worsened;

(b) if so, the main reasons for the same; and

(c) measures being taken by the Union Government to improve the administration and maintain the law and order situation in these States?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

Border incidents on J&K border

1461. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there was heavy movement of troops on the J&K border due to the recent disturbances in Pakistan;

(b) if so, whether some border incidents also took place;

(c) if so, how many border incidents were there during the months of March and April 1977; and

(d) how they were met by the Indian military?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (d). As far as Government is aware, there has not been any heavy movement of troops on the J&K border recently; nor have border incidents of any major consequence occurred in March and April this year. Our security forces are maintaining constant vigilance on the borders and have orders to take firm action where necessary.

Small Car

1462. SHRI P. K. DEO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) when the licence was given to "Maruti" for manufacture of small car;

(b) what was the time limit by which the car should have been produced; and

(c) the reason for delay?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) The letter of intent granted to M/s. Maruti Ltd., for manufacture of passenger cars was converted into an industrial licence on 25th July, 1974.

(b) Within a period of 2 years, that is by 24th July, 1976.

(c) M/s. Maruti Ltd., reported commencement of production from 7th July, 1975.

पिछड़े हुए उपेक्षित क्षेत्रों के विकास की योजनायें

1463. **श्री रामानन्द तिवारी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्रों के विकास की विशेष योजनाएं बनाने पर जोर दिया है

(ख) क्या बिहार के क्षेत्र को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लिया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) नीतियों और योजनाओं को तैयार करते समय बिहार के क्षेत्रों सहित ऐसे सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

अनिवार्य सेवा निवृत्तियां

1464. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात-स्थिति के दौरान विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार, कितने आई० पी० एस० अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य-वार, कितने आई० ए० एस अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया ; और

(ग) पूरे देश में गृह मंत्रालय के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आपात-स्थिति के दौरान 12 आई० पी० एस० अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के शीर्षक 2 में दिया गया है । इनमें से मध्य प्रदेश संवर्ग का एक अधिकारी बाद में पुनर्नियुक्त किया गया है ।

(ख) आपात-स्थिति के दौरान ग्यारह आई० ए० एस० अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के शीर्षक 3 में दिया गया है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के मेज़ पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

राज्य का नाम	अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त अधिकारियों की संख्या	
	आई० पी० एस०	आई० ए० एस०
आन्ध्र प्रदेश	2	2
गुजरात	—	3
मध्य प्रदेश	3	1
महाराष्ट्र	1	1
उड़ीसा	—	1
पंजाब	3	—
राजस्थान	—	1
तमिल नाडु	3	1
पश्चिम बंगाल	—	1
योग	12	11

Irregularities committed by the D.T.C. Management for the purchase of Accessories for Buses

1465. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the irregularities committed by the DTC Management for the purchase of accessories for buses;

(b) if so, whether Government propose to set up a Commission to examine these irregularities; and

(c) if so, facts thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Certain irregularities alleged to have been committed by the

DTC Management in regard to purchases of accessories for buses and items like paint, printing paper etc. are being looked into by the Stores and Purchase Committee of the DTC Board. So far as the allegations about purchase of tyres and boiler are concerned, enquiries are being conducted by CBI.

Setting up of a new T. V. Station at Ahmedabad in Gujarat

1466. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a regular new T.V. station at Ahmedabad in Gujarat;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which it is proposed to be set up?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

Setting up of Shipyard on the Eastern and Western Coasts of India

1467. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have now reached some concrete decisions regarding the setting up of new additional shipyards on the Eastern and Western coasts of India; and

(b) if so, facts thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Deployment of B.S.F.

1468. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of policemen and officers employed in the Border Security Force and the nature and actual states of their operations during the last 3 years (1974, 1975 and 1976) in the various parts of the country;

(b) whether Government propose to formulate a new policy regarding deployment and use of the B.S.F.;

(c) if so, broad details thereof; and

(d) the total cost to the exchequer for the maintenance of the B.S.F. in the year 1974, 1975 and 1976?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (d). A statement showing the sanctioned strength of the B.S.F. and the expenditure incurred on the Force during 1974, 1975 and 1976 is attached. During these years, BSF mainly remained deployed on border security duties on the international borders. However, occasionally it was made available to the State Governments, at their request, to assist them in the maintenance of law and order.

(b) and (c). The changes brought about by Article 257-A of the Constitution in regard to the deployment of BSF and other para-Military forces would be reviewed alongwith the other provisions of the 42nd amendment to the Constitution in due course.

Statement

Strength as on	Officers	Subordinate officers and other ranks
1-1-1974	1427	82,305
1-1-1975	1425	82,444
1-1-1976	1524	82,636

Years	Expenditure in thousands of Rupees
1974-75 ..	6,11,445
1975-76 ..	6,94,016
1976-77 ..	7,19,393

Starting of new A.I.R. station/commercial section at Surat

1469. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to start the new AIR full station or the commercial section or both at Surat in Gujarat during the year 1977; and

(b) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. Surat District in Gujarat is already covered by the high power medium wave transmitter at Ahmedabad.

(b) Does not arise.

Expenditure on security of Prime Minister and other Ministers

1470. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the annual expenditure incurred on the security arrangements for the Prime Minister and other Ministers; and

(b) whether there has been cent per cent increase in this expenditure during the last two years and if so, the outlines thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):

(a) The annual expenditure in Delhi on the security of the Prime Minister and other Ministers during the last three years is given in the statement given below:

(b) No, Sir.

Statement

	1974-75	1975-76	1976-77
	Rs.	Rs.	Rs.
Prime Minister	5,01,402·14	5,73,598·00	6,70,252·73
Ministers	23,87,999·80	25,46,244·00	26,9[illegible]

C.B.I. and Judicial Inquiries Against Excesses during Emergency

1471. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of C.B.I. and Judicial Inquiries Government have ordered against the excesses committed during emergency and salient features thereof, State-wise;

(b) whether papers regarding Maruti firm are missing as alleged in newspapers;

(c) if so, the steps Government have taken against such activities in future;

(d) whether Government have taken steps to seal the official papers of the cases in order to have an objective inquiry; and

(e) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) The Central Government has set up the Shah Commission of Inquiry to go into excesses committed during the emergency, the Mathur Commission of Inquiry to go into allegations

against the Maruti Group of firms, the Reddi Commission of Inquiry to enquire into the Nagarwala case and another Commission of Inquiry under Justice Reddi to go into allegations against Shri Bansi Lal. Some CBI inquiries have also been instituted, but it will not be in the public interest to disclose the details at this stage.

(d) Government has no information about papers regarding Maruti Firm missing as alleged in newspapers.

(c) Does not arise.

(d) and (e) The State Governments, Union Territories, Administrations and Union Ministries/Departments have been requested to ensure safe custody of all relevant papers, files and documents.

Shortage of Power in Karnataka

1472. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of power in Karnataka;

(b) whether Government of Karnataka have approached Union Government to seek help in this regard and to get four gas turbines which a West German firm has agreed to supply as a relief measure; and

(c) if so, the reaction of Central Government in this regard?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) There is shortage of power in Karnataka at present.

(b) and (c). The Government of Karnatak had sent a feasibility report for a gas-cum-steam plant comprising of four units of 25 MW gas turbine sets and two units of 20 MW steam turbine sets utilising waste heat from the gas turbine. The Government of Karnataka had indicated that a West German firm had offered to supply these units.

The feasibility report of the Karnataka Government has been techno-economically appraised by the Central Electricity Authority and an *Adhoc* Technical Committee has been set up to examine the most suitable sources from which such turbines can be procured keeping in view the most economical unit size and commercially attractive and competitive prices. The Committee will also keep in view the aspect of transfer of technology to Bharat Heavy Electricals Ltd., in order to enable future indigenous manufacure of such equipment.

The Committee is yet to submit its report.

Scheme for Training Maintenance Staff by R.E.C.

1473. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a scheme for training maintenance staff has been included in the new rural electrification projects approved by the Rural Electrification Corporation;

(b) if so, the names of the States covered for extending power supply to villages; and

(c) the details regarding the establishment of training centres of linemen, State-wise, as well as the amount of loan so far allocated, State-wise?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir. The Corporation has introduced a scheme to provide financial assistance for setting up of Linemen Training Centres in States.

(b) All 22 States are eligible for financial assistance for rural electrification schemes being sanctioned by the Rural Electrification Corporation. The Corporation has so far sanctioned 1,567 rural electrification schemes of the following 21 States:—

1. Andhra Pradesh
2. Assam

3. Bihar
4. Gujarat
5. Haryana
6. Himachal Pradesh
7. Jammu and Kashmir
8. Karnataka
9. Kerala
10. Madhya Pradesh
11. Maharashtra
12. Manipur
13. Meghalaya
14. Nagaland
15. Orissa
16. Punjab
17. Rajasthan
18. Tamil Nadu
19. Tripura
20. Uttar Pradesh
21. West Bengal

All 22 States are eligible for financial assistance from the Corporation for setting up of Linemen Training Centres.

(c) The Corporation has sanctioned the following financial assistance for establishment for training centres for linemen:—

Sl. No.	Training Centre (State)	Grant (Rs. in lakhs)	Loan (Rs. in lakhs)
1.	Barapani (Meghalaya)	5·79	These centres will *
2.	Jorhat (Assam)	5·11	
3.	Ranchi Bihar	1·31	4·671
4.	Ludhiana Punjab		5·69
5.	Amritsar Punjab		5·69
6.	Karnal Haryana		6·539
7.	Thanjavur Tamil Nadu		5·957
8.	Tirunelveli Tamil Nadu		5·957
	TOTAL	12·21	34·504

*serve Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura

The training centre at Barapani (Meghalaya) has already started functioning

Industrial Loss in Karnataka due to Power Cut

1474. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been industrial loss due to the power cut in the State of Karnataka;

(b) if so, the amount of loss during the last two years; and

(c) the steps taken by the Central Government to help the State?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). The Karnataka State has been facing power shortage and power cuts had to be imposed on various industries. It has affected production in certain industries. However, it is difficulty to assess precisely the loss due to power shortage alone beacuse a number of other factors e.g., non-

availability of raw materials, finance and lack of demand etc., also affect industrial production.

(c) The Government of Karnataka had approached the Central Government some time ago for arranging power supplies from Kerala to meet its power demands. Accordingly, the matter was taken up with Tamil Nadu who has agreed to supply part of the power received by it from Kerala to Karnataka with a maximum of 1 MU a day. About 142 MU of power was exported by TNEB to Karnataka from 23rd September 1976 to 17th May, 1977. Relief from Maharashtra to Karnataka has also been arranged. Additional generating capacity of 965 MW is expected to be commissioned within the next 3-4 years.

Electrification of Villages in Assam

1475. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the number and names of villages in Assam which were electrified in 1975-76 under the Rural Electrification scheme; and

(b) the number of villages proposed to be electrified in 1977?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) 190 villages in Assam were electrified during 1975-76. The information regarding the names of the villages electrified is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The State electricity Board has a programme of electrification of 700 villages in Assam during 1977-78.

Construction of Bridges from Porbandar to Rajkot

1477. SHRI DHARMASINH BHAI PATEL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of bridges being constructed on the National Highway from Porbandar to Rajkot;

(b) whether all this work is likely to be completed before the onset of monsoon and if so, when; and

(c) the amount of grant provided so far to Gujarat for the portion of the National Highway in the Gujarat State and the amount still to be provided

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Fifteen minor bridges are under construction.

(b) Yes.

(c) A sum of Rs. 7,74,000/- was allotted to Gujarat Govt. for all bridge works, and another sum of Rs. 43,89,005/- for the Road Works for the year 1976-77 for development works. As regards the allotment of funds for the year 1977-78, the State Government have been informed that funds to the extent of Rs. 100 lakhs are available for expenditure on National Highway system for the State as a whole during the period from April to July '77. As for further funds to be allotted to the State Government for the period August 1977 to March 1978, the same shall be intimated after the Budget has been voted by the Parliament.

National Metallurgical Laboratory

1478. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether National Metallurgical Laboratory has saved the country crores of rupees by import substitution through its development programme; and

(b) if so, facts thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Floating of Lotteries

1479. SHRI DHARMA VIR VASISTHA:
SHRI OM PRAKASH TYAGI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the policy of Government regarding floating of lotteries as a source of government finance raising; and

(b) whether some State or States have abolished floating of lotteries?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) States and Union Territories have been floating lotteries with the permission of the Central Government to raise finances for development and welfare projects like hospitals, dispensaries, etc.

(b) Information has been received from 12 States and 8 Union Territories. The position is as under:—

(i) Haryana, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Delhi have floated lotteries which are continuing.

(ii) Gujarat, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Mizoram, Pondicherry have not floated any lottery.

(iii) The following States have suspended their lotteries:—

(1) *Andhra Pradesh*.—Started in August 1974 but discontinued after seventh draw on 13-7-1975.

(2) *Bihar*.—Floated in 1970 and suspended in April, 1976.

(3) *Himachal Pradesh*.—Floated in October 1971 and suspended in June, 1976.

(4) *Jammu and Kashmir*.—Floated in 1969 and suspended in 1971.

(5) *Tamil Nadu*.—Floated in August 1968 and suspended in September, 1975. Again started from August 1976 but kept in abeyance from June, 1977.

Separation of Indian Photo Interpretation Institute from the Survey of India

1480. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government propose to separate Indian Photo Interpretation Institute from the Survey of India and merge it with the National Remote Sensing Agency;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether such a merger with a registered society will be desirable from the point of view of the country's security; and

(d) whether Government consider the advisability of obtaining independent opinion on such merger or transfer apart from that of the sponsors of the proposal, before giving effect to it?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Indian Photo Interpretation Institute was merged with the National Remote Sensing Agency with effect from the 1st July, 1976.

(b) The National Remote Sensing Agency is the primary organisation in the country to carry out surveys of natural resources and to conduct crop disease surveillance using remote sensing techniques. Interpretation of aerial photographs is closely related to and forms part of remote sensing. In order that there is close inter-action and coordination of their activities and in order to reduce expenditure, it was considered desirable to merge the Indian Photo Interpretation Institue, which imparts training and provides consultancy in aerial photo interpretation techniques, with the National Remote Sensing Agency.

(c) The National Remote Sensing Agency is administered and controlled by a Governing Body which has senior level representatives from the Departments of Science and Technology and Space; Ministries of Defence and Finance and Air Headquarters, besides three scientists with experience related to remote sensing technology and its use. The Chairman of the Governing Body is the Cabinet Minister incharge of Science and Technology. The Agency handles classified information and all the necessary security precautions in the storage, handling and dissemination of such information are taken.

(d) Does not arise.

Examination for Promotion to Class II Service from Class III Employees in the Military Lands and Cantonments Service

1481. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether in the Military Lands and Cantonments Service class III employees are debarred from taking the examination for promotion to class II service, after crossing the age of 45; and

(b) if so, whether Government propose to consider the desirability of making certain percentage of promotions on the basis of seniority from this age group as is the practice in the other departments?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बहराइच में कागज-मिल और प्लाइवुड फैक्टरी

1482. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहराइच, उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है परन्तु वहां घास और लकड़ी प्रचुर मात्रा में होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर कागज मिल और प्लाईवुडार फैक्टरी स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में काम कब प्रारम्भ करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, जिसमें बहराइच नामक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला स्थित है घास समेत तनों से मिलने वाले कच्चे माल उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) इस समय सरकार का बहराइच जिले में कागज मिल या प्लाईबुड का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

1483. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सचिवालय अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद तथ पद एवं मर्यादा के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन आरोपों की जांच की है और यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सामान्य कार्यविधि के अनुसार, इस मामले को तथ्यों का पता लगाए जाने के लिए बिहार के राज्यपाल को भेज दिया गया है ।

Atrocities on Harijans

1484. SHRI P. K. DEO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the number of incidents of atrocities on Harijans all over the country was on the increase and even during the Emergency, Harijans were murdered in many States;

(b) if so, the number of cases of atrocities on Harijans detected during the last three years, year-wise; and

(c) the constructive steps Government propose to curb the cases of atrocities on Harijans and the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). According to information received from the State Governments and Union Territory Administrations, the number of cases of alleged atrocities (including murders) on Harijans reported during 1974, 1975 and 1976 was 8,860, 7,781 and 5,887 respectively.

(c) It has been impressed upon State Governments that all cases involving any form of violence against harijans should be investigated promptly and efficiently and that persons suspected to have committed any such offence should be brought to book according to law.

It has also been impressed upon the State Governments that when such incidents come to their notice, effective and adequate measures should be taken to instil a sense of security amongst the affected persons and strengthen preventive arrangements.

12.08 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PAPERS UNDER MAJOR PORT TRUST ACT, 1963 NOTIFICATIONS UNDER MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 SEAMEN'S P. F. (AMDT.) SCHEME, 1976, ETC. ETC.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I beg to (A) to relay* on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trust Act, 1963:—

(i) Annual Accounts of the Cochin Port Trust for the year 1973-74 and the Audit Report thereon.

(ii) Annual Accounts of the Cochin Port Trust for the year 1974-75 and the Audit Report thereon.

(iii) Annual Accounts of the Cochin Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon.

(iv) Annual Accounts of the Paradip Port Trust for the year 1974-75 and the Audit Report thereon.

(v) Annual Accounts of the Paradip Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-425/77].

(vi) Annual Accounts of the Calcutta Port Trust for the year 1974-75 and the Audit Report thereon.

(vii) Annual Accounts of the Calcutta Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-426/77].

---

*The papers were previously laid on the Table on 6-4-1977.

(viii) Annual Accounts of the Bombay Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-427/77].

(ix) Annual Accounts of the Madras Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-428/77].

(x) Annual Accounts of the Kandla Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-429/77].

(xi) Annual Accounts of the Visakhapatnam Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-430/77].

(xii) Annual Accounts of the Mormugao Port Trust for the year 1975-76 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-431/77].

**(2) A copy of the Shipping Development Fund Committee (Employees' Contributory Provident Fund) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 93 in Gazette of India dated the 15th January, 1977, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [*Placed in Library. See* No. LT-432/77].

**(3) A copy of the Seamen's Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1284 in Gazette of India dated the 4th September, 1976, under section 24 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-433/77].

(B) to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:—

(i) The Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1976 published in Notification No. G.S.R. 1602 in Gazette of India dated the 13th November, 1976.

(ii) The Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Amendment Rules, 1976 published in Notification No. G.S.R. 30 in Gazette of India dated the 1st January, 1977.

(iii) The Merchant Shipping (Registration of Sailing Vessels) Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 389 in Gazette of India dated the 19th March, 1977.

(iv) The Shipping Developments Fund Committee (General) (Second Amendment) Rules, 1976 published in Notification No. G.S.R. 388 in Gazette of India dated the 19th March, 1977.

(v) The Shipping Development Fund Committee (General) Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 389 in Gazette of India dated the 19th March, 1977.

(vi) The Shipping Development Fund Committee (General) Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 562 in Gazette of India dated the 30th April, 1977. [*Placed in Library. See* No. LT-434/77].

(2) A copy of the Motor Vehicles (National Permits) Amendment Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No.

---

section (4) of section 133 of the 619A of the Companies Act, 1956:—

G.S.R. 29 in Gazette of India dated the 1st January, 1977, under sub-section (4) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [*Placed in Library. See* No. LT-435/77].

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) (a) Review by the Government on the working of the Shipping Corporation of India Limited, Bombay for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Bombay, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-436/77].

(ii) (a) Review by the Government on the working of the Cochin Shipyard Limited, Cochin, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Cochin, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-437/77].

(iii)(a) Review by the Government on the working of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-438/77].

(iv)(a) Review by the Government on the working of the Electronics Trade and Technology Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Electronics Trade and Technology Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-439/77].

(v) (a) Review by the Government on the working of the National Research Development Corporation of India, New Delhi for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the National Research Development Corporation of India, New Delhi, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-440/77].

(vi) (a) Review by the Government on the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (3) (vi) above. [*Placed in Library. See* No. LT-441/77].

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) for the year 1975-76 on the working of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-442/77].

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Remote Sensing Agency, Secunderabad, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts. [*Placed in Library. See* No. LT-443/77].

(ii) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Remote Sensing Agency, Secunderabad, for the year 1975-76 along with Audited Accounts. [*Placed in Library. See* No. LT-443/77].

(iii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Reports. [*Placed in Library. See* No. LT-443/77].

(7) A copy of Notification No. S.O. 1980 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 11th June, 1977 declaring the highway starting from its junction at Batote on National Highway No. 1-A and connecting Doda with Kishtwar to be a national highway, under section 10 of the National Highways Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-444/77].

U.P.S.C. (MEMBERS) AMDT. REGULATIONS, 1976, NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951, TAMIL NADU OFFICIAL LANGUAGE (AMDT.) ACT, 1976 ETC. ETC.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1331 in Gazette of India dated the 18th September, 1976 issued under article 318 (a) of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT-445/77].

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) uner sub-section (2) of section (3) of the All India Services Act, 1951:—

(i) The Indian Police Service (Recruitment) Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 550 in Gazette of India dated the 30th April, 1977.

(ii) The Indian Police Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1977 published in Notification No. G.S.R. 551 in Gazette of India dated the 30th April, 1977.

(iii) The Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) (Amendment) Regulations, 1977 published in Notification No. GSR 261(E) in Gazette of India dated the 3rd June, 1977.

(iv) The Indian Police Service (Appointment by Promotion) Second (Amendment) Regulations, 1977 published in Notification No. GSR 262(E) in Gazette of India dated the 3rd June, 1977.

(v) The Indian Forest Service (Appointment by Promotion) (Amendment) Regulations, 1977 published in Notification No. GSR 263(E) in Gazette of India dated the 3rd June, 1977.

[*Placed in Library. See* No. LT-446/77.]

(3) A copy of the Tamil Nadu Official Language (Amendment) Act, 1976 (President's Act No. 41 of 1976) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 12th November, 1976, under sub-section (3) of section 3 of the Tamil Nadu State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1976.

(4) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the document mentioned at (3) above. [*Placed in Library. See* No. LT-447/77].

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under clause (5) of article 320 of the Constitution:—

(i) The Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 1976 published in Notifi-

fication No. GSR 1063 in Gazette of India, dated the 24th July, 1976 [*Placed in Library. See* No. LT-448/77].

(ii) The Union Public Service Commission (Extension from Consultation) Amendment Regulations, 1977 published in Notification No. GSR 610 in Gazette of India, dated the 14th May, 1977.

(6) An explanatory memorandum in respect of the Notifications mentioned at item (5) above. [*Placed in Library. See* No. LT-449/77.]

ANNUAL REPORTS OF INDIAN MOTION PICTURES EXPORT CORPORATION LTD., BOMBAY AND NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LTD., NEW DELHI WITH STATEMENTS FOR DELAY.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Motion Pictures Export Corporation Limited, Bombay, for the year 1975-76 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comtproller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-450/77.]

(ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, New Delhi, for the period from 1st May, 1975 to 31st March, 1976 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Twe statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Reports mentioned at item (1) above. [*Placed in Library. See* No. LT-451/77].

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944 AND CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE (13TH AMDT.) RULES, 1977.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of Notification No. GSR 733 (Hindi and English versions) published in Gazette of India, dated the 11th June, 1977 making certain amendment to Notification No. 128/CE dated the 6th June, 1970 issued under the Central Excise Rules, 1944. [*Placed in Library. See* No. LT-452/77].

(2) A copy each of the following Notifications Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) GSR 238(E) published in Gazette of India, dated the 12th May, 1977 together with an explanatory memorandum.

(ii) GSR 268(E) and 269(E) published in Gazette of India dated the 6th June, 1977 together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R. 270(E) published in Gazette of India dated the 6th June, 1977 together with an explanatory memorandum.

[*Placed in Library. See* No. LT-453/77.]

(3) A copy of the Central Excise (Thirteenth Amendment) Rules, 1977 publishe in Notification No. G.S.R. 273(E) in Gazette of India, dated the 9th June, 1977 under sub-section (2) of section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [*Placed in Library. See* No. LT-454/77.]

BIHAR ELECTRICITY SUPPLY UNDERTAKINGS (ACQUISITION) 2ND ORDINANCE, 1977, ANNUAL REPORT OF D. V. C. 1975-76 WITH STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Bihar Electricity Supply Undertakings (Acquisition) Second Ordinance, 1977 (Hindi and English versions) promulgated by the Governor of Bihar on the 29th April, 1977, under article 213(2)(a) of the Constitution read with clause (c) (iv) of the Proclamation, dated the 30th April, 1977 issued by the Vice-President acting as President in relation to the State of Bihar. [*Placed in Library. See* No. LT-455/77].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation along with the Audit Report on the accounts thereof for the year 1975-76, under sub-section (5) of section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

(3) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Report mentioned at item (2) above. [*Placed in Library. See* No. LT-456/77].

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS OF MINISTRY OF EXETRNAL AFFAIRS FOR 1977-78

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1977–78 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसंस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[*Placed in Library. See* No. LT-457/77].

REVIEWS AND ANNUAL REPORTS OF NATIONAL NEWSPRINT AND PAPER MILLS LTD., NEPANAGAR, HINDUSTAN PAPER CORPO. LTD., NEW DELHI, ETC., ETC. AND NOTIFICATIONS UNDER INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1951

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i)(a) Review by the Government on the working of the National Newsprint and Paper Mills Limited, Nepanagar, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the National Newsprint and Paper Mills Limited, Nepanagar, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT-458/77].

(ii)(a) Review by the Government on the working of the Hindustan Paper Corporation Limited, New Delhi, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Hindustan Paper Corporation Limited, New Delhi, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT-459/77].

(iii)(a) Review by the Government on the working of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootaca-

mund, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-460/77].

(iv)(a) Review by the Government on the working of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, for the year 1973-74.

(b) Annual Report of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT-461/77].

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:—

(i) S.O. 242(E) published in Gazette of India dated the 18th March, 1977 regarding the continuance of control over the management of Messrs. Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta.

(ii) S.O. 311(E) published in Gazette of India dated the 2nd May, 1977 regarding the continuance of control over the management of Messrs. Smith, Stanistreet and Company Limited, Calcutta.

[*Placed in Library. See* No. LT-462/77].

Proclamations revoking Presidents' Rule in Haryana and Rajasthan

SHRI CHARAN SNGH: I beg to lay on the Table a copy each of the following Proclamations (Hindi and English versions) under article 356(3) of the Constitution:—

(1) Proclamation dated the 21st June, 1977 issued by the Vice-President acting as President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 30th April, 1977 in relation to the State of Haryana, published in Notification No. G.S.R. 389(E) in Gazette of India dated the 21st June, 1977.

(2) Proclamation dated the 22nd June, 1977 issued by the Vice-President acting as President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 30th April, 1977 in relation to the State of Rajasthan, published in Notification No. G.S.R. 390(E) in Gazette of India dated the 22nd June, 1977.

[*Placed in Library. See* No. LT-469/77].

12.13 hrs.

Petition re. Release of Political Prisoners

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): I beg to present a petition signed by Shri Pijush Dey and others of West Bengal regarding release of political prisoners. (*Interruptions*)

Sir, these people do not know. Hundreds of them are awaiting release order.

MR. SPEAKER: Yes, all right.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Shipping Board

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2)(a) of Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may

direct, four members from among themselves, to be members of the National Shipping Board."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2)(a) of Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves, to be members of the National Shipping Board."

The motion was adopted

(ii) COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGES

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from among themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from among themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

The motion was adopted.

(iii) COIR BOARD

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): I beg to move:

"That in pursuance of sub-rule (1)(e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-rule (1)(e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

The motion was adopted.

12.15 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SECOND REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move:

"That this House do agree with the Second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 21st June, 1977."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 21st June, 1977."

The motion was adopted.

12.16 hrs.

CARDAMOM (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Cardamom Act, 1965.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Cardamom Act, 1965."

The motion was adopted.

SHRI MOHAN DHARIA: I introduce the Bill.

12.17 hrs.

YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER MANAGEMENT) BILL*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो योग सोसाइटियों के उपक्रमों का लोकहित में और उनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध-ग्रहण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the undertakings of the two Yoga Societies for a limited period in the public interest and in order to secure the proper management thereof and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजनारायण : मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करता हूं ।

17.18 hrs.

STATEMENT *RE.* YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : श्रीमन्, दिल्ली में 1958 से विश्वायतन योगाश्रम नामक एक पंजीकृत संस्था खोली गई थी । इस सोसाइटी के उद्देश्यों में अन्य बातों के..... व्यवधान).....देखिए, जरा हल्ला न कीजिए । इसकी दोनों प्रथाएं हैं । टेबल पर भी भी रखा जा सकता है और अगर कुछ कहना चाहें तो कहा भी जा सकता है । अगर विरोधी दल के लोग विरोध करना चाहें तो वे विरोध भी कर सकते हैं कि इसकी अनुमति नहीं देंगे । इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह क्या प्रथा है ? पार्लियामेंटरी पद्धति हमें सिखाने की कृपा न करें ।

मैं योग उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

RE. CALLING ATTENTION

SHRI VASANT SATHE (Akola): What about the calling attention?

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 22-6-77.

]Introduced with the recommendation of the Vice-President acting as President.

MR. SPEAKER: The Minister wants it to be taken up at 2 o'clock. He is not yet ready.

SHRI VASANT SATHE: The practice has been to give us the statement in advance so that we may be ready to participate better.

MR. SPEAKER: Mr. Shanti Bhushan, have you any information to give now?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I am making a statement at 2 o'clock.

MR. SPEAKER: You are not circulating it?

SHRI VASANT SATHE: We must go by the practice of the House, namely, a copy of the statement is given, at least half an hour earlier, to the member who has given the notice so that he may be ready to participate in the discussion.

MR. SPEAKER: Because it is not ready, they are asking for time. They are getting the information or something is happening, in between. Therefore, they have asked for time. If it is not ready, how can they circulate it?

SHRI VASANT SATHE: I do not mind its being taken up at 2 o'clock. But by 1.30 let me have a copy of the statement.

12.20 hrs.

GENERAL BUDGET 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER: Shri Satyanarayan Rao was speaking yesterday. He may continue.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : अध्यक्ष जी, कल एक मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा था, बजट के मुताल्लिक कहा था। जनता पार्टी के पावर में आने के बाद यह पहला बजट है—जनता यह उम्मीद कर रही थी कि यह बहुत डाइनेमिक बजट होगा, बहुत अच्छा बजट होगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा—लेकिन दुख है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता पर्टी में जितनी भी पार्टियां मिली हुई हैं, जैसे समुद्र में बहुत सी नदियां आकर मिल जाती हैं, उसी तरह से वे पार्टियां इसमें आकर मिल गई हैं। इस समुद्र में मिलने से पहले उनकी जितनी आइडयोलाजीज थीं, जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र भी थे, दूसरे लोग थे, वे सब अपनी-अपनी आइडयोलोजीज को भूल गईं। कम से कम हम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि सोशलिस्ट पार्टी वहां मिलने के बाद इस तरह का कैपिटिलिस्टिक बजट पेश करेगी। यह बहुत ताज्जुब की बात है। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पार्टी को, पूरे हिन्दुस्तान की गरीब जनता को इससे बहुत निराश हुई है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कल पटनायक साहब ने यहां भी भाषण दिया था और राज्य सभा में भी भाषण दिया था। यहां भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—चूंकि पटेल साहब कुछ नहीं बोल सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है, कूव्वत नहीं है कि सुब्रह्मण्यम साहब का जवाब दे सकें, इसलिये मुझे इस डिबेट में इटरवीन करना पड़ा है। उन का पूरा भाष ण बजट के ऊपर नहीं था, सिर्फ सुब्रह्मण्यम साहब के खिलाफ अटेक था। हर मेन्टेस में वह सुब्रह्मण्यम-सुब्रह्मण्यम कहते रहे और खत्म भी उन्होंने सुब्रह्मण्यम साहब के नाम से किया। वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं, अगर होते तो ज्यादा अच्छा था।

[अध्यक्ष जी, जनता पार्टी में जाने से पहले जो लोग कांग्रेस पार्टी में थे—जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी, जो 23 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, इसी में पैदा हुए, इसमें फले फूले, मुख्य मंत्री रहे, सेन्टर में बड़े-बड़े पोर्टफोलियोज उन्होंने होल्ड किये, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

रहे, आज वह कहते हैं कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, खराब किया, हिन्दुस्तान को तबाह कर दिया । न सिर्फ श्री मोरार जी देसाई, बल्कि उनके दूसरे साथी—चन्द्र शेखर जी, मोहन धारिया जी, जगजीवन राम, बहुगुणा जी, पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर रविन्द्र वर्मा जी, रामचन्द्रन जी, सब के सब अपनी पिछली बातों को भूल गये—यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । पिछले दो सालों में हम से कुछ गलती हो गई है—उस को तो मैं मान सकता हूं, लेकिन यह कह देना कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, देश को बरबाद कर दिया—यह बात ठीक नहीं है । जनता पार्टी तो अभी पैदा हुई है—उसके लिये कहना कि जनता पार्टी ऐसा करेगी, वैसा करेगी, पूरे हिन्दुस्तान को ले जाकर आकाश में पहुंचायेगी—ऐसी बात न कीजिये । पहले भी जब मैं यहां था, जब मेरे कई साथी इस तरह की बात बोलते थे तो मैं उनको भी ऐसा कहता था कि ऐसा मत बोलिये, कभी हमको इस तरफ भी आना पड़ सकता है, जिम्मेदारी की बात कीजिये । मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप गैर जिम्मेदारी की बात न बोलिये, जिम्मेदारी की बात कीजिये । आज लोगों को आप से बहुत उम्मीदें हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं—आज जनता पार्टी जो पावर में आई है वह आप लोगों की कुरबानियों की वजह से नहीं आई है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से आई है ।

In politics there is no *mat dan*: there is only suicide. यह मैं मानता हूं कि हमने डेफनीटली गलती की है और गलती करके खुदकशी की है और इसीलिए आज हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब इस लोक सभा का पहला सेशन शुरू हुआ था, तो हमारे लीडर श्री वाई० बी० चव्हाण ने कहा था कि हमारा कंस्ट्रक्टिव कोआपरेशन रहेगा और हम रेस्पोंसीबिल अपोजीशन की तरह से काम करेंगे । हम लोग इधर बैठ कर कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगे जैसे पहले कुछ उधर बैठने वाले लोग करते थे । बड़ी गैर-जिम्मेदारी की बातें वे करते थे । श्री राज नारायण भी ऐसी ही बातें करते थे और आज जबकि वे मंत्री हो गये हैं, फिर भी ऐसे ही बोलते हैं जैसेकि अपोजीशन लीडर की तरह हों । मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा जिम्मेदारी से बात करें और कुछ काम करिये । हम आपको कोआपरेशन देने के लिये तैयार हैं । ये जो आए दिन आप फिजूल की बातें करते हैं, वे न करिये । रोजाना कमीशन बैठाने की बातें होती हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक चलता रहेगा । इसके पहले के सेशन में और इस सेशन में भी हम रोजाना देखते हैं कि कुछ न कुछ आता ही रहता है, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ और कभी संजय गांधी के खिलाफ । क्या इनके सिवा आपके पास कुछ करने को नहीं है ।

श्री **मधु लिमये** (बांका) : सैकड़ों लोगों को मरवा दिया ।

श्री **एम० सत्यनारायण राव** : इसीलिए तो हम लोग आज इधर बैठे हुए है । वरना कोई वजह न थी कि हम उधर न बैठते ।

श्री **शिवनारायण** (बस्ती) : जरा अपने स्पीकर साहब को देख लीजिये ।

श्री **एम० सत्यनारायण राव** : आप बैठ जाइए । फालतू बातें मत करो । इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि आप जरा जिम्मेदार बनें । अगर आप गैर-जिम्मेदारी से बोलेंगे तो हम भी कुछ कम नहीं हैं । हम यहां पर 153 हैं । इससे पहले 10 लोग अपोजीशन में रह कर न्यूसेंस क्रिएट किया करते थे । हम तो 153 सदस्य है । हम चाहें तो हम भी वैसा ही कर सकते है । इसलिए मेहरबानी करके आप बैठ जाइए और बीच में दखल मत दीजिए । मैं यही बोलना चाह रहा था कि ऐसी चीजें

नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के वास्ते आप को कुछ करना चाहिए। इसके लिए हम कोआपरेशन देने के लिए हमेशा तैयार हैं।

दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कांग्रेस की जो एकोनामिक पालिसी है, उसमें कोई गलती नहीं रही है। पोलीटीकली हमने जरूर कुछ गलतियां की हैं। अब वे चाहे एक आदमी ने की हों या दो आदमियों ने की हों, मैं मानता हूं कि हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं और एक आदमी के लिए ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एकोनामिक पालिसी अपनाई वह खराब है, या लोगों ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। इस गलतफहमी में आप मत रहिये। कांग्रेस की जो एकोनामिक पालिसी है, वह बहुत साउण्ड है और बहुत हैल्थी एकोनामी कांग्रेस ने आप के हाथ में दी है और ऐसी बात नहीं जैसा कि कल श्री पटनायक साहब कह रहे थे। सुब्रह्मण्यम साहब ने परसों अपना भाषण करते हुए कहा था कि यह आपकी खुशकिस्मती है कि दो साल पहले जो एकोनामी इतनी खराब हो गई थी, उसको इतना अच्छा करके, इतनी साउण्ड एकोनामी करके आप को दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस हालत में आपको एकोनामी दी गई है उसको आप बनाए रखेंगे और यह बहुत अच्छा होगा। कल जब श्री पटनायक साहब बोल रहे थे, तो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा था कि क्या साउण्ड एकोनामी दी है और सब सत्यानाश करके हम बैठे हैं। जिन्होंने पटेल साहब की बजट स्पीच को पढ़ा होगा, उन को पता होगा कि उन्होंने खुद माना है कि गुजिश्ता दो सालों में तरक्की हुई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि कल एक जिम्मेदार मिनिस्टर साहब यहां बोल रहे थे और कह रहे थे कि कोई साउण्ड एकोनामी नहीं है, कोई हैल्थी एकोनामी नहीं है :

"In the last two years, while India's exports have increased rapidly, imports during 1976-77 were restrained both on account of the bumper harvest of 1975-76 and increased domestic production of such critical inputs as fertilizers. The rapid increase in inward remittances has given added strength to India's balance of payments and our reserves have gone up considerably. Nevertheless, we would be foolish if we did not take note of the fact that our balance of payment still remains vulnerable to the effects of sudden shocks, such as harvest fluctuations. The current level of food stocks and foreign exchange reserve do give us wider options in the management of the economy than ever before. Foreign exchange reserves will have to be so deployed as to assist in the maintenance of price stability, as also in acceierating the process of growth."

उन्होंने यह माना कि पिछले दो साल के अन्दर क्या हुआ और जो पैसा है उसको वे यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो स्टेटमेंट है कि देश की एकोनामी खराब हुई है वह ठीक नहीं है। आपके हाथ में कांग्रेस सरकार ने 18 मीलियन टन फूड ग्रेन छोड़ा है। यह मामूली बात नहीं है। आप यह मत भूलिये कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप तीन साल भी यहां टिकने वाले नहीं हैं। हम यह जानते हैं कि एक साल के अन्दर क्या कुछ हो सकता है।

मगर कल मैं एक बात कह रहा था जिसको फिर दोहराना चाहता हूं। मैं अपने पटेल साहब से नाराज नहीं हूं। वे बहुत ईमानदार आदमी हैं और उनकी जो पालिसी आज तक रही, उसी पर वे अभी भी डटे हैं। मैं जानता हूं कि वे स्वतंत्रता पार्टी में रहे हैं और उस

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

पार्टी के जो ख्यालात सोशलिज्म के बारे में थे, वे उसी पर डटे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको दोष नहीं देना चाहता । लेकिन हमारे जो दोस्त आज तक सोशलिज्म की बात करते रहे हैं, उनको चुप देख कर मैं हैरान होता हूं। हमारे सोशलिट दोस्त गरीबों की इस हाउस में बड़ी वकालत करते थे । वे कहा करते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं कर रही है। लेकिन आज इस बजट में लेण्ड रिफार्म्स और लेबर वेजिज के बारे में कुछ न देख कर ताज्जुब करता हूं। क्या हुआ उन सब का जिनके बारे में हमारे जनेश्वर मिश्र और मधु लिमये बहुत कुछ कहा करते थे । आपने इस बजट मे क्या किया ? सिवाय इसके कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कंसेशन दे दिये हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और लेण्ड रिफार्म्स के वास्ते इस बजट में कोई प्रावि-जन नहीं किया गया। मेरे दोस्त जो सोशलिस्ट्स थे, वे आज जनता पार्टी में बैठे है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज वे चुप क्यों है ? मै समझता हूं कि इस तरह का बजट पेश करना न तो जनता पार्टी के वास्ते अच्छा है, न हिन्दुस्तान के वास्ते अच्छा है। आप लोग रूलिंग पार्टी में हैं, अब आप लोग गरीबों को उठाने की कोशिश कीजिए । अगर आपने देश मे गरीबों को नहीं उठाया तो यह मत भूलो कि आप यहां बैठे रहेंगे। देश में इंक्लाब आ जाएगा, हम तो तीस साल यहां बैठे रहे, आप तीन साल भी हकुमत नहीं कर सकोगे । जब हम गरीबी हटाओ की बात करते थे तो आप लोग हंसते थे । अब आप क्या गरीबी हटाओ का यह प्रोग्राम दे रहे हैं ? मैं तो यह समझता हूं कि आप इस बजट मे गरीबी नहीं हटा रहे हैं बल्कि गरीबों को हटाने का प्रोग्राम दे रहे हैं । मुझे इस बजट के बारे में अपने सोशलिस्ट दोस्तों को खामोश देख कर हैरानी होती है । आज जनेश्वर मिश्र खामोश बठे हैं, हमारे दूसरे दोस्त खामोश बैठे हुए हैं ।

मैं यहां जार्ज बर्नार्ड शाह की एक बात रिमाइण्ड कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"If a person who is below 30 years of age does not believe in socialism, he has no heart, hut after forty years, if he still believes in socialism, he has no mind."

शायद इस बात को मेरे सोशलिस्ट दोस्त भी जानते होंगे । मैं समझता हूं कि वे लोग अब 40 साल से ऊपर के हो गये हैं इसलिए ऐसा मालूम होता है कि वे यह सोशलिज्म की बातें भूल गये हैं ।

बजट देखने के बाद मुझे कुछ नहीं मालूम होता कि आप स्मगलर्स के वास्ते क्या करने जा रहे हैं ।

मैं चाहता हूं कि जितने स्मगलर हैं और ब्लैक मार्किट करने वाले हैं उन को कंट्रोल किया जाए । अभी तक आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की है ।

स्टेटमेंसी आफ एग्रिकलचर के बारे में आप ने बहुत कुछ कहा है । आपने तो ऐसी बात कही जिससे यह ध्वनित होता है कि इससे पहले वाली कांग्रेस सरकार ने एग्रिकलचर के बारे में कुछ किया ही नही था । रोड्ज के बारे में, पोलट्री फार्म्ज, डेरी, वेजीटेबल, सरिकलचर, ड्रिंकिंग वाटर आदि पर जो आपने बहुत ज्यादा जोर दिया है उससे आपने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने इन क्षेत्रों में कुछ नहीं किया था । बीस सूत्री कार्यक्रम को आप देखें । उस में यही बातें थी, एग्रिकलचर से सम्बन्ध रखने वाली बातें थीं जिन पर सब से ज्यादा जोर दिया गया था । यह अलग बात है कि कुछ गलतियां हो गई । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीस सूत्री कार्यक्रम अच्छा नहीं था । आप जितना रूरल डिवेलेपमेंट करने की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम ने किया था। अभी भी जो कांग्रेस सरकारें हैं वे भी कर रही हैं। आपको तो मालूम ही है कि इलैक्शन में किन लोगों ने आपको स्पोर्ट दी है । सब बड़े बड़े जमींदार लोग थे जिन्होंने आपको स्पोर्ट किया है । इसलिए जनता पार्टी आ सकी है। उनको यह भरोसा था कि अगर जनता पार्टी

आ गई तो उनके पास जो जमीनें हैं उनको वे रख सकते हैं । उन पर सीलिंग का कानून आगे लागू नहीं होगा । लैंड रिफार्म्ज की बात आपने निकाल ही दी है, उसका जिक्र तक नहीं किया है । आप लोग उनकी स्पोर्ट ले कर चल रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है । अगर इसी तरह से आप चलते रहे तो मैं कहता हूं कि देश में इनकलाब हो जाएगा और इससे न आपको फायदा होगा और न ही हम को होगा, इससे फायदा मार्क्सिस्ट दोस्तों को होगा, वही लोग इससे बैनिफिट उठा सकेंगे । इस वास्ते मैं अभी से आपको इसके बारे में वार्न कर देना चाहता हूं । लैंड रिफार्म्ज आदि पर आप अभी से ज्यादा ध्यान दें ।

इरिगेशन के बारे में मैं आपको दो चार सजैशंज ही देना चाहता हूं । आप तो जानते ही हैं कि तीस परसेंट लैंड ही अंडर इरिगेशन है, बाकी सत्तर परसेंट में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है । डा० के एल० राव ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था । जहां आपने इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की है उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि गंगा और कावेरी को मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और वहां यह फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है ।

रिवर वाटर डिसप्यूट्स भी अभी तक कुछ पैंडिंग पड़े हुए हैं । कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ को हल कर दिया था । फिर भी अभी कावेरी का डिसप्यूट बाकी है । इसको तथा दूसरों को आप सैटल करने की कोशिश करें ।

मैं अब पावर के बारे में कहना चाहता हूं । रामचन्द्रन साहब बैठे हुए हैं यह खुशी की बात है । आंध्र प्रदेश की सरकार ने आपके पास पावर के बारे में एक रिक्वैस्ट भेजी है ।

Regarding super thermal power station at Ramagudam, plenty of labour is available there and Godavari water is there. The labour is very cheap and everything is available there. The only thing is that because of Congress Government there, You should not discriminate. I think, the hon. Minister will not discriminate. If this super thermal power station is established there, not only the problem of solved. My request to the Minister Andhra but whole of south will be solved. My request to the Minister through you, is that he must see that this super thermal power station at Ramagudam is established.

डिफेंस एक्सपेंडिचर आपने 56 करोड़ कम कर दिया है । ऐसा करके आपने अच्छा नहीं किया । इससे पता चलता है कि श्री जगजीवन राम की कुछ नहीं चल रही है जनता पार्टी में । अगर चलती होती तो कोई कट न किया गया होता । उनका शीर्ष ही इससे कटा हुआ मालूम होता है ।

बजट स्पीच में आपने 21 करोड़ रुपये का कट लगाया जिसका बैक्वर्ड एरियाज में न्यू रेलवे लाइंज का विकास करने में असर पड़ेगा । इससे उनको नुक्सान पहुंचेगा । रेलवे में जो एलोकेशन पहले था उसको आप बहाल करें, इस कमी को आप पूरा करें ।

वाइजग स्टील प्लांट श्री पटनायक उड़ीसा में ले जाना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । इसी तरह से सुपर थर्मल पावर की बात है । अगर ये दोनों वहां न किए गए तो बहुत नाइंसाफी होगी और इसके खिलाफ बड़ा एजीटेशन होगा । अगर इस प्लांट को आप उड़ीसा में ले गए तो यह बड़ी भारी सैलफिशनैस होगी । यह एक नैशनल प्राजैक्ट है । इससे न सिर्फ आंध्र को फायदा होगा बल्कि सारे देश को होगा । यह ऐसी चीज है जिसको आप निगलैक्ट नहीं कर सकते हैं । अगर निगलैक्ट करेंगे तो आपको इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, यह मैं आपको आज वार्निंग देना चाहता हूं ।

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

न्यूकलियर पावर स्टेशन के बारे में भी एक प्रोपोजल आंध्र प्रदेश से आई है। मैं समझता हूं कि आप ने एक्सपर्ट कमेटी भी कांस्टीट्यूट की है। इस सिलसिले में रिपोर्ट क्या हुई है उसको भी आप देखें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ओटोमोबाइल टायर्स का जो प्रोजैक्ट है मंगलगिरि प्रोजेक्ट, इनको भी पूरा कीजिये। ऐग्रीकल्चर के बारे में जो रूरल सैक्टर में आपने कहा है अपनी स्पीच में कि पहली कांग्रेस सरकार ने इस सैक्टर को नैग्लैक्ट किया है, इस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐलोकेशन आपने किया है वह 3,024 करोड़ है जब कि कांग्रेस सरकार ने इस पर 3,447 करोड़ रु० का ऐलोकेशन किया था। मतलब यह हुआ कि आपने 400 करोड़ रुपया इस सैक्टर में कम कर दिया। तो आप जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और खादी पर हम काफी पैसा लगा रहे हैं वह तथ्य से दूर है। वास्तविकता यह है कि आप इस में कटौती कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: Now, before I leave the Chair, I want to say something. The Congres party has exhausted all its time. But from the Speaker's time, I gave some time to Mr. Satyanarayan Rao. The CPI has not taken any time. The A.I.A.D.M.K. has also not spoken at all. The Janata Party has got 1 hour and 44 minutes. Some Members from their side also will be called. If they take 5 minutes each, a large number of Members can be accommodated. I am trying to explain the position for the guidance of the next Chairman.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam) Sir, on the first day, it so happened that one Member from the Government side and one from the Congress side were called. Yesterday, for one on our side two or three were called from the other side. They were not ready with their speakers on the first day. So, we were asked to speak. Many of us have now been prevented from speaking. In your discretion, You may give some more time to us.

MR. SPEAKER: It is not a question of the number of speakers but it is the time that is allowed. From the Congress side, the senior Members, the ex-Ministers and the ex-Chief Ministers have taken 30 to 40 minutes each. From the ruling party-side, they are making maiden speeches of 5 to 7 minutes each. The Speaker has got some spare time which can be given. But don't demand it. Nobody from the C.P.I. and the A.I ADMK has spoken.

Now, I call Mr. Govindan Nair from the C.P.I. to speak. After him, the A.I.A.D.M.K. Member will speak. Then, the Janata Party Members will have 5 minutes each so that a large number of Members can speak from their side.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, आप जो समय अलाट करते हैं तो शुरू के स्पीकर अधिक समय ले जाते हैं और पीछे वालों के लिये 5, 5 मिनट का समय रह जाता है।

MR. SPEAKER: That is why I say it will be given now.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): I would like to make a brief submission and request that the time allotted may in line with what used to happen in the House from 1962-72 again be restored—that tradition may be restored. From 1962 to 1972, the time allotted for discussion on general debate used to be 20 hours. It was only after 1972 that it was reduced to 15 hours. Let us reverse that tradition and go back to the earlier tradition.

MR. SPEAKER: This time we have begun discussion on the Budget late because of elections all over the country. A number of demands will be guillotioned. If you want more general discussion, then some time is required. Yesterday, the Business Adisory Committee had discussed all these aspects and they had also accepted this schedule. Now Mr. Govindan Nair.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Mr. Speaker, Sir permit me, at the outset, to congratulate the Janata Party on their glorious victory in the Lok Sabha as well as in the Assembly elections. Now they are comfortably settled on Government both at the Centre and in most of the States. The line is now clear for them to fulfil the promises they had made to the people. I am not blaming the Janata Party if they do not join the socialist creed. But they had assured the people that they would uphold the democratic values, they would reflect the Constitution both in words and spirit and they will follow the democratic norms in their functioning.

So I am judging them by what they had promised and I am sorry to note that inspite of the repeated assurances they have given—from the papers, all of you must have known—defections are being encouraged. A number of Lok Sabha, Rajya Sabha and Assembly Members are now crossing over to the Janata Party.

SHRI C. SUBRAMANIAM (Palam): Tempted to cross over.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: There are defections or an exodus, I do not know. But this goes very much against the assurances that the Prime Minister himself has given. It is a shame to convert our Assembly members into Aya Rams and Gya Rams. It was expected especially when the Prime Minister himself had made a categorical statement that he would never permit anybody to cross-over and join the Janata Party. Only a few days have passed since this statement was made and you can see what is happening now. Not only Lok Sabha and Rajya Sabha Members are crossing over, but the big news is that a number of MLAs are also crossing over to the Janata Party. This is something which is deplorable. The point is what the Prime Minister himself says today just the opposite happens the very next day. Where is the credibility? How are we to function? Therefore, I think steps should be taken to see that this kind of defections do not take place. I am interfering with the liberty of any person to join any political party, but if he wants to do so he should resign his membership of Legislative Assembly or of Parliament and then join another party. I hope the hon. Prime Minister will give attention to the point I have raise.

Secondly, I was very much amused that was taking place in this House between the Congress Party and the Janata Party. Mr. Subramaniam spoke for the Congress Party. Well, he knows that this Budget of the Janata Party was also made of the same mould which he had prepared except that it was disfigured by dropping certain basic features to give it the Janata look. That is all. In the main, we expected a new approach as they were saying that they were going to change the life of the rural people in this country. They said that they would eradicate poverty and unemployment. I am quite sure the Finance Minister did not consult even his colleagues when he prepared the Budget. I say this because they are speaking so much about unemployment, especially among the rural people. And what is the allotment that they have made? They have allotted Rs. 35 crores for khadi and village industries and Rs. 20 crores for handlom. He must be completely ignorant of the condition of the handloom workers or the handloom industry. If he were so, he could have

[Shri M. N. Govindan Nair]

consulted his friend and colleague, Mr. Charan Singh, who is an expert on handloom industry. The Finance Minister has allotted Rs. 20 crores for handloom. Does he know that the accumulated stock with the cooperatives and the weavers organized under them alone will cost more than Rs. 20 crores? They claim that they will give employment to 25 lakh people. Will they be able to maintain the existing weavers to carry on their work and make a living? The solution that the hon. Home Minister has been suggesting will finish off both handloom industry as well as the textile industry. I am not going into that now.

He has allotted Rs. 35 crores for khadi and village industries. Many a time the functioning of the khadi and village industries has been discussed in this House. I do not want to comment on it, but I can only say that, in spite of the tall talk they have made, nothing has been done to tackle the problem of unemployment. Now, they were speaking about allocation for development of agriculture. From the Report before us it is very clear that our main drain of foreign-exchange, even to this day, is in respect of agricultural products, for food—not only cereals but edible oils and pulses etc. All these things are sought to be got from other countries. We claim that our economy is agrarian but even today, after thirty years, we are in a position where we have to depend on other countries for our essential commodities. This state of affairs must change. When an emphasis or an overemphasis was laid on this by the Janata leaders, I thought there would be sufficient provision at least to improve upon what the previous Governments were doing. They have said that agriculture should be modernised. Everybody knows that if you want to increase agricultural production, it should be modernised. That means there should be irrigation facilities there should be fertilisation, new hybrid variety of seeds should be used etc. Now, I ask you, is there any provision other than the normal one for increasing the utilisation of any of these things in the field of agriculture? You are speaking about poultry; you are speaking about dairying and, for all these things that you are speaking of, some money has already been allocated. But to make a radical change, has there been any change in the allocations? There is none. For approach roads, transport infrastructure etc., what is the allocation? Which are the new Railway lines we are going to open? Which are the new roads we are going to construct? I am sorry to say that for none of these vital things has sufficient allocation been made so as to effect a real change in the rural economy of the country.

If you want to change the rural life of the people, one important thing, which I forgot to mention, is land reforms. No mention of this has been made in this budget. Of course, I don't say that the word itself has not been mentioned: the word has been mentioned, but what is the provision in the Budget for taking up land reforms seriously? I come from a State where land reforms were implemented. Have you any idea of the number of landless people in this country? How are you going to solve their problems unless you enforce radical land reforms and distribute land to the cultivators? Speaking from my experience, lakhs of people in my State were destitutes and they have been provided with land. Unless the Janata Party takes up the question of land reforms seriously, they are not serious about the development in the rural sector.

13 hrs.

When you speak about the rural population and when my friends on the other side harp on democracy and democratic values, we have to see what is the state of affairs in the rural side. You and I become very eloquent and our moral indignation knows no bounds when we hear racial discrimination outside our country, but what is happening in your own vil-

lages? Do you treat the backward people in the villages, the Harijans as your equals? Bihar is the home State of Jayaprakash Narayan; this State is otherwise also very important. During the last one and a half years, the number of Harijans killed according to Government reports is 100 and the number of Harijan women raped is 75. The atrocities committed during the last few years have been increasing. In 1972, the number of cases of attrocities against the Harijans was 98, in 1973, it was 105, in 1974, it was 259, in 1975, it went upto 300 and in 1976, it was 1200. For the year 1977, the Government have not published the figures as yet, but we know, what has been happening in Bihar. You have read about how people were burnt to death in Bihar. The explanation given by the Home Minister was that it was a fight between two criminal gangs and they killed each other, but why is it that only Harijans were killed? Is that the only State with this situation? What about Gujarat, what about Andhra Pradesh and what about Tamil Nadu? You speak about democracy. Democracy for whom? For us, for the elite, not for the poor people?

If you want a change in the society, you have to raise the status of these people and protect them from the socially dominating section. I am sorry to say that after the Janata Government have come, the rural rich feel that it is their Government and their aggression on the poor section of the people is on the increase. I am not blaming any particular party for this state of affairs because we had inherited an undemocratic society. Centuries of tradition, sanctity of religion—all these are so deep-rooted that unless the entire people move against these and try to mould a democratic society out of our village people, all talk of democracy has absolutely no meaning. Therefore, if you want to make a change in the rural life of the people, the first thing is that you have to come forward with land reform. Secondly, you have to democratise the village society and thirdly you will have to find employment for them. Some people say that they are following Gandhian economics. Well, in my own way I have tried to understand Gandhiji. Gandhiji was murdered, physically murdered, but don't try to kill him spiritually also by saying that it is the Gandhian economics you are going to follow. When he raised the slogan of village industries, it was the time of the freedom struggle. When against the economic enslavement of the people of the country he had given a call, the spirit of the call was to struggle against the economic enslavement from the British imperialism and also develop a sense of self-reliance. If this spiritual Gandhian politics is forgotten, you are rejecting Gandhiji because I often heard that you are again restoring Gandhian values. How it has been worked out in villages, I have already told you. There also, in today's circumstances, if you want to build up your economy, if you want to solve the problem of unemployment, sticking on to village industries alone will never do. You have to have modern industries also. People here are speaking about Japan, about Sweden and say, 'Let us follow them'. But, have you studied their economy? Japan is one of the most highly industrially developed nations of the world. They are competing and defeating even the highly developed countries of the world and with the ancillary industries in the villages, they are providing jobs. Now, if you forget this and if you want to turn this nation into a hermit nation, you will not be able to survive.

Here also, the emphasis that the earlier governments have given on public undertakings is not there and what it means also one can understand. If you want to leave industries to the private sector, if you want to encourage them, well, that would be at the risk of industrial

[Shri M. N. Govinda Nair]

development. Well, if there is another occasion, I will speak about it.

Now, Sir, much is talked about these small scale industries. The small scale industries, just as in the case of others, are also talked about. But what is he provision in the budget? Now everybody is praising him for reducing the deficit. This reduction has been caused by shifting certain sectors. This is how the reduction was made.

I ask a question—can any small scale industry survive with the present rate of interest which has to be paid to the banks? There is a small percentage of the advance that they make which you can get at a lower rate of interest. Even that percentage has not been raised. According to the existing arrangement if you pay half a per cent of the advance, you get at a lower rate known as differential interest rate. But that is only for half a per cent. It will benefit only a very small percentage. Even that has not been changed.

I do not want to take much of the time. I only say that the assurance and promises that the Janata Party has made to the people of this nation are not at all reflected in this Budget and I am sure, unless a radical change in the entire approach is made, our country will head to an economic crisis.

MR. SPEAKER: We extend our discussion. The hon. Minister will reply to-morrow at about 15.30 hours.

श्री विजयकुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट को जनता पार्टी का बजट कह कर, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने और कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने जो वादे किये थे, जनता पार्टी ने जो उम्मीदें लोगों को दिलायी थीं उनका कोई रिफ्लेक्शन इस बजट में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी समझदार आदमी यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि इस बजट के अन्दर जो वादे जनता पार्टी ने किये, उनका पूरा रिफ्लेक्शन इस बजट के अन्दर हो सकता है। यह बजट सितम्बर, अक्टूबर, 1976 में बनना शुरू हुआ, जनवरी में इसको पूरा कर दिया गया। जनवरी में जो बजट कम्प्लीट कर दिया गया हो, क्या उस बजट में जून में कोई खास चेंजिज की जा सकती हैं? यह बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। क्या प्लान के फोर्थ इयर में, चौथे साल में कोई रेडिकल चेंजिज हो सकती थी। यह एक तरह से मुश्किल सी बात है, नामुमकिन सी बात है। क्या चौथे साल की कैरी ओवर स्कीम्स को बीच में छोड़ा जा सकता है, अधूरा छोड़ा जा सकता है? उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बजट कांग्रेस का बजट है, पिछले साल में तैयार किये गये बजट के मुताबिक इसको बनाया गया है। लेकिन हमारे विन मंत्री जी ने इस बजट में एक दिशा निर्देश दिया है जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

13.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

इन सर्कमस्टांसिज में, इन हालात में जबकि बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, उनमें भी इस बजट में जनता पार्टी का रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गयी है। सब से पहली इम्पार्टेंट बात इसमें यह है कि जो घाटा 632 करोड़ का एक्सपैक्टिड था उसको उन्होंने कम कर दिया है और उसको वह केवल 72 करोड़ पर ले आए हैं। पिछले बारह सालों में 1969–70 को छोड़ कर इससे कम घाटा कभी नहीं दिखाया गया। इतना कम घाटा दिखाने वाला जो बजट उन्होंने हमारे सामने रखा है यह कोई मामूली बात नहीं है। अब

इसकी जो आलोचना करते हैं उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि वे आलोचना करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। एक बात साफ है कि जनता पार्टी कीमतें कम करने के लिए घाटे की अर्थ व्यवस्था को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है और इसी दिशा में उसने अपनी एफर्टस का डायरैक्ट किया है।

सुब्रह्मण्यम साहब तथा दूसरे दोस्तों ने कहा है कि यह कैपिटलिस्ट बजट है, पूंजीवादी बजट है, इस में पूंजीपतियों का पोषण किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवाद कांग्रेस हमारे देश में लाई थी उसको यह जनता सरकार खत्म न करे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवाद का नाम लेने की स्थिति में वे आज भी अपने आपको पाते हैं? क्या ऐसा कहते हुए उनको संकोच नहीं होता है या लज्जा का अनुभव नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीस साल में कांग्रेस के चार प्लांज के बाद भी क्या यह हकीकत नहीं है कि बड़े बड़े पूंजीवादी जो घराने हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बिड़ला, टाटा हैं उनके यहां पर दौलत सौ-सौ गुना अधिक बढ़ गई है? जो लोग पचास करोड़ की मिलकियत के थे 1950 में आज वे 1800 करोड़ की मिल्कियत वाले हो गए हैं। उसके साथ ही दूसरी तरफ चालीस परसेंट लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, सबसिस्टैंस लेवल के नीचे चले गए हैं। रेट आफ ग्रोथ सारे भारत में पिछले बीस साल में तीन परसेंट एवरेज भी नहीं बैठता है जबकि बड़े बड़े मौनोपोली हाउसिस के एवरेज रेट आफ ग्रोथ को आप देखें तो वह 18 परसेंट तक चला गया है। यह कांग्रेस के समाजवाद का बमूना है जिस ने केवल पूंजीवाद पैदा किया चाहे वह सरकारी पूंजीवाद हो या निजी पूंजीवाद हो। इसके बावजूद भी वे कहें कि वे समाजवाद लाना चाहते थे तो सिवाय आश्चर्य के कुछ नहीं होता है।

1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और जब सुब्रह्मण्यम साहब ने क्विट पावर्टी का नारा दिया उस समय हिन्दुस्तान के लाइव रजिस्टरों में कुल मिला कर 31 लाख लोगों के नाम, बेरोजगारों के नाम दर्ज थे। उसके बाद वह समाजवाद लाए और और उसका नतीजा यह है कि आज 1976 में पिछले साल प्लान के अन्दर जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 97 लाख 84 हजार बेरोजगारों के नाम वहां दर्ज थे। इसका मतलब यह होता है कि तीन सौ परसेंट की उसके अन्दर बढ़ौत्तरी आज हो गई है। उसके बाद भी कोई समाजवाद की बात करे तो उन्हें क्या कहा जाए।

1976 में पांच लाख 20 हजार गांव देश में ऐसे थे जिन में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। तीस करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिन को प्राइमरी हैल्थ सेंटर की कोई सुविधा बीस मील के घेरे में उपलब्ध नहीं है। करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा सकते है, स्कूलों में उनकी पढ़ाई नहीं होती है और जो भीख मांगते हैं या जो छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। जनता पार्टी इस तरह की जो डिसपैरिटीज हैं जो समाजवाद के नाम पर यहां क्रियेट की गई है यकीनी तौर पर उनको खत्म करना चाहती हैं, भारत के माथे पर यह जो कलंक का टीका है इसको धोना चाहती है।

सब से बड़ी हैरानी की एक और बात है। कांग्रेस के बहुत से मित्रों तथा कम्युनिस्ट पार्टी के मैम्बरों ने चौधरी चरण सिंह की इस बात के लिए आलोचना की हैं कि उन्होंने कहा था कि वह भारत में काटेज इंडस्ट्रीज को, स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कंज्यूमर आइटम्ज हैं और जो काटेज इंडस्ट्रीज बना सकती है उनको बड़ी इंडस्ट्रीज के बनाने पर बैन लगा देना चाहिये। उनकी इस बात पर उनको बड़ी तड़पन हुई और उन्होंने

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

कहा कि इससे जो माडर्न नो हाऊ है वह खत्म हो जाएगा, भारत में बैकवर्डनेस आ जाएगी, भारत पीछे चला जाएगा। उनका तड़पना मेरी समझ में आता है। जिन पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया ले कर जो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं जो उनके जर खरीद गुलाम हैं उनकी तरफ से पूंजीपतियों की वकालत न हो यह कैसे हो सकता था। उन पूंजीपतियों पर आज अगर चोट होती है तो इनका तिलमिलाना मेरी समझ में आता है।

एक दो फिगर मैं और देना चाहता हूं। पहले प्लान में स्माल स्केल इंडस्ट्री के वास्ते 4 करोड़ 20 लाख रुपया रखा गया था और बड़ी के वास्ते 6 करोड़ 50 लाख। यानी करीब करीब बराबर दोनों के लिए पहले प्लान में प्राविजन किया गया था। लेकिन 1976-77 में पिछले साल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज के वास्ते जहां प्लान में 95 करोड़ रखा गया वहां बड़ी इंडस्ट्रीज के वास्ते 2185 करोड़ रुपया रखा गया। बड़ी इंडस्ट्री को स्माल स्केल इंडस्ट्री से करीबन 20, 21 गुना प्रोवीजन 1976-77 में रखा गया। नेशनलाइज्ड बैंक्स ने बड़ी इंडस्ट्रीज को 90 परसेंट लोन दिया और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को 10 परसेंट लोन दिया। इम्पोर्ट लाइसेंस 1975-76 में छोटी इंडस्ट्री को 87 करोड़ के दिये गये जब कि बड़ी इंडस्ट्री को 620 करोड़ रु० के दिये गये। 10 परसेंट केवल इम्पोर्ट लाइसेंसेज छोटी इंडस्ट्री पर गये। छोटी इंडस्ट्री ऐम्प्लायमेंट देती है 60 परसेंट और बड़ी इंडस्ट्री देती है 40 परसेंट। लेकिन सारे लोन्स, इम्पोर्ट लाइसेंस स्केयर्स रा-मैटीरियल बड़ी इंडस्ट्री 90 परसेंट ले जाती है। इसी कारण से गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता चला गया। इस का एक ही रास्ता है कि देश देश में जितने कन्ज्यूमर्स आइटम्स हैं यह बड़ी इंडस्ट्रीज न बनायें बल्कि छोटे छोटे सैक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज में बनें तभी देश के अन्दर से डिस्पैरिटी खत्म हो सकती है और इकोनामिक पावर का डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो सकता है। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़ी इंडस्ट्री की वकालत करते हैं और वर्ग संघर्ष के नाम पर उस को बनाये रखना चाहते हैं तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

रेट आफ ग्रोथ जो चौथी प्लान में 28 परसेंट होनी चाहिये थी वह केवल 14 परसेंट हुई। 1976-77 में रेट आफ ग्रोथ 2 परसेंट रही है। रेट आफ ग्रोथ का टार्गेट जब तक 6, 7 परसेंट नहीं किया जाएगा और जब तक उस के लिये प्लान ऐक्सपेंडिचर जो बढ़ाना चाहिये वह नहीं बढ़ाया जायगा तब तक देश में से 10 साल में पूरी बेरोजगारी समाप्त करने का जो हमारा संकल्प है वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये अगले साल के प्लान में इस टार्गेट को बढ़ाना पड़ेगा और रेट आफ ग्रोथ के लिये बोल्ड स्टैप ले कर 6, 7 परसेंट एक वर्ष के हिसाब से करना पड़ेगा।

कुछ दोस्तों ने शिकायत की कि हरिजनों और आदिवासियों के लिये तथा स्लम्स आदि के लिये ज्यादा रुपया नहीं रखा गया है। मैं नेशनल इवैलुएशन काउन्सिल में 5 साल तक मैम्बर रहा हूं, मुझे मालूम है कि सब स्टैट्स इस बात के लिये आग्रह करती रहीं कि जो कुछ भी ग्रान्ट्स, उन को मिलती हैं वह सारी उनको दे दी जाय और स्टैट्स फिर आगे उन को अलग अलग सैक्टर में अलोकेट करेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस पैटर्न को फौरन बदलना चाहिये क्योंकि लम्पसम ग्रान्ट और अनिस्पैंड चली जाने के बाद जो स्लम डैवलर्स हैं, बीकर सैक्शन हैं, हरिजन और आदिवासी हैं उन को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उन को स्टैट्स के अन्दर रुपया नहीं दिया जाता है। इसलिये एक स्पैसिफिक ऐलोकेशन होना चाहिये और स्टैट्स उस के अन्दर खर्च करें तभी उनको पैसा मिलना चाहिये और इसी मद के अन्तर्गत

उस पैसे को स्टेट्स खर्च करें। शुरू में यही पटर्न था कि जो रुपया रखा जाता था वह सारा स्टेट्स में हरिजनों और आदिवासियों पर खर्च होता था। लेकिन जब से लम्प सम रूपया स्टेट्स को दिया जाने लगा तब से उस काम पर पैसा खर्च न हो कर अपने अपने क्षेत्रों को लोग फायदा पहुंचाने लगे। इसलिये मेरा कहना है कि इस पैटर्न को चेंज किया जाय और इस प्लान में कुछ रुपया इस के लिये रखें। वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह कुछ पैसा बढ़ा लेंगे अगर स्टेट्स कोआपरेट करने के लिये तैयार हैं तो। लेकिन स्पेसिफिक ऐलोकेशन इस के लिये जरूर हो और स्टेट्स को कहा जाय कि यह रूपया इसी मद के अन्दर खर्च करना होगा तभी उन को इस के लिये असिस्टेंस मिलेगी।

मैट्रोपालिटन सिटीज में जो स्लम्स है उन के बारे में भी कोई स्पेसिफिक ऐलोकेशन नहीं किया गया। वह जरूर होना चाहिये और जो कांग्रेस सरकार ने कर रखा था कि जो सरकारी जमीन पर स्लम्स है उनमें कोरपोरेशन कोई सुधार नहीं कर सकती, इस बैन को कम से कम हटा देना चाहिये। दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, मद्रास में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जमीनों पर नरक की जिन्दगी बिताने वाले जो लोग हैं उन के अन्दर कोई सुधार करना चाहिये। पहले सुधार करने की कोरपोरेशन या वहां की स्टेट गवर्नमेंट को इजाजत कांग्रेस सरकार ने बन्द कर रखी थी, जब कि बिजली, पानी, ड्रेनेज आदि देना एक इन्सानी फर्ज बनता है। इसलिये उस बैन को हटा लेना चाहिये और मैट्रोपालिटन फंड की दुबारा स्थापना की जानी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कि दिल्ली के केपिटल रीजन के लिये दिल्ली के आसपास के 40 मील इलाके के विकास के लिये एक केपिटल रीजन फण्ड की भी स्थापना होनी चाहिए और उसके लिये इसमें प्रावीजन किया जाना चाहिये। क्योंकि आसपास की जो स्टेट्स हैं, उनका इन्ट्रेस्ट इस बात में नहीं है कि दिल्ली के आसपास के इलाके का डैवलपमेंट हो। दिल्ली की पापूलेशन इतनी तादाद में न बढ़ सके, जितनी बढ़ रही है, वहां पर इन्फलक्स ज्यादा न हो, उसके लिये जरूरी है कि आसपास के कस्बों और शहरों का पूरा विकास किया जाये। इसके लिए केपिटल रीजन फण्ड की बहुत जरूरत है।

सेल्स टैक्स की एबोलिशन इस मुल्क के लिये बहुत जरूरी है। जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में भी उसका जिक्र है कि हिन्दुस्तान से सेल्स टैक्स की लानत को खत्म किया जाये। सेल्स टैक्स को खत्म कर के उसको एक्साइज ड्यूटी में कन्वर्ट किया जाये जिस से कंज्युमर को और प्रोड्यूमर को, सब को फायदा हो और करप्शन पूरी तरह से इलीमिनेट हो जाये। इसके लिये मैं यह मानता हूं कि जब तक स्टेट्स नहीं मानेगी, तब तक यह काम नहीं किया जा सकता है। अगर उनको इससे नुक्सान न हो और इस से जो रुपया मिल रहा है वह और किसी रूप में मिल जाय, उसके पास रुपये की कमी हो, तो सेल्सटैक्स को पूरी तरह से एबालिश करने की जरूरत है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि सारे टैक्स के ढांचे पर पुनर्विचार किया जाये। जिस तरह से आज टैक्स हैं, उनको सिम्पलीफाई कर के एक दो टैक्सों में कन्वर्ट किया जाये ताकि न लीकेज हो और ब्लैक मार्केट हो सके। यह भी जरूरी है कि इनकम के बजाये एक्सपेंडीचर पर टैक्स लगाने की बात सोची जाये। इससे अगर मोबोलीडेट कर सकें तो शायद बहुत आसानी इस से हो सकती है यूथ वैलफेयर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर स्पैसिफिक तौर पर कुछ विशेष बातें सामने नहीं रखी गई हैं। कांग्रेस ने पिछले 25, 30 सालों में यूथ वैलफेयर के नाम पर कुछ नहीं किया। हिन्दुस्तान में करोड़ों नौजवान आज बेकार हैं, उनको कोई कंस्ट्रक्टिव एवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए स्पैसिफिक प्रावीजन जरूर होना चाहिए और अगले बजट में जरूर सोचना चाहिए।

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

नेहरू युवक केन्द्र बनाए गए थे, उनकी इतनी बुरी हालत हुई कि पार्टी परपज के लिये उनका यूज किया गया। उनको डैन्स आफ करप्शन ऐसी जगह बना दिया गया कि जहां पर एन्टी सोशल काम होते थे। उनका मकसद खत्म हो गया। उसकी बजाए आज नौजवानों के लिए खेल कूद, सोशल सर्विस, आर्ट कल्चर आदि ऐसे कामों के लिये बजट में प्रावीजन करना बहुत जरूरी है। यह अभी हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके बारे में अगले बजट में अवश्य सोचना चाहिये।

अब हिन्दुस्तान को एशियन गेम्स का मौका सन् 1982 में मिल रहा है। पहले हिन्दुस्तान में एशियन गैम्स होते रहे हैं, उसके बाद अब सातवां या आठवां गेम्स हिन्दुस्तान में यह होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस पेस से आज हम चल रहे हैं, अगर उस से ही चलते रहे, जैसे कि पिछले दो साल में इनको नैगलैक्ट किया गया है, तो बाद में हिन्दुस्तान एशियन गेम्स को कर नहीं पायेगा। यह हिन्दुस्तान के लिये बड़ी बेइज्जती और बदनामी की बात होगी कि हिन्दुस्तान को गेम्स एलाट की जाये और वह उनको यहां न कर सके। इसके लिये बजट में कोई एलोकेशन नहीं है, जिसके बिना काम चल नहीं सकता। हमें इसमें एक दिन का भी डिले नहीं करना चाहिये और इसके लिए खास प्रावीजन रखना चाहिए किएशियन गैम्स को हम हिन्दुस्तान में कर सके और उसके लिये जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाया जाए उसको पूरा किया जाए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि पावरलूम को जो सुविधा दी गई है, वह मुनासिब नहीं है। पावरलूम को दी गई सुविधा से हैंडलूम इंडस्ट्री तबाह हो जायेगी। बड़ी इंडस्ट्रीज इन पावर लूम का सहारा लेकर इनसे माल बनवायेंगी और इस सुविधा से लाभ उठायेंगी। मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी में यह बात हो गई है। हैंडलूम को प्रोटैक्शन मिलना चाहिए, उसको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिये। पावरलूम को जो सुविधाएं दी गई हैं, उनके बारे में पुनर्विचार जरूर करना चाहिए।

इसी प्रकार से चैरिटेबल कार्यों के लिये दान में टैक्स एग्जैम्पशन के सम्बन्ध में दो लाख रुपए की सीलिंग को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर भी विचार करें ताकि इस प्रावीजन का कहीं मिस यूज न हो।

इस बजट में एग्रीकल्चर और खास तौर पर पीने के पानी के बारे में इन्फ्रा स्ट्रेक्चर बनाने की नई बातें कही गई है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए परन्तु यह कहना कि इसमें प्रावीजन बहुत कम है, हमारे साथियों को यह समझना चाहिए कि जून के महीने में कोई प्राविजन कर के फरवरी तक उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह की कोई आइटम जिसकी प्लानिंग न हुई हो, सर्वे न हुआ हो, उसके लिये पैसा रख दे और बाद में बर्बाद हो तो यह ठीक नहीं है। यह बजट रीयलिस्टिक है और जो कुछ इसमें हो सकता था, उसको ध्यान में रखकर बड़ी समझदारी से इसको बनाया गया है परन्तु अगले वर्ष में नया बजट बनाते समय रैडिकल चैन्जेज होनी चाहिये। उस में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये। कांग्रेस के तीस साल के शासन में बेकारी हर साल भीषण रूप से बढ़ती रही। उस को खत्म करने के लिये हैंडलूम और स्मालस्केल इंडस्ट्रीज के लिये एलोकेशन होना चाहिये। हमें यह तय कर देना चाहिये कि नेशनलाइज्ड बैंक बड़ी इंडस्ट्रीज को 50 परसेन्ट से ज्यादा लोन नहीं देंगे, और 50 परसेन्ट रूपया छोटी इंडस्ट्रीज को दिया जायेगा जो सेक्टर जितनी एम्पलायमेंट जेनीरेट करता है, उस को उसी हिसाब से रूपया तथा अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिये। अगर स्मालस्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज 60

परसेंट एम्पलायमेंट जेनीरेट करती हैं, तो 60 परसेंट लोन्ज, स्केयर्स रा मैटीरियल और इम्पोर्ट लाइसेंसिज उन को मिलने चाहिये ऐसा करने पर देश की बेकारी बहुत बड़ी मात्रा में दूर हो सकती है।

बीड़ी पर ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिस का असर गरीब आदमियों पर पड़ेगा। यह ठीक है कि बीड़ी पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस से केन्सर होता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इस का उपाय यह है कि लोगों को समझा कर बीड़ी-सिग्रेट पीने से मना किया जाये। जो गरीब लोग इस समय बीड़ी पीते है, इस ड्यूटी के बढ़ने से उन पर बोझ बढ़ जायेगा। इस लिये अच्छा तो यह होगा कि शराब पर ड्यूटी को बढ़ा दिया जाये और बीड़ी को छोड़ दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को यह बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं। कांग्रेस के शासन में देश मे गरीबी, बेकारी, भुखमरी और डिसपैरिटीज बढ़ती रही हैं। उन को दूर करने के लिये वित्त मंत्री ने एक दिशा-निर्देश किया है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष इस सम्बन्ध में रैडिकल चेंजिज की जायेंगी।

SHRI VENUGOPAL GOUNDER (Wandiwash): Sir, I would be failing in my duty if I do not congratulate the Prime Minister and the Agriculture Minister for giving due consideration to the rural economy. Hitherto much was claimed as having been done for the agriculturists, but in actual practice, the statistics show that the benefits given by way of loans, aid etc. to industries, both small and medium and big, have been much more than the benefits given to the agriculturists. It is a big question mark whether even the benefits given to intended agriculturists actually have reached the intended persons—the small and medium farmers and the marginal farmers—who are actually engaged in agriculture. In the past, the tillers of the land have not enjoyed the benefits. The big landlords got the fruits of the benefits. This may be due to poverty, illiteracy and other factors. I request the government to plan in such a way as to enable the benefits to reach the real tillers of the land—medium or small and the marginal farmers. Then only we can improve agricultural production.

Another problem facing the agriculturists is the lack of marketing facilities. The industrialists are in a position to fix the prices of the products they produce but the agriculturist is not in that position. He is at the mercy of the middlemen who know nothing about agriculture. The government should fix the prices in such a way that they are economical to the farmer. I suggest that regulatory marketing committees should be established in each and every village. The agriculturists must get reasonable price for his produce. If the market prices are low, the government should not hesitate to purchase the produce at a reasonable price and build up buffer stocks. Otherwise, the poor agriculturists are at the mercy of the middlemen who are exploiting

[Shri Venugopal Gounder]

the situations. So, I request the Government to see that each and every village should have a regulatory market.

There is another aspect which I would like to touch. Suppose there is a bumper harvest. The theory of supply and demand will operate fully. The producer in the industrial sector is in a position to create an artificial demand so that he is in a position to get more money whereas the agriculturists is not in a position to do so. If the regulated market is operated, then something could be done.

Another important aspect is the distribution of fertilizers to the agriculturists. During the past two years all of a sudden the price of fertilizer Urea had gone up. Without relation to the cost of production of agricultural produce, the prices of fertilizer have gone up. So, the prices of fertilizers should be reduced and they should be distributed to the agriculturists. For proper distribution of fertilizer, it is better that fertilizers are distributed through cooperative agencies or panchayats so that they can be given to needy persons without any delay.

As far as Tamil Nadu is concerned, we are mostly dependent on the vagaries of the monsoon. Sometimes no water is available. Even the available water is subjected to dispute. There is a longstanding dispute between Tamil Nadu and Karnataka relating to Cauvery waters. So the dispute should immediately be settled. I hope the Centre is interested to see that it is amicably settled.

I would like to suggest that river waters in the country should be treated as a national asset. If the river waters become a national asset, then disputes can be averted.

I would like to state that for agriculture, as far as Tamil Nadu is concerned, we are subject to power cuts. The former Chief Minister, Mr. Karunanidhi without considering all the aspects dismantled the Samayanallor power plant. He has not constructed another power plant after dismantling it. So we are suffering a lot. Every village in Tamil Nadu is experiencing a power cut for about six months in a year. So, I would like to suggest that as far as agriculturists are concerned, they may be exempted from this power cut. If the power cut is imposed in respect of small and marginal agriculturists, they will be put to a lot of suffering. So, I would like this Government to advise the electricity boards of all State Governments to exempt agriculturists from imposition of power cuts.

श्री यू० एस० पाटिल (लातुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जनता पार्टी के वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि बजट एक ऐसा साधन है जिस से यह जाहिर होता है कि जो आइन्दा आने वाला समाज है, वह किस तरह से प्रस्थापित होगा । यह सही है कि पिछले तीस सालों में देश में कांग्रेस सरकार ने समाजवादी समाज की रचना या समाजवाद लाने की घोषणायें तो की थी, लेकिन उनकी जो सब से आखरी घोषणा हुई "गरीबी हटाओ", उस को लोगों ने पकड़ लिया कि हम गरीब रहना नहीं चाहते हैं । यह एक बड़ी अच्छी चीज है और मौजूदा हुकूमत को आगे खींचने वाली एक ड्राईविंग-फोर्स साबित होगी । लेकिन जैसा मेरे माननीय मित्र मल्होत्रा जी ने कहा, बल्कि आंकड़े देकर स्पष्ट किया—उन तीस सालों में समाजवाद तो नहीं आया, लेकिन मोनोपोलिस्टिक इण्डस्ट्रीज देश में पैदा हो गई । इस देश में पिछले दिनों में इण्डस्ट्रीयल वैल्थ बहुत बढ़ी है, इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आपात-स्थिति के जो आंकड़े बजट में कांग्रेस सरकार ने रखे थे, उस में बहुत ज्यादा कन्सेशन उद्योगपतियों को दिया गया, न सिर्फ इस देश के उद्योगपतियों को, बल्कि अमरीका, जर्मनी और दूसरे देशों के उद्योगपतियों को बुला कर यहां इन्वेस्ट

करने के लिये कहा गया । मल्टी-नेशनल कार्पोरेशन्ज को इन्वीटेशन देकर यहां इन्वैस्ट करने के लिये उस कांग्रेस सरकार ने कोशिश की और जब मोनोपोलिस्ट्स कहीं आम-जाते हैं, थोड़े से लोगों के हाथों में जब पूरी इकानमी चली जाती है तो उस का परिणाम होता है—बेरोजगारी, इन्फलेशन, बेकारी, गुरबत—ये सब चीजें बढ़ जाती हैं ।

आज हमारे देश में यही हालत है—समाजवाद का नाम लिया, लेकिन गुरबत बढ़ी । "जोतनेवाले की जमीन" का स्लोगन दिया गया, लेकिन 1961 से 1971 तक की रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये, देश में मजदूरों की तादाद बढ़ गई है, वे अपनी जमीन को खो बैठे हैं, जोतनेवाले जमीन पर नहीं रहे, के मजदूर बन गये । आज जनता पार्टी के सामने यही प्राब्लम है । जनता पार्टी किसानों के लिये बहुत कुछ करना चाहती है—लेकिन देहाती जनता को अभी विश्वास नहीं है । जब तक कोई चीज वास्तविक रूप में उन के सामने न हो, उन को रिअलाइज नहीं होता है कि कोई चीज हो रही है । इसी लिये समाजवाद के नाम के साथ-साथ आज गांधी जी के सिद्धान्तों की घोषणायें हो रही है । लेकिन मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि हमें सिद्धान्तों के झगड़े को छोड़ देना चाहिये, कुछ वास्तविक रूप में कर के दिखाना चाहिये । आप देखिये—डी-सेन्ट्रलाइज्ड इकानमी कांग्रेस का आदर्श था, लेकिन वह डी-सेन्ट्रेलाइज नहीं हुई, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सैन्ट्रलाइज होती रही । गांधी जी का सिद्धान्त है कि विलेज सेल्फ-रिलायेंट रूरल कम्यूनिटी बने—इस बात की घोषणा वित्त मंत्री जी ने भी की है । लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे विलेजेज की 40 परसैन्ट पोपुलेशन बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों—बम्बई, दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों में जा रही है । आज छोटे किसान और मार्जिनल फार्मर्ज की यह हालत है कि वे जमीन रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बैंकों से उन्हें कर्जा नहीं मिलता है और अगर कहीं मिला भी है तो बहुत थोड़ा मिलता है । 65 परसेन्ट जो हमारे छोटे किसान हैं, जब तक उन की उपज नहीं बढ़ती है, तब तक उन को जमीन पर काम करने में कोई फायदा नहीं होगा । उन के लिये फाइनेंस का इन्तजाम होना चाहिये, मार्केटिंग का इन्तजाम होना चाहिये, इनपुट्स के लिये पैसा दिया जाना चाहिये—जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी हमारे देश की इकानमी बढ़ नहीं सकती । इस बजट में भी यही कमी है: आप ने घोषणा की है कि हम देहातों में जो कम पैसा दिया जाता है, उन को अधिक देंगे, हम खेती को बढ़ाना चाहते हैं, छोटे किसानों को आगे लाना चाहते हैं । वित्त मंत्री के भाषण के हर पैराग्राफ में इस बात को काफी जगह दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो लेबर मवमेन्ट हो रहा है, बड़े बड़े शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं उस की वजह से हमारी खेती की इकानमी बरबाद होती जा रही है । यह आज से नहीं है—पिछले 30 सालों का नतीजा है । कांग्रेस के पिछले मिनिस्टर्ज और आज के फाइनेन्स मिनिस्टर देखें—यह उन्हीं की लैगेसी है, इस को बदलने की उम्मीद हम करते हैं, जनता पार्टी की कोशिश है कि इस को बदला जाय, लेकिन बदलते वक्त भी इस बजट स्पीच में जो रखा गया है—मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जो घोषणा की गई है, वह किसान को मिल सकेगा ।

अगर आप सरकारी क्षेत्र में जो उद्योग हैं, उन को कम पैसा दें, अगर आप छोटी मछली को बड़ी मछली द्वारा खाने का सिद्धान्त फिर अमल में लाना शुरू कर दें और सिक यूनिट को बड़े यूनिट में मर्ज होने के लिए इन्वेस्टमेंट में कुछ कन्सेशन्ज दें, तो यकीनन इस मुल्क में मोनोपली के ट्रेंड बढ़ जाते हैं । अगर आप का बजट मुट्ठी भर लोगों के, अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग 10 पर सेन्ट लोगों के हाथों में दे देते हैं, तो 90

[श्री यु० एस० पाटिल]

पर सेन्ट लोगों में गुरबत आ जाती है ।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन को कम करने के जो तरीके इस बजट में अपनाये गये हैं, वे कोई नये तरीके नहीं हैं । रिजर्व बैंक की तरफ से क्रेडिट स्क्वीज की जाती है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बैलेंस रखा जाता है, तो ऐसे मेजर्स वेस्टर्न कन्ट्रीज कई मर्तबा अपना चुके हैं लेकिन उनके कोई रिजल्ट्स नहीं निकले हैं । जब श्री मो० डी० देशमुख फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उस वक्त से यह होता चला आ रहा है कि जब कोमोडिटी महंगी हो जाती है, तो रिजर्व बैंक बैंकों को आर्डर करता है कि इतना क्रेडिट कम कर दो और फला फला चीज कर दो । पांच, छः महीने में मार्केट एडजस्ट हो जाता है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है । इमर्जेंसी के जमाने में आपने देखा कि 5, 6 महीने कुछ चीजें डाउन आ गई और वे भी एग्रीकल्चर कामोडिटीज लेकिन इन्डस्ट्रियल कामोडिटीज पर कोई खास असर नहीं पड़ा और वे बढ़ती गईं । इस तरह से ये जो मेजर्स लिये गये हैं ये कोई नये नहीं हैं और वही पुराने तरीके हैं जिन को कांग्रेस पिछले 30 सालों से अपनाती आ रही है । अगर जनता के फाइनेन्स मिनिस्टर उन्हीं मेजर्स पर अपनी इमारत रखेंगे, तो मैं नहीं समझ सकता कि इन्फ्लेशन को आप कम कर सकते हैं ।

एक दूसरी बुनियादी चीज यह है कि हमारे मुल्क में छोटे किसानों का बहुत बड़ा मसला है और सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है । किस तरह से इस को बढ़ाएं, यह देखने की बात है । न सिर्फ यही, बल्कि बैंकिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है । आज किसान को खेती के कामों के लिए बैंकों से इतना कर्जा नहीं मिल पाता कि वह उस में उन्नति कर सके । इस के अलावा मार्केटिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है । मार्केटिंग में हायस्ट एक्सप्लायटेशन अगर किसी प्रोफेशन का है, तो वह किसानों का है । जब तक इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और कैपिटल फार्मेशन नहीं होता है, तब तक यह धंधा आगे नहीं बढ़ सकता है । इंडस्ट्रीज में अगर किसी चीज में नफा नहीं होता है, तो वह सरकार के लिए सिर दर्द हो जाती है । मालिक उस को बन्द कर देता है और कोई दूसरा काम करने लगता है लेकिन किसान का ऐसा प्रोफेशन है कि अगर उस को अपने धंधे में नुकसान भी रहता है, तो भी वह उस को नहीं छोड़ सकता और वह हमेशा सिक रहेगा । अगर उस का प्रोडक्शन जीरो भी हो जाता है, तो भी वह उस धंधे को क्लोज नहीं करता लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी एकोनामी पर पड़ता है । आप के पास कपड़ा है और यहां पर ग्राहक नहीं है, तो आप उस कपड़े को अमेरिका और इंगलैंड भेज देते हैं लेकिन किसान की पैदावार के लिए ऐसा नहीं होता है । अगर उस की प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं है या ग्राहक नहीं है, तो उस को नुकसान उठाना पड़ता है और इस तरह से उस की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है । इस तरह से 70 और 80 फीसदी धंधा जो खेती का है, वह इन 30 सालों में बर्बाद हो चुका है और कांग्रेस सरकार के जमाने में उन के सिद्धान्त चाहे जो भी रहे हों और चाहे जो भी घोषणाएं हुई हों, किसान हमेशा बर्बाद होता रहा है ।

देहातों में अनएम्पलायमेंट बहुत बढ़ गया है । अर्बन में भी यह बढ़ गया है और इस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप के जो ग्रेजुएट और मेट्रीकुलेट लड़के हैं और जो खेती के काम में लगे हैं और जिन के पास तीन, चार या पांच एकड़ जमीन है, उन को सेल्फ एम्पलायमेंट की स्कीम में सौ फीसदी कर्जा देने के लिए आप सोचिये । अगर उस को एक तहसीलदार या दूसरी गजेटेड पोस्ट की तनख्वाह के बराबर उस में इन्कम हो जाती है, तो वह भी शहरों में नौकरी करने के लिये नहीं आएगा । उस को एम्पलायमेंट देने का एक ही जरिया है कि बैंक 100 फीसदी कर्जा उसे दें और कम सूद

पर वह कर्जा दिया जाए और 15, 20 इंस्टालमेंट्स में उस का पेमेंट हो। इस के अलावा जो वह पैदा करता है, उस में उस को 15 पर सेन्ट का फ़ायदा हो, तो आप की अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम कुछ सोल्व हो सकती है। इस तरह से जो छोटे किसान हैं, उन के लिए सैल्फएम्पलायमेंट की स्कीम होने की बहुत आवश्यकता है।

जापान की मिसाल यहां पर दी जाती है। बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जापान में जो सीलिंग है, वह एक यूनिट की 7 एकड़ की मैक्सीमम सीलिंग है। हमारे देश में सीलिंग का झगड़ा अभी भी चल रहा है। आज अगर एक किसान के पास 100 एकड़ जमीन भी है, तो भी उसको खाने को नहीं मिलता है। एक एक किसान के पास 25, 25 और 50, 50 एकड़ जमीन होने पर भी कोई ज्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनटेंसिव कल्टीवेशन अगर हो, तो अच्छा है और जमीन की सीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि यह देखा जाए कि एक फैमिली में खेती करने की कितनी कुव्वत है। उसी हद तक आप सीलिंग रखें। इसलिए इस सबन्ध में मैं यही कहूंगा कि दो चीजें आप किसान को जरूर दीजिए, एक तो बैंकिंग फैसिलिटी और दूसरे उसके सामान के लिए मार्केट। जापान कम्युनिस्ट देश नहीं है। उसमें भी 45 के बाद से सात एकड़ जमीन पर सीलिंग है। लेकिन एक एकड़ में हिन्दुस्तान में जितनी मैन पावर लगी है, उससे चार गुना मैन पावर को एम्प्लायमेंट देने की उसमें कुव्वत है। हमारे देश में भी इतनी कुव्वत है लेकिन हमारे देश में प्लान बनाने वाले, प्लानिंग कमीशन यह गलत समझ बैठे हैं कि हम इतनी पापुलेशन को धंधा नहीं दे सकते हैं। वह पापुलेशन को इस तरह से तकसीम कर देते हैं कि अगर पानी होगा तो हम इतने लोगों को धंधा दे सकेंगे, अगर पावर होगा तो इतने लोगों को धंधा दे सकेंगे। अगर हम खेती में इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं तो हम दस गुना लोगों को एम्प्लायमेंट दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लान बनाते समय हमें खेती को अधिक एम्प्लायमेंट देने का साधन बनाना चाहिए। हमें अपने मुल्क के गरीब किसानों और मार्जिनल फार्मर्स की इन्कम भी बढ़ानी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि एक मजदूर को कम से कम पांच से दस रुपए रोजाना मजदूरी मिलनी चाहिए। जब हम देहात में कोई इण्डस्ट्री चलाते हैं, शुगर इण्डस्ट्री लगाते हैं या टैक्सटाइल इडस्ट्री लगाते हैं तो कम से कम उसको पौने दो सौ या डेढ़ सौ रुपया महीना मिल जाता है। जो भाई गन्ने को पानी देता है उस बिचारे को दो से तीन रुपए रोज मिलता है। इस हालत में तो खेती करने वाले को मजदूर मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज मजदूर की कमी है। अगर आप चाहते हैं कि इर्रीगेटेड ट्रेक्स के लिए मजदूर मिलता रहे तो आपको अनएजूकेटेड या एजूकेटेड बेकारों को खेती की ओर बढ़ाना चाहिए।

दूसरी चीज, महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज हो रही है। वहां एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम चालू है। इस स्कीम को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें काफी खामियां और त्रुटियां हैं। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के लोगों के हाथ में पावर होने से उसमें अच्छी तरह से काम नहीं लिया जाता। इस स्कीम से हम लोगों को बारह महीने काम दे सकते हैं। कहने वाले लोग कहते हैं कि किसान और मजदूरों के हाथों में पैसा देने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके मायने क्या हैं? किसान को उसकी तनख्वाह मिल गयी तो इंफ्लेशन बढ़ता है और अगर इस फिलासफी को लेकर हम चलते हैं तो उसको क्या हम मार्जिनल किसान ही रखना चाहते हैं? क्या हमने प्लानिंग इसलिए की है कि गरीब किसान को हम उसका हक न दे सकें, उसको सामर्थ्यवान न बना सकें? वह भी इस मुल्क की जमीन का मालिक बने, कारखाने का हिस्सेदार बने। अगर आप

श्री यू० एस० पाटिल,

सही मायने में गांधी फिलासफी को जानते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि इस देश की जमीन के मालिक सभी लोग है, गांव की जमीन का मालिक गांव का आदमी है । यह मुल्क इस देश की जनता का है । मुझे डर है कि जनता पार्टी में भी जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के लोग हैं वे अपने मफाद के लिए गांधीवाद को न चलने देंगे । इससे देश की बर्बादी होगी । हमारा समाज सभी लोगों का है, यह मुल्क भी सभी लोगों का है, इसलिए हमें सभी लोगों को काम देना है । जितने भी इस देश में तालीम याफ्ता नौजवान है उन सभी को काम में लगाना है । गांव के हर आदमी को काम में लगाना है । मुझे इस बात की खुशी है कि इलेक्शन के बाद से देश का नौजवान अपने सवालात को हल करने के लिए खड़ा हो गया है ।

अब मैं इस बजट की दो-तीन खामियों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । इस वक्त उसके लिए प्राविजन आपने बहुत कम किया है । अगले साल आप क्या करते हैं इसको देखेंगे । आपको ऐसे कदम उठाने चाहियें ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके । देश में प्रोडक्शन जो होता है उसको वे खरीद सकें, उसको बढ़ावा मिले । वर्ना हालत खराब हो जाएगी । आज क्या हो रहा है । कॉटन आप बाहर से मंगा रहे हैं, लेन्स आप बाहर से मंगा रहे हैं, अनाज बाहर से मंगा रहे हैं और जो चीजें यहां पैदा होनी हैं वे यहां बिकती नहीं हैं और उनको बाहर भेजने की कोशिश की जाती है । यह अमल इकोनोमी है । जो कच्चा माल हम को कारखानों के लिए चाहिए वह हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा पैदा होना चाहिए तभी हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वह मजबूत हो सकता है, पक्का हो सकता है । ऐसा न होने से क्या होता है ? हम नई इण्डस्ट्रीज जो स्थापित हो सकती थीं वे स्थापित नहीं होती हैं और इसके बजाय पन्द्रह सिक यूनिट्स की श्रेणी में चली जाती हैं और अब जमा और खर्च का हिसाब लगाया जाता है तो पता चलता है कि हम नुकसान में गए हैं, घाटे में गए हैं । लोगों को आप रोजगार देने की व्यवस्था करें, उनके लिए काम धंधे देने की व्यवस्था करें, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, सत्तर परसेंट पापुलेशन जो है उसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें, उसका स्तर ऊंचा करें, यही मुझे आप से निवेदन करना है ।

श्री लक्ष्मण राव मानकर (भंडारा) : अर्थ मन्त्री महोदय ने अपने बजट में कुछ बातों को दिशा देने का प्रयास किया है । प्रमुख रूप से उन्होंने बताया है कि इस देश में तीस साल तक जो प्लानिंग हुआ है उस प्लानिंग की वजह से बहुत सी खराबियां पैदा हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है । डिफिसिट फाइनेंसिंग करने से हमेशा महंगाई बढ़ती है । इस वास्ते इसको कम करने का प्रयास इस बजट में किया गया है । कुछ बातें इसमें दिशा के रूप में दर्शाई गई हैं । मैं मानता हूं कि कई मदें ऐसी हैं जिनमें और अधिक प्राविजन करने की आवश्यकता थी । मैं मानता हूं कि जो भी प्राविजन विभिन्न मदों में किए गए हैं वे काफी नहीं हैं । लेकिन जो एक दिशा, निदेश मन्त्री महोदय ने किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए ।

मैं कांग्रेस मित्रों के भाषण सुन रहा था । उन्होंने कहा है कि बजट में स्मॉल फार्मर्ज स्कीम के लिए एग्रीकल्चर लेबर आदि के लिए बहुत कम प्राविजन किया गया है । मैं मानता हूं कि इसको बढ़ाया जा सकता था । दूसरी मदों पर भी खर्च को बढ़ाया जा सकता था । लेकिन आप देखें कि पिछले साल के बजट में एग्रीकल्चर लेबर के लिए जहां 26 करोड़ का प्राविजन किया गया था इस साल के बजट में 46 करोड़ का किया गया है । ज्यादा प्राविजन करने का इसमें प्रयास किया गया है । लेकिन ऐसा डिफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा कर ही किया जा सकता था । कांग्रेस शासन ने पिछले अनेक वर्षों में डिफिसिट फाइनेंसिंग

को खूब बढ़ाया है । ऐसा हम भी कर सकते थे । लेकिन हमने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा ।

यह भी कहा गया है कि स्टेट सैक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है । आप देखें कि भिलाई कारखाने के लिए प्राविजन बढ़ा दिया गया है । कारण यह है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर आगे बढ़े । जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, वहां बेकारी का सवाल है, खेतीहर किसानों का सवाल है, उनके बारे में इस बजट में एक दिशा देने का प्रयास किया गया है । एग्रीकल्चर बेस्ड और फारेस्ट बेस्ड इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले इस बात की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया । यह बहुत सफ़िशियेंट है ऐसा मैं नहीं मानता हूं । किन्तु कुछ बातों की तरफ़ ध्यान देने की आवश्यकता है । जैसे कि जंगलों में अनेक चीजें पैदा होती हैं, मिसाल के लिए लाख है जो जंगलों में पैदा होती है जिसकी वजह से लोगों को उद्योग और जो मजदूरी मिलनी है वह काफ़ी नहीं है । बहुत कम मात्रा में उनको मजदूरी मिलती है । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को, जो लाख का काम करते हैं, तीन रुपया देने की बात कही । लेकिन तीन रुपया किसानों को कभी नहीं मिला । लाख से हम को फ़ौरेन एक्सचेंज मिलती है । किन्तु अनेक प्रान्तों में अलग अलग प्रकार की नीति आदिवासियों और गरीबों के लिए रखी जाती है । जिन लोगों का जीवन ही जंगलों में पैदा होने वाली चीज़ों पर चलता है उन पर ऐसे नियंत्रण डाले गए है जिसकी वजह से आदिवासी लोगों को और जंगलों में रहने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue later because at two O'clock, we have to take up Calling Attention. Shri Chitta Basu.

---

14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PRE-ELECTION POLITICAL SITUATION IN JAMMU & KASHMIR AND POSTPONEMENT OF THE ASSEMBLY ELECTION.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I call the attention of the Minister of Law, Justice and Company Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Pre-election political situation in Jammu and Kashmir and reported postponement of the Assembly election scheduled to be held from June 30 to July 3, 1977."

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Deputy Speaker, Sir, Elections to the Legislature of Jammu and Kashmir are held under the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir and the laws made thereunder. The functions of the Election Commission of India also extend to the elections to the State Legislature. It is open only to the Election Commission to postpone the dates of polling by a notification under section 155 of the Jammu & Kashmir Representation of the People Act, 1957 for reasons which it considers sufficient. As it is, the elections to the State Legislative Assembly are scheduled to be held on June 30, July 2 and 3. These dates were fixed by the Election Commission of India under section 41 of the J & K Representation of People Act, 1957.

There has been considerable resort to violence in the Kashmir Valley in the course of the election campaign for some time now. Several clashes have already taken place between rival political groups.

The present series of incidents of disorder started with Shri Sheikh Abdullah's entry into the Valley early

[Shri Shanti Bhushan]

in April. There was a clash between a large number of his followers who had been brought in buses to escort him from Qazi Gund to Srinagar on the one hand and students of Anantnag Degree College who were demonstrating against him on the other. Various allegations about police and national Conference Workers having entered the College premises and beaten up girl students and staff were made and are presently under judicial enquiry. Following the Sheikh's arrival in Srinagar there were demonstrations and counter demonstrations accompanied by a little violence mainly in Srinagar City. As election tempo picked up incidents of occasional disorder continued in Srinagar City in the form of clashes between the followers of Shri Sheikh Abdullah on the one hand and those of Maulvi Farooq on the other. In one major incident, a lady Janata candidate Dr. Jagat Mohini sustained serious fractures at the hands of National Conference workers. A further incident occurred when Maulvi Farooq of Awami Action Committee went to Anantnag on 11th June. There were clashes between his people and the local National Conference supporters at Anantnag and also on their return journey at two or three places *enroute*. At one place, Awantipur, an incident of arson also occurred which is under investigation. Series of measures have been taken from time to time to tighten law and order arrangements and curb violence.

There is no proposal before the Election Commission for the postponement of the dates of election. Neither the State Government nor anybody else has approached the Election Commission for such postponement. Since the superintendence, direction and control of the conduct of elections vests in the Election Commission of India under section 138 of the Jammu & Kashmir Constitution, the Election Commission is expected to keep a close watch over the situation to see that a free and fair election takes place.

The Central Government have been providing the fullest possible assistance to the State Government in maintaining law and order. Both the Governments are anxious to ensure peaceful conditions in which fair and free elections can be held. The effort of both the Governments is to curb violence firmly and to ensure free and fair elections.

SHRI CHITTA BASU: Sir, it has been admitted in the statement that the pre-election situation in Kashmir is very tense and also alarming. Unlike the other States, there have been widespread disorder, violence, murder, arson, loot, etc. The reasons behind certain incidents have been mentioned by the hon. Minister in the course of his statement, but those couses are not the result of foolproof and complete investigation. In the interest of the country's integration, one has to go into the depth of the Kashmir situation now. May I know, in this context, from the hon. Minister whether the following events are the causes for the present flare-up in Kashmir, namely, (i) the suggestion for abrogation of article 370 of the Constitution of India made by certain spokesmen of the Janata Party; (ii) the sudden and arbitrary stoppage of subsidies in respect of rice to the people of Kashmir; (iii) admission into the Janata Party of certain erstwhile rabid communalists and protagonists of secession of Kashmir and inclusion of some of them in the list of candidates of the Janata Party; (iv) provocative speeches made by the leaders of different political parties adding to the tension and imparting communal overtones to the election campaign; and (v) apprehension of the people of Kashmir of large scale rigging as in the past elections.

I also want to now from the hon. Minister whether any code of conduct for the election campaign was decided upon by all the political parties in Kashmir after mutual consultations

and consent, and if so, what was the code and who were responsible for the violation of the agreed code.

It is understood that the Governor has made a report to the Government of India about the political situation, particularly about the pre-election political situation, in Kashmir. May I know from the hon. Minister whether any report has been received by the Government of India from the Governor of Jammu & Kashmir? If any report has been received, it should be laid on the Table of the House.

In view of the fact that the currents and crosscurrents in Kashmir are likely to have wide repercussions on the national polity of our country and also in view of the fact that Kashmir occupies a very sensitive and strategic position in our country, may I know from the hon. Minister whether the Government of India would agree that a conference of the representatives of all political parties of Kashmir as well as of the country be held immediately to devise ways and means to restore normalcy in Kashmir and ensure free and fair elections?

In conclusion, I would like the Government to take note of the fact that a situation of this nature cannot be tackled properly only at the administrative level; it should be tackled at the political level also. In that context, may I know whether Government, in the interest of democratic polity of our country, in the interest of national integration, would depend more on political skill than on administrative ruthlessness?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Hon. Member has raised various points as to whether these are the causes which might have contributed to the present situation which is obtaining in Jammu & Kashmir. He has, in the first instance, referred to something about abrogation of Art. 370. May I say, on behalf of the Government, that very categorical assurances have been given on several occasions by the External Affairs Minister and other Ministers on behalf of the Government of India, that there is no question of abrogation of Art. 370. It is for the people of Jammu & Kashmir to decide and it is only is no question of imposing the abroga- so that any question of the abrogation of Art. 370 can arise: otherwise, there is no question of imposing the abrogation of Art. 370 on the people of Kashmir. So the question of abrogating Art. 370 arbitrarily does not arise. This assurance was given on behalf of the Government on several occasions and, in that light, it is rather surprising that on behalf of Sheikh Abdullah quite a lot of election campaigning was done on the basis of Art. 370. There was some kind of an apprehension which was wholly imaginary, even after such a categorical assurance had been given on behalf of the Government by members of the Government that there was no question of abrogating Art. 370. It is not understood why so much attention was being given on behalf of the National Conference in the election campaigning to making references to Art. 370.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): How does the External Affairs Minister come into the picture?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Government acts with combined responsibility and if a Cabinet Minister makes a statement, he makes it on behalf of the Government. I had said that several Ministers have made the statement; it is not only the External Affairs Minister but the House Minister and the Prime Minister also who made it. I referred to the Minister of External Affairs because my impression was that he was the first one to make the statement on behalf of the Government. Otherwise, not only he but the Home Minister and the Prime Minister also have made very categorical statements in that regard, that there need not be any apprehension from that point of view in the mind of any person.

[Shri Shanti Bhushan]

Then, the Hon. Member also referred to 'arbitrary stoppage of subsidy'. So far as that is concerned, the Hon. Member would recall that before the Legislature was dissolved and there was a Government in the State which was headed by Shelkh Abdullah himself, it was that Government which had stopped the subsidy being received by the Jammu & Kashmir Government. So, the Government of India does not come into the picture here. I believe, again, that the Home Minister had occasion to say, in this connection that it will be for the Government of Jammu & Kashmir, when it is formed, to consider this question of subsidy being received from the Government of India.

Then, the Hon. Member also referred to the fact as to whether the admission to the Janata Party of some rabid Communalists is also a factor which was responsible. I, at least am not aware of any rabid communalists having been admitted to the Janata Party. If the Hon. Member's definition of 'rabid Communalists' is that all secular persons are rabid Communalists or that those who do not make any distinction between the treatment meted out to various communities should be regarded as rabid Communalists, perhaps there might be some point in his making a reference to it: otherwise, Government is not aware of any rabid Communalists having been admitted to the Janata Party.

Then, the Hon. Member also referred to some trouble about the list of the Janata Party candidates. Now, so far as any trouble arising out of the list of the Janata Party is concerned, if there had been any reports of trouble between different sections of the Janata Party, then perhaps one could have thought that there has been some interference—somebody not being given a ticket and another person being given a ticket by the High Command of the Janata Party. But so far as the clashes which have occurred and the breaches of peace which have occurred are concerned, they have been between members of different political Parties, mainly between members of the National Conference and members of the Awami Action Commitee and also between members of the National conference and those of the Janata Party: they were not *inter se* clashes between one section and another section of the Janata Party. Therefore, this is also not a factor which is responsible for the present situation in Jammu & Kashmir.

Then, the Hon. Member has said that there is some apprehension about rigging in the elections, which is responsible for the present situation or turmoil or breach of peace in Jammu & Kashmir. So far as this is concerned, I would say on behalf of the Government that after the manner in which the last elections were held to the Lok Sabha in March this year and the way in which the State Assembly elections have been held only very recently, not only this country but other democratic countries are also proud of the manner in which elections have been held in this country, both in March last and also quite recently. Therefore,nobody either in this country or outside in any other country could have any apprehension of any kind of rigging in the elections that are going to take place in Jammu and Kashmir. I do not see how the present situation obtaining in Jammu and Kashmir can be attributed to any kind of apprehension in any quarters about the rigging of the elections.

The hon. Member has also enquired as to whether any report has been received from the Governor about the political situation there. So far as reports from the Governor are concerned, reports have been received from time to time about the law and order situation in Jammu and Kashmir whenever any situation has developed because it is for the Government of India also to lend all assistance which may be necessary to the State Government to maintain the law and order situation, to maintain peace in the

State of Jammu and Kashmir. Therefore, the Governor from time to time has been sending reports about the law and order situation to the Ministry of Home Affairs, and a report about all these incidents which have taken place has also been received.

The hon. Member has also enquired, as to whether it would be considered feasible to have a conference of all political parties in Jammu and Kashmir and all political parties in the whole country in order to deal with the situation. So far as this is concerned, it depends on the situation how it develops. It is not one single party which can achieve something in regard to that.

The hon. Member also referred to the code of conduct. I am speaking on the basis of the impressions that I have that perhaps there was an effort to evolve a code of conduct between the various political parties, but perhaps a complete agreement between the various political parties about that was not found possible. If there is a desire among all the political parties about this, then it is open to all the political parties to meet and discuss this matter, but it is not for one political party to do that. And, it is not possible for the Government to arrange for a conference between all political parties to evolve any code of conduct between all political parties.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after having read the statement made by the hon. Minister, I have a feeling that in the first three-fourths of his statement, he seems to have tried to throw the entire blame for the situation in Jammu and Kashmir on Sheikh Abdullah and the National Conference. The entire tenor is that since Sheikh Abdullah and the into the Valley in April, the clashes began. Universities were raided, girl students were beaten up and other disorders started with the attacks and clashes between Sheikh Abdullah on one hand and Maulvi Farooq on the other. Even a lady doctor of the Janata Party, Dr. Jagat Mohini sustained serious fractures. The hon. Member has, however, not given any facts about the other side of the picture. Government is expected to give a statement with full facts. I have here with me a report appearing in the *Times of India* today, where Mrs. Abdullah has joined issue, with the Home Minister when he also made a similar reference in electioneering speeches recently in Jammu & Kashmir, she says:

> "The Home Minister had gone out of his way to talk of the alleged attack on Janata Party candidate, Dr. Jagat Mohini and even Maulvi Farooq's public meeting in Anantnag, but had not said a word about the burning of the houses of National Conference workers in Awantipura, the murder of a National Conference worker near Narbal."

Now, therefore, it does not appear as if it is one political party which is responsible for creating such a situation in Kashmir.

The hon. Minister also made a reference to the confusion created about Article 370. But there also there is a reference in a news item in the *Hindustan Times* of yesterday which says:

> "The Home Minister said that in the morning when the Vice-president of the National Conference, Mirza Afzal Beg and three other leaders of the party had met him, they had assured him that they accepted the accession and had made no speeches criticising it. They also clarified that they had been talking of Art 370 only after a demand had been made by a Janata Party MP.....

And a very prominent MP.

> ...Mr. Subramaniam Swami asking for its abrogation."

So, the whole mischief began from there when a prominent member, a

[Shri Shanti Bhushan]

self-declared think-tank, brain-tank, economist and a very big man asked for its abrogation. It goes on saying:

> "The National Conference leaders also blamed the workers of the Janata Party for the recent violence."

Now, I would like to know. When you are in charge of Jammu & Kashmir--Governor's rule is there—you cannot say that it is some other government which is in authority there and they are responsible for law and order. How can the government of India absolve itself of their duty and responsibility to protect the lives of the citizens there, to see that law and order is maintained, and to take protective measures? Can you say that the Election Commission is responsible for this because it is the Election Commission which is responsible for conducting the elections in a free and fair manner and, therefore, 'we are not responsible for this.'? Can the Government get away by saying this?

The entire tenor of your statement appears to be, 'what can we do? We are helpless. It is these political forces.' I would like to know from the learned Law Minister. Your statement gives an impression of helplessness on your part. There is a failure on the part of the government. While you say that you are responsible for law and order and have the fullest authority, attacks like this are being made, and you try to explain it saying that this was not something internal between Janata Party, it is between two political parties, then it has to be allowed and only if it is internal between the Janata Party, you will be responsible. There is law and order to be maintained. Whichever the political force, any clash which creates a disturbance of law and order must be prevented. That is the duty of the Government. You have totally failed in discharging this duty. In this statement although you have said that there is no proposal from the State Government, reading between the lines, I have a lurking feeling that a situation is deliberately being created, high-lighted by the hon. Home Minister as we find in this statement that 'the situation is deteriorating fast'. The Home Minister in his statement in Jammu & Kashmir has said and I quote again the *Hindustan Times*:

> "The Union Home Minister Shri Charan Singh also remarked at the end of his visit to Srinagar to-day that the law and order situation was worse in Jammu & Kashmir than what it was in other States before the elections there."

So, therefore, what is the picture that emerges from this? On the one hand you are saying that the law and order situation is deteriorating, becoming worse and yet you say "at present there is no proposal. We do not know what the Election Commission will do. It is for the Election Commission to decide."

My fear is that there is something up your sleeves because it is on your recommendation—the Governor's recommendation—that the Election Commissioner will act. He is not responsible for law and order. If there is complete break of law and order situation, what can the Election Commission do? How can he hold the election?

You were saying what can we do. Law and order situation has also become worse. Now it is for the Governor to say what he wants. He has given his factual report. It is for the Election Commission to decide and the Election Commission has taken this decision. This is how you stated in the statement. That is why prominent papers like the *Times of*

India have reporte on the front page I quote:

> "While there has been some report suggesting postponement of the poll, the Election Commission said, they had received no such proposal."

At present where are you? No proposals are there. But Srinagar Correspondent added:

> "Election to Jammu & Kashmir Assembly scheduled to take place between June 30 and July 3 are likely to be postponed.

I cannot attribute irresponsibility to a correspondent of the *Times of India*. There must be some basis. Further, he says:

> "A decision to this effect is understood to have been taken during the week end visit of Union Home Minister, Shri Charan Singh to Srinagar."

This is a categorical statement. Further it has been said:

> "The Governor Shri L. K. Jha has not so far asked the Election Commission for postponement. But he is likely to do so shortly pending the consent of the Prime Minister."

So your statement 'no proposal has been made' is neither here nor there. I would like to have a categorical statement. I am glad that the hon. Minister Shri Charan Singh is here. I would like a categorical statement that there will be no postponement and you will take care to see that law and order situation does not deteriorate and free and fair election is made possible. You do not make any proposal but ensure that the election is not postponed. If it is postponed, it will be a highly retrograde step for democracy and for this Government. I would like a categorical assurance. I do not mind if it comes from the hon. Law Minister.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Mr. Sathe has first raised the point that the statement which I have just made creates an impression in his mind that there has been an attempt to cast all responsibility on Sheikh Abdullah for the clashes. Even though it may be Sheikh Abdullah or his party which might or might not have been responsible for some of the clashes, he has made that statement. Now, he has referred to my statement in that connection. I would invite his attention to the last line in the first page of my statement. I have said this:

> Various allegations about police and national conference workers having entered the college premises and beaten up girl students and staff were made and are presently under judicial enquiry.

Obviously if certain allegations have been made, those allegations have been supported by concrete material. I have certain photographers here of the serious injuries to certain ladies and girl students etc. who are in hospital. If the hon. Member is anxious he may have a look at that. To his charge that attempt is made to fix the responsibility only on the quarter, on behalf of the Government I would say that that is not correct. It has been said that all facts have not been given. It has been said that a lady Janata candidate Dr. Jagat Mohini sustained serious fractures. Obviously it will not be the Janata workers who will cause a serious fracture on Dr. Jagat Mohini, their own candidate. Now, regarding the allegations and so on, this is a matter for investigation. He said that no reference is made to the Awantipur incident. I have said in my statement as follows:

> At one place, Awantipur, an incident of arson also occurred which is under investigation.

So, it has been stated by me that this is being investigated.

Then it has been said that Mrs. Sheikh Abdullah has joined issue with

[Shri Shanti Bhushan]

the Home Minister. It is always open to Begum Abdullah to join issue with the Home Minister who would be very happy with it. But then, as I said, all these matters will be investigated and conclusions will be arrived at. Whoever is guilty will be punished under the law. Action will be taken against those persons.

The hon. Member quoted from the *Hindustan Times* of 21st June with reference to Article 370. He said that it was only when a member of Parliament of Janata party, Mr. Subramaniam Swamy, asked for abrogation that this campaign in respect of Article 370 was built up; but what I submit with great respect is this. May be a single member or may be one belonging to Janata party might have raised this. But there is democracy in this country and every single member is free to express his views. But it is not the individual member's view, however high or low he may be, which constitutes the policy of the government. It is for the spokesmen of the Government to spell out this policy in regard to Article 370. This has been very clearly spelt out by Cabinet Ministers including even the Home Minister and the Prime Minister. And if that has been done then in that case there was no justification to make a reference to a statement, made, prior to that, by one Member of Parliament even though belonging to the Janata party. If subsequent to that an authorised statement at the level of the Prime Minister has been made then in that case there was no justification to build up any campaign on the basis of Article 370 and to pollute the atmosphere in Jammu and Kashmir on that basis and try to ruffle the feelings of the people.

It was also said by the hon. Member: Is it that only when there would be some trouble between the Janata party members *inter se* than only the Government of India protect the lives and if there is trouble between one party and another party then the Government of India will not be in the picture at all? I would like to submit that the hon. Member has misunderstood what I said. Earlier a question had been posed to me. Is it that the present political situation in Jammu and Kashmir has arisen because of some trouble on account of distribution of tickets? In that connection I said that that was not a fact because then there would be trouble between the different sections of Janata party.

Sir, it was said: Why is it that the Government of India is not accountable if some clashes occur? So far as the constitutional position is concerned I would like, Sir, through you to remind the hon. Member that when the legislative assembly of J & K was dissolved of course, later the legislative assemblies in other States were dissolved too—there was a constitutional distinction between the two cases. So far as other States were concerned, Presidents rule had been imposed under Article 356 of the Constitution. So far as J & K is concerned, President's rule was never imposed on J&K. It was dissolution by the Governor himself and it was the Governor's rule which has been imposed on Jammu and Kashmir so that Jammu and Kashmir is not being administered by the Government of India, Government of India, therefore, is not responsible for the running of the government in Jammu and Kashmir. At the same time I am saying, whenever any State is being run and the law and order situation is the responsibility of the State Government whatever assistance is required from the Government of India, the Government of India is always willing to give that assistance and my statement said that the Government of India have always been giving that assistance to the Jammu and Kashmir government for solving these problems which have arisen so that an atmosphere of peace may prevail and a completely free and fair election may be the outcome.

SHRI VASANT SATHE: Under whose authority does the Governor function?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The provision is different. That difference in the provision was discussed when the Jammu and Kashmir Assembly was dissolved and the Governor's rule came. There is provision for Governor's rule. It is not the Government of India which runs the administration there unlike in the other States. That is the constitutional position.

SHRI VASANT SATHE: As far as law and order is concerned, what is the sanction of Governor except you?

SHRI SHANTI BHUSHAN: If he does not recognise the constitutional position but recognises the extra-constitutional position then the position is different. So far as we on our side are concerned, we only recognise the Constitution and Constitutional authorities, not extra-Constitutional things and extra-Constitutional centres of power.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): We are asking who appoints the Governor and who gives him the authority.

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Governor is appointed by Government. Even the Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the Government, even the Election Commissioner is appointed by the Government. But does it mean that they cease to be independent authorities just because they are appointed by the Government and therefore the Government will be responsible for whatever judgement may be given by the Chief Justice of the High Court or the Chief Justice of the Supreme Court or the Government of India would be responsible for the discharge of the Election Commission's functions? Therefore, what I pointed out was that so far as the postponement of the dates of the poll was concerned, the Government does not come into the picture except in the sense, in the theoretical sense, just as any individual citizen, any individual member of the political party, any political party can approach the Election Commission and draw the attention of the Election Commission to a certain fact, it is open to anybody, it is even open to the Government of Jammu and Kashmir to approach the Election Commission. But as for the reference which has been made by the hon. Member relying upon certain press reports as if the Home Minister has taken a decision that the Elections in Jammu and Kashmir must be postponed, I wish to make a strong statement on behalf of the Government that this is entirely untrue. The Home Minister has not taken any decision, namely, that the elections in Jammu and Kashmir would be postponed. In fact--I would like to say ultimately that we are extremely hopeful that the elections in Jammu and Kashmir would be held on time (*interruption*) naturally, because I would not like to make a definite statement. The hon. Member wants an assurance from the Government that the elections would be held on time. May I ask the hon. Member, can the Government arrogate to itself the functioning of an independent Constitutional authority, namely, the Election Commission? The law is quite clear on that point. It is only for the Election Commission to fix the dates of the election and to postpone the dates of the election. Who is the Government to give an assurance to anybody or to this House on behalf of the Election Commission? It would be highly improper, I submit, for the Government to extend any kind of assurance.. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: You kindly give an assurance only on your behalf. Let the Election Commission take care of itself and give us an assurance that you will not recommend to the Election Commission for the postponement, as there is a lurking feeling about the Home Minister's mind.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Since my esteemed Colleague is present here,

[Shri Shanti Bhushan]

on my own behalf, on behalf of my esteemed colleague and on behalf of the Government, I give an assurance that the Government would not approach the Election Commission for the postponement of the election. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: I hope that that will include the Governor also. I hope that will include Mr. L. K. Jha.

SHRI SHANTI BHUSHAN: No, that is for the Governor to do (*Interruptions*). I am not suggesting that the Governor will approach. I should not be taken in that sense. I am speaking only on behalf of the Government of India. I cannot speak on anybody else's behalf because there might have been occasions when somebody might have tried to speak on behalf of everybody. But so far as we are concerned, we cannot speak on behalf of others. I am making a statement on behalf of the Government of India that the Government of India does not want the postponement of elections; the Government of India will not approach Election Commission for the postponement of the elections and if I may be allowed to say so, I am very hopeful that the election will take place on time. But I am not a sooth-sayer and I do not claim to be an expert in the art of fortune telling, etc., because that is the function of the Election Commission. The law gives the Election Commission all the responsibility to arrange for free and fair election and if at a certain stage some such circumstances arise in which the Election Commission thinks that free and fair election cannot take place, it will be the responsibility of the Election Commission to take an appropriate decision in that reg. But as things stand at the moment, well we are very hopeful that the election will take place on time.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Can the Governor approach the Election Commission?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Yes, anybody can approach. Mr. Kamath can approach, Mr. Sathe can approach.... (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: Mr. Law Minister, don't fall into the trap of Mr. Kamath. He is an experienced parliamentarian.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I appreciate the attitude of the members of a party which has been losing election after election that they may not be anxious to face another election very soon. Therefore, it may be quite open to the hon. member, Mr. Sathe, to approach the Election Commission. Nobody can come in his way.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mankar may continue his speech on the budget.

14.47 hrs.

GENERAL BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री लक्ष्मण राव मानकर उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण उद्योगों की बात कर रहा हूं । केन्द्रीय सरकार ने खादी ग्रामोद्योग मण्डल के लिए भी इसमें 35 करोड़ का प्रावधान किया है । वह प्रावधान कमीशन का है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं । ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज है, उनमें जो दिक्कतें है, वह शासन के ध्यान में लानी आवश्यक है ।

मैं अनेक वर्षों से इस देश में जो भ्रष्टाचार फैला है, उसका कारण तो अनेक प्रकार के नियन्त्रण है । आज भी गांव का कोई तरुण कोई इण्डस्ट्री खोलने की बात करता है तो उसके लिए इतने नियन्त्रण है, इतने परमिट और लाइसेंस के चक्कर में उसे जाना पड़ता है कि वह उस कार्य को कर नहीं सकता है । इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग करने वाले हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज है या फारेस्ट बेस्ड इण्डस्ट्रीज है, उनको इन नियन्त्रणों से निकालना होगा, तभी गांव का तरुण वहां पर आसानी से ठीक प्रकार से अपना उद्योग प्रस्तावित कर सकेगा, इसकी छानबीन करें ।

इस तरह से जो नया सुझाव, नई दिशा और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग डालने की बात चल रही है, उसके लिये जितने निराकरण कम होंगे उतना ही भ्रष्टाचार दूर होगा। इस बजट में भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की गई है, यह जनता पार्टी ने बनाया है।

बीड़ी के ऊपर टैक्स लगाया गया है। इस उद्योग का विचार कर के क्या यह टैक्स लगाया गया है। इस उद्योग का ग्रामीण क्षेत्रों में कौन करता है। यह हाथ से चलने वाला उद्योग है, यदि बड़ी इण्डस्ट्री के साथ इसको जोड़ दिया गया तो हाथ से काम करने वाले गरीब लोगों, खेड़े में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों को बड़ा नुकसान होगा। इस ग्रामोद्योग के धंधे पर टैक्स लगा कर गरीब लोगों को धंधे से वंचित किया गया है। मैं सुझाव दूंगा कि इस बारे में फिर से विचार हो।

मैं आज की स्थिति से आपको अवगत कराता हूं। अनेक प्रान्तों में जहां बीड़ी का उद्योग चल रहा है आज भी बीड़ी मजदूरों को 2, 2 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। इस उद्योग को नियन्त्रण में लाने के लिये प्रान्तीय सरकारों ने नियम बनाये हैं, उसमें फैक्टरी एक्ट का कानून लगा दिया है। इतने नियम लगा दिये गये हैं कि गांव में सामान्य मजदूर को जो काम मिलता था, उससे वह वंचित हो गया है। इस तरह से बीड़ी उद्योग का समुचित ढंग से विचार करके, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हरिजन और गरीब लोग काम करते हैं, वह लोग काम से वंचित न हों इस तरह से उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खंडसारी का उद्योग भी है, जिसमें काफी लोगों को काम मिलता है। लेकिन उसके साथ शक्कर कारखानों के समान व्यवहार किया गया है। खंडसारी पर एक्साइज ड्यूटी हर साल बढ़ाई जाती रही है। अप्रैल, 1974 तक उस पर लैवी 1180 रुपये प्रति टन थी। 1 मई, 1974 से उसको बढ़ा कर 2360 रुपये प्रति टन कर दिया गया और फिर 1 मार्च, 1975 को वह लैवी 5900 रुपये प्रति टन कर दी गई। मेरा निवेदन यह है कि अगर इस ग्राम उद्योग पर, जो एक लेबर-इनटेन्सिव इण्डस्ट्री है, इस तरह लैवी बढ़ाते चले जायेंगे, तो यह उद्योग कैसे चलेगा? इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण उद्योगों पर लैवी इस तरह से न बढ़ाई जाये, ताकि वे उद्योग जिन्दा रह सकें और उनके द्वारा लोगों को काम मिल सके। इसके अतिरिक्त खंडसारी के कारखाने ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की शर्त लगानी चाहिए; ये कारखाने केवल शहरों में नहीं खुलने चाहिएं।

लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में जो प्रावीजन किया गया है, वह सफिशेंट है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में जो कमियां और गलतियां हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में प्रयास करे।

एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम इस देश की नेशनल इनकम का 50 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में इस उद्योग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और किसान को अपनी उपज की जो कीमत मिलनी चाहिए, वह उसको नहीं मिली है। एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन ने धान का भाव 74 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। क्या किसान इस भाव पर धान पैदा कर सकता है? सब चीजों के भाव बढ़ने के बावजूद किसान अपनी उपज कन्ज्यूमर को सस्ते भाव पर दे, यह सम्भव नहीं है। खाद पर लैवी बढ़ा दी गई है, उसके दाम दुगने हो गये हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि सामान्य आदमी को चीजें ठीक दाम पर मिलें। लेकिन जब तक किसान को अपनी उपज का ठीक दाम नहीं मिलेगा, तब तक वह उत्पादन नहीं कर सकेगा। खाद और इनसेक्टीसाइड

[श्री लक्ष्मण राव मांकर]

आदि इनपुट्स के भाव बहुत बढ़ गये हैं। जिला परिषदें बीज 125 रुपये में खरीदते हैं और 250 रुपये में बेचती हैं। किसान के उपयोग की चीजों के भाव बहुत बढ़ गये हैं, लेकिन किसान को ठीक दाम नहीं मिलते हैं। फिर कहते हैं कि हम किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह किसान ऊपर नहीं उठ सकेगा।

इण्डस्ट्रीज के बारे में हम विचार करते हैं कि उनका खर्चा लगा कर उनकी प्राडक्ट्स के दाम उन्हें ठीक मिलें। किसान के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? इंडस्ट्रीज को कई प्रकार की कनसेशन्ज दी जाती हैं, उनको सीड मनी मिलता है और बैकवर्ड एरिया में तो उन्हें और भी सहूलियतें दी जाती हैं। लेकिन इस देश के पांच एकड़ से नीचे के 60 परसेंट किसानों को क्या कोई राहत दी गई है? स्माल फार्मस स्कीम इसमें दी गई है। पिछले वक्त में, कांग्रेस के राज में ही यह शुरू हुई है, कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी हुआ नहीं। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। एक करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। उसके केवल 35 लाख रुपया खर्च हो सका। बाकी सब वापस आ गया। तो आखिर यह एजुकेशन का मामला है। यह प्रशासन जो बिगड़ चुका है उसको ओवर अप करने की आवश्यकता है। हम ग्रामोद्योग की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे जो भी कहें लेकिन प्रशासन को ठीक प्रकार से सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो पैसा कितना ही दे दें उस का उपयोग नहीं होगा। इसलिए प्रशासन को ठीक करने की दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है।

निर्यात की बात आती है। लेकिन निर्यात किस चीज का किया? खली का। इस देश में जानवर जो खेती के काम में आते हैं, जिन से दूध मिलता है उनके खाने की जो चीज है उस खली का निर्यात 141 करोड़ का आपने किया। उसका नतीजा यहां पर क्या हुआ इसको भी आपने देखा? किसान जानवरों को जो चारा देते हैं, फाडर जिसे कोंडा कहते हैं उसकी क्या हालत बनी? धान के भाव 74 रुपए तब किए और वह जो भूसा है उस भूसे की कीमत 100 रुपये हो गई। तो किसान जानवरों को खिलाएगा क्या? खली जो आपने बाहर भेज दी तो उसका भाव यहां पर ढाई सौ और 300 रुपये हो गया। तो इसमें कोई तारतम्य रखने की बात आप सोचेंगे या नहीं?

जीवन के लिए आवश्यक चीजें जो हैं चाहे वह खेती के लिए हों या सामान्य आदमी के लिए हों, मेरा आग्रह है कि नीति निर्धारण इस तरह से करें कि इस प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को बाहर नहीं भेजा जायेगा। इनको आप यहां पर इस्तेमाल के लिए छोड़ देंगे। इस दिशा में कुछ परिवर्तन आप को अपनी नीति में करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि सरकार इसके ऊपर सोचे।

किसानों को दिए जाने वाले लोन के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। किसानों को जो डेवलपमेंट लोन देते हैं वह कैसे देते हैं। 18 रुपये, 20 रुपये उस पर ब्याज पड़ता है और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो लोन उनको दिया जाता है, मान लीजिए कुआं खोदने के लिए लोन इस साल दिया। कुआं खुद नहीं पाया। लेकिन दूसरे साल से उसकी किस्त और ब्याज के पैसे वसूल करने लग गए जबकि उत्पादन उससे निकला ही नहीं। मेरा यह कहना है कि बड़े बड़े किसानों की बात आप चाहे छोड़ दीजिए लेकिन जो मार्जिनल किसान

हैं 6 एकड़ से नीचे के, ढाई ढाई तीन तीन एकड़ के किसान, इनको विकास लोन चाहे वह एलेक्ट्रिक पम्प के लिए हो, कुआं खोदने के लिए हो, जमीन से पानी निकालने के लिए हो या लिफ्ट इरीगेशन के लिए हो, यह लोन उस को बिना ब्याज के तीन साल तक के लिए मिलना चाहिए, तीन साल के बाद ब्याज और किस्त शुरू हो। जैसे इण्डस्ट्री में आपने कहा कि चार प्रतिशत या 6 प्रतिशत की दर से दिया जाये, कुछ सहूलियत उसको दी जाये, जो बैकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्री खोलते हैं वहां कुछ सहूलियत दी जाये, वैसे ही जो इस देश का अत्यन्त पीड़ित और गरीब किसान है पांच छः एकड़ से नीचे का, जो अपना जीवन भी नहीं चला सकता उसको प्रगति करने के लिए कुछ राहत आप देने वाले हैं या नहीं ? अभी तक तो दिया नहीं। उल्टे और बोझा उसके ऊपर पड़ा। उसको उसके उत्पादन की कीमत नहीं मिली, और कोई सहूलियत उसके लिए हमने उपलब्ध नहीं की जिसका परिणाम यह है कि इस देश का वह 80 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबा हुआ है। आज आप उसको कितना ही और कर्जा देने की कोशिश करें, उसको लेने की कैपेसिटी ही उसके अन्दर नहीं है। इसलिए पहले तो उस की कीमत ठीक तरह से तय करने की आवश्यकता होगी और फिर उसको और सहूलियतें भी देने की आवश्यकता होगी। उसको विकास लोन आप दें और मैं तो यह कहता हूं कि जैसे एक व्यापारी आदमी को कमीन कैश लोन देते हैं वैसे ही किसान को भी क्यों नहीं देते ? उसको भी एक इंडस्ट्री मान कर उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे अगर वह किसी बैंक में जाय तो जो उसकी लिमिट हो उसके अनुसार वह कर्जा ले और अपनी खेती में लगाए। इस दिशा में सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करने के बारे में सोचे।

कुछ बातें अच्छी आई हैं। ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में, बेकारी दूर करने की दिशा में और खेती का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। यह प्रयास हम ठीक प्रकार से करें तो सफल हो सकते हैं। जो विकास की दर विभिन्न योजनाओं के दौरान निश्चित की गई थी, क्या वह कभी पूरी हुई ? इसलिये मेरा कहना है कि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक इस देश की महंगाई, बेकारी—ये सारी समस्यायें हल नहीं होंगी, इन्फलेशन कम नहीं होगा। इसलिये उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जो भी नैसर्गिक साधन हमारे पास मौजूद हैं, उनका पूरा उपयोग करें, तब हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगी।

15.4 hrs.

मेरे मित्र इस बजट के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हमारे अर्थ मन्त्री जी ने इस बजट में जो दिशा दी है, उन अर्थ-संकल्पों का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **मनोहर लाल** (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं जनता सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के इतिहास में 1977 का वर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। पिछले तीस सालों में हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस शासन के वित्त मंत्री ही अब तक इस सदन में बजट पेश करते आये हैं—लेकिन यह पहला मौका है जब जनता सरकार के वित्त मंत्री का बजट इस देश के सामने आया है। बजट एक ऐसा साधन होता है, जिससे अन्दाज लगाया जाता है कि उस देश की सरकार की मंशा क्या है, सरकार उस देश के अन्दर रहने वाली आम जनता के साथ क्या करना चाहती है, उनके लिये क्या करने जा रही है।

अभी थोड़ी देर पहले मैं काल-एटेन्शन पर श्री साठे साहब के सवाल को सुन रहा था जो जम्मू-काश्मीर के बारे में था। मैं उनसे संक्षेप में ही पूछना चाहता हूं—25 जून,

[श्री मनोहर लाल]

1975 को जब दिल्ली के अन्दर प्रजातन्त्र रूपी द्रौपदी का चीर-हरण किया गया था, उस समय साठे साहब और उन के दूसरे साथी कहां थे। एमर्जेंसी के दौरान जब भारत के महान नेताओं को पकड़ कर जेल में बन्द किया जा रहा था, इस संसद के लिए चुने हुए सदस्यों को बन्द किया जा रहा था, जब देश में कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम लागू की गई थी, उस समय कांग्रेस के दोस्त साठे साहब कहां थे। एल०आई०सी० के साथ जो एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, जब उसको तोड़ा गया, उस समय कांग्रेस के दोस्त कहां थे, उस समय उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला? ढाई लाख लोगों को उस समय जेल में डाल दिया गया था, डी०आई०आर० और मीसा के तहत बन्द कर दिया गया था। देश के संविधान को ताक पर रख कर, उसको तोड़-मरोड़ कर हिन्दुस्तान की जनता पर तानाशाही का शासन लाद दिया गया था—उस समय हमारे ये कांग्रेसी दोस्त जो आज प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे है, कहां थे?

उपाध्यक्ष जी, जनता पार्टी की सरकार को बने हुए अभी तीन महीने हुए है—अभी से ये कांग्रेसी दोस्त परेशान होने लगे है और हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया है। 30 साल तक यह देश आपके शासन में रहा—इस काल में देश में बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही बढ़ी—इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर इस सवाल का जवाब पूछें तो आप इस बात को मानेंगे कि इस सारे शासन काल में—सिर्फ डेढ़ साल के पीरियड को छोड़ कर जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री रहे, सन् 1947 से लेकर अब से तीन महीने पहले तक इस देश पर किसने शासन किया—नेहरू परिवार के लोगों का शासन रहा। उन्होंने जिस तरह से चाहा देश का सत्यानाश किया—इसके लिए इसदेश की जनता, इस देश का नौजवान कभी माफ नहीं करेगा। आज जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, एमर्जेंसी समाप्त होने के बाद, जनता यदि आजादी की सांस ले रही है, उसको पता लग रहा है कि उसके क्या मौलिक अधिकार हैं और हमारी सरकार जब यह आश्वासन दे रही है कि हम जनता के मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेंगे, जिस तरह से इन लोगों ने छीना था, तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये सारी बातें जनता पार्टी की देन हैं। जनता के अन्दर एक विश्वास की भावना पैदा हो रही है, उसके सामने एक उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ने लगा है।

15.02 hrs.

[SHRI SONI SINGH PATIL *in the Chair*]

जहां तक इस बजट का सवाल है—यह बजट हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। पहली बार आज महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रख कर यह बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है इस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं—लोकनायक जय प्रकाश नारायण को और हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता को जिसने बिना किसी खून-खराबे के इस कांग्रेस सरकार को हटा दिया, जिस के लिए न केवल हिन्दुस्तान की जनता, बल्कि दुनिया के लोग यह समझते थे कि इन्दिरा गांधी को हटाना बिलकुल नामुमकिन है। इन्दिरा गांधी के बाद संजय गांधी प्रधान मंत्री बनेंगे, हम सब लोग यही समझने लगे थे लेकिन एक बिलकुल अनहोनी चीज हुई और लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिस तरह से हिन्दुस्तान के करोड़ों करोड़ों नौजवान लोगों ने कांग्रेस शासन को उखाड़ फैंका है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के लाखों नौजवान लोगों ने संगठित होकर इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिहाद बोल दिया और उसके बाद हालत यह हो गई है कि अब कांग्रेस के लोगों की भी जबान खुल गई हैं और वे जनता सरकार पर तरह-तरह के आक्षेप लगाते हैं

श्री मनोहर लाल (कानपुर)—जारी

और उसे बदनाम करने की बातें करते हैं। आज जो वे ऐसी बातें करते हैं, मैं उन से कहूंगा कि जरा वे अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि पिछले सालों में उन्होंने क्या क्या किया है जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा ।

सभापति जी, अब मैं बजट पर आता हूं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह स्वागत के काबिल है और हम उसका स्वागत इस माइने में करते है कि जनता पार्टी ने जिन परिस्थितियों में बजट तैयार किया है और ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी जो कुछ उसने जनता को दिया है, वह पहली बार ही हुआ है। इस बजट में काश्तकारों के लिए तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। इस में ग्राम विकास के लिए, लिंक रोड्स से गांवों को जोड़ने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था के लिये प्रोविजन किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो परिस्थितियां जनता सरकार के सामने थीं, उनमें यह बजट स्वागत योग्य है ।

इस बजट में वित्त मंत्री महोदय ने 72 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है जब कि पहले 306 करोड़ रुपए घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से आप देखें कि पिछले तीस सालों में जो बजट कांग्रेस सरकार प्रस्तुत करती रही है, उससे कहीं अच्छा है और आज ये लोग हम से कहते है कि हिन्दुस्तान के अन्दर बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज यह हम से कहते है कि महंगाई बढ़ गई है। यह सही है कि आज लोगों को रोजी, रोटी और मकान की आवश्यकता है और आज नौजवानों को नौकरी की तलाश है। 30 साल तक हुकूमत करने के बाद भी कांग्रेस सरकार लोगों के लिए रोजी, रोटी और कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाई और आज यह कहते हैं कि जनता सरकार इन तीन महीनों के अन्दर इन सब की व्यवस्था लोगों के लिए कर दे। यह बिल्कुल असंभव बात है। जो भी व्यवस्था इस बजट के अन्दर इन चीजों के लिए की गई है, वह परिस्थितियों को देखते हुए, उचित ही है क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ने जैसा बताया है कि बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हो जाती है और जो भी आंकड़े हैं वे कांग्रेस सरकार के जमाने में एकत्रित किये गये थे और उस समय वे ही कुर्सी पर थे। उन आंकड़ों में थोड़ी सी रद्दोबदल करके बजट रखा गया है लेकिन जो भी बजट रखा गया है वह वास्तव में आम जनता का ही बजट कहा जाएगा ।

बेकारी और बेरोजगारी के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह सही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो जन-शक्ति है, वह काफ़ी बेकार है। आज आप देखें कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो बी०ए०, एम०ए० और एम०एस०सी० तथा आई०टी० आई० की ट्रेनिंग के डिप्लोमा और डिग्री लेने के बाद भी इधर उधर बेकार मारे मारे फिर रहे है, लेकिन इसके लिए अगर कोई जम्मेदार है तो वह कांग्रेस सरकार ही है जिसने 30 सालों तक देश का शासन चलाया है। जन-शक्ति को जो जंग लगा है, उस के जिम्मेदार कांग्रेस के लोग ही हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से और अपनी सरकार से पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो बेरोजगार हैं, उन नौजवानों को रोजगार दिया जाए और उसके लिए मेरा सुझाव यह है और मैंने प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी लिख कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं, उन में से 10 प्रतिशत इस तरह के लोगों को कम्पलसरीली दी जाएं, जो कि पढ़े लिखे हैं और बेकार हैं ।

[श्री मनोहर लाल]

आजकल लोगों को काम देने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की अपनी मर्जी पर है। अगर उन पर वह जिम्मेदारी डाल दी जाये कि दस परसेंट लोगों को रोजगार देने की वह व्यवस्था करे तो उन्हें लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा। इस तरह हम समझते हैं कि बहुत से बेकार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। ऐसी व्यवस्था जनता पार्टी की सरकार को करनी चाहिए। यह व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। इस बजट के द्वारा अब सरकार को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में यह व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी तरफ खेती की भी काफी तरक्की की जाए, खेती को बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ तब से हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। उनका ध्यान हमेशा बड़े बड़े उद्योग धंधों की तरफ रहा। कभी उन्होंने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने खेती की तरफ ध्यान दिया होता तो आज यह समस्या न होती। हमारी बहुत सारी समस्याएं खेती की उपेक्षा करने के कारण खड़ी हुई है। नेहरू जी ने सदा बड़े बड़े उद्योग धंधों की तरफ ध्यान दिया, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर वे इनकी तरफ ध्यान देते तो हम पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकते है कि यह बेकारी की समस्या हमारे देश में न होती। बेकारी के साथ इसका परिणाम यह भी हुआ कि खेती पर भार बढ़ गया और यह भार बढ़ता ही जा रहा है। जहां हमें बेकारी को दूर करना है वहां हमें खेती पर पड़े भार को भी कम करना है। भूमि पर भार को कम करके हम खेती का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम खेती पर भार को कम नहीं करेंगे तो हम कोई भी समस्या हल नहीं कर सकेंगे। देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या के साथ जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो उतनी ही रहेगी। मिसाल के तौर पर आज से 6 साल पहले जहां एक परिवार में दस लोग थे आज उसी परिवार में पन्द्रह लोग हो गये। इससे खेती पर भार बढ़ रहा है और पैदावार बढ़ नहीं रही है। खेती पर जो भार बढ़ रहा है, इसको कम किया जाये। खेती पर निर्भर आबादी को हमें छोटे-छोटे उद्योग धंधों में लगाना चाहिए। इसके लिए हमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम—जैसा कि पिछली सरकार ने किया—नसबन्दी करके लोगों को खत्म करना शुरू कर दें हमें उन्हें छोटे-छोटे धंधों में लगाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट में छोटे उद्योग धंधों के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर हम छोटे धंधों को बढ़ा सके तो इससे खेती पर भार कम होगा और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि खेती पर से भार कम करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए छोटे छोटे धंधों को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में दस परसेंट लोगों के रोजगार की व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा जनता पार्टी को शिक्षा में भी मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए। कांग्रेस सरकार द्वारा हमेशा कहा गया और बड़े बड़े नारे दिये गये कि हम शिक्षा में परिवर्तन करेंगे लेकिन तीस साल के बाद भी आज तक वे शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं ला सके। सन् 70–71 में नारा दिया गया कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम गरीबों को मकान देंगे, उन्हें जमीन देंगे लेकिन ये सब नारे ही सिद्ध होकर रह गये। इन्होंने इन पर कोई काम करके नहीं दिखाया। अगर कांग्रेस इन मसलों पर कुछ काम करके दिखाती तो आज जो इतनी

श्री मनोहर लाल (कानपुर)—जारी

सम याएं देश के सामने हैं वे न होतीं। आज गांवों में समस्यायें हैं, बेरोजगारी की समस्या है । हमें गांवों में तरक्की करनी है, बेरोजगारी की समस्या हल करनी है । कांग्रेस सरकार तीस साल से बराबर मुद्रास्फीति का सहारा लेती रही । अगर यह न होता तो हमारा मुल्क इस स्थिति में न होता। पिछले सालों में बराबर देश में मुद्रा-प्रसार बढ़ता रहा है । इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है । इस मुद्रास्फीति को, मुद्राप्रसार को रोकने के लिए हमारी सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे क्योंकि पिछले तीस सालों में इस मुद्रास्फीति को एक साधन के रूप में सरकार ने बराबर अपने सामने रखा है । मुद्रास्फीति कोई समस्या नहीं होती है । यह तो एक प्रवृत्ति होती है । सही अर्थ नीति अपना कर इसको रोका जा सकता है, मुद्रा प्रसार पर काबू पाया जा सकता है । मुद्रा स्फीति और विकास की दर में बहुत फर्क होगा तो मुद्रा स्फीति अपना भयंकर रूप दिखाए बिना नहीं रहेगी। आपको काले धन पर भी काबू पाना होगा। इससे भी मुद्रा स्फीति बढ़ती है । किसी भी देश की उन्नति के लिए उत्पादन उसका बढ़ना चाहिए । इसके वास्ते यह जरूरी है कि मुद्रा स्फीति पर भी रोक लगाई जाए । मुद्रा प्रसार और विकास की दर इन दोनों में आपको चाहिए कि आप वैधानिक रिश्ता कायम करें, वैधानिक एक अनुपात निर्धारित करें । मूल्यों को स्थिर रखने के लिए और स्थिर रखने के लिए ही नहीं बल्कि उनको नीचे लाने के लिए भी आप को चाहिए कि आप उचित कदम उठायें । मेरा यह पक्का विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम मूल्यों को स्थिर ही नहीं रख सकेंगे बल्कि उन में गिरावट भी आएगी ।

चूंकि आप चाहते हैं कि मैं समाप्त करूं मैं इतना ही अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेसी मित्र जो अब बोलें कम से कम वे अपने दिल पर हाथ रख कर बोलें और सच सच बात कहें । जिस तरह की बातें वे आज कर रहे हैं क्या उस समय कह सकते थे जब कांग्रेस का शासन था ? उनके शासन काल में बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार , रोजी रोटी की समस्या आदि कितनी बढ़ी थी ? आज वे लोग प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं। क्या इसके लिए जनता सरकार जिम्मेदार है, यह जो सभी समस्यायें खड़ी है क्या ये जनता सरकार द्वारा खड़ी की गई है । वे अपने दिल पर हाथ रख कर सोचेंगे तो वे पायेंगे कि ये उनके शासन की देन है । मैं आशा करता हूं कि जनता ने हमारी पार्टी में जो विश्वास व्यक्त किया है उसके इस विश्वास को झुठलाया नहीं जाएगा और इस काम में जो नीतियां हम निर्धारित करेंगे और जो जनता की भलाई के लिए होंगी, उसके उत्थान के लिए होंगी, काश्तकारों की तरक्की के लिए होंगी, गांवों की तरक्की के लिए होंगी, उन में कांग्रेस दोस्त हमारा साथ देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं ।

SHRI B. C. KAMLE (Bombay South-Central): Mr. Chairman, Sir, while it is true that the budget proposals have been framed by the hon. Finance Minister with a great deal of difficulty and that he had not sufficient time for consultation, still, I submit that these proposals must be considered from the point of view of

[Shri B. C. Kamble]

the conditions of the Indian masses are concerned, who constitute the Republic of India.

Now, if we consider these proposals, we have also to consider the slogans which were raised by the Congress Party as well as the Janata Party for getting votes. The Congress Party had raised the slogan of 'garibi hatao' and the Janata Party had raised the slogan of 'total revolution.' The Congress Party was punished by the electorate for the simple reason that they had declared that the poverty would be removed—whatever the analysis of Congress party for its defeat, the prominent reason is that the Congress Party had failed to redeem the pledge about removing the poverty.

Therefore, the Janata Party must also take a lesson and see whether the slogan of 'sampoorna kranti' materialises. Now, looking to the budget proposals, it appears that there is only a change of emphasis from industrial to agricultural bias. So far as agriculture is concerned, again whether the Janata Party will be able to redeem the pledge is also a doubtful question.

Now I will go into its details. But before I do that, I would like the hon. Finance Minister to consider preliminarily two thinks: one is whether our monetary system has been stabilised. That is really the crux of the problem so far as rising prices are concerned. Every time every Finance Minister comes before the House, it appears as if he is a helpless witness and he has no remedy so far as rising prices are concerned. To me it appears that the real causes are in the monetary system. We should examine whether our monetary system has been stabilised, whether the Reserve Bank is functioning in accordance with the provisions of that particular Act, whether the assets and liabilities of the Issue Department of the Reserve Bank are co-extensive. Unless these things are examined in detail, I am quite sure, the problem of rising prices, under which the entire masses are being ground, cannot be solved. Who is responsible for excesses in the monetary system? We must fix the responsibility somewhere. Is it that the Board of Directors of the Reserve Bank of India is helpless? Is it that the Government is helpless? Who is to be blamed? Who is responsible? These matters must be gone into in great detail. It appears to me that our monetary system, inherited from the Congress Government, is a diseased system. It must be given some tonic, so that its health is improved. Unless that is done, I am quite sure, whatever may be the assurances that may be given in the budget proposals, they will be of no consequence at all.

Then, there are certain Constitutional obligations which the Finance Minister should take itno consideration. I refer particularly to articles 268, 269 and 270 of the Constitution of India: these articles relate to collection of taxes and distribution of taxes between the Union and the States. Then I refer to article 340 which refers to the grants to be given so far as backward classes are concerned. I find no mention whatsoever so far as compliance with these articles is concerned. I would also request the hon. Finance Minister to give us more information about the details of defence expenditure. The Janata Party has a certain social policy and a certain economic policy. These should be spelt out. What is the social policy? What is the kind of society towards which the Janata Party wants to take the country? What is the economic policy? Whatever policy the Congress pursued, whether a socialistic policy, or a policy in favour of the public sector, but what happened ultimately was that the poor were made poorer; that was the result. This should be taken as a warning by the Janata Party, that merely changing the emphasis from industry to agriculture is

not going to be sufficient at all. The Directive Principles of the Constitution must always be borne in mind. Of course, the Directive Principles are not enforceable in a court of law; that is correct. But they are enforceable in this court of Parliament. The Directive Principles are in the nature of instruments of intructions. Just as formerly there were certain instructions given to the Governors-General, so also these are instructions given by the Constituent Assembly to run the Government accordingly, whatever Government may be there. Therefore, I am not satisfied with the Ceiling Laws.

They are talking about land reforms. How much land will one get, even if the Ceiling Laws are implemented? It would be hardly one acre per head! And the provision that has been made for the Backward Classes comes to only fifty paise per head. Then how can the Backward Classes be improved? More than 50 per cent of the people are absolutely without any kind of land and they have no means of livelihood at all. Therefore, according to the Directive Principles, what is required is that every citizen, man and women, must be given adequate means—not only 'means' but 'adequate means'—of livelihood. Unless the economic system is pursued in that direction, I am quite sure that the masses will remain always in utter poverty. If this hapepns, I am afraid and I am sorry that India will not be a civilised nation at all. If India is to be a civilised nation, if India is not to continue to be a poor nation (as India is now sitting among a group of developing countries which are asking aid from the rich countries) and since the fate of India is the fate of the poor people of this country in relation to the propertied classes, I submit that there should be a direction to see that our men and women have adequate means of livelihood.

Now, I am very sorry that the Finance Minister has stated in his speech that so far as the plan for the Backward is concerned, it is the responsibility of the States. The State Governments say that it is the responsibility of the Zilla Parishads and the Zila Parishads say that it is the responsibility of the Gram Panchayats. This is how the responsibility with regard to the Backward Classes is being shunted from the Centre to the State, from the State to the District and from the District to the Village Panchayats, ultimately throwing them to the wolves. The provision for the Backward Classes includes the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and there are other categories of people also. Therefore my submission is that this Government should shoulder the responsibility as per the Constitution. If this responsibility is not shouldered by this Government, it will be a breach of the Constitution.

Now I come to another point. The defence expenditure is increasing enormously. In the year 1950 it was Rs. 260 crores and today the Defence expenditure has risen to Rs. 2646 crores, rising in porportion to the rise in the Budget. Even though there is a certain amount of cut—and I welcome that cut—there should be a still further cut because this is going to be a budget within a budget. Just as the Railway Budget is a budget within a budget, the Defence budget is going to be a budget within a budget. Though our frontiers must be well guarded, this Defence amount which is rising out of all proportions must be checked.

Then, I come to subsidy. The subsidy is of the order of Rs. 460 crores. Is there any relief given to the consumers? Let the subsidy be given in a manner by which the consumers are benefited.

Finally, I come to the *per capita* gross national product. India's *per capita* gross national product is so low that the USA's is 50 times greater and Japan's is 30 times higher. Why

[Shri B. C. Kamble]

is our *per capita* gross national income so low? It is for the simple reason that the relationship of the propertied classes and the propertyless classes is of disburst and so wide. This relationship has continued even from the time of the foreign rule, the same relationship is continuing. To-day there is no change whatsoever in that relationship. Unless there is a change, I am quite sure the *per capita* national gross product will not rise.

Finally, I make a few suggestions. My first suggestion is that so far as the food subsidy is concerned, it should be given to the rural masses. Secondly, as I submitted, there should be a further cut in defence expenditure. My third suggestion is that this budget should be divided into certain sectors and there should be one sector with regard to poorer people. They are nearly 30 crores. My fourth suggestion is that drinking water should be an item of first charge. These are the suggestions for the consideration of the Finance Minister. It is true that the Finance Minister has attempted in his own way to see that the Budget proposals are made agreeable, but having regard to the goal of *Sampurna Kranti*, total revolution, even though there is some peace in the land, I am quite sure people will not remain silent and there will be tension again. Therefore, the Janata Party government should think over these suggestions and implement them.

With these words, Sir, I conclude.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South): As I rise to offer a few comments on the General Budget, I would like to refer to one matter which is of very great importance to the rights of the Parliament. My esteemed friend, Shri Kamath, yesterday said that there is an erosion in the hours of our debate in respect of the budget and that over the years, the number of hours allowed has been going down. I have another complaint, far more serious than that. Over the years the information available to Parliament has been continuously going down. I will illustrate this point.

In the past a conventional presentation of budget included a Statement of Accounts for the year ended, a Statement of the Revised Estimates and then a Statement of the Budget Proposals for the year ahead. In the last few years we have somehow omitted to give the accounts for the year ended with the result that there has been no opportunity for the Parliament to compare the Revised Estimates with the actual figures for the year ending. I have got one or two figures to show how the Parliament has not been able to check and verify whether the revised estimates presented in the previous year have been correct, accurate appropriate and proper. You take the Budget speech for the year 1976-77. Then the Finance Minister said that in the current year, that is, in 1975-76, there was expected to be a deficit of Rs. 490 crores. Now in this budget there is no Statement of Accounts for the year 1975-76 with the result that we do not know whether the budget deficit was Rs. 490 crores or Rs. 400 crores or Rs. 300 crores or no deficit at all or whether it was a surplus. Again this year the Finance Minister has stated that the revised estimates for the year 1976-77 is expected to close with a deficit of Rs. 425 crores. Next year unless the actual figures are provided in the budget for the year 1978-79, we will not be able to judge whether there was in fact such a deficit. So, whatever considerations induced a change in the procedures in the past, it is time that Parliament asserted itself and asked for the figures for the year ended along with the revised estimates so that we may know whether the revised estimates were properly made, and whether the revised estimates tally with the accounts ended and if there

are variations, why there are such variations so that it may serve a guide for the future.

It is one of the privileges of Parliament to know how the finances have been managed. Parliament does not meet only to sanction the budget proposals for the next year. It has a duty as the custodian of the national finances to check and verify whether the amounts sanctioned have been properly spent and whether there has been any deviation.

This year the Finance Minister has gone one step forward. He did not give the reasons for the variations between the buget estimates and the revised estimates. This is very surprising. In the past at least they were giving the reasons for the variations between the budget estimates and the revised estimates but this year the Finance Minister has not given the reasons. In fact he stated:

> "The document which I am presenting to-day repeats the revised estimates for the year 1976-77 as given in the interim budget."

So, I was hoping, in the interim budget he would have given the reasons for the variations between the budget estimates and the revised estimates. In the interim budget presented in March this year, the Finance Minister stated:

> "It is not necessary for me to take you over various details of budgetary development during the current year for which the present Government can obviously assume no responsibility."

This is a new interpretation of our Constitution. It is really a strange interpretation. The pilots may change administration goes on. Whosoever may be the incharge of the Government, they must give to the Parliament the budget estimates and the reasons for the variations in the revised estimates. It is necessary for the Finance Minister to give figures. It is his duty to come forward and stated what the budget estimates were and what the revised estimates are and what are the reasons for that variation.

It may be that he can say that he is not responsible for the variations because he was not in charge. It is one thing to say that he is not responsible for it but it is another thing to say that he will not give even the variations in figures. It is an extraordinary thing and I am quite sure Mr. Speaker will take a note of this and see that at the time of presentation of budget in future such a left handed treatment is not afforded to Parliament. I very strongly protest against the manner in which this House has been treated. To state merely that he is not going to give the reasons for the variations because he was not responsible is not good. It is not a question of fixing responsibility. It is a question of the country, of the people, of the Parliament. Parliament must know the variations that have taken place, the modifications that have taken place and the reasons for that and then it is for the Parliament to fix responsibility. To refuse to give the figures is a blatant failure of duty of which I am afraid the Finance Minister is guilty. I hope that what I have stated here will be appreciated by Government and that this will not be taken as a precedent and that they will continue to give the figures which are the absolute right of Parliament to get.

Sir, I will not cover the same ground covered by the speakers on this side of the House. I wish only to refer to some of the points made by my esteemed friend Mr. Biju Patnaik in the coarse of the debate yesterday. He is an old friend of mine and I thought he would be here. It may be that he has just gone out. There is

[Shri R. Venkataraman]

nothing personal against him, but I am saying this only to meet his argument. It has been repeated by the Finance Minister that during the year ending January 1977 the money supply in the country increased by 17.1 per cent causing inflation and a price hike in the country. It was implied that the money supply was mismanaged by the previous Government and that the price hike and inflation consequent thereon were the results of such mismanagement.

Now, Sir, if one looks at the facts one would realised that the increase in the money supply was an index as well an effect of the affluence which the country was going through.

There was the buffer stock of 18 million tonnes which had to be financed by bank borrowing. It led to the large issue of money to meet these charges. Now, Mr. Patnaik asked yesterday a direct question addressed to my friend Mr. Subramaniam. He asked: Why did you accumulate 18 million tonnes of foodgrains in this country? After all this country wants only 11 to 12 million tonnes of foodgrains in case of deficit. Therefore, why did you accumulate 18 million tonnes? This is what he asked. Now, had we not accumulated or bought these surplus foodgrains what would have happened? The prices would have slumped. Agriculturists would have suffered. The whole agricultural economy would have slumped and would have become completely ruined. This is what would have happened.

Secondly, as hon. Members of Parliament are aware, throughout the advanced countries, there is always a policy of giving 'price support' for the agricultural products. Whenever agricultural products go down in price, the Government steps in order to sustain the agricultural prices. Otherwise agriculturists will suffer or there will be a tendency to divert utilisation of land from food to some other crops, leading to possible food shortage. Therefore, it is the imperative duty of any civilised Government to buy surplus food stock which is grown in the country in order to give support to them. If that thing had not been done, the agriculturists would have been ruined and the country's economy would have been ruined also.

My second point is this. Suppose the Government had not purchased the food. What would have happened? The private traders would have bought them at lowest prices. They would have certainly exploited the situation. They would have sold it at much profit for themselves. This would have been the direct result if such a thing had not been done. That is why surplus food had to be bought.

MR. CHAIRMAN: The hon Member's time is over.

SHRI R. VENKATARAMAN: I have some more points to deal with.

MR. CHAIRMAN: You may have another five minutes.

SHRI R. VENKATARAMAN: I want half-an-hour.

MR. CHAIRMAN: Time allotted is very short. You can have a few more minutes.

SHRI R. VENKATARAMAN: Some of us have spent hours and hours and days and days on this. I was a Member of Planning Commission. I am an intellectual who has strayed into politics. I had prepared a few points for the benefit of the House as a whole. If you think that I am talking irrelevant then you stop me.

MR. CHAIRMAN: I am not on that point.

SHRI R. VENKATARAMAN: I will talk in telegraphic English. The second reason for the larger money supply is the large inflow of remittances that have taken place. Is it

wrong for the country to have foreign exchange remittances? What should the Finance Minister do in order to restrict the money supply? Should he immediately put a ban on foreign remittances? This is a fantastic porposition.

Then Mr. Patnaik said because you did these two things so you have ruined the economy and inflation has come into this country. I think he is not supported even by the Finance Minister in this respect. The Finance Minister has said and I quote:

> "The current level of food stocks and foreign exchange reserves do give us wider options in the management of the economy than ever before."

In fact, the Finance Minister has cancelled the argument of Mr. Patnaik.

MR. Chairman, Sir, the next point that I would like to touch is about 'rapid growth rate'. It is an axion that you cannot have a graphic growth rate unless you have savings and investment and the policies which have been enunciated in the budget go contrary to the encouragement of savings in the country.

Take, for instances, the savings in other countries as compared to ours. In Japan the savings are 37 per cent of the national product; in Canada it is 33 per cent; in France it is 25 per cent and in our country it is 14.5 per cent.

The Planning Commission in its report for the Fifth Plan has said that by 1978-79 the savings should be of the order of 13,913 crores of which 85.05 crores will be in the household sector. If you analyse the household sector you find that bank deposits are the most important element in the household sector. What have you done? By reducing the interest rate on the savings bank deposits from 5 to 3 per cent you have introduced disincentives to savings in this country. While on the one hand you say that you want private savings in order to enable further investment on the other hand you reduce the savings bank interest rate. The answer which was given by the hon. Member was that some of these people are using the savings bank account as a current account. If people use savings account as current account then the obvious thing to do is to check this abuse. It is not that you are the only country in the world who have got this problem. The Western countries have also got the problem. They have solved it in a different way. For instance, in a Western country, if a person having a savings account wants to ask the facility of cheques, he pays a small service charge on each cheque. In some countries they limit the number of cheques that can be issued in a month. In our country also you can allow 5 per cent interest on the savings deposit and say that a depositor can issue only 3 cheques in a month or you can say if the depositor uses more than 3 cheques in a month, then the amount standing in his credit will lose interest for that particular month. That is the way to encourage savings. The second thing which will affect the savings is the raising of the surcharge percentage from 10 to 15 on all incomes over Rs. 10,000. Sir, this 15 per cent surcharge is a regressive tax. It falls heavily on the lower income groups and lightly on the higher income groups. Persons who have an income of Rs. 15,000 to Rs. 20,000 have to pay this increased surcharge. Persons who are getting Rs. 2,000 per month are to pay this increased surcharge. The hon. Minister has increased surcharge, which means that whatever little savings that the lower and middle class people can contribute to the welfare of the country, to the wealth of the country, will not be available any more. Added to that, you have got compulsory deposit. Here I have a suggestion to make. So far as the incomes between Rs. 10,000 and Rs. 30,000 are concerned, the 10 per cent surcharge which is now in vogue may be continued. So far as the incomes over Rs. 30,000 or Rs. 50,000 per

[Shri R. Venkataraman]

annum are concerned, the enhanced surcharge of 15 per cent may take effect. By this we will be helping the lower and middle income groups to save not only for their own purpose, but in the process of saving, the country will be benefited by using such savings for the purpose of economic growth. This is very important.

Now, by reducing the bank rate of interest, what will happen? The deposits that are likely to go to the banks will now go to the private companies who are giving attractive rates of interest. Now many of these companies are not now returning their deposits. While the Reserve Bank says that you can advertise calling for deposits giving all these concessions, the Reserve Bank does not say that if you do not repay the money to the depositors, you should not receive their money. Now, I have received many complaints against the companies which have received deposits but have not returned them when they wanted it. They have been issuing either bogus cheques or bouning cheques of something like that. The reduction in the bank interest rate will mean diversion of investment from the banking channel to the private companies which while offering attractive rates of interest seldom return it to the depositors when the time comes. This point needs consideration. I have no time to focus all my points.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : जिन परिस्थितियों में इस सरकार ने इस बजट को बनाया है और जिस प्रकार में पहली कांग्रेस सरकार कुछ योजनाओं को हमारे सामने उपस्थित कर के चली गई थी उनका जिस तरह से इस बजट में मेल बिठाया गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसको मैं जनता पार्टी का बजट तो नहीं कह सकता लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में, जनता पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में यह एक बहुत अच्छा प्रयत्न है।

वित्त मंत्री महोदय इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारी आर्थिक नीति में जो एक प्रकार की भंयकर भूल चली आ रही थी और जिसको सुधारा जाना बहुत आवश्यक था उसको सुधारा है। इसी भूल के फलस्वरूप देश में गरीबी बेकारी, एकाधिकार, आदि बीमारियां बढ़ीं थीं। उस को आपने बदला है इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। भंयकर भूल क्या रही है। अब से नहीं पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही यह भूल होती आ रही है। देश का जब आर्थिक ढांचा तैयार किया गया तो यूरोप को मापदंड बना कर के तैयार किया गया जबकि भारत की परिस्थितियां यूरोप की परिस्थितियों में बिल्कुल भिन्न थी, विपरीत थी। गांधी का भारत उनके मस्तिष्क में न हो कर यूरोप उनके दिमाग में था। इसी लिए वहां की आर्थिक नीति की उन्होंने नकल की। नकल करके मशीनबेस्ड उन्होंने आर्थिक नीति को बनाया। यूरोप में दो समस्यायें हैं। वहां जन संख्या कम है काम ज्यादा है, वहां खेती कम है और उत्पादकता ज्यादा है। उनके हाथ में मार्किट ज्यादा है। इस वास्ते यूरोप के देश उन दो बातों की तरफ ध्यान देते हैं। भारत की परिस्थिति सर्वथा भिन्न थी। यहां जन संख्या अधिक और काम कम है। इसलिए हमारी लेबर बेस्ड पालिसी होनी चाहिए थी, आर्थिक नीति होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सरकार ने यह नीति नहीं अपनाई यह भूल थी।

दूसरी चीज जो अब तक चली आ रही थी वह यह थी कि आर्थिक ढांचे में जितनी भी योजनायें बनती रही हैं उन सब में हमारा एक ही लक्ष्य रहा कि कल कारखाने बनें, देश का भौतिक विकास हो, भौतिक विकास पर ही

एक मात्र बल दिया गया लेकिन भौतिक विकास का जो उपयोग करने वाला आदमी है, जो वास्तविक राष्ट्र है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इंसान को इंसान बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इंसान बनाने का जो महत्वपूर्ण काम था उसकी उपेक्षा की गई अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र की उपेक्षा की गई । यह भी एक भूल थी । इन भूलों के सुधार के लिए आपने कुछ कदम बढ़ाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं । इसके सुपरिणाम सामने आयेंगे ऐसा मैं आशा करता हूं ।

अब मैं थोड़े से आंकड़े आपको देना चाहता हूं । उक्त भूल के किस प्रकार के कुपरिणाम देश में हुए, गरीबी बेकारी किस रूप में फैली, किस तरीके से गरीब गरीब बनता गया और अमीर अमीर बनता गया, और आज का भारत जो देहातों में रहता है वह किस प्रकार पिछड़ता चला गया और मुट्ठी भर देश के शहर पनपते चले गए, इसके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं । पहली पंचवर्षीय योजना से चौथी योजना तक जो रुपया खर्च किया गया उस में से 31255 करोड़ रुपया पब्लिक सैक्टर पर खर्च किया गया और अग्रिकलचर पर केवल 6559 करोड़ खर्च किया गया । पावर प्रोडक्शन पर जहां 3737 करोड़ रुपया खर्च किया गया उस में से बिजली जो पैदा हुई उसका केवल दस प्रतिशत भाग ही देहाती क्षेत्रों के लिए, कृषि आदि के लिए दिया गया । इस प्रकार से जो भारत देहात में रहता है उस की उपेक्षा हुई और सारी सुविधायें मुट्ठी भर शहरों तक सीमित कर दी गई और उन्हीं पर आप की उन्नति योजनायें केन्द्रित हुई जिस का कुपरिणाम सामने आया । खेती पर कुल प्लान का 22.5 परसेंट खर्च हुआ जिस का कुपरिणाम यह हुआ कि गांव उजड़ते चले गए और गांवों के लोग शहरों की तरफ भागे और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या पैदा की ।

16 hrs.

जो सामाजिक सुविधायें हम को प्राप्त होती हैं वह किस प्रकार से केवल शहरों को दी गई इस का मैं उदाहरण देना चाहता हूं । स्वास्थ्य को ले लीजिए । भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उस के लिए जितनी होस्पिटल बैड्स देश में हैं उस का 30 प्रतिशत ही उन को मिला और 20 प्रतिशत डाक्टर्स गांवों में हैं । बाकी सब शहरों में हैं । जो घर निर्माण की योजनायें कांग्रेस सरकार ने बनायी उन के लिए चौथी योजना में 189.47 करोड़ रु० रखा गया जिस में उन देहाती क्षेत्र के लिए केवल 17.8 करोड़ रुपया ही दिया गया, अर्थात् 9.5 परसेंट ही उस पर खर्च हुआ । वाटर सप्लाई के लिए 1.16 लाख गांवों के 610 लाख लोगों के लिए चौथी योजना में 401 करोड़ रुपए में से केवल 125 करोड़ रु० गांवों के लिए दिया गया ।

जहां तक ट्रेड का सम्बन्ध है उस में भी देहाती क्षेत्र के साथ अन्याय किया गया और शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ पक्षपात किया गया । शहरी क्षेत्र में जितने उद्योग धंधे स्थापित हुए उनको सरकार ने प्रोटेक्शन दिया ताकि वह फेल न हो जायें, उन में उत्पादन कितना होता है, लागत माल पर क्या आती है उसके अनुसार दाम निर्धारित करने की भी आप ने उनको छूट दी । लेकिन देहाती क्षेत्र में किसान द्वारा जो कुछ पैदा हुआ तो सरकार

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

किसान के सीने पर बैठ गई कि तुम्हारा उत्पादन इधर से उधर नहीं जा सकता, एक जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकता, और उन की कीमत निर्धारित करने के लिए भी मनमानी की। इसके अतिरिक्त जो सामान किसान को मिलता था बिजली, पानी, खाद उस बारे में भी उनके साथ अन्याय किया गया। किसान को बिजली मिलती है महंगी, जब कि शहर के लोगों को सस्ती दर पर मिलती है। कांग्रेस सरकार इस भेदभाव को देखती रही। गांवों में ट्यूब वैल लगे हैं लेकिन जो वहां मीटर लगे हैं उन पर 15 रु० प्रति होर्स पावर के हिसाब से मूल्य लगा दिया जो हर महीने किसान को देना पड़ता है चाहे उसे बिजली मिले या न मिले। सिंचाई एरिया बना दिया पानी जाये या न जाये, उस को पूरी भराई देनी पड़ेगी। इस प्रकार से देहाती क्षेत्र को सरकार ने जानबूझ कर उजाड़ा।

जब तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी 1950–51 तक तब तक गांवों की पर कैपिटा इनकम 197.80 पैसे थी जो 1960-61 में बढ़ कर 219.20 हो गई। परन्तु कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आयी। 1961-62 के बजट में कृषि के लिए 254 करोड़ रु० रखा गया और 1976–77 में 510 करोड़ रु० इस के लिए रखा गया फिर भी 1976–77 में प्रति व्यक्ति आय 196.50 पैसे हो गई। इस से यह हुआ कि जहां प्रति व्यक्ति आय 1950–51 में 197.80 पैसे थी कृषि के क्षेत्र में वह 1976–77 में घट कर 196.50 रह गई। यानी घाटा हो गया, जहां तरक्की की बात कर रहे हैं, वहां भारत नीचे चला गया।

मैं शहरी क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। देहाती क्षेत्र की जहां पर-कैपिटा इनकम नीचे गिरती चली गई वहां शहरी क्षेत्र में, जो कि भारत में केवल 28 प्रतिशत है, उसकी पर-कैपिटा इनकम बढ़ती रही। उदाहरणार्थ प्रति व्यक्ति आय 1950–51 में 399 रुपए थी वहां 1976–77 में वह 811 रुपए हो गई। शहरी क्षेत्र में सूखे, वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खेत में चाहे अन्न पैदा हुआ हो या न हुआ हो, पर शहरी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कि गांव में प्रति व्यक्ति आय 1960–61 की अपेक्षा 1976–77 के मध्य 10 प्रतिशत घट गई, वहां शहरी क्षेत्र में 52 प्रतिशत आय बढ़ गई। इसका कुपरिणाम क्या हुआ? 1971 की जनगणना के अनुसार किसानों की संख्या 16 प्रतिशत घटकर 78 लाख रह गई। खेतिहर मजदूरों की संख्या 75 प्रतिशत बढ़कर 47.5 लाख हो गई। खेतिहर मजदूर व किसान काम की खोज में देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ आकर जमा हो गए। मैं कुछ और भी प्रमाण देना चाहता हूं।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो गरीबी की रेखा का माप-दण्ड था वह रु० 40.60 प्रति व्यक्ति प्रतिमास था। उसके अनुसार गरीबी के माप-दण्ड के नीचे गरीबों की संख्या 172 लाख से बढ़कर 245 लाख हो गई है। एक ओर शहरों में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उद्योगों में घाटा है। पहले जो लोग पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे, उनकी संख्या 172 लाख थी जब कि योजना का प्रारम्भ नहीं था, लेकिन अब पावर्टी लाइन से नीचे 235 लाख आदमी रहते हैं। इसका

कुपरिणाम यह हुआ कि जब देहाती क्षेत्र गड़बड़ा गये, तो इससे शहर नहीं बच सकते थे और जो उद्योगों में उत्पादन होता था, कपड़ा मिलों में कपड़ा पड़ा रहा क्योंकि जो खरीदने वाले थे वे अधिकांश गांव के लोग थे, उनकी आमदनी घटती गई और कपड़ा मिलों में कपड़े का स्टाक जमा हो गया । और बहुत सी कपड़ा मिलें बीमार होकर बन्द हो गईं ।

बेकारी बराबर बढ़ती चली गई । सन् 1951 में बेकारों की संख्या 3 लाख थी, जो कि 1971 में 18 लाख हो गई और 1972–73 में बेकारों की संख्या 71 लाख हो गई । इन बेकारों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई । मैं एक आवश्यक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । भारत में हमारा इन्वैस्टमैंट 1972–73 में 3.7 गुना बढ़कर 3044 करोड़ हो गया और औद्योगिक उत्पादन 3.8 गुना बढ़ा । लेकिन गरीबी और बेकारी इतने पर भी बढ़ती चली गई । यह आश्चर्यजनक है और यही कारण था कि मूल में ही भूल थी ।

मैं जो सुझाव देना चाहूंगा, वह यह है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति एवरेज आफ लैंड होल्डिंग 2.30 हैक्टर है और पापूलेशन डैन्सिटी पर स्कवेयर किलोमीटर 178 है और हमारी पर-कैपिटा इनकम केवल 54 रुपये सालाना है । लेकिन हम ने अमरीका आदि देशों की नकल की है, जहां ऐवेरेज लैंड होल्डिंग 158 हैक्टेयर पापुलेशन की डेन्सिटी केवल 22 पर स्वैवेयर किलोमीटर है और नम्बर आफ वर्कर्ज पर वन थाउजेंड हैक्टेयर्स केवल 17 है । हम ने अमरीका की नकल की, लेकिन जापान को नहीं देखा । जापान में नेशनल ऐवरेज आफ वर्कर्ज पर वन थाउजंड हैक्टेयर्ज 2031 है, जब कि भारत में वह केवल 881 है । अगर हमें आर्थिक नीति में नकल करनी ही थी, तो जापन की नकल करनी चाहिए थी, न कि यूरोप और अमरीका की ।

हम कितना भी उत्पादन कर लें, लेकिन अगर हमने इन्सान को इन्सान न बनाया, तो इस देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी आदि खत्म नहीं होंगे । आजादी के बाद हम आशा करते थे कि इस देश में जातिवाद, प्रान्तवाद और भाषावाद आदि संकीर्णतायें समाप्त हो जायेंगी । वे तो समाप्त हुई नहीं, मगर घूसखोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ते चले गये । इसका कारण यह है कि हमने किसी भी बजट में शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बजट में भी शिक्षा को वह स्थान नहीं मिला है, जो कि उसे मिलना चाहिए था । अगर हमने इन्सान को इन्सान न बनाया, और इन्सान हैवान बन कर खड़ा हो गया, तो हमारी सब योजनायें फेल हो जायेंगी । इस लिए शिक्षा पर हमारा अधिक धन व्यय होना चाहिए ।

वित्त मंत्री से बीड़ी पर कर तो बढ़ा दिया है, लेकिन बीड़ी की मां या दादी कैसे बच गई ? बीड़ी गरीब आदमी पैदा करता है—और लाखों आदमी इस काम में लगे हुए हैं—और गरीब ही पीता है । वह तो वित्त मंत्री की नजर में आ गई, लेकिन शराब नहीं आयी । मैं न बीड़ी पीता हूं और न शराब. लेकिन मैं गरीबों का ध्यान करके कहना चाहता हूं कि अगर बीड़ी पर कर न बढ़ा कर शराब पर मन-माना कर लगा देते, तो यह बड़ी बीमारी इस देश में समाप्त हो जाती ।

वित्त मंत्री ने 10,000 रुपये तक आयकर की छूट दी है । लेकिन

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

उन्होंने यह व्यवस्था कर दी है कि अगर आमदनी 10,000 रुपए की सीमा से अधिक बढ़ती है, तो करमुक्ति केवल 8,000 रुपए पर मिलेगी । वित्त मंत्री ने यह उचित नहीं किया है । 10,000 रुपए की करमुक्ति सबको समान रूप से मिलनी चाहिए ।

सरकार ने हैंडटूलों पर कर लगाया है; परन्तु अगर हैंडटूल बड़े कारखानों में बनते हैं, तो सरकार उन पर कर लगाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन पंजाब आदि प्रान्तों में जो हैंडटूल, छोटे-छोटे हाथ के औजार, देहाती क्षेत्र में और लघु उद्योगों द्वारा बन रहे हैं, उन पर कर नहीं लगाना चाहिए ।

अध्यक्ष जी, इस देश में काला धन एक बहुत बड़ी प्राबलम है । जब तक देश में काला धन है, तब तक इनफलेशन समाप्त नहीं होगा, और जब तक इनफलेशन समाप्त नहीं होगा तब तक महंगाई खत्म नहीं होगी । काला धन पैदा करने का अगर कोई एकमात्र कारण है, तो वह इनकम टैक्स की वर्तमान पद्धति है । मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह इस को सरल और सीधा बनायेंगे । ऐसा करने पर किसी को काला धन बनाने की आवश्यकता या प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । यदि वित्त मंत्री किसानों के काम आने वाली खाद के कर में कुछ छूट दे दें, ताकि किसान को कुछ राहत मिल जाए, तो मैं उन का बहुत आभारी हूंगा ।

अन्त में अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री को पुनः धन्यवाद देता

श्री नवाब सिंह चौहान (अलीगढ़): सभापति महोदय, पिछले आपातकालीन वर्षों में लोग इतने परेशान थे और शायद उसी वजह से इतने क्षुब्ध थे, क्योंकि बहुत वादे किए गए थे लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ था और अत्याचार भी किए थे इसी से क्षुब्ध होकर लोग उनकी रुत्री के साथ साथ राष्ट्र-निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू के ऊपर भी बरस पड़ते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने देश को बिगाड़ा था । यह कहना उचित नहीं है । यही नहीं, ये लोग गांधी जी और जवाहर लाल जी के बीच में एक रेखा खींचने की कोशिश करते हैं । जवाहर लाल जी और गांधी जी दो चीज नहीं हैं । गांधी जी ने तो जवाहर लाल जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था । यह लोग कहते हैं कि नेहरू जी तो यूरोपीय पद्धति के हामी थे जब कि हमारी व्यवस्था भारतीय ढंग से होनी चाहिए थी । जवाहर लाल जी ने ऐसी क्या चीज यहां कर दी ? रूरकेला और दूसरी जगहों के बड़े बड़े इस्पात के व अन्य कारखाने बनाए तो क्या बुरा किया ? आप देखेंगे कि उस वक्त से ही हमारी अर्थ व्यवस्था मिली जुली रही है । जिसका मतलब यह है कि बड़े-बड़े कारखाने भी चलेंगे और साथ साथ छोटे छोटे गृह उद्योग जो हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा । अब यह चीज ठीक ढंग से नहीं चल पायी तो इसका क्या किया जाये ? अब भी हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ही चल रही है । क्या हम भी बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों को संग संग नहीं चलाना चाहते हैं । हां, यह जरूर है कि हम चाहते हैं कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों का गला न घोट दें । बहुत से लोग तो कहते हैं कि देश में पिछले तीस सालों में कुछ नहीं हुआ । यह बात सही नहीं है । बहुत कुछ हुआ । आखिर के दो तीन सालों में जो कुछ हुआ, जैसा मैंने कहा उसी से लोग क्षुब्ध हैं और

उसी को लेकर यह कह देते हैं कि पिछले तीस सालों में कुछ भी नहीं हुआ । पहले यहां सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज व अन्य तमाम चीजें यहां बन रही हैं । अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें हम अपने यहां खुद बनाते हैं और बहुत सी चीजें तो हम निर्यात भी करते हैं । वह चीजें आयात नहीं होती हैं । हम यह मंजूर करते हैं कि तरक्की हुई हैं लेकिन उछलती कूदती हुई है, यानी यहां हुई, वहां नहीं हुई, व समान रूप में नहीं हुई । उसके लिए हम लोग कोशिश करें । यह न हो कि हम लोग एक दूसरे की व्यर्थ की आलोचना करते रहें । हम लोग इस तरह की जो बात कहते हैं वह ठीक नहीं है । हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो नहीं हुआ है उसको करें, यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र विर्माता के ऊपर धूल उछालें ।

गांधी जी ने जवाहर लाल जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और जवाहर लाल जी जी ने अपनी लड़की को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया । इस प्रकार गांधी जी और जवाहर लाल जी एक ही चीज हैं, उनमें आपस में फर्क डालना ठीक नहीं है । जो लोग पहले गांधी जी को बुरा कहते थे, जो उनको पूंजीपतियों का ऐजेंट कहते थे वे आज गांधी जी का नाम लेकर जवाहर लाल जी का बुराई करते हैं । इसलिए हम ऐसी चीजें न करें । अच्छा हो हम गांधी जी और जवाहर लाल जी का नाम न लें और अपना काम करें । . . (व्यवधान) . . . . आप भी अब गांधी जी की बात कहने लगे जो पहले उनको पूंजीपतियों का ऐजेंट कहते थे । मैं कहता हूं कि कम्यूनिस्ट देशों में भी तमाम चीजें नहीं हुईं । रूस भी आज तमाम चीजें नहीं कर पाया है । आप जानते हैं कि हम से पांच छः गुना ज्यादा जमीन रूस के पास है और हमारे हिन्दुस्तान की आबादी की केवल आधी आबादी वहां है लेकिन तब भी वे अपने यहां खाने पीने की समस्या हल नहीं कर पाए और अमेरिका से अन्न मंगाते है । तो हमारे ऊपर ये कम्यूनिस्ट लोग क्यों दोष लगाते हैं चाहे वह सी० पी० आई० के हों या और दूसरे लोग हों जो रूस व इसी प्रकार के देशों से प्रेरणा लेते हैं ।

अब मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा । जो बजट बनाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जो रुपया आप इकट्ठा करते हैं टैक्सों के जरिए अगर उसको ठीक ढंग से खर्च करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह उसी तरह से चला जायेगा जिस तरह से पहले चला गया जिसकी आपको व हम सबको शिकायत है । वह क्या चीज है जिसके उपर आपको ध्यान देना है ? वह हैं भ्रष्टाचार जिसे आपको मिटाना होगा ।

सबसे पहले जिस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि किसानों की पानी की और बिजली की दिक्कत दूर हो । यह उनको नहीं मिल पाती है जिसका कारण यह है कि बिजली विभाग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है । त्यागी जी ने जो कहा मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं । प्रति हार्स पावर पर 15 रुपया मासिक लगाया जाता है चाहे बिजली लें या न लें । दस हार्स पावर है तो एक सौ पचास रुपए हो गए, पांच रुपया लाइट का हो गया चाहे लाइट हो या न हो, बिजली आऐ या न आए, यह रुपया वे मुफ्त में ले जाते हैं ।

इसी तरह से कमांड एरिया के टैक्स की बात है । अगर आपका खेत ट्यूबवैल के कमांड एरिया में पड़ता है तो आबपाशी आप करें न करें यह कर आप से

[श्री नवाब सिंह चौहान]

ले लिया जाएगा । इस तरह की अनेक बातें चल रही हैं । भ्रष्टाचार ऊपर तक भरा हुआ है । इसलिए सबसे पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि क्या बातें हैं, किस चीज की कमी है बिजली के उत्पादन में कमी है या वितरण की और इसमें किस का कसूर है। इन सारी बातों के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बैठानी पड़ेगी और उससे यह कहना पड़ेगा कि एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे, मालूम करे कि कितनी कमी है और किस तरह से दूर हो सकती है एमर्जेन्सी के जमाने में अनेक गलत काम किये गये हैं। सरकारी कर्मचारियों पर ऊपर के नेताओं ने दबाव डाला कि इन कारखानों को जल्द से जल्द चालू दिखाया जाये । नतीजा यह हुआ कि यहां भी माक-फायरिंग हुआ । फौज में तो माक-फायरिंग होना ही है, लेकिन यहां भी हुआ, उन्होंने डीजल जला कर चिमनियों में धुंआ निकाला ताकि ऊपर यह रिपोर्ट दी जा सके कि पावर-प्लांट चालू हो गये हैं । लेकिन इससे उनकी टर्बाइन्ज टूटी व ट्यूबें फट गईं, बहुत नुकसान हुआ । हमारे हर्दुआगंज में पावर स्टेशनस हैं, वहां लाखों व करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात की जांच की जाये कि किस वजह से बिजली नहीं बन रही है, किस वजह से नुकसान हो रहा है । अगर आज ऐसा नहीं करेंगे तो जो रुपया आप देंगे, चाहे स्टेट को दें या कहीं भी दें, वह बेकार चला जाएगा ।

आबादी की समस्या की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अब हमारी नीति बन गई है कि जोर-जबरदस्ती से नसबन्दी नहीं होगी । लेकिन हमें दूसरे साधनों का प्रचार तो करना ही होगा जिससे आबादी न बढ़े । इसलिए हमें सन्तति निग्रह के अन्य उपायों के बारे में जनता में प्रचार करना चाहिये जो अपनी मर्जी से नसबन्दी करना चाहें उसके लिए उसको आजादी होनी चाहिये, लेकिन पिछले दिनों में लोगों के अन्दर नसबन्दी विरोधी भावना फैल गई है और वे नसबन्दी से डरने लग हैं, क्योंकि उनके साथ जोर-जबरदस्ती की गई थी । इसलिए नसबन्दी को छोड़ कर सन्तति को रोकने के जो दूसरे तरीके हैं उनका बड़े पैमाने पर हमें प्रचार करना चाहिये ।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रचार और प्रसार का बहुत महत्व है । इस काम में हमारे रेडियो और टेलिविजन विभाग बहुत सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। हमारे टीविजन विभाग में अभी भी बहुत भ्रष्टाचार है, जिसे आपको सुधारना होगा एमर्जेन्सी के जमाने में इस विभाग में ऐसे लोगों की भर्ती की गई जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, शकल देख कर भरती कर लिया गया । इस बारे में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा—एक शख्स ने आखरी मन्जिल से कूद कर आत्म-हत्या कर ली थी, इसलिए कि वह असन्तुष्ट था, उसके साथ अन्याय हुआ था। इसकी छान-बीन करनी चाहिये और अपराधियों को दंडित करना चाहिये । आगे दूरदर्शन को इस ढंग से चलाना चाहिये कि वह सुचारु रूप से काम कर सके । जहां कहीं भी आप रेडियो स्टेशन या टी० वी० सेन्टर बनायें, उनको ठीक ढंग से बनायें ताकि क्षेत्रीय जनता को उनका लाभ मिल सके । पिछले संचार मंत्री मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत सी जगहों पर ऐसे-ऐसे रेडियो स्टेशन बना दिए गए जिनसे क्षेत्रीय जनता को ठीक ढंग से सुनाई नहीं पड़ता है । कोई भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिये जो 20 किलोवाट से कम हो । मथुरा में बृज क्षेत्र के लिये एक रेडियो स्टेशन बनाया गया जो एक किलो-

बाट का है । उससे बृज क्षेत्र में ही ठीक सुनाई नहीं पड़ता, इस तरह के रेडियो स्टेशन बनाने से क्या फायदा है ।

हमें जनता के स्वास्थ्य की तरफ भी देखना चाहिए । जिस तरह से आज आप जनता शाप्स खोलने जा रहे हैं, उसी तरह से आपको जनता अस्पताल भी खोलने चाहियें, जिसमें वैद्य भी हों, होमियोपैथी के डाक्टर भी हों और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को ऐसी शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे वे अपना स्वास्थ्य-सुधार कर सकें । हमारी पिछली सरकार की एक बहुत बड़ी देन है—मलेरिया । मलेरिया आज कल किसानों को बहुत परेशान कर रहा है, खेती में हल चला रहे हैं, लेकिन मलेरिया में पड़ जाते हैं । इस मलेरिया को हमें अपने देश से पूर्ण रूप से निष्कासित करना चाहिये ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे जनता का भला हो । बहुत सी फैंसी योजनाएं आज कल चलती हैं—बहुत तरह की वाड़ियां चलती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षायें चलती हैं—इन सब में सुधार होना चाहिये जिससे व्यर्थ में इन पर खर्चा न हो ।

पिछले शासन के शिक्षा मंत्री ने एक अलीगढ़ यूनीवर्सिटी कानून बनवाया । उस कानून को मुस्लिम नहीं चाहते थे । इस कानून के जरिए सरकार ने उनके मौलिक अधिकार छीन लिये । न केवल अलीगढ़ बल्कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों के अन्दर इससे बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। मैंऐसा अनुभव करता हूं—चाहे हिन्दू शिक्षण संस्था हो या मुस्लिम शिक्षण संस्था हो, सरकार को इस तरह से उनके कार्य में दखल नहीं देना चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था, उसको वापस लिया जाये । हां, यह परिवर्तन जरूर चाहता हूं कि जो नामीनेशंस होते हैं वे न हों । उस में केवल बड़े बड़े मुस्लिम ही न रखे जाएं बल्कि उसमें गरीब लोगों को भी रखा जाए और वर्किंग क्लास के लोगों का भी प्रतिनिधित्व नामिनेशन होना चाहिए ।

इसके बाद आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो आपने पैसा एकत्रित करके रखा है, उसको खर्च सही तरीके से होना चाहिए । जब तक आप भ्रष्टाचार को नहीं मिटायेंगे, तब तक इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा । आज तो जगह जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । योजनाएं पहले भी बनती थीं । जवाहरलाल जी ने भी ग्राम-सुधारों के लिए योजनाएं बनाई थीं और स्वतन्त्रता से पूर्व ही एक एग्रीरेरियन कमेटी बनाई थी और प्लानिंग का कार्य भी उसी वक्त शुरू हो गया था जब तक कि हम आजाद भी नहीं हो पाए थे । बीच में भी कुछ चीजें हुई और योजनाएं बनीं लेकिन अमल में गलती रही है । बड़े बड़े कारखानों के काम करने में भी ग़लती हुई है और काटेज इंडस्ट्रीज की जो ग्रामीण योजनाएं थीं, उनके कार्यान्वयन में भी ग़लती हुई है । इसलिए जब आप योजनाएं बनाते हैं तो उन पर ठीक ढंग से अमल होना चाहिए जिससे उनका पूरा लाभ गरीब किसानों व मजदूरों को मिल सके ।

मैंने भी कृषि मंत्री जी को लिखा था कि खरीद केन्द्रों पर भारी मात्रा में गेहूं खले में पड़ा हुआ है । वर्षा ऊपर है इससे बहुत सा अनाज बर्बाद हो जाएगा । मुझे मालूम हुआ है कि कृषि मंत्री जी ने आफ़िसर्स को लिखा भी है कि इस अनाज को ढकने का काम तुरन्त किया जाये । इस पर अफ़सरों ने यह किया कि पहले देश भर से यह पूछा जाए कि कितनी तिरपालों की जरूरत होगी और बाद में टैंडर लेने की रस्म पूरी की जाए ।

[श्री नवाब सिंह चौहान]

बारिश आने को है और हो भी रही है, अफ़सर लोग इस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं । इस टेंडेंसी व कार्यविधि को बदलना होगा और फौरन युद्ध के स्तर पर ऐसे कामों को करना चाहिए । यह लोग तो सोचते ही रहेंगे कि इतने तिरपाल चाहिए । और कितना इस पर खर्च होगा । किन्तु प्रकृति अपना काम कर पायेगी और अधिकारियों के इस तरह से कार्य करने से जनता का कोई फ़ायदा नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

*SHRI P. S. RAMALINGAM (Nilgiris): Mr. Chairman, Sir, in my capacity as a Member of the Lok Sabha from the Nilgiris constituency of Tamil Nadu, I rise to express my views on the General Budget and I am grateful to you for having given me an opportunity to make my maiden speech in this House. I have to regretfully point out that, while Gandhian economy is being bandied about by the ruling party Members....

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): On a point of order. There is no English translation coming of his speech.

SHRI V. ARUNACHALAM (Tirunalveli): There should be translation. Otherwise, we are insulted. Translation is necesary. Otherwise, Members are not able to understand what we say. The routine practice is that simultaneous translation is necessary.

SHRI P. S. RAMALINGAM: When the hon. Members of the ruling party are frequently expressing their implicit devotion to Gandhian economic ideals, it is inexplicable to us that the powerlooms have been exempted from excise duty. Is this not a clear illustration of the gap between precepts and practice? While the handlooms are in the grip of worsening crisis, the powerlooms which fan the flame of that crisis are being strengthened by this exemption from excise duty and that too by the Government which asserts about its commitment to Gandhian economic ideals.

It is common knowledge that 80 per cent of our population lives in rural areas. The new Government has declared that it would chart a new path for the economic upliftment of the people living in the rural areas. The leaders of the ruling party go on repeating that they would usher in a new era, as they have brought about a political transformation. I would like to state that the people of our country will not tolerate any undue delay in bringing about economic transformation, without which the political transformation will soon be in quick-sand. In this context, it is strange that *Beedi*, which is dear to the common man, has been taxed heavily in this Budget. The hon. Health Minister may feel happy that by smoking less *Beedi* the common people will be more healthy. But the common people will definitely feel the pinch on their already depleted purse.

The radio and the transistors, which were once luxury items, have now become the common people's requirement. I cannot appreciate the incidence of increased taxation on them and also limit of Rs. 500/- fixed for this purpose. Here, I have to refer to the insidious role played by the All India Radio during the recent elections. In fact, you will appreciate that greater

*The original speech was delivered in Tamil.

emphasis on the All-India news at the cost of regional happenings, and that too over the regional station of the All India Radio, cannot inspire the confidence of the people. During the night news relayed by the regional station all the importance and prominence was given only to the all-India news and the regional news was relegated to the background. In between the news relays, only Hindi songs were broadcast. Could not Tamil songs be played during this interval? I have to painfully point out that this is not conducive for strengthening the national integration.

I would like you not to misconstrue that I am threatening, but I would like to warn the new Government about the language issue. The people of Tamil Nadu are very sensitive about their language Tamil, which has traditions of thousands of years. In the new Tamil Nadu Assembly, the D.M.K. is the next major party. Our revered and beloved leader, Thiru M.G.R. has said that the people of Tamil Nadu look to the All India Anna D.M.K. for protecting their rights and their language. They are not prepared to believe any of the All India parties other than A.D.M.K. in the matter of language. That is why they have voted D.M.K. as the second party.

In this connection, I have per force to say that, after Pandit Jawaharlal Nehru, no political leader of the country has appreciated the sentiments of the people of Tamil Nadu so far as their language Tamil is concerned. I emphasise this point because of my eagerness that the new Government should have no reservation in appreciating Tamil people's love for their language and it should ensure that the ugly language problem does not come to the forefront again.

While talking about Jawaharlal Nehru, I remember that he once said that the cycle is the common man's easiest and cheapest mode of transportation. Today the scooter has replaced the cycle and if you go out of the Parliament House you will find the evidence for this statement. I am sorry that the new Government, which professes deep sympathy for the common man, has increased the taxes on scooters and other components. It is axiomatic that the essential commodities and the day-to-day necessities of common people must be spared from an overdose of taxation. Instead, the luxury goods can be taxed more and more, the common people must be enabled to make their both ends meet comfortably.

I would like to illustrate another dichotomy of the ruling party at the Centre. While the income tax exemption minimum limit has been raised from Rs. 8000 to Rs. 10,000, it is regrettable that those having an income of more than Rs. 10,000 will have to pay income tax from Rs. 8000 onwards. A man getting an income of Rs. 9500 need not pay any income tax; but a man with an income of Rs. 10500 will have to pay income tax on Rs. 2500. And the surcharge has also been increased from 10 per cent to 15 per cent. This is unfair and unjust. It may be that only a few will be affected by this. Yet, the number should not be the criterion in this matter. This House should not be a party to perpetuate unfair and unjust actions on the part of the Government. I appeal to the Finance Minister that he should come forward to remedy this unjust tax proposition.

I would like to state that this Budget does not give any indication about the labour policy of this Government. Similarly, there is no indication about the land reform policy of this Government. It is good that the Finance Minister has stated that the next instalment of Compulsory Deposit amount will be given next year in cash. I don't think that this is a sop to the sobbing poor. It should neither be an eye-wash nor a political drama.

[Shri P. S. Ramalingam]

The new Government must be aware of the fact that the previous Government was thrown out of office because of its callous attitude towards the needs of the people and other concomitant misdeeds. The people expect from the new Government not merely a narration of the previous government's nefarious activities but also the Government's programme of constructive activities for their welfare. Planning and Budgetting are the potent instruments in the hands of the Government for ushering in an era of welfare for the people of the nation. I hope that this Government will bear in mind the fate of the previous Government and will make an effort in the proper direction which will save it from becoming a similar victim in the hands of the people.

With these words, I conclude my speech.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): To begin with, I want to say something good about the Janata Government. I would like to congratulate the Hon. Minister of Information and Broadcasting for throwing open the All India Radio and Doordarshan to Opposition parties. In my view, it is a very significant step which will help to further democracy in this country.

Then, there is a matter which was referred to by my friend Shri Govindan Nair. Only a few days ago there was a conference held by the Prime Minister and other Ministers with the Opposition parties and the subject was the Anti-defection measure. We were told by the Prime Minister himself that they want this anti-defection measure to be passed but that the Congress Party had some reservations. Perhaps he thought that he was not being quite fair to the Congress Party and so he added that there were some honest differences. This was what he stated only a few days ago, but now in today's papers we find that the Janata Party has thrown open its doors both in the Rajya Sabha and the Lok Sabha to as many as 17 defectors. Now, Sir, we have great regard for the uprightness and good character of the Prime Minister, but if it is going to be demonstrated in this way, I am afraid the confidence that all Sections of the House have been reposing in him may be impaired. I endorse every word my friend Mr. Govindan Nair has said on this subject.

Now, there is talk about the austerity that Ministers of the Janata Government observe. I would like to draw your attention to one or two things in this regard. You might have read in today's papers that a train was held up so that Mr. Raj Narain, the Minister of Health and Family Welfare could board it. This is something which does not speak of much austerity.

There is a much more serious thing. A Railwaymen's Conference was convened in Madras in the beginning of this month, which was addressed by the Hon. Railway Minister, the Hon. Minister of Communications, and also the Hon. Minister of Energy. I have information that five special trains were ordered to be run to Madras from various towns like Olavokkot Bangalore, Madurai, Tiruchirapalli and Guntakal to enable people to attend the Railwaymen's Conference at Madras organised by the Southern Railway Mazdoor Union, an affiliate of the All India Railwaymen's Federation. You are aware that this is the Unit which sponsored the Railwaymen's strike in 1974. The special trains had 17 First Class passenger coaches and Second Class sleeper coaches each and were accommodated with diesel engines by cancelling some goods trains. No tickets were purchased by the passengers and thousands of them travelled by the special trains. Heavy loss of revenue has been incurred by the Railways due to this ticketless travel and also due to the cancelling of goods trains for providing diesel engines to

the five special trains. The Secretary of the Southern Railway Mazdoor Union gloated over it in this manner:

> "Everyone of us in the Southern Railway Mazdoor Union can legitimately feel proud that this is the first time that five or six special trains are run in connection with a zonal conference. In the living memory no trade union has so far got 5-6 special trains. This is a clear evidence that SRMU is not only the biggest union but sets the pace for others."

This is what has happened and I leave it to the House to judge how far it squares with the claim of austerity of the Ministers of the Janata Government.

Now the House finds itself in a very peculiar situation to-day. Those who should be on the offensive are on the defensive and those who should be on the defensive are on the offensive. It looks as if the government and the Opposition have exchanged their roles. If a visitor suddenly enters the galleries, he will be led to think that the government has chosen to sit on the left of the Chair and the Opposition on the right. I think this is a twilight period and we will soon outgrow it when the government and the Opposition will fall into their natural places and start functioning normally.

The hon. Finance Minister in his budget speech has been trying to take shelter behind a plea that he is not able to present a full-blooded Janata budget because of various constraints. What are the constraints? He says that the Planning Commission is not available for him to consult. Planning Commission, as is pointed out, with reference to the Finance Ministry is a continuing institution. The Deputy Chairman may be there or may not be there but the whole machinery of the Planning Commission is there for the government to consult. What is the other excuse? He says that the State Governments are not there for him to consult. The State Governments are also continuing entities. There may be elections, there may be temporary arrangements for running the state administrations, but, if he wants to consult with reference to slum clearance or irrigation schemes, major, medium or minor, all the people of the state governments are available. The whole administration is available and he says that he did not have the time to consult. Again he says that he is not able to re-order the priorities. What are the priorities that he would like to re-order? He says that heavy commitments have been made on on-going projects. It looks as if all these on-going projects are wrong things, now he is not in a position to pull back the rein and so he is willy-nilly to continue the expenditure on these on-going projects and that has been cited as one of the constraints. I should be excused. These are all school-boy's excuses. He should take us into confidence and tell us which are the on-going projects which stand in the way of his re-ordering the priorities according to the things which are stated in the Janata Party manifesto. He should tell us, 'This is the project that stands in my way. Otherwise, I would have re-ordered my priority.' Is it any irrigation project? Or is it any power project or any fertiliser project that stands in your way? So what are the projects that stand in the way of his re-ordering the priorities—we should like to know. Evidently, I suspect that this plea has been trotted out by the hon. Finance Minister to satisfy the Opposition in his own party. If this budget had been presented by the Congress government, some of the fire-eaters in his party would have denounced it in no uncertain terms and in the extreme language. Now they have to cook in their own juice. They are not able to say anything. So, the Finance Minister comes with the excuse that this is a budget which is a neither-

[Shri O. V. Alagesan]

here-nor-there budget. This is a budget which is a sort of a mid-way house, between a congress budget and a Janata budget and so he is not able to do full justice. But, he cannot, in my view, escape in this manner because he should tell us where he wants to re-order the priorities. Is it in the agricultural sector? Is it in the private sector of the industry? Is it in the public sector of the industry? Now as far as the agricultural sector goes he has levelled a charge that though the previous Government was talking all along about the agricultural sector and about the improvement of the agricultural sector and the development of the rural sector, etc., they have not done enough justice. In fact that was refuted very effectively by my friend Shri C. Subramaniam when he spoke.

What has the Finance Minister done? He has provided 30.4 per cent of the total outlay to the agriculture sector and other allied services during this year. On the other hand, last year according to the Economic Survey, as much as Rs. 3741 crores which come to 44 per cent of the total outlay which was allocated for this sector.

Yesterday, when my friend Shri Biju Patnaik was speaking, this was sought to be contradicted. They said items included are different. Evidently, the office has been asked to go and make an exercise and manipulate the figures. I do not know. He says 20 per cent. It may be 20 per cent. I may point out that the spokesman of the Finance Ministry has come out with a figure of 29.4 per cent. He said it was only slightly less last year. So, it cannot be said that the Congress Government gave less for the development of the rural sector or agriculture sector. So, there is no question of re-ordering priority in the agriculture sector. If you look at the Budget Speech, it is of a comparative degree.

Much more remains to be done in power, planning and development. Modern industry needs to be developed further and that is the field of exports. More irrigation, better cultural practices, increased use of fertilizers and weeding, etc. have to be provided. Fast agricultural growth has to be made and greater attention will have to be paid to the development of rural infrastructure and so on and so forth. It is all one of comparative degree.

In fact the present Finance Minister is continuing with what the previous Finance Minister did. In fact I can read to you some passages of this year's budget and that of last year's budget. It has been more or less paraphrased.

I quote from the last budget speech of Shri C. Subramaniam:

"It does not require much argument to prove that abolition of mass poverty in a country such as ours can be ensured only through a sustained attack on rural poverty. As Mahatma Gandhi reminded us so often India lives in its villages. This means the foremost priority must continue to be given to problems of agricultural development and such supporting sectors as power, irrigation, fertilizers and pesticides."

What does Shri H. M. Patel say:

"It goes without saying that in any strategy we devise, the primacy of agriculture has to be emphasised."

There the words used were: Foremost priority must be given. Here the words used are: The Primacy of agriculture has to be emphasised in a country in which 80 per cent of the people live in rural areas. It is only re-phrasing; it is only paraphrasing. He says: 'Increase in agricultural productivity is almost a pre-condition of any successful programme for removal of poverty'—the same thing in

other words. It is only re-phrasing; paraphrasing and saying the same thing in some other way. That is all. The same people are there to prepare the budget. They have to look into the previous budget. Mr. Patel might not have looked into it, but they have to see that and they have to take pains to say the same thing in different words. I will not go into the points raised by Mr. Biju Patnaik yesterday. I am afraid you may ring the bell at any moment. But I only want to ask him: Why do you want to re-order the priorities? As far as the private sector goes he has given concessions after concessions. Will he take the House into confidence? Will he tell us how much it has cost the exchequer? Will he tell us how much this costs the poor man in the country? He has not said this. But he has heaped concession upon concession on the private sector. I do hope that in his reply he will come and tell us what all these things cost to the exchequer the country and to the poor man of the country utimately. This is my request to him.

Where does he want to re-order the priorities? Is it in the public sector? I say this because we are inevitably led to the suspicion. The conclusion is inescapable. The suspicion is that he may meddle with the public sector. He has not one good word to say about the public sector. It has done extremely well and I can quote any amount of figures. The growth rate is 15 per cent in 1975-76 and it is 11 per cent in 1976-77. Mr. Biju Patnaik pointed out this thing yesterday. Our steel production has gone up. But we have not been able to sell all the steel within the country. There is accumulation of stocks. But are you going to stop production itself? I say this because there is a fear that when it comes to reordering priorities, the Janata Government may interfere with, meddle with, the further growth of the public sector. The suspicion gets confirmed by what one of the spokesman said and what the Minister stoutly denied. One of the spokesmen said that the commanding heights of the economy will not be permitted to be managed by the public sector. They will be entrusted to the private sector. This is what one of your self-proclaimed economist said. So, Sir, this is the conclusion to which we are evidently driven. The question is whether the Janata Government, in reordering of the priorities—which it says, it is not able to do just now,—going to interfere with the growth of the public sector in this country which has given a good account of itself. That is the main question how.

Yesterday Mr. Biju Patnaik got angry with Mr. C. Subramaniam who referred to the budget as swatantra budget. We should get into the background of the Janata now. Shri Jaya Prakash ji has been the inspirer of the total revolution, which at its crest, brought about the present Janata Government and he may be considered to be the godfather of this Government. But, I would tell you who the real godfather is The real godfather of this government is Rajaji in Heaven. It was Rajaji who said that the Congress in this country is moving more and more towards the left under various influences. Therefore, as an alternative, as a balancing factor, we need to have a rightist party, and that is why he created the Swatantra party. He very much desired that the Congress Government should be replaced by a rightist Government, namely, the Swatantra Government. Unfortunately, this objective of his could not be realised during his lifetime but he should be glad in his heavenly abode—I hope he is in heaven—to see that the government of his conception has now taken over.

Mr. Chairman, whatever may be character of this party, this party can be compared to *'khichri'*....

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : यह खिचड़ी आपको हजम नहीं होती है ।

SHRI O. V. ALAGESAN: Among the ingredients of this 'khichri' you do not find the name of Swatantra but it is salted and flavoured by Swatantra. This aspect has been well brought out by Mr. Patel in his budget by giving concession after concession to the priavte sector.

You had a comfortable position of foreign exchange reserves at the end of 1976-77. It amounted to Rs. 2,863 crores. I am told today it stands at Rs. 3,360 crores. Even this was considered to be a burden by my friend. Shri Biju Patnaik. You are going to draw Rs. 800 crores out of this. The Finance Minister has not spelt out as to what is he going to do with these Rs. 800 crores. I understand various committees at the government level have been doing an exercise as to how to utilise it. If you had drawn Rs. 870 crores from these reserves, then your budget could be called a balanced budget and if you had drawn Rs. 900 crores, then it could be called a surplus budget. There are some reports to the effect that this sum will be utilised to buy more ships and trawlers.

MR. CHAIRMAN: At this stage I would like to point out that you have three triangular steel plants in the South which are yet to come up. These steel plants had been promised sufficient money but I find sufficient money has not been allotted. The foreign exchange reserves can be utilised for purchasing machinery to bring these three steel plants to fruition at a much earlier date.

I am glad to find that a sum of Rs. 13 crores has been allotted for the Salem steel plant. Last year only Rs. 3 crores had been allotted but as the year advanced, the then Steel Minister and the then Prime Minister wanted to give more money. I am happy that a larger sum has been allotted for this purpose now. Then a word about the Kalpakam atomic power plant. It has been delayed for quite a long time and I find that the provision made for both the units now is even less than what was made last year. I do not know why is it so. We are told that the first unit will become critical in 1979 and go into production in 1980. The second unit will become critical in 1981 and go into production only in 1982.

Mr. Ramachandran, please see that all these things come up when you are the Minister of Energy. So some thing should be done to expedite these things whether it is more money or whether it is something which can be purchased with a huge amount of foreign exchange that is at your command. So you do something and expedite to see that these things come up much earlier.

17.00 hrs.

Then, for Neyveli a provision of Rs. 46.76 crores has been made out of which a paltry sum of Rs. 5 crores has been earmarked for a new lignite based power plant with a capacity of 200 MW. Lignite is available there. Now, this is a half hearted measure. But what we should ask for is that there should be a second mine cut. We do not want a 200 MW plant there. We cannot jump on to a 1000 MW plant even at the first stage. This can be done in stages. But it should be a 1000 MW power plant based on a second mine cut. It is all right, you are going to increase lignite to 6 million tons capacity and above as the immediate programme. But as far as the second power station is concerned, you should be clear that it should be a 1000 MW power plant based on a second mini-cut.

Then I come to handlooms. My constituency is full of handloom weavers. Of course, Tamil Nadu consists of a large number of handloom weavers. An exemption from duty has been given to 20s. Now the handloom weavers do use yarn of 40s and 60s also and a lesser exemption has been

given—a small reduction in duty has been given—with reference to 40s and 60s. I would plead that if the exemption has been given to 20s, it should also be given to 40s and 60s. A lot of concessions have been given to powerlooms. We have no objection to powerlooms being encouraged, but there is a factor which should be taken note of. There is a possibility that the powerlooms would set themselves up as a very powerful competitor and as a harmful competitor to handlooms. I am told that the Sivaraman Committee recomended that handlooms should be protected against powerlooms. This is a step in the right direction. At present you should not set up a powerful competitor against the handloom industry and against the poor weavers who are eaking out their livelihood from this industry. This has to be examined very carefully. Whatever concessions you have given to powerlooms should not in any way harm the interests of lakhs and lakhs of handloom weavers. Sir, this is all what I wanted to say.

श्री रामजी लाल सुमन (फीरोजाबाद): अध्यक्षता महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया यह बजट निस्संदेह अब तक जो बजट पेश किये गये हैं उन की तुलना में एक अच्छा बजट है और जनता पार्टी ने लोक सभा चुनावों में जनता के साथ जो वायदे किये थे, उन वायदों को पूरा करने का काम इस बजट में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वित्त मंत्री ने इस में बजट चार चांद लगाये हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर जो इस बजट में रखी गयी हैं

मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि रुग्ण उद्योगों को स्वस्थ उद्योगों के साथ जोड़ना जहां ठीक है वहां मुनाफ़े की दर पर भी असर पड़ेगा और राजस्व की हानि होगी क्योंकि रुग्ण उद्योग पूंजीपति अपने हित में करते हैं। वे अपने मिल का विकास और आधुनिकीकरण तो नहीं करते बल्कि दूसरे उद्योगों में अपनी आय लगाते हैं। परिणामस्वरूप मूल उद्योग रुग्ण हो जाता है तथा दूसरे उद्योग उभरते हैं। इसके लिए अच्छा यह होगा कि रुग्ण उद्योगों के मालिकों के जो अन्य उद्योग हों, उनके साथ इन्हें जोड़ा जाए तथा इन मामलों की उचित जांच की जाए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के लिए 85.67 करोड़ की व्यवस्था है और स्कूली शिक्षा पर 4.35 करोड़ की व्यवस्था है। जनता पार्टी 12 वर्ष में सब को कम से कम मिडिल तक शिक्षा देना चाहती है। अगर स्कूली शिक्षा पर व्यय इसी अनुपात में रहेगा तो 12 के स्थान पर 22 वर्ष में भी सब को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जिससे देश के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो धनराशि शिक्षा पर खर्च की जा रही है वह कम है—शिक्षा पर और ज्यादा धनराशि खर्च होनी चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य के लिए 83.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसमें से चिकित्सा पर 11.48 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि है, जिसमें भारतीय पद्धति तथा होम्योपेथिक पद्धति के लिए केवल 2.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस देश में आयुर्वेदिक दवाएं जन जन तक पहुंचती हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए न तो कोई रसायनशाला सरकार खोल रही है और न ही उसके लिए कोई विशेष धन दे रही है जबकि स्वास्थ्य मन्त्री जी रोजाना यह कहते हैं कि देश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली का विकास होगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा हैं उस पर इस सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता देहातों में निवास करती है

[श्री रामजी लाल सुमन]

इस देश में 80 परसेन्ट लोग देहातों में रहते हैं और जहां पर जिन देसी दवाओं का प्रचलन विशेष रूप से होता है, उन पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए ।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में एक बात कही गई थी और वह यह थी कि जनता पार्टी की सरकार अगर केन्द्र में आसीन हुई, तो वह झुग्गी-ध्वंस होने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी । इसमें उनको बसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । बुल-डोजर के शिकार हुए लोगों को बसाने का वायदा जनता सरकार ने किया था मगर बजट में आवास मन्त्रालय के लिए जो 26.58 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, उनमें इन व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । सौन्दर्यकरण के नाम पर जो हजारों लोगों को उजाड़ा गया है, जनता पार्टी की सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए । मेरा मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे इन लोगों की तरफ विशेष ध्यान दें ।

ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 83.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें खादी ग्रामोद्योगों के लिए केवल 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । हथकर्घा उद्योग के लिए 16.75 करोड़ की अल्प राशि रखी गई है । यह बहुत अल्प धनराशि है और ग्रामों में सभी बेरोजगारों में से केवल 5 प्रतिशत को ही इस राशि से रोजगार दे पाएंगे । मैं आप के माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और सरकार को चाहिए कि इस पर गंभीरता से ध्यान दे और ज्यादा राशि इसके लिए रखे ताकि बेरोजगारी का निदान हो । नहीं तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं ।

जहां तक सड़कों का सवाल है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चुनाव के वक्त बहुत सी सड़कें बनाने का वायदा जनता के सामने किया गया था और जहां पर सड़कें नहीं थीं, वहां पर नाप का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था । जहां सड़कें अधूरी हैं, उन सड़कों का निर्माण किया जाए । जनता पार्टी की सरकार को इन सड़कों के निर्माण के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिएं । बजट में सड़कों के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो कि बहुत कम है । सरकार को चाहिए कि इसमें और धनराशि जोड़ कर सड़कों का निर्माण कार्य तेज करे ।

जहां तक पीने के पानी का सवाल है इसके लिए भी 40 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है । यह अच्छा काम है । लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो धनराशि खर्च की जाए उससे जनता को लाभ पहुंचे । इससे पहले इस मद में जो धनराशि खर्च की गयी उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हिदायतें दे कि इस काम को जन प्रतिनिधियों के सहयोग से अच्छे ढंग से पूरा करें । पीने के पानी की व्यवस्था का गांव वालों के लिए बड़ा महत्व है ।

हरिजनों के लिए सुविधाएं उनके गांव के पास ही मुहैया होनी चाहिएं । जहां तक उनके लिए प्रावधान का सम्बन्ध है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए इस बजट में कोई धनराशि नहीं रखी गयी । शिक्षा के नाम पर भी इस बजट में हरिजनों के लिए कोई प्रावधान नहीं है । उनके लिए छात्रावासों और विद्यालयों में स्थान का प्रबन्ध होना चाहिए । इस देश में जो लोग हरिजन हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों की दशा सुधारने के लिए जरूर प्रयास करें ।

घड़ियों के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क 120 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि तैयार घड़ियों के आयात पर दस प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया है। इससे विदेशी घड़ियों की स्मगलिंग बढ़ेगी। वित्त मन्त्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

धन कर में जो बढ़ोत्तरी की गयी है वह कम है। क्योंकि यह वर्ग सरकार को अधिक कर दे सकता है। यदि वित्त मन्त्री जी 2.5 लाख रुपये पर आधा प्रतिशत के स्थान पर पौन प्रतिशत कर सकते हों तो अच्छा है। जबकि इनकम टैक्स प्रथम श्रेणी में अधिभार के रूप में बढ़ाया गया है। आय कर के लिए जो आयकर की सीमा बढ़ाई गई है उससे ढाई लाख लोगों को लाभ होगा।

कुल मिलाकर इस बजट में जनता की मान्यताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो जर्जर अर्थव्यवस्था छोड़ी है उसमें निस्संदेह जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करना एक साल में सम्भव नहीं है। फिर भी अब जो बजटप्रस्तुत किये जाएंगे वे क्रांतिकारी बजट होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह ठीक है कि यह बजट हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता। लेकिन जो वादे हमने किये थे, उनको किसी हद तक यह पूरा करता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आपने इस बजट में टैक्स बढ़ाये हैं। लेकिन अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उसके बाद लोगों पर टैक्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

जो भी बजट आते हैं अगर वे ठीक से इम्प्लीमेंट किये जायें तो उनसे देश में काफी तरक्की हो सकती है। बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी निर्भर करना पड़ता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के बहुत से राज्यों में अब जनता पार्टी की सरकारें बन गयी हैं जिससे हमें अपने बजटों पर अमल कराने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगी कि वे इस बात को देखें, कि बजट का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो।

अब मैं दो-तीन बातें खेती के लिए कहना चाहती हूं। उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है। खाद के ऊपर कोई खास बात नहीं कही गई है। खाद काफी मंहगा है। जितना वजन लिखा रहता है उतना वजन भी नहीं निकलता है। जहां से पैक हो कर आता है वहां आपको इसको देखना चाहिए। किसान तक कट्टा जब पहुंचता है तो उसका वजन पांच से ले कर दस किलो तक कम निकलता है। जबकि उसमें कीमत पूरी ली जाती है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि जितने वजन की उसे कीमत ली जाती है उतना वजन उसको दिया जाये आपको इसका प्रबन्ध करना चाहिए कि किसान तक पूरा वजन पहुंचे।

एग्योर्ड बिजली और एग्योर्ड पानी भी किसान के लिए आपको देना चाहिए और इसका पक्का इंतजाम करना चाहिए। जितनी पैदावार आज होती है उससे कहीं ज्यादा पैदावार हो सकती है यदि आप इन दो चीजों का पूरा पूरा इंतजाम कर दें।

[श्रीमती च द्रावती]

छोटे किसानों के लिए एक स्कीम चली थी एम एफ डी एक । इस स्कीम के लिए जो पैसा रखा गया था उसका अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स से हिसाब मंगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब इसका सारा पैसा सरेंडर हो गया था । एक मद का पैसा दूसरी में खर्च भी कर दिया जाता है । कही का पैसा कहीं दूसरी जगह चला जाता है। मार्जिनल फार्मर्ज को यह पैसा नहीं दिया गया ।

ऐसा किसी चीज में नही होता है जैसा किसान की पैदावार में होता है । कपड़ा अगर ज्यादा बन जाता है तो कपड़े के भाव गिर नहीं जाते हैं । अगर ज्यादा गज कपड़ा तैयार हो जाता हैं तो उस हिसाब से उसकी कीमतें गिरती नही है। मिल मालिक ही उसकी कीमत तय करते है । लेकिन किसान की पैदावार के साथ यह बात नही होती है । जैसे ही उसकी पैदावार उसके घर में आती है चाहे जो भी जिस की, तिलहन हो, मूगफली हो, मरसों हो, गेहूं हो, चावल हो, जैसे ही वह खेत से उसके घर में आती हैं उसके भाव गिर जाते हैं । उसका इफैक्ट बड़े किसान पर नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसेटी होती हैं और वह उसको स्टोर करके रख सकता है । लेकिन छोटा किसान ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आपने इस पर विचार किया है कि जिस दिन उसके खेत से अनाज इकट्ठा हो जाता है उसी दिन उसकी कीमत घटनी क्यों शुरु हो जाती है और क्या इसका कोई उपाय आपने सोचा है ? अनाज आदि की कीमत घटने से मजदूर को इसका लाभ नहीं पहुंचता है । मजदूर तो रोज ले कर खाता है । उन्हीं को इससे फायदा होता है जिन को एक्सोर्ड इनकम है । एक्सोर्ड इनकम इस देश में गवर्नमेंट सर्वेंट के सिवाय किसी को नहीं है । चपड़ासी को भी मैं इस में शामिल करती हूं । बाकी लोगों की नहीं है । मैं चाहती हूं कि इसका फायदा उनको पहुंचे जिन को पहुंचना चाहिए । किसान तो घाटे में रहता है । इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ।

उसके पीछे चूहे भी लगे रहते है। एक गांव में तो लोग इस वास्ते खुश हो गए कि गांव के चूहे मरवा दिए गए थे । यह बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

मुझे याद है दो साल पहले जो सीड बाजरे का, संकर बाजरे का सप्लाई किया गया था उससे जो बाजरा पैदा हुआ वह कड़वा था । पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया इसके बारे में । किसी प्रकार की किसान की उसने सहायता नहीं की । सहायता की बात तो दूर इस बात तक की जांच नहीं करवाई कि यह कैसे सप्लाई हो गया । इसके बारे में भी इनक्वायरी होनी चाहिए ।

1972-73 की बात होगी । बड़ा भारी गेहूं के सीड का स्कैंडल हुआ था । बम्बई वह भेजा गया था । तब क्या हुआ यह भी इनक्वायरी की मांग करता है । किसान से किस भाव से

लेते हैं और कंज्यूमर को किस भाव से देते हैं यह भी आपको देखना चाहिए ।

छोटी मोटी चीजें हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । प्रिवलेज्ड क्लास कोई नहीं रहनी चाहिए । हाथ की घड़ी सब को नहीं मिलती है । मुझ से दो तीन आदमी दस्तखत करवा करके ले गए हैं । बाजार में सब को यह खुली मिलनी चाहिए । गैस का चूल्हा हर एक गृहणी को चाहिए । इसको आप नहीं कर सके हैं । कुछ ही लोगों को गैस चूल्हा मिला है । सब को मिलना चाहिए ।

पहले वक्ता ने शिक्षा की बात कही और कहा है कि इस में ज्यादा खर्च होना चाहिए । मैं इसको मानती हूं । कि अगर हम शिक्षा ही लोगों को दे दें और कुछ न दें तो वह अपने आप चीजें पैदा कर सकते हैं । लड़कियों की पढ़ाई आज नहीं के बराबर है, पिछले 10 सालों में जो स्कूल , टैक्नीकल स्कूल या सिलाई के स्कूल थे सब डीजेनरेट हो गए । टैक्नीकल स्कूलों की मशीनरी बेच कर खा गए । भ्रष्टाचार का बोलबाला है । मुझे एक बात का अफसोस है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं इन का संविधान में एश्योरेंस दिया गया है इकोनामिक सेक्योरिटी का. यह सब लोग करप्ट हैं । इन को आसानी से हाथ नहीं लगाया जा सकता । करप्ट पोलिटीशियन्स को तो जनता ने छुट्टी दे दी, लेकिन करप्ट सर्विसेज के लोगों में कैसे सुधार होगा, यह चिन्ता का विषय है । जब तक हम लोगों को क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं देते तब तक कोई लाभ जनता को नहीं होगा ।

इसी प्रकार से जो भवन निर्माण का दौर चल रहा है उस पर पाबन्दी लगनी चाहिए, 5 साल तक कोई भवन निर्माण नहीं होगा । भिवानी का एक उदाहरण देना चाहती हूं कि बाबू छज्जू राम जी एक सेठ हुए हैं जिन्होंने एक अस्पताल बनाया था जो 200 साल तक टूटने वाला नहीं था । लेकिन उस को तोड़ कर 6,7 करोड़ का एक नया भवन दिया गया, एक लाइब्रेरी बना दी । जिन्होंने इस तरह नुकसान कराया है उन से पैसा लिया जाय ।

हमारे यहां मुन्डी की पढ़ाई होती थी जो दुकानदार का पहला पाठ होता था । इसी तरह से अपने स्कूलों में चाहे खेती हो, दुकानदारी हो, ज़मीन मैनेज करने की बात हो जब तक शिक्षा को उस तरह का नहीं करेंगे जिस से इन कामों में लगे लोगों को लाभ मिले तब तक बेकारी का कोई हल हम नहीं निकाल सकेंगे । आखिर कितने कलर्क दफ्तरों में भर्ती करें ? इनऐफिशियेंसी की एक यह भी वजह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत भारी है । हरियाणा में 5 जिले के 10 जिले बनाये गए और एक कास्टीट्यूऐंसी का एक एक सब-डिवीजन बना दिया । वहां 20 डी० आई० जी हैं । पुलिस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है । इस तरह के बेकार ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को काट कर वेलफेयर के काम में उस पैसे को खर्च करना चाहिए चाहे हमें वेलफेयर का दूसरा महकमा खोलना पड़े । जंगल लगाने पर ज्यादा खर्च करना चाहिए । बजट में हम कितना पैसा शिक्षा या पानी के लिए देते हैं यह प्रश्न नहीं है । बल्कि प्रश्न इमप्लीमेंटेशन का है ।

मैं पानी का जिक्र जरूर कर दूं क्योंकि खेती से इस का घनिष्ट सम्बन्ध है । मुझे

[श्रीमती चन्द्रावती]

याद है, बहुत दिन हो गए एक बांध बनाना है व्यास प्रोजेक्ट का जो 1973 में पूरा होना था, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान को पानी जा रहा है लेकिन लिंक कैनाल नहीं बनाई गई अभी तक। इन सब कामों में देरी के लिए पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।

अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में दो, चार बात कहना चाहती हूं। मेरा हमेशा विचार रहा है कि सड़क के साथ सभ्यता आती है। हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत घपला है। अगर इस को ठीक तरह से चलाया जाय तो अकेला ट्रांसपोर्ट ही तीन चौथाई बजट को चला सकता है। उस में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आवागमन का साधन हमारे यहां हवाई जहाज होना चाहिए। इस में कई लाभ होंगे, पहला तो यह कि हवाई जहाज ज्यादा बनेंगे जो लड़ाई के समय काम आ सकते हैं, साथ ही बहुत से पायलट भी देश में तैयार हो जायेंगे, और सब से बड़ा लाभ यह होगा कि अगर मुझे मद्रास जाना है और मुझे पता है कि 2 घंटे में वहां से वापस आ जाऊंगी तो मुझे हवाई जहाज से जाने में कोई हिचक नहीं होगी। इस से नेशनल इंटेग्रेशन में बड़ी मदद मिलेगी। लोग पायलट बनना सीखेंगे जो लड़ाई के दिनों में मुफ्त में हम को इतने सारे पायलट मिल सकते हैं और हवाई जहाज भी मिल सकेंगे जिनकी कि इतने बड़े देश को बहुत बड़ी जरूरत है।

मैं उद्योग के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। मैं यहां पहली बार एम० पी० बनी हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ज्ञान तो हरियाणा का ज्यादा है। सन् 1975 के अप्रैल, मई महीने में हमें ऐसा लगा कि शायद बंसीलाल चले जायें और बनारसी दास आ जायेंगे तो मैंने उद्योगों का डाटा वहां इकट्ठा किया था। 27 घोस्ट फैक्टरियां मैंने उस समय भिवानी में गिनी थीं और वह सिर्फ कोयला हड़प करने के लिए थीं। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में कितनी घोस्ट फैक्टरियां हो सकती हैं और कितना कोटा सरकार से लेकर बेचा जाता है। मारुति के नाम से भी कोटा बेचा गया था, दिल्ली के चावड़ी बाजार में मोटर पार्ट्स या शीट्स बनाकर बेचा जाता था।

इसी तरह से अम्बाला में ट्रांसफार्मर की फैक्टरी खोली गई थी, उस वक्त भी सवाल आया था कि तांबा ही ब्लैक में बेच दिया गया होगा। मैं वित्त मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहती हूं कि वह यह देखें कि फरीदाबाद में कितनी फैक्टरियां कागज पर रन कर रही हैं। अगर वह सब काम कर रही हों तो कितने लोगों को इससे एम्पलायमेंट मिल सकता है। यह ठीक ही है कि छोटे उद्योग धंधों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है लेकिन जो बजट रखा गया है, उसमें मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं। एक तो मैं अप्रत्यक्ष कर से सहमत नहीं हूं और एक मैं मिक्सड इकनामी के हक में नहीं हूं। जैसे चीनी की बात लीजिए, आधी चीनी तो कंट्रोल पर बिकती है और आधी बाजार में बिकती है। इससे क्या हुआ कि बाकायदा हम ब्लैक को रिकग्नाइज करते हैं। जैसे स्कूटर है अगर उसके मूल्य पर लेना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लैक में मिल ही जायेगा। इस तरह की चीजें हो रही हैं। हमें प्रोडक्शन के साथ साथ कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है। हम नहीं चाहते कि बड़ी मशीनरी लगाने वालों को कम्पीटीशन ही न हो।

कम-से-कम बड़ी मशीनरी बनाने वालों का भी कंपीटीशन होना चाहिए जिससे अच्छी चीज बन सके, भले ही वह कार हो या कूटर हो। आज इनमें कंपीटीशन नहीं है, इसलिए चाहे जैसी चीज बाजार में आयेगी और जिस प्राइस पर आयेगी, कंज्यूमर को वह लेनी पड़ेगी।

आज आम आदमी की पहुंच तक के लिये रैफ्रीजरेटर क्यों नहीं-मिल सकते हैं। यह बड़े लोगों की चीज़ है, उसको पैसे वाले ही ले सकते हैं। मैं तो चाहूंगी कि 500 रुपये की कीमत के रैफ्रीजरेटर बनें जिससे आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास तक वह पहुंच सके।

विदेशों की चीजों के लिए हममें बड़ा अट्रेक्शन है। इसीलिये हमारे यहां टेलीविज़न है। हिन्दुस्तान में कितने फीसदी लोग टेलीविज़न देखते हैं। मुझे याद है कि हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति की इमेज बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपये के टेलीविज़न आए थे। उसके पुर्जे विदेशों से आते हैं। यहां जो हम कान में सुनने का यंत्र लगाते हैं, यह भी हालैंड का बना हुआ है। जब हम लोगों के रिप्रेजैंटेटिव यहां विदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों का क्या हाल होगा और मैं समझती हूं कि इसीलिए स्मगलिंग बढ़ता है।

मैं बिजली के बारे में भी दो शब्द कहना चाहती हूं। पिछले आंकड़ों से पता चला है कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन जापान जैसे छोटे से देश के मुकाबले में 1/6 है। बिजली का मतलब है वैलफेयर स्टेट—वैलफेयर स्टेट और बिजली का एक दूसरे से सम्बन्ध है, उसके बावजूद भी इतने ब्रेकडाउन हमारे यहां होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बजली के ब्रेकडाउन से उद्योग और खेती दोनों को बहुत नुकसान होता है। ब्रेकडाउन का कारण इनएफ़िशेंसी भी है और घटिया सामान भी। बताया जाता है कि कुछ उद्योग धंधों द्वारा बनाई गई चीजों के लिए स्टैंडर्ड का सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जिससे इनएफ़िशेंसी बढ़ती चली गई है। करप्शन और इनएफ़िशेंसी इकट्ठे हो जाते हैं। हम कितना भी बढिया बजट बनायें, लोगों को कितना भी इनिशिएटिव दें, लेकिन अगर हम उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और अगर हम भ्रष्टाचार के रास्ते बन्द नहीं करेंगे, लूप होल्ज़ को प्लग नहीं करेंगे, तो फिर चाहे इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस या कोटे का सवाल हो, चाहे खेती के औज़ार बनाने का मामला हो और चाहे बाहर से खाद मंगाने का प्रश्न हो, हम किसी भी क्षेत्र को भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रख सकेंगे।

हमारे देश के लिये जंगलात का भी बहुत महत्व है। उनके कट जाने से छोटी छोटी नदियां रास्ता बदल लेती हैं। हमारे अम्बाला ज़िले में एक नदी के रास्ता बदलने के कारण उस पर दो पुल बनाये गये। अगर ज्यादा जंगल लगेंगे, तो नदियां रास्ता नहीं बदलेंगी। चिरापूंजी में भी अब पहले की सी बरसात नहीं होती है, क्योंकि वहां ज्यादातर जंगल काट लिये गये और उनकी जगह नये जंगल नहीं लगाये गये।

हमारे देश की असली तरक्की उस वक्त होगी, जब गांव का बढ़ई, जो हल बनाता था, जिसके दादा-परदादा हजारों वर्षों से हल बनाते आ रहे थे, उसकी जगह ट्रैक्टर बनाने लगेगा, जब गांव का आर्टिसन चमड़े का कारखाना लगायेगा, जब तानी बुनने वाला हैंडलूम लगायेगा। जब ऐसी व्यवस्था की जायेगी, तभी हम समझेंगे कि हमारा बजट विलेज-ओरियंटिड है। केंद्रीय सरकार को प्रदेश सरकारों को यह हिदायत करनी चाहिए कि यहां जो पालिसी बनाई जाती है, वे उसको रिलिजसली इम्प्लीमेंट करें।

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Budget proposals. I congratulate the Finance Minister, Mr H. M. Patel, for well-drafting the Budget proposals though the lofty Janata mountain has delivered only a mouse.

[Shri Manoranjan Bhakta]

He has stated in his Budget speech about agriculture and rural development. I quite understand his sentiments and I congratulate him for such a measure. But simultaneously I feel that he has not mentioned anything about land reforms. If there is no land reforms in the country, I cannot understand how these things are going to be implemented.

In the Budget he has shown a deficit of only Rs. 72 crores. It is only a manipulation because he has drawn Rs. 80 crores out of the foreign reserves. The previous Government can certainly claim the credit for this achievement due to which the Janata Government could get this much amount and show a deficit of only Rs. 72 crores.

But, in the meantime, I cannot understand why he has not drawn another hundred crores by which he could say that there is surplus budget. Of course, Dr. Subramaniam Swamy is not here and his friends could have easily beaten the drum, because of the surplus budget. I am not to criticise anybody personally here, but I observe that in the Finance Minister's speech, he has not mentioned anything about the working class, though I understand that many of the leaders who are now sitting on the Treasury Benches, they were fighting for the working classes for many years in the past. There are so many temporary workers. They have already worked in the CPWD and other departments for so many years, but still they are not made permanent. In his budget speech, he has not indicated for making them permanent.

As far as National Wage Policy is concerned, it is very much necessary, because I understand that two young men having the same qualifications are getting different emoluments—one is working in a bank and he is getting more emoluments than the other man who is working as LDC in the Government's Department. The LDC is getting less emoluments. If this type of disparity is not removed, we cannot serve the working class properly.

I come from a territory which is far away—as you know Andaman and Nicobar Islands. It is well-known as *kala pani*. There the local Government employees are denied Andaman special allowance. They have been fighting for a long period for this purpose. I appeal to the new Janata Government that they should consider this particular point. I know that in Arunachal Pradesh special allowance is given to all the Government employees. When they are getting it, why it should not be given to the employees of Andaman and Nicobar Islands. I appeal to the Government to keep this thing in mind and see that they should also be given Andaman special allowance irrespective of the place of recruitment and residence.

As far as central excise is concerned, it is mentioned here 23 paise, is alone earned by the Central Exchequer. But I do not find anything specific has been done for the welfare of the central excise staff. This machinery should be much more streamlined for the effective collection of revenue.

I find that in this budget nothing has been provided for them. In the Central Excise Department, for the collection of revenue, he has suggested change specific to *ad valorem*. I understand that the *ad valorem* system is much more progressive, radical and rational, but until and unless the machinery is not ready to cope with the new system, how he is going to solve the problem of litigation, because already there are a large number of litigations pending in the Central Excise Department. If you do not correct this machinery, then there will be many more litigations. In future, this point should be kept in mind.

We are aware that thousands and thousands of East Bengal refugees are rotting in the Mona camp and other places and they are not still rehabilitated. I have to say this with deep regret that in the budget speech, he has not mentioned anything for those homeless people; he has not mentioned when he is going to rehabilitate all these people. That is not a big problem now. All the old people who are in the Mona camp should be rehabilitated. On this issue proper care and attention is very much necessary.

I belong to a very backward territory of the country. Once upon a time this territory was chosen for life transportation of Indian patriots by the Britishers—the cellular jail, Bastile of India, having hallowed memories of the national liberation movement. The Andaman and Nicobar islands in the midst of Bay of Bengal, a group of 319 small and big islands, constitute a cosmopolitan Indian society, irrespective of caste, creed, religion and language—symbolic of a mini India.

This Union Territory is still under bureaucratic rule. Time and again the people of that Territory have been voicing their demand that they should be given this democratic right of having a popular set-up like Arunachal Predesh, Pondicherry and other Union Territories. The Janata Government are advocating for democracy, many of their Members say that they have liberated the people, that they are working for the restoration of democracy. I would like to appeal to them to think of providing this democratic right to us, to instal a popular set-up in the Andaman and Nicobar Islands. The Territory is now under the bureaucratic rule of the Chief Commissioner and is directly administered by the Union Home Ministry. Six types of very poor tribal people are residing there, people from all over the country, from north to south, are residing there; they belong to the working class; they are poor, tribal people. There are no roads, there is no provision for supply of drinking water. All these years there was no political murder there, but now due to the instigation of my old friend, this time, that also has happened, for the first time in the history of Andaman and Nicobar Islands, there was a political murder on 8th June. I tried to raise this issue in the House, but could not get the time. I tried many times to meet the Union Home Minister, but I could not, I do not know what happened, either the message was not conveyed to him by his personal staff or he did not like to meet me. As ours is a Union Territory and is under the direct administration of the Home Ministry, it is very necessary for us to meet the Home Minister frequently in connection with all these issues.

In this budget I do not find any specific incentive being provided for the industrial development of the bockward districts. I would like to appeal to the Finance Minister to draw up a programme for providing necessary incentives for development of backward districts in the country and, as my district and my territory is one of the most remote and backward territories, I would like proper care to be taken of it by the Finance Minister.

The Hon. Finance Minister has not considered the income-tax payers belonging to the salaried class being exempted from the compulsory Deposit Scheme which has been extended for another two years. I would appeal to him that at least the salaried class should be exempted from this.

While concluding I would like to mention another interesting point which I have noticed. There is no mention about smugglers and tax-evaders in the Budget speech. Does this mean that the drive against black-money and smuggling has been so well

[Shri Manoranjan Bhakta]

done by the earlier Congress Government that there is no need now for taking steps to curb blackmoney in the country?

Before I conclude I would once again request that the cooperatives, which play a vital role in the distribution system, should also be left out or exempted from income-tax up to Rs. 1,00,000.

I thank you very much for giving me an opportunity to speak.

SHRI SHEO NARAIN (Basti):

"For the last 21 months, the country lived through under the nightmare of absolute rule, wherein people were deprived of their fundamental rights and civil liberties, the judiciary lost its independence, the press was muzzled and the voice of dissent was silenced".

ये लाइनें मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं ताकि इन लोगों के काले कारनामों का एक चित्र आपके सामने आ जाए । यह किसने कहा है ? यह दादा कृपलानी ने कहा है जो कि 93 वर्ष के बुजुर्गवार हैं और कांग्रेस के सर्वेसर्वा रहे हैं । **ही इज दि फादर आफ दि कांग्रेस** ।

अब मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस बजट के लिए सुब्रहमणयम साहब ने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई दी है क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई यह चीज है । हम ने तो जल्दी जल्दी में थोड़ा रद्दोबदल करके बजट दे दिया है ।

'Next year you will get the real Janata Budget'.

अब मैं आपकी इजाजत से वर्तमान जनता सरकार से कहना चाहता हूं कि आप उनकी नकल न करें और उनके कदमों पर आपको नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह सरकार जनता की बनाई हुई है । न यह मोरारजी की सरकार है और न मेरी सरकार है बल्कि पीपुल्स गवर्नमेंट है । सब से पहले जो नेशनल प्राब्लम है, उसको हमें सोल्व करना चाहिए । बरसात होने जा रही है । घाघरा नदी के किनारे से मैं आता हूं और 36 मील तक वह फैली हुई है । मैं बिहार के इरिगेशन के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से कहना चाहता हूं कि उस नदी को कन्ट्रोल करें । उस पर केवल 80 करोड़ रुपया खर्च आएगा । अगर इतना रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट खर्च कर दे तो हम सारे बंगाल को चावल खिला सकते हैं ।

सभापति जी, फूड और एग्रीकल्चर की प्राब्लम है । यह इस देश की बड़ी समस्या है । 80 परसेंट लोग गांवों में बसते हैं । अन्न के लिए सारे देश में हाहाकार मचता है । इसको देख कर हमारी नयी गवर्नमेंट ने क्या किया ? हमने गांव गांव में जनता को आश्वासन दिया कि तुम्हारे गेहूं का दाम चरणसिंह दिलवाएगा, तुम्हारे गन्ने का दाम चरणसिंह दिलवाएगा । जब 105 रुपये क्विंटल दाम था तो मैंने चरण सिंह जी के कान में कहा कि हमने उनके दाम बढ़ाने का आश्वासन उन्हें दिया है और उसी पर उनसे वोट मांगे हैं तो गेहूं का दाम 110 रुपये क्विंटल हुआ । दूसरा काम इस गवर्नमेंट ने यह किया कि कण्ट्रोल को रिवोक किया । हमने गेहूं को फ्री कर दिया । आपने इसको बन्द कर रखा था । गेहूं का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था । आपने सबको बन्द कर रखा था । इसके लिए गवर्नमेंट बधाई के पात्र हैं ।

अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं । पिछली गवर्नमेंट ने गांव गांव में ट्यूबवेल खुदवाये । यह गलत काम नहीं था । लेकिन इन ट्यूबवेलों को बिजली 24 घंटे में आध घंटे मिलती । शहरों में एयर कंडीशनर चलते, पंखे चलते । अध्यक्ष महोदय हमसे

तीन रुपये से पन्द्रह रुपये फी होर्स पावर वसूल किया जाता । हर महीने हमें 117 रु० 8 आने जमा करना पड़ता है । हम कंज्यूमर हैं, हम बिजली कंज्यूम करते हैं लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती । अब कहां से हम टैक्सेशन दें, कहां से हम बिजली का दाम दें ।

गन्ने का दाम सवा बारह रुपये क्विंटल हमको मिला है । जबकि एक क्विंटल में दस किलो होती है । दस किलो चीनी के पचास रुपया मिल मालिक को मिलते हैं । हमको सवा बारह रुपये और मिल-मालिक को पचास रुपये । कितना मुनाफा । मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि किसान को गन्ने का सही दाम दिया जाए । मैं यह भी कहता हूं कि चीनी को डीकंट्रोल किया जाए । क्यों इसको फोरन में भेजा जाता है ? आप इसको अमेरिका में दो रुपया किलो में बेचते हैं और गांव में यह पांच रुपये किलो में मिलती है । आपको पैसा चाहिए तो आप अपने मुल्क वालों से लीजिए । हम अपने लोगों को उपवास करायें तथा दूसरों लोगों को चीनी दें । यह इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का नमूना है । मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि पहले अपने मुल्क को को खिलाओ तब अगर बचे तो इसे बाहर भेजो । गन्ने का लाखों रुपया मिल मालिकों के पास बाकी है । मैं कहना चाहता हूं कि इसको वसूल करके किसानों को दिया जाए । किसानों ने हमको पांच साल का टाइम दिया है । पांच साल का समय असेम्बली में दिया है और पार्लियामेंट भी में पांच साल का समय देकर हमें थम्पिंग मेजोरिटी में भेजा है । इसलिए हमें किसानों के लिए बहुत कुछ करना है ।

अब मैं शिक्षा पर आता हूं । मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी पालिसी को चेंज करो, नयी पालिसी लाओ । मुल्क में हर जगह पर चाहे वह पंजाब हो, चाहे असम हो, चाहे कश्मीर हो, एक ही करीकुलम हो । सारे मुल्क में शिक्षा का एक करीमकुलम होना चाहिये । बंगाल, असम, काश्मीर देश का कोई भी भाग हो वहां पर एक प्रकार का करीकुलम होना चाहिए ।

दिल्ली के नतीजे निकले हैं । यह खबर निकली है कि कई हजार बच्चों को एडमीशन नहीं मिल पाएगा । सबको एडमीशन मिलना चाहिये । जब कालेज खुलेंगे तो इस कारण से जुलाई में हंगामा न मचे इसका आपको प्रबन्ध करना चाहिए । हड़तालें हों, बकवास हो यह नहीं होना चाहिये । हम लोगों ने फ्रीडम आफ स्पीच दी है, इस वास्ते सामने बैठे हुए माननीय सदस्य ललकार रहे हैं । इंदिरा जी के राज में इनकी बोलती बन्द थी । ये बोल नहीं सकते थे । राम और रावण की सीता की वजह से लड़ाई हुई । द्रोपदी की वजह से महाभारत हुआ था । इन्दिरा जी के सामने ये सब नपुंसक हो गए थे । ये बोल नहीं सकते थे । नसबन्दी जब शुरू हुई तब क्या.....

MR. CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs has to make a statement on behalf of the Home Minister. You continue tomorrow.

Now Minister of Parliamentary Affairs will make a statement.

17.55 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

PROCLAMATION REVOKING PRESIDENT'S RULE IN HIMACHAL PRADESH

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): On behalf of Shri Charan Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated the 22nd June, 1977 issued by the Vice-President acting as President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 30th April, 1977 in relation to the State of Himachal Pradesh, published in Notification No. G.S.R. 391(E) in Gazette of India dated the 22nd June, 1977, under article 356(3) of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT-469A/77].

STATEMENT *RE.* POWER SHEDDING IN DELHI AND THE CLOSURE OF UNIT NO. 1 IN BADARPUR THERMAL POWER STATION

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): A section of the workers of Badarpur Termal Power Project went on a lightning strike on the morning of 18th June. As a result, the only machine of 100 MW which was in operation had to be stopped. The demands raised by the workers related to matters pertaining to recognition of the Union, improvement in pay and allowances, regularisation of Muster Roll and work-charged employees and re-instatement of some dismissed employees, etc.

The power requirements of Delhi are met by generation from the stations of Delhi Electric Supply Undertaking supplemented by generation from Badarpur Thermal Power Station. The total stoppage of generation from Badarpur has aggravated the power shortage in Delhi necessitating recourse to load-shedding.

The situation has been generally peaceful and I am glad to inform the House that thanks to the intervention of my colleague Shri Ravindra Varma, Minister for Labour and Parliamentary Affairs, an understanding has been reached between the Management and the workers. The strike has since been called off, and steps have been initiated to re-start the unit.

श्री हुक्म चन्द कछवाय (उज्जैन) : जो वक्तव्य मन्त्री महोदय ने रखा है उसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर जिन कारणों से हड़ताल हुई थी उनको दूर कर दिया जाता । हड़ताल का पहले से नोटिस दिया गया था । उनकी कुछ समस्यायें थीं, मांगें थीं । इस सरकार ने जानबूझ कर उन मांगों को मंजूर नहीं किया और उन लोगों को मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा । सरकार को इस कारण से काफी क्षति उठानी पड़ी है । मजबूर होकर उन लोगों को यह कदम उठाना पड़ा है । भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए । जब कभी हड़ताल का नोटिस आए, जब कभी मजदूरों की कोई जायज मांगें हों सरकार को उनके साथ समझौता वार्ता करके उनको हल कर लेना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN: You please meet the hon. minister tomorrow and then say what you want to say.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): There is only an inner contradiction between the members of ruling party.

We are not getting water in the M.Ps flats in the North Avenue since this morning. I bring it to the notice of the Minister of Energy. Mr. Kachwai is talking of a strike.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Hon. members are not allowed to raise questions after the statement is made by the Minister. I hope you are not allowing a departure from the practice.

चौधरी बलवीर सिंह (होशियारपुर) : आप कांग्रेस वालों को कहें कि जो फ्लैट्स उन्होंने रखे हुए हैं उनको वे छोड़ दें । यह उनका मार्किट रेंट दे सकते हैं क्योंकि इनके पास हराम की कमाई है । हमें मकान नहीं मिल रहे हैं ।

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 23, 1977/Asadha 2, 1899 (Saka).

GMGIPND—L—771LS—998